राष्ट्रीय संस्करण

CopyRight - Jagran.com

शतकों की हैट्रिक पर होगी मयंक की नजरें

>> 14

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 131

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 19 अक्टूबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सरोकार

उत्तर प्रदेश में अंत्योदय की खातिर 'ग्राम उदय'

अंबेडकर नगर : उप्र के फतेहपुर मानिकपुर गांव में भी दूसरे गांवों की तरह

समस्याएं थीं, अब अंत्योदय के खातिर यहां 'ग्राम उदय' हो रहा है। अब इस गांव में देसी-विदेशी पुस्तकों से समृद्ध लाइब्रेरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहित युवाओं की मदद के लिए अलग-अलग समितियां भी हैं। (पेज-10)

जागरण विशेष

नक्सलगढ़ के बच्चे गोलियां नहीं दनादन दागते हैं गोल

भिलाई : छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र राघाट और आसपास के 64 गांवों के बच्चों

की खेल प्रतिभा को भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) निखार रहा है। यहां के 40 से अधिक बच्चे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और खो-खो में राष्ट्रीय स्तर पर रहे हैं। (पेज-10)

हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या, आइएस पर शक

दुस्साहसिक वारदात ▶ लखनऊ में दो हत्यारों ने पहले जबड़े में गोली मारी, फिर शरीर पर चाकू से 13 वार भी किए

आवास में सुरक्षाकर्मी की मौजूदगी में दिया गया घटना को अंजाम, पैदल ही भाग गए हत्यारे

जागरण संवाददाता, लखनऊ

हिंदू महासभा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की शुक्रवार को उनके लखनऊ स्थित आवास में सनसनीखेज तरीके से दिनदहाड़े गला रेतकर हत्या कर दी गई। कमलेश अयोध्या मामले में एक पक्षकार भी थे। उनकी हत्या ऐसे समय की गई जब इस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ दिनों में फैसला सुनाने वाला है। हत्यारों ने कमलेश के चेहरे पर गोली भी मारी है। साफ है कि हत्यारे यह तय करना चाहते थे कि किसी तरह कमलेश की जान न बचे। हत्यारे वारदात के बाद पैदल ही भाग निकले। इस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस हाई अलर्ट पर है। हत्याकांड की जांच के लिए डीजीपी ओपी सिंह ने एसआइटी का गठन किया है।

कमलेश तिवारी फाइल फोटो

सीसीटीवी फुटेज में कैद कमलेश तिवारी के संदिग्ध हत्यारे

पत्नी से कहा था, कोई बधाई देने आ रहा है

कमलेश की पत्नी किरन ने बताया कि पति के मोबाइल फोन पर किसी ने कॉल कर अयोध्या राम मंदिर मामले की सुनवाई पूरी होने पर बधाई देने के लिए घर आने की बात कही थी। इसके बाद कमलेश ने उन्हें कमरा ठीक करने के लिए कहा था। कमलेश के मकान के निचले हिस्से में हिंदू समाज पार्टी का कार्यालय है।

कमलेश लंबे समय से सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगा रहे थे और यह वारदात तब हुई जब उनके घर के बाहरी हिस्से में एक पुलिसकर्मी मौजूद था। बता दें, गुजरात एटीएस ने एक वर्ष पूर्व इस्लामिक स्टेट (आइएस) के दो आतंकियों के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया था,जिसमें कमलेश की हत्या की साजिश रच जाने का जिक्र था। 13 अक्टूबर 2019 को कमलेश ने एक ट्वीट पीएम, गृहमंत्री को टैग किया था।

लखनऊ में भगवा कुर्ता पहने दो बदमाश मिठाई के डिब्बे में चाकू और पिस्टल छिपाकर कमलेश के आवास में सुबह करीब 11:47 बजे घुसे थे। दोनों करीब 36 मिनट तक घर में रहे। इस आधार पर पुलिस का मानना है कि हत्यारे कमलेश के संपर्क में थे। जब यह वारदात हुई, तब कमलेश घर के ऊपरी हिस्से में बने कमरे में अकेले थे। बेटा ऋषि और पार्टी कार्यकर्ता सौराष्ट्र सिंह बाजार गए थे। पत्नी किरन चाय देकर दूसरे कमरे में चली गई थीं। कमलेश के घर की पहली मंजिल में सीसी कैमरा लगा हुआ था। हालांकि यह कैमरा काम नहीं कर रहा है।

16 अक्टूबर की रात खरीदी गई थी मिठाई : हत्यारे जिस मिठाई का डिब्बा लाए थे वह सूरत (गुजरात) में 16 अक्टूबर की रात 9:30 बजे खरीदी गई थी। डिब्बे में मिले बिल से इसका पता चला। 13 अक्टूबर को कमलेश ने ट्वीट कर अपनी सुरक्षा पर सवाल उठाया था।

कमलेश की हत्या के पीछे आतंकी संगठन की किसी साजिश को भी नकारा नहीं जा सकता। कमलेश की पत्नी किरन ने बिजनौर के मुफ्ती नईम काजमी व मौलाना अनवारुल हक के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। ज्ञात हो, इन दोनों ने एक समय कमलेश की जान लेने के लिए 1.61 करोड़ के इनाम का एलान किया था।

पैगंबर मुहम्मद पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी : कमलेश 2015 में तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने पैगंबर मुहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद कमलेश पर रासुका के तहत कार्रवाई हुई थी और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट : पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारों ने कमलेश तिवारी के बाएं जबड़े पर गोली मारने के बाद गला रेत दिया। इसके बाद धारदार हथियार से गला रेत दिया और श्वास नली कटने से उनकी मौत हुई। उनके शरीर के ऊपरी हिस्से में 13 घाव चाकू के वार से हैं।

हत्या के पीछे इस्लामिक स्टेट के कनेक्शन से इन्कार नहीं पेज>>5

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। हत्यारे कमलेश के परिचित लग रहे हैं। कॉल डिटेल से भी कई जानकारियां मिली हैं। 48 घंटे में घटना का राजफाश हो जायेगा।

-ओपी सिंह, डीजीपी

कमलेश हिंदू महासभा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। महासभा की तरफ से वह अयोध्या मामले को देख रहे थे। ऐसे में उनकी हत्या में राममंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के पहले देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश लग रही है। राज्य सरकार हत्या की जांच कराए और शामिल लोगों को पकड़े। साथ ही कमलेश के परिजनों की मदद करे।

-चक्रपाणि, अध्यक्ष, हिंदू महासभा

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

जस्टिस बोबडे हो सकते हैं देश के अगले मुख्य न्यायाधीश

नई दिल्ली : सीजेआइ रंजन गोगोई अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए शरद अरविंद बोबडे के नाम की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट की परंपरा है कि मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने से पहले अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश सरकार को भेजते हैं।

महासमर ▶ पृष्ठ 4

राहुल बताएं उनके परिवार ने आदिवासियों के लिए क्या किया

गढ़चिरौली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर रोष प्रकट करते हुए उनके नेता राहुल गांधी से पूछा है कि पिछले 70 सालों में उनके परिवार की चार पीढ़ियों ने आदिवासियों के लिए क्या किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले पांच साल में यह क्षेत्र नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

भारत अभी भी सबसे तेज गति वाली इकोनॉमी : सीतारमण

वाशिंगटन : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आइएमएफ द्वारा विकास दर का अनुमान घटाने के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेज विकास करने वाली इकोनॉमी है।

आजकल ▶ पृष्ठ 16

पहली बार सिर्फ महिलाओं ने की अंतरिक्ष में चहलकदमी

वाशिंगटन : अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय स्पेस सेंटर (आइएसएस) के बाहर चहलकदमी कर इतिहास रच दिया है। यह पहली बार है, जब सिर्फ महिला अंतरिक्ष यात्रियों की टीम ने आइएसएस के बाहर चहलकदमी की है।

नई चुनौती

टेस्ट सीरीज भारत 2 द. अफ्रीका 0

सुबह 9:30 बजे से

स्थान : रांची

प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने कहा, अयोध्या मामले पर कोई समझौता मंजूर नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले पांच वकीलों ने बयान जारी कर कहा है कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के कुछ हिंदू पक्षकारों के साथ कथित समझौता किए जाने की खबरों से वे अचंभित हैं। वे समझौता प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते।

जिन पांच वकीलों की ओर से मीडिया में बयान जारी किया गया है उनमें यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील शकील अहमद सईद भी शामिल हैं। हालांकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के ही वकील सैयद शाहिद रिजवी ने गुरुवार को मीडिया के समक्ष दिए बयान में समझौते की बात स्वीकारी थी। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दो अपीलें लंबित हैं। इनमें से एक में शकील अहमद एओआर (वकील) हैं और दूसरे में शाहिद रिजवी एओआर हैं।

सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया है समझौता प्रस्ताव : मालूम हो कि 16 अक्टूबर को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई थी, मध्यस्थता कमेटी की ओर से कोर्ट को मध्यस्थता रिपोर्ट सौंपी गई थी। बताते हैं कि रिपोर्ट के साथ एक समझौता प्रस्ताव भी सौंपा गया है जिसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारुकी और चार हिंदू पक्षकारों के बीच समझौते की बात है। इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड कुछ शर्तों के साथ जमीन पर दावा छोड़ने के लिए तैयार है।

मीडिया में आते ही अन्य मुस्लिम पक्ष हुए सक्रिय : ऐसी खबरें मीडिया में आने के बाद से मामले को लेकर चारों ओर उथल-पुथल है। सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने वाले अन्य मुस्लिम पक्षों के वकीलों की ओर से शुक्रवार सुबह मीडिया में बयान जारी कर समझौते का प्रस्ताव स्वीकार करने से इन्कार किया गया। बयान जारी करने वाले वकीलों में एजाज मकबूल, शकील अहमद सईद, एमआर शमशाद, इरशाद अहमद और फुजैल अहमद अयूबी शामिल हैं।

- इस पक्ष के पांच अपीलकर्ताओं के वकीलों ने जारी किया बयान
- सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के कुछ हिंदू पक्षकारों के साथ कथित समझौते की आई थी खबर

समझौते पर बात आगे बढ़ी तो फैसले में होगी देरी

नई दिल्ली : अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद लोगों की निगाहें फैसले पर टिकी हैं, लेकिन बीच में मध्यस्थता से समझौते की चर्चा ने नया पेच उलझा दिया है। इस केस की सुनवाई करने वाली पीठ के अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं इसलिए उसके पहले ही फैसला आने की उम्मीद है, लेकिन कानूनविदों का कहना है कि अगर कोर्ट मध्यस्थता समिति की ओर से पक्षकारों के बीच हुए समझौते पर संज्ञान लेगा तो 17 नवंबर की समयसीमा के भीतर फैसला आना मुश्किल होगा। (पेज-5)

मध्यस्थता कमेटी और निर्वाणी अखाड़ा पर लगाया आरोप पेज>>5

चिदंबरम की उपस्थिति ही गवाहों को डराने और धमकाने के लिए काफी : सीबीआइ

- कहा, अहम गवाहों से पूछताछ तक पूर्व वित्तमंत्री को नहीं दी जाए जमानत
- आइएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

नई दिल्ली, प्रेट्र : आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की जमानत का विरोध करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने शुक्रवार को कहा कि जेल से बाहर उनकी उपस्थिति ही गवाहों को डराने-धमकाने के लिए काफी है। जांच एजेंसी ने इस संबंध में एक अज्ञात गवाह का उल्लेख किया। सीबीआइ ने कहा, चिदंबरम के खिलाफ भ्रष्टाचार के इस मामले में जिस व्यक्ति की गवाही मुख्य आधार है, उसे गिरफ्तारी से पहले कांग्रेस नेता की तरफ से डराया-धमकाया जा रहा था। वह व्यक्ति जानता था कि भ्रष्टाचार को किस तरह अंजाम दिया गया, यही कारण है कि चार्जशीट में उस गवाह की पहचान उजागर नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

अब तक माना जा रहा था कि आइएनएक्स मीडिया की पूर्व प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी की गवाही ही चिदंबरम के खिलाफ इस केस में मूल आधार है। जस्टिस आर भानुमति, एएस बोपन्ना और ऋषिकेश रॉय की पीठ के समक्ष सीबीआइ की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, उस व्यक्ति ने सीआरपीसी की धारा 164 (न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज) के तहत दर्ज बयान में कहा था कि गिरफ्तारी से पूर्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता द्वारा उसे डराया धमकाया जा रहा था। चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने चिदंबरम को जमानत देने से तो इन्कार कर दिया था, लेकिन कहा था कि पूर्व वित्तमंत्री देश छोड़कर नहीं भाग सकते और न ही वह गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं।

सीबीआइ ने कहा, विदेशी निवेश प्रवर्द्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की मंजूरी संबंधी आइएनएक्स मीडिया मामले में तो जांच लगभग पूरी हो गई है, लेकिन अभी कई कंपनियों को मिली मंजूरी की जांच चल रही है। मेहता ने चिदंबरम के देश छोड़कर भागने की आशंका भी जताई। चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने मेहता की दलील का विरोध किया। उन्होंने शीर्ष अदालत में चार्जशीट के तथ्यों का उल्लेख करने पर भी आपत्ति जताई। सीबीआइ ने चिदंबरम के खिलाफ 15 मई, 2015 को केस दर्ज किया था। इसी मामले में जांच एजेंसी ने उन्हें 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। चिदंबरम फिलहाल इसी मामले से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं।

पी. चिदंबरम फाइल फोटो

चिदंबरम का वजन पांच किलो घटा: चिदंबरम ने बीमारी और घटे वजन का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की अपील की। जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ से चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, 43 दिनों तक जेल में रहने के दौरान पूर्व मंत्री का वजन पांच किलोग्राम घटकर 73.5 से 68.5 किलोग्राम रह गया है। दो बार वह पांच और सात दिनों तक बीमार रहे हैं और उन्हें एंटीबॉयटिक दवाईयां देनी पड़ी हैं। सिब्बल ने आशंका जताई कि मौसम में बदलाव के चलते उन्हें स्वास्थ संबंधी और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

एफडीआइ मंजूरी देने में चिदंबरम ने किया था अपने पद का दुरुपयोग : सीबीआइ पेज>>3

दक्षिण दिल्ली में रविदास मंदिर के लिए प्लाट देने को तैयार केंद्र

- सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने रखा प्रस्ताव
- शीर्ष अदालत ने दूसरे पक्षों से सोमवार तक मांगी आपत्तियां

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह रविदास मंदिर के निर्माण के लिए श्रद्धालुओं की समिति को दिल्ली में 200 वर्ग मीटर का प्लाट देने के लिए तैयार है।

जस्टिस अरुण मिश्र और जस्टिस एस. रवींद्र भट्ट की पीठ ने केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके. वेणुगोपाल द्वारा पेश इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड पर रखा। साथ ही मंदिर निर्माण कराने के इच्छुक पक्षकारों से सोमवार तक आपत्तियां दर्ज कराने को कहा। वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने श्रद्धालुओं और सरकारी अधिकारियों समेत सभी पक्षों से परामर्श किया है और केंद्र सरकार इस मसले की संवेदनशीलता और मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए उतना ही बड़ा प्लाट देने के लिए राजी है, जितने बड़े प्लाट पर मंदिर स्थित था। उन्होंने यह भी बताया कि मंदिर को हटाए जाने के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले सात में से पांच याचिकाकर्ता इस प्रस्ताव पर सहमत हैं। कोर्ट ने चार अक्टूबर को मंदिर निर्माण की मांग कर रहे पक्षकारों से मंदिर के लिए किसी स्थान का सुझाव मांगा था।

ज्ञात हो, दिल्ली के तुगलकाबाद वन क्षेत्र में स्थित रविदास मंदिर को शीर्ष अदालत के आदेश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हटाया था। इसको लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह हर किसी की भावनाओं का सम्मान करती है, लेकिन कानून का पालन होना चाहिए।

एनआरसी समन्वयक हजेला का मप्र तबादला

नई दिल्ली, एजेंसियां : सुप्रीम कोर्ट ने असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के समन्वयक प्रतीक हजेला को अधिकतम संभव समय के लिए उनके गृह राज्य मध्य प्रदेश प्रतिनियुक्ति पर भेजने का आदेश दिया है। केंद्र और राज्य सरकारों को जारी निर्देश में शीर्ष अदालत ने तबादला आदेश का कारण तो नहीं बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि हजेला के जीवन को खतरे की आशंका में यह आदेश आया है।

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस आरएफ नरीमन की विशेष पीठ ने हजेला को अंतर-कैडर तबादले के तहत प्रतिनियुक्ति पर भेजने का आदेश दिया है। केंद्र की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने जब इसका कारण जानना चाहा तो प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, 'क्या कोई आदेश बिना वजह या कारण के पास किया जा सकता है।'

असम-मेघालय कैडर के 1995 बैच के आइएएस अधिकारी हजेला एनआरसी को अंतिम रूप देने और उसके प्रकाशन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। 31 अगस्त को एनआरसी का अंतिम प्रारूप जारी किया गया था, जिसमें तीन करोड़ 30 लाख की आबादी में से 19 लाख से ज्यादा लोग बाहर हो गए थे। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने भारतीय नागरिक होने के संबंध में कोई दस्तावेज जमा नहीं कराए थे। केंद्र के साथ ही असम की भाजपा सरकार ने भी दावा किया है कि बड़ी संख्या में असली भारतीय नागरिकों को एनआरसी में जगह नहीं मिली है। जबकि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को इसमें शामिल कर लिया गया है।

प्रतीक हजेला फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की नहीं बताई वजह, खतरे की आशंका हो सकता है कारण

हजेला पर खतरे को लेकर रिपोर्ट नहीं मांगी गई : असम पुलिस

असम के पुलिस महानिरीक्षक (विशेष शाखा) हिरेन नाथ ने पीटीआइ से कहा कि हजेला को खतरे को लेकर असम पुलिस से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि असम पुलिस को हजेला के जीवन को खतरे को लेकर कोई जानकारी भी नहीं है। हिरेन नाथ ने कहा कि सोशल मीडिया पर हजेला की आलोचना जरूर हो रही है। असम में कई सारे संगठनों ने एनआरसी और उसके राज्य समन्वयक हजेला के खिलाफ बयानबाजी की है। हजेला के खिलाफ कई एफआइआर भी दर्ज की गई है। इस संबंध में हजेला की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने हजेला को एनआरसी समन्वयक नियुक्त किया था।

एफएटीएफ की काली सूची में जाने से बचा पाकिस्तान

नई दिल्ली : आतंकी संगठनों को धन मुहैया कराने के ढांचे को रोकने में पाकिस्तान मोटे तौर असफल रहा है इसके बावजूद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उसे ब्लैक लिस्ट नहीं किया है। आतंकी फंडिंग रोकने के लिए सुझाए गए उपायों पर ठोस कार्रवाई करने के लिए पाक को अब फरवरी, 2020 तक का वक्त दिया गया है और तब तक के लिए उसे ग्रे सूची में ही रखा गया है। एफएटीएफ के अध्यक्ष शियांगमिन लिउ ने पेरिस में पिछले तीन दिनों की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में चेतावनी भरे लहजे में कहा, 'पाक सरकार को 27 मानकों पर कार्रवाई करने को कहा गया था लेकिन सिर्फ 5 मानकों पर संतोषप्रद कार्रवाई हुई है। अगर वह फरवरी, 2020 तक शेष मानकों पर ठोस कदम नहीं उठाता है तो उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।' (पेज-13)

सरकार से सिफारिश

राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने कहा- किसी घटना के बाद लाश का इस्तेमाल कर दबाव बनाना गलत, इस प्रकार के दुरुपयोग को दंडनीय अपराध बनाया जाए

शव के भी अधिकार, स्वार्थ के लिए न हो दुरुपयोग

मनीष गोधा, जयपुर

राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग ने एक अहम सिफारिश की है। आयोग ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि सड़क पर शव रखकर मांगें मनवाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर लगाम लगाना आवश्यक है। आयोग के मुताबिक शव के भी कुछ अधिकार होते हैं और उसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।

आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि किसी घटना के बाद आक्रोश में शव रखकर मांगें मनवाने की घटनाओं को रोकने के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की यह राय इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे देश में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जब किसी घटना-दुर्घटना के बाद लोग शव मुआवजा, सरकारी नौकरी अथवा अन्य किसी मांग को लेकर यातायात ठप कर देते हैं।

जबरन दबाव बनाना गलत : राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया ने कहा कि शव का दुरुपयोग किए जाने, इसकी आड़ में आंदोलन कर अवैध रूप से सरकार, प्रशासन, पुलिस, अस्पताल और डॉक्टरों पर दबाव बनाकर धनराशि या अन्य कोई लाभ प्राप्त करना गलत है। ऐसी घटनाओं को आयोग शव का अपमान और उसके मानवाधिकारों का हनन मानता है। अयोग ने कहा है कि इसे रोकने के लिए आवश्यक नीति निर्धारण और विधि के प्रावधानों को मजबूत किया जाना जरूरी है। आयोग ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का भी उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है कि संविधान के तहत सम्मान और उचित व्यवहार का अधिकार जीवित व्यक्ति ही नहीं बल्कि उसकी मृत्यु के बाद उसके शव को भी प्राप्त है।

जस्टिस प्रकाश टाटिया जागरण

सम्मान सहित अंतिम संस्कार ही कर सकते

जस्टिस टाटिया ने अपने आदेश में कहा है कि मृत व्यक्ति के शरीर पर अधिकार उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को नहीं मिलता। वह सिर्फ 'कस्टमरी लॉ' के तहत अंतिम संस्कार के लिए उसके शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। उसका बंटवारा, व्यापार या शरीर के अंगों का व्यापार नहीं किया जा सकता। आयोग ने कहा है कि विश्व के किसी भी धर्म के अनुसार शव का एकमात्र उपयोग उसका सम्मान सहित अंतिम संस्कार ही है।

आयोग ने कीं ये सिफारिशें

- दाह संस्कार में लगने वाले समय से अधिक तक शव को नहीं रखा जाए।
- परिजन अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कराए।
- यदि किसी अपराध की जांच के लिए शव की जरूरत नहीं है तो ऐसी स्थितियों में पुलिस को अंतिम संस्कार का अधिकार दिया जाए
- शव को अनावश्यक रूप से घर या किसी सार्वजनिक स्थान पर रखना दंडनीय अपराध घोषित हो।
- शव का किसी आंदोलन में उपयोग दंडनीय अपराध माना जाए

कश्मीर में आतंकियों ने जलाई सेब से भरी पेटियां

श्रीनगर : कश्मीर में आतंकियों ने सेब कारोबारियों को निशाना बनाने की अपनी साजिश को जारी रखते हुए उत्तरी कश्मीर की सोपोर मंडी में सेब से भरी पेटियों में आग लगा दी। दहशतगर्दों ने वहां मौजूद कुछ ट्रक चालकों को भी पीटा और उन्हें कश्मीर छोड़ने का फरमान सुनाया। इसके बाद आतंकी भाग निकले। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। (पेज-6)

स्वदेश पहुंचे मेक्सिको से वापस भेजे गए 311 भारतीय

नई दिल्ली : मेक्सिको के जरिये अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने की कोशिश में पकड़े गए 300 से ज्यादा भारतीय शुक्रवार को स्वदेश लौट आए। इनमें एक महिला भी है। ज्यादातर लोग पंजाब और हरियाणा के रहने वाले हैं। एक उच्चाधिकारी ने यहां बताया, '311 भारतीयों को वापस भेजा गया है। मेक्सिको के 74 अधिकारी उन्हें यहां लेकर आए हैं।' भारतीयों को स्वदेश लौटने के लिए 36 घंटे की यात्रा करनी पड़ी। (पेज-7)

वामपंथी सोच वाले हैं अभिजीत, उनकी स्कीम ठुकरा चुकी है जनता : पीयूष

- कांग्रेस ने लोस चुनाव के अपने घोषणापत्र में 'न्याय' योजना का किया था जिक्र

पुणे, प्रेट्र : रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी पर परोक्ष तौर पर हमला किया है। उन्होंने कहा, 'मैं अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार मिलने की बधाई देता हूं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि उनकी सोच वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है। उन्होंने 'न्याय' योजना बनाने में मदद की थी, लेकिन भारत की जनता ने उनकी सोच को पूरी तरह से खारिज कर दिया।

बता दें कि कांग्रेस ने अप्रैल में हुए लोकसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र में 'न्याय' योजना का जिक्र किया था। इसके तहत देश के 20 फीसद सबसे गरीब लोगों को 72 हजार रुपये सालाना देने की बात कही गई थी। अभिजीत बनर्जी को मोदी सरकार के प्रमुख आलोचकों में भी माना जाता है। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है और वर्तमान आंकड़े इस बात की गवाही नहीं देते हैं कि हाल-फिलहाल इसमें कोई सुधार होने वाला है। उन्होंने नोटबंदी को लेकर भी अर्थव्यवस्था में नुकसान की बात कही थी। अभिजीत को उनकी पत्नी के साथ नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें यह पुरस्कार 'वैश्विक गरीबी खत्म करने के प्रयोग' के लिए दिया गया है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और माकपा ने इसे भाजपा की संकुचित मानसिकता का प्रतीक बताया है।

महाराष्ट्र के पुणे में शुक्रवार को पीयूष गोयल ने प्रेसवार्ता के दौरान अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी पर निशाना साधा। प्रेट्र

689 शिकायतें भेज चुकी हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 46 टीमें निरीक्षण में विभिन्न एजेंसियों को। इनमें सबसे अधिक शिकायतें मलबा डालने, खुले में कूड़ा, सड़कों की धूल और गड्ढों से जुड़ी हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 19 अक्टूबर 2019

सख्ती ▸ ईपीसीए की बैठक में राहत देने से किया इन्कार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से चार दिनों में एक्शन प्लान देने को कहा

21 तक जारी रहेगी एनसीआर में डीजल चालित जनरेटर पर रोक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

एनसीआर के शहरों में डीजल जनरेटर पर रोक 21 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इन शहरों में जनरेटर पर रोक हटाने या जारी रखने पर 22 अक्टूबर को फैसला होगा। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण की शुक्रवार को इस बाबत हुई बैठक में राहत देने से इन्कार कर दिया। ईपीसीए ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से चार दिनों में इस बाबत पूरा एक्शन प्लान देने को कहा है। इस बीच सीपीसीबी का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में पांच फीसद प्रदूषण की वजह डीजल जनरेटर हैं।

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेप लागू होने के साथ ही 15 अक्टूबर से दिल्ली-एनसीआर में डीजल जनरेटर पर भी प्रतिबंध लग गया है। पिछले दो साल से एनसीआर के शहरों को छूट दे दी जाती थी लेकिन इस साल पहली बार उन्हें भी शामिल का लिया गया। समस्या यह है कि एनसीआर के शहरों में कहीं ग्रिड से बिजली का नेटवर्क नहीं होने तो कहीं अघोषित कटौती होने से परेशानी उत्पन्न हो रही है। इसीलिए हरियाणा सरकार और नोएडा प्रशासन की ओर से ईपीसीए अध्यक्ष भूरेलाल को पत्र लिखकर जनरेटर पर प्रतिबंध से छूट देने की मांग की गई थी। हरियाणा सरकार ने खासतौर पर इस प्रतिबंध को लागू करने में असमर्थता जताई थी। इसके बावजूद ईपीसीए ने किसी भी तरह की छूट देने से इन्कार कर दिया है। ईपीसीए के मुताबिक, दो साल तक एनसीआर को इस नियम से छूट दी गई है। अब तीसरे साल भी यह छूट नहीं दी जा सकती। इसलिए इन राज्यों से 22 अक्टूबर तक एक्शन प्लान मांगा है, जिसमें वह समय सीमा के साथ पूरा प्लान देंगे।

ईपीसीए को हरियाणा की तरफ से जानकारी दी गई कि राज्य के पास सरप्लस बिजली है। 11 हजार मेगावाट की मांग है और राज्य के पास 12500 मेगावाट बिजली है। इस बिजली से सभी कॉलोनियों और डीएलएफ साइबर सिटी में बिजली आपूर्ति की जा सकती है। गुरुग्राम में 100 किलोवाट की क्षमता वाले 5540, फरीदाबाद में 1833, सोनीपत में 753, पानीपत में 74 और बहादुरगढ़ में 17 डीजल जनरेटर सेट हैं। इनमें से 80 फीसद जनरेटर उद्योगों में बैकअप के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ईपीसीए के अनुसार, उन्हें जानकारी मिली है कि हरियाणा में हजारों प्लांट प्रोसेसिंग और मैन्युफेक्चरिंग के लिए बिजली का नहीं, बल्कि डीजल जनरेटरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तरफ से जानकारी दी गई कि उनके पास पर्याप्त बिजली है। अभी करीब 23 घंटे तक बिजली आपूर्ति की जा रही है। ईपीसीए ने कहा कि उसे जो रिपोर्ट मिल रही है, उसके मुताबिक बिजली कटौती की काफी शिकायतें आ रही हैं। 22 अक्टूबर को हरियाणा और उत्तर प्रदेश का एक्शन प्लान देखा जाएगा। उसके आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा।

राजधानी में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए लोग बचने के लिए मास्क का सहारा ले रहे हैं। बाजार में 100 रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक का मास्क बिक रहा है। प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 50 लाख नि:शुल्क मास्क बांटने का फैसला किया है। सोमवार से दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से इसकी शुरुआत की जाएगी। जागरण

पिछले साल की तुलना में अधिक जल रही पराली

नई दिल्ली : हरियाणा और पंजाब सरकार के साथ-साथ केंद्र की ओर से भी पराली जलाने की घटनाओं में इस साल कमी आने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे परे है। पिछले साल की तुलना में पराली जलाने के मामलों में काफी वृद्धि हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, पंजाब और हरियाणा में पिछले साल की तुलना में इस बार काफी अधिक पराली जलाई जा रही है। ऐसे में जब भी हवाओं का रुख बदलेगा, दिल्ली की स्थिति काफी अधिक खराब होगी। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल इन दोनों राज्यों में पराली जलाने के 1198 मामले सामने आए थे। इस बार अब तक 1631 मामले सामने आ चुके हैं। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, पराली जलाने में इस बार सबसे आगे अमृतसर है। दूसरे नंबर पर करनाल, तीसरे नंबर पर तरन तारन और चौथे नंबर पर कैथल है।

वर्क फ्रॉम होम और कार पूलिंग की दी सलाह

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर की निरंतर बिगड़ती हवा के मद्देनजर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने कॉरपोरेट और आइटी कंपनियों के कर्मचारियों को 'वर्क फ्रॉम होम' की सलाह दी है। सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों को कार पूल करने एवं सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करने के लिए कहा है। इसके अलावा स्कूलों को बच्चे घर से लाने और छोड़ने के लिए कहा गया है।

दरअसल, वायु प्रदूषण की स्थिति पर सीपीसीबी ने शुक्रवार सुबह टास्क फोर्स की बैठक रखी। इसमें मौजूदा स्थिति से बचाव और प्रदूषण की रोकथाम को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा के बाद तीन बिंदुओं पर एडवाइजरी जारी करने का निर्णय हुआ। इसे स्वीकृति के लिए पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) को भेजा गया है। ईपीसीए इसे क्रियान्वयन के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार को भेजेगा।

सीपीसीबी के सदस्य सचिव डा. प्रशांत गार्गवा ने बताया कि सफर और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण की स्थिति और खराब होगी। 23 अक्टूबर तक हवा की दिशा और गति पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। इस दौरान हवा खराब या बहुत खराब श्रेणी में रहेगी। सर्दियों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 13 हॉट स्पॉट बनाए गए हैं, यहां लोकल प्लान के हिसाब से काम किया जा रहा है। इसके अलावा 15- 15 दिन के पुर्वानुमान के लिए आइआइटी दिल्ली से करार किया गया है।

एडवाइजरी में कॉरपोरेट और आइटी सेक्टर की कंपनियों से अपील की गई हैं कि वे वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें और कर्मचारियों को इसके लिए प्रोत्साहित करें। सरकारी विभागों और निजी कंपनियां कर्मचारियों को निजी गाड़ियों की बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने या कार पूल करने का सुझाव दें। सीपीसीबी के अनुसार गाड़ियों से निकलने वाला धुआं सर्दियों में प्रदूषण की बड़ी वजह है। स्कूलों को भी सलाह दी है कि वह बच्चों के लिए पर्याप्त बसों का इंतजाम करें।

सड़कों पर धूल उड़ी तो जिम्मेदारों पर चलेगा मुकदमा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली की सड़कों पर धूल उड़ने से प्रदूषण हुआ तो अब जिम्मेदार विभागों व अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

गहलोत ने द्वारका सेक्टर-8 स्थित वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वैज्ञानिकों से वायु गुणवत्ता की निगरानी के तरीकों की जानकारी भी ली। उन्होंने डीपीसीसी द्वारा द्वारका में तय किए गए हॉट स्पॉट का निरीक्षण किया और वायु की खराब गुणवत्ता की स्थिति को सुधारने के लिए सेक्टर-8, 12, 14 और आसपास के स्थानों का भी जायजा लिया। मंत्री ने डीपीसीसी को निर्देश दिया कि वह धूल भरी सड़क की पहचान करके संबंधित एजेंसियों के जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमें दायर करने के लिए विशेष अभियान शुरू करें। उन्होंने एसडीएम को क्षेत्र का दौरा करने और उन स्थानों का पता लगाने का भी निर्देश दिया, जहां निर्माण और डंप कचरा डाला जाता है। साथ ही एसडीएम भूमि के मालिकाना हक वाली एजेंसियों के साथ मिलकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित जुर्माने की रकम भी तय करेंगे। गहलोत ने दक्षिणी नगर निगम को क्षेत्र में मैकेनिकल स्वीपिंग करने और व्यापक जल छिड़काव के भी निर्देश दिए। उन्होंने भारतीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान में स्थापित डीपीसीसी के सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन का दौरा किया। कहा कि दिल्ली में वास्तव में एक विश्वस्तरीय वायु गुणवत्ता निगरानी सेटअप है, जो रियल टाइम में हवा की गुणवत्ता का पता लगाने और सुधारात्मक कदम उठाने में सहायक है।

मेरठ, पानीपत और सोनीपत पर भी रहेगी सीपीसीबी की नजर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने भी दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से लड़ने के लिए कमर कस ली है। निगरानी के लिए 46 टीमें बनाई गई हैं। इसके साथ ही पहली बार मेरठ, सोनीपत व पानीपत जैसे शहरों में भी वायु गुणवत्ता मापने का निर्णय लिया गया है। यही नहीं, दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता की मौजूदा स्थिति के आकलन के लिए सीपीसीबी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और तीनों नगर निगमों के साथ जल्द ही बैठक करेगा।

सीपीसीबी के मुताबिक सभी नोडल एजेंसियों से आग्रह किया गया है कि वे खुद के सोशल मीडिया हैंडल/अकाउंट बनाएं। इससे सीपीसीबी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो शिकायतें मिलेंगी, उन्हें संबंधित एजेंसी के सोशल मीडिया अकाउंट पर भेजा जा सकेगा। शिकायत पर हुई कार्रवाई की सूचना भी संबंधित एजेंसी से सीपीसीबी को मिल सकेगी। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता बिगड़ने के साथ-साथ सीपीसीबी ने प्रदूषण से निपटने के लिए ऑनलाइन सक्रियता बढ़ाने सहित अन्य प्रयासों को तेज किया है। इसी दिशा में सीपीसीबी का केंद्रीय नियंत्रण कक्ष सक्रिय हो गया है। सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर के निवासी प्रदूषण से जुड़ी शिकायतें सोशल मीडिया, वेबसाइट, ई-मेल और चिट्ठियों के जरिये दर्ज करा सकते हैं।

न्यूज गैलरी

विस अध्यक्ष के सचिव हुए झपटमारी के शिकार

नई दिल्ली : पश्चिम विहार वेस्ट थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के सचिव अजय रावल का मोबाइल फोन झपट लिया। घटना के समय वह पत्नी के साथ बाजार जा रहे थे। करीब सवा सात बजे पुलिस को मामले की जानकारी मिली। पुलिस ने अजय रावल के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर झपटमार की पहचान में जुटी है। अजय परिवार के साथ पश्चिम विहार वेस्ट के अंबिका विहार में रहते हैं। गुरुवार शाम वह पत्नी के साथ बाजार जा रहे थे। जब वह अंबिका विहार स्थित केंद्रीय विद्यालय के पास पहुंचे तभी पीछे से मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाशों ने मोबाइल फोन झपट लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। (जासं)

एयरपोर्ट पर सोने के आठ बिस्कुट के साथ तस्कर धरा

नई दिल्ली : आइजीआइ एयरपोर्ट पर कस्टम ने विदेश से आए सोना तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसने जूते के अंदर सोने की बिस्कुट छुपा रखे थे। उससे 933 ग्राम भार के सोने के आठ बिस्कुट बरामद हुए हैं जिनकी कीमत 36 लाख रुपये से ज्यादा है। आइजीआइ एयरपोर्ट के वरिष्ठ कस्टम अधिकारी ने बताया कि घटना 15 अक्टूबर की है। दुबई से इंडिगो की उड़ान आइजीआइ एयरपोर्ट पर उतरी थी। इससे आया 37 वर्षीय संदिग्ध भारतीय एयरपोर्ट से बाहर निकलने की जुगत में लगा था। शक होने पर कस्टम अधिकारियों ने उसे दबोच लिया। तलाशी लेने पर पता चला कि उसने जूते के अंदर सोने के बिस्कुट छुपा रखे हैं। (जासं)

उनके घर में कुछ और ही ढूंढ रहे थे चोर : सत्येंद्र जैन

नई दिल्ली : स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजधानी की कानून-व्यवस्था पर तंज कसते हुए केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा है। स्वास्थ्य मंत्री जैन ने गत दिनों अपने सरस्वती विहार स्थित घर में हुई चोरी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी के साथ हुई लूटपाट की तो वारदात को दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा लिया। लेकिन मेरे घर में हुई चोरी के बारे में पुलिस को कोई सुराग तक नहीं मिला है। जैन ने कहा कि मेरे घर जो चोरी हुई थी वह चोरी नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल करने की कोशिश थी। (जासं)

मारपीट के मामले में विस अध्यक्ष को छह माह की सजा सुनाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेता व बिल्डर मनीष घई के घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल, उनके बेटे सुमित गोयल समेत पांच लोगों को छह-छह माह की सजा सुनाई है। सभी पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने सभी को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत की स्वीकृति दी।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि सभी आरोपितों के खिलाफ मामला साबित हुआ है। अदालत इस पक्ष में है कि इस मामले में सजा दिए जाने की जरूरत है। अदालत ने यह भी कहा कि राम निवास गोयल, सुमित गोयल, हितेश खन्ना, अतुल गुप्ता और बलबीर सिंह को भारतीय दंड सहिता की धारा 448 (मकान में जबरन घुसने) के तहत दोषी पाया गया है। अदालत ने सह आरोपित सुमित गोयल को आइपीसी की धारा 323 (चोट पहुंचाने) के तहत दोषी पाया।

> मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं और न्यायपालिका का सम्मान करता हूं। इस आदेश को चुनौती देने के लिए ऊपरी अदालत में अपील दायर करूंगा।
> **-राम निवास गोयल, विधान सभा अध्यक्ष**

राम निवास गोयल (74) ने अधिवक्ता मुहम्मद इरशाद के माध्यम से इस मामले में उन पर लगे आरोपों को खारिज किया था। स्थानीय बिल्डर मनीष घई की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके अनुसार उनके विवेक विहार स्थित घर में कुछ मजदूर काम रह रहे थे। छह फरवरी 2015 की रात उनके पास फोन आया कि गोयल और उनके समर्थक घर में जबरन घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। मजदूरों ने मना किया तो उनके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि गोयल अपने बेटे और समर्थक के साथ मनीष के घर में यह कहते हुए घुसे थे कि चुनाव में बांटने के लिए उनके घर में शराब रखी गई है। घटना के बाद पुलिस ने घर का सामान जब्त कर रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी थी।

चिड़ियाघर की निदेशक का हुआ तबादला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : चिड़ियाघर में गुरुवार को एक युवक के बाड़े में कूदने की घटना के बाद पर्यावरण मंत्रालय ने निदेशक रेणु सिंह का तबादला मंत्रालय में कर दिया। रेणु वहां पर उपमहानिदेशक की जिम्मेदारी संभालेंगी। घटना वाले दिन ही नोटिस जारी कर रेणु सिंह से कार्यभार लेकर तुरंत सुनीश बख्शी को निदेशक के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। सुनीश ने शुक्रवार को पदभार भी संभाल लिया है। बख्शी एजीएमयूटी कैडर के वर्ष 1998 बैच के अधिकारी हैं।

निदेशक का तबादला चिड़ियाघर प्रशासन के अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। चिड़ियाघर में गुरुवार को युवक रेहान शेर के बाड़े में कूद गया था। रेणु सिंह के नेतृत्व में प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया था। प्रशासन के भीतर किसी को तबादले की बात पच नहीं रही है। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वर्ष 2014 में विजय बाघ द्वारा मकसूद को मारने की घटना के बाद किसी भी अधिकारी पर गाज नहीं गिरी थी, लेकिन इस बार जब व्यक्ति को सुरक्षित बचा लिया गया है तब इस तरह का फैसला हैरान करने वाला है।

बच्चों को मानसिक प्रताड़ना से बचाएं स्कूल : कोर्ट

▸ **मानसिक उत्पीड़न की आरोपित टीचर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की**

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली

बच्चों को स्कूल में हर तरह की प्रताड़ना से बचाने की जरूरत है। फिर चाहे व मानसिक हो या फिर शारीरिक। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नाजुक उम्र के बच्चों का बहुत खयाल रखने की जरूरत है। उक्त टिप्पणी हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति बृजेश सेठी की पीठ ने नारायणा विहार स्थित ज्ञान मंदिर पब्लिक स्कूल की बायोलॉजी की टीचर रितिका की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए की। शिक्षिका पर छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है। छात्रा ने खुदकशी कर ली थी। पीठ ने कहा कि छात्रा ने सुसाइड नोट में स्पष्ट तौर पर क्लास टीचर आरती व बायोलॉजी की टीचर रितिका का नाम लिखा था। गवाहों ने भी बयान दिया है कि रितिका ने छात्रा के लिए कड़वे व द्वेषपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हुए चरित्रहीन तक कहा था।

अग्रिम जमानत याचिका पर अपने फैसले में अदालत ने कहा कि जैसा कि पहले ही कहा गया कि इस तरह के शब्द मासूम बच्चे के दिमाग को आघात पहुंचा सकते हैं और इसी वजह से छात्रा ने खुदकशी करने जैसा गंभीर कदम उठाया। यह असंभव है कि छोटी उम्र की छात्रा बिना किसी कारण के अपनी शिक्षिका पर झूठा आरोप लगाएगी। अदालत की राय में प्राथमिक तौर पर याचिकाकर्ता पर आत्महत्या की धमकी का सीधा और गंभीर आरोप है और प्राथमिक तौर पर इन तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सभी तथ्यों एवं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अदालत याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने से इन्कार करती है और उसकी याचिका खारिज की जाती है।

बायोलॉजी की टीचर ने कहा था, जाओ और मर जाओ : एक छात्रा ने अदालत में बयान दिया कि उसकी दोस्त ने उसे बताया था कि बायोलॉजी शिक्षिका रितिका ने उसे चरित्रहीन कहा था। जब उसने 30 नवंबर 2018 को पीड़ित छात्रा को खेलने के लिए कहा तो रोते हुए उसने बताया था कि बायोलॉजी की शिक्षिका ने उसे लैब में बुलाया और कहा कि तुम अपने परिवार का नाम खराब कर रही हो। जाओ और मर जाओ। छात्रा की मां ने भी बयान रिकॉर्ड कराते समय कहा था कि उनकी बेटी ने कई बार अपनी क्लास टीचर व बायोलॉजी की टीचर की शिकायत की थी कि वे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। स्कूल बदलने को भी कहती थीं।

यह थी घटना

नारायणा विहार ई-ब्लाक स्थित ज्ञान मंदिर पब्लिक स्कूल में सातवीं में पढ़ने वाली छात्रा ने घर में फांसी लगाकर खुदकशी कर ली थी। छात्रा की मां तीस हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। आरोप है कि 30 नवंबर को घर आने के बाद छात्रा ने मां से कहा कि वह एक दिसंबर को स्कूल नहीं जाएगी। मां एक दिसंबर को अदालत गई और ट्यूशन टीचर को उसे टेस्ट की तैयारी कराने के लिए। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी ट्यूशन के लिए नहीं गई तो वह घर पहुंचीं। घर अंदर से बंद था। उन्होंने जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर कमरे में उनकी बेटी ने खुदकशी कर ली थी। उसने सुसाइड नोट लिखा था और हाथ पर भी लिखा था। उसने लिखा था कि उसकी मौत की खबर स्कूल तक जरूर पहुंचाना। पत्र में उसने क्लास टीचर आरती और बायोलॉजी टीचर रितिका का नाम लिखा था।

दिवाली से पहले मुख्यमंत्री देंगे 100 और मोहल्ला क्लीनिक का तोहफा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिवाली से पहले दिल्लीवालों को 100 और मोहल्ला क्लीनिक का तोहफा देंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल तिमारपुर के मोहल्ला क्लीनिक से इनका विधिवत उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दिल्ली में इनकी संख्या 302 तक पहुंच जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी दी।

सत्येंद्र जैन ने बताया कि अगले ढाई महीने में 200 और मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने की तैयारी चल रही है। इसके बाद दिल्ली में इनकी संख्या 500 के पार हो जाएगी। पूरी दुनिया में दिल्ली एक मात्र ऐसा प्रदेश है, जहां पांच साल में तीन सौ से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। इससे पहले दिल्ली में 70 साल के दौरान 250 ही स्वास्थ्य केंद्र खुले थे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में एक हजार मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने की योजना है। इसके लिए किराये पर जमीन देने के नियम को सरल किया गया है। अब 40 वर्ग मीटर जमीन पर मोहल्ला क्लीनिक खोलने की इजाजत दे दी जाएगी। इसमें एक शौचालय होना जरूरी होगा। पहले 60 वर्ग मीटर जमीन पर मोहल्ला क्लीनिक खोलने की इजाजत थी। साथ ही दो शौचालय होने जरूरी थे। सरकार चाहती है कि लोग आगे आएं और मोहल्ला क्लीनिक के लिए अपनी जगह दें। आठ से दस ऐसे लोग हैं, जिन्होंने मोहल्ला क्लीनिक के लिए दिल्ली सरकार को मुफ्त में अपनी जगह दी है। इनमें से छह पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी मोहल्ला क्लीनिक में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कुछ जगहों पर यह काम शुरू भी हो गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मोहल्ला क्लीनिक में रोजाना 40 हजार से ज्यादा लोग इलाज करा रहे हैं, जो कि दिल्ली में प्रतिदिन ओपीडी जाने वालों की कुल संख्या का 20 फीसद है। मोहल्ला क्लीनिक में अब तक 1.69 करोड़ लोगों ने ओपीडी सेवा ली है। 16 लाख लोग टेस्ट करा चुके हैं। इनमें 75 फीसद लोग ऐसे हैं, जिन्होंने पहली बार सरकारी स्वास्थ्य सेवा का लाभ लिया है। मोहल्ला क्लीनिक की वजह से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों का विश्वास बढ़ा है।

सब्जी मंडी, मेट्रो स्टेशन और बस स्टेशनों में भी मोहल्ला क्लीनिक

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में तीन मेट्रो स्टेशनों व आजादपुर, गाजीपुर, नरेला, नजफगढ़ और ओखला समेत पांच सब्जी मंडियों में भी मोहल्ला क्लीनिक खोलने का काम चल रहा है। आइएसबीटी कश्मीरी गेट, आइएसबीटी आनंद विहार और सराय काले खां में भी मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे, जिन पर काम चल रहा है।

जेवर एयरपोर्ट की बिड में अधिकतम छह कंपनियां ही होंगी सफल

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकनीकी बिड में अधिकतम छह कंपनियां ही सफल हो सकेंगी। फाइनेंशियल बिड में इनमें से एक कंपनी का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। चयनित कंपनी एयरपोर्ट का निर्माण एवं संचालन करेगी। एयरपोर्ट के लिए अभी तक बीस कंपनियां बिड प्रपत्र खरीद चुकी हैं। हालांकि अभी तक एक भी कंपनी की ओर से बिड नहीं डाली गई है। बता दें कि बिड जमा करने की अंतिम तिथि तीस अक्टूबर है।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर देश-विदेश की कंपनियों की निगाहें लगी हैं। बिड खरीदने वाली कंपनियों में से चार विदेशी कंपनियां हैं। देश की सभी प्रमुख कंपनियां भी जेवर एयरपोर्ट की बिड में रुचि दिखा रही हैं। इससे एयरपोर्ट की बिड को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। छह नवंबर को तकनीकी बिड खुलेगी। नियमानुसार इसमें अधिकतम छह कंपनियां ही सफल हो सकती हैं। अगर बिड करने वाली कंपनियों की संख्या इससे कम रही तो सभी को फाइनेंशियल बिड में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। वहीं, 29 नवंबर को फाइनेंशियल बिड खुलेगी।

> जेवर एयरपोर्ट की तकनीकी और फाइनेंशियल बिड नवंबर में खुलेगी। बिड प्रक्रिया तय समय के अनुसार पूरी की जाएगी।
> **-डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ नियाल**

जेवर एयरपोर्ट से राजस्व बंटवारे को लेकर नई शुरूआत की जा रही है। प्रदेश सरकार व एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी के बीच राजस्व का बंटवारा प्रति यात्री के हिसाब से किया जाएगा। इससे सरकार को फायदा होगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट के निर्माण एवं संचालन के लिए कंपनियां समूह बनाती हैं तो उन्हें बिड में शामिल होने से पहले इसे गठित करना होगा। इसके साथ ही निर्माण एवं रखरखाव के लिए वह किस कंपनी के साथ अनुबंध करेंगी, उसका उल्लेख भी बिड में करना होगा। देश में बने एयरपोर्ट की बिड में शामिल कंपनियों के लिए अभी तक यह सुविधा थी कि वे बिड में सफल होने के बाद समूह गठित या निर्माण एजेंसी का चयन कर सकती थीं। पहले से इसकी जानकारी देने की बाध्यता नहीं थी।

मेट्रो के कारण क्षतिग्रस्त हो रहे मकानों को मुआवजा देने पर मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : मेट्रो के निर्माण और मेट्रो के आवागमन से होने वाले कंपन से जिन मकानों को क्षति पहुंची है उन्हें मुआवजा देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार व दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) से जवाब मांगा है। मुख्य पीठ ने नोटिस जारी करते हुए छह नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। याचिकाकर्ता ने याचिका में निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में दिल्ली सरकार व संबंधित एजेंसियों को निर्देश देने की मांग की है।

मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने डीएमआरसी से कहा कि पीड़ित को मुआवजा देने के संबंध में अगर कोई नीति है तो इसे दर्शाती हुई रिपोर्ट पेश करें। मुख्य पीठ ने उक्त आदेश एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट की तरफ से दायर याचिका पर दिया। याचिका में दावा किया गया कि मेट्रो रूट पर पड़ने वाले घरों की दीवारों और दरवाजों में ट्रेन के चलने से होने वाले कंपन से दरारें आ चुकी हैं। याचिका में कहा कि दक्षिण दिल्ली में यह गंभीर समस्या बनी हुई है।

योजना

नोएडा में बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा हेलीपोर्ट

हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता चार एजेंसियों को मिल सकती है जिम्मेदारी, प्राधिकरण बनाएगा आठ हेलीपैड

कुंदन तिवारी, नोएडा

दिल्ली के बाद नोएडा में देश का दूसरा सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनने जा रहा है। इसका संचालन चार हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता एजेंसियां कर सकती हैं। नोएडा प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2031 में परियोजना को शामिल कर बोर्ड बैठक में मंजूरी दे दी है। सेक्टर-151ए में 10 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है।

परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर बनाई गई है। जल्द ही सलाहकार कंपनी का चयन होगा। इसके लिए रिक्यूवेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी होगा, जो परियोजना को समझाने के लिए पूरी योजना का ब्ल्यू प्रिंट तैयार करेगा। इसमें प्राधिकरण की जमीन लागत निकालने के साथ-साथ सुविधा शुरू होने से होने वाली आय का पूरा लेखा-जोखा शामिल होगा। साथ ही नोएडा की प्रॉपर्टी इस परियोजना से कितना बूम कर सकती है और कितना नया निवेश होगा, इसका भी पता लग जाएगा। इसके बाद प्राधिकरण को परियोजना का खाका सौंपा जाएगा।

सांकेतिक फोटो

> हेलीपोर्ट के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। यह निवेश व पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा। परियोजना पीपीपी मॉडल पर तैयार की जाएगी, जिसे हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां संचालित करेंगी।
> **-एससी गौड़, महाप्रबंधक, नियोजक/वास्तुकला, नोएडा प्राधिकरण**

बता दें कि देश में चार एजेंसियां हैं, जो हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करती हैं। इनमें पवन हंस व एसआइटीसी के अलावा दो अन्य शामिल हैं। पवन हंस का कार्यालय नोएडा सेक्टर-एक में है। सेक्टर-151ए स्थित हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उतरने के लिए आठ हेलीपैड बनाए जाएंगे। हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए केबिन बनाए जाएंगे। इनकी पार्किंग की व्यवस्था होगी। पहले चरण में योजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो रही है, जिसे क्लीयरेंस के लिए आइआइटी भेजा जाएगा। वहां से संस्तुति मिलने पर राज्य सरकार से मंजूरी ली जाएगी।

जहां पर हेलीपोर्ट बनाया जाएगा, उसे प्राधिकरण क्षेत्रीय पर्यटन की तर्ज पर विकसित करने जा रहा है। राजस्थान की चौखी ढाणी समेत शहीद भगत सिंह पार्क विकसित किया रहा है, ताकि लोग यहां पर आकर देश के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति से वाकिफ हो सकें।

देश के हर कोने से होगी सीधी कनेक्टिविटी : हेलीपोर्ट सेवा शुरू होने से देश के किसी कोने से शहर की सीधी कनेक्टिविटी होगी। हालांकि जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले से बन रहा है, जहां देश-विदेश से लोग आएंगे। ऐसे में निवेश व पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में प्राधिकरण ने यह कदम उठाया है। यहां से किसी भी समारोह के लिए आसानी से हेलीकॉप्टर किराये पर लिया जा सकेगा। साथ ही इसका प्रयोग सरकारी (वीवीआइपी) कार्यक्रमों के लिए भी किया जाएगा।

ईस्टर्न-वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लिए दिल्ली सरकार देगी 1,000 करोड़

▸ **सुप्रीम कोर्ट ने उप्र, दिल्ली और हरियाणा को कैबिनेट सचिव के साथ बात करके गतिरोध खत्म करने को कहा**

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेस-वे को लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को कैबिनेट सचिव के साथ बात करके गतिरोध खत्म करने के लिए कहा है। साथ ही दिल्ली सरकार को परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया है। बता दें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे गाजियाबाद, फरीदाबाद, गौतमबुद्धनगर (ग्रेटर नोएडा) और पलवल के बीच सिग्नल-फ्री कनेक्टिविटी की परिकल्पना पर आधारित है, जबकि वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे मानेसर के माध्यम से कुंडली को पलवल से जोड़ता है।

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने यह आदेश संबंधित समिति द्वारा रखी गई रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए दिया है। इस रिपोर्ट में दोनों एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत के लंबित हिस्से का मुद्दा उठाया गया था। प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट की मदद कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक लागत 844 करोड़ रुपये थी, जो बाद में बढ़कर 8,462.03 करोड़ रुपये हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 3,585.42 करोड़ रुपये पहले ही जमा किए जा चुके हैं जबकि 4876.61 करोड़ अभी जमा किए जाने हैं। एमिकस क्यूरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2005 में स्वीकार की गई कैबिनेट सचिव की रिपोर्ट में कहा गया था कि भूमि अधिग्रहण की लागत दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार 50:25:25 के अनुपात में वहन करेंगी। दिल्ली सरकार को इस मद में जहां 3,577.52 करोड़ रुपये जमा करने हैं, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार को 1,218.12 करोड़ रुपये जमा करने हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों एक्सप्रेसवे दिल्ली के लाभ के लिए हैं, क्योंकि इससे दिल्ली में यातायात को कम करने में मदद मिलेगी।

1986 में देश में की गई थी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की स्थापना, संगठन में मान्य कर्मचारियों की कुल संख्या 889 है, लेकिन मौजूदा समय में ब्यूरो के पास सिर्फ 60 फीसद ही कर्मचारी हैं।

'समुद्री सुरक्षा के खतरों से अकेले निपटना किसी देश के लिए कठिन'

ब्रिटिश एडमिरल बोले, हिंद महासागर में भारत संग सहयोग की इच्छा

संजय मिश्र, नई दिल्ली

समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों के आयाम इतने बढ़ गए हैं कि दुनिया के किसी भी देश के लिए ऐसे बहुआयामी खतरों से अकेले निपटना कठिन है। समुद्री सुरक्षा की ऐसी नई चुनौतियों के साथ वैश्विक आतंकवाद के खतरों का मुकाबला करने के लिए ब्रिटेन भारत के साथ मजबूत सहयोग चाहता है। विशेष रूप से हिंद महासागर की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की रणनीति में ब्रिटिश रॉयल नेवी भारतीय नौसेना के साथ मिलकर काम करने को तैयार है।

वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से जुड़े मसलों पर भारतीय सैन्य और रणनीतिक विशेषज्ञों से चर्चा के लिए आए ब्रिटेन के वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल टीम फ्रेजर ने 'दैनिक जागरण' से विशेष चर्चा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि समुद्री सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ी चुनौती अंतरराष्ट्रीय नियमों की अनदेखी है। साथ ही अवैध मछुआरों की समस्या भी गंभीर है जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाते हैं। हिंद महासागर के सुरक्षा आयामों से जुड़े सवाल पर एडमिरल फ्रेजर ने कहा कि बेशक संप्रभुता का आदर करते हुए स्वतंत्र आवाजाही के अधिकार का ब्रिटेन समर्थन करता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय नियमों की अनदेखी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम मानते हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा में भारत की अहम भूमिका है। इसीलिए रॉयल नेवी भारतीय नौसेना के साथ मिलकर इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए प्रभावी तरीके से काम करने को तैयार है। समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपना इंफॉरमेशन फ्यूजन सेंटर स्थापित करने के लिए उन्होंने भारत की तारीफ की। इससे सूचनाओं के आदान-प्रदान में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही समुद्र में जहाजों की आवाजाही की विशेष जानकारी भी मिल सकेगी।

भारत-पाक के बीच सभी मसले द्विपक्षीय : भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनावपूर्ण रिश्तों के संदर्भ में ब्रिटिश वाइस चीफ ऑफ डिफेंस ने कहा कि वह दोनों देशों के बीच सभी मसलों को द्विपक्षीय मानते हैं। इसीलिए इनका दीर्घकालिक राजनीतिक समाधान भारत-पाक आपसी द्विपक्षीय वार्ता से ही निकाल सकते हैं।

ब्रिटेन आधुनिक एयरक्रॉफ्ट कैरियर देने को तैयार

रणनीतिक संबंधों के अलावा भारत के साथ रक्षा सहयोग की भावी संभावनाओं के सवाल पर एडमिरल फ्रेजर ने कहा कि अगर भारत चाहेगा तो ब्रिटेन अपने सबसे आधुनिक एयरक्रॉफ्ट कैरियर 'क्वीन एलिजाबेथ' देने के विकल्प पर गौर करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक संचालित 65 हजार टन भार क्षमता वाला यह एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। गहरे समुद्र में आधुनिक पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट उड़ान भर सकें इस लिहाज से इसका निर्माण किया गया है। रॉयल नेवी का यह सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना के साथ प्रस्तावित अगले सैन्य अभ्यास में जल्द ही यहां आएगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह भारतीय नौसेना की तकनीकी विशेषज्ञता की महारथ को हासिल करने में रॉयल नेवी की दिलचस्पी है।

लुटेरे व ड्रग तस्कर अंतरराष्ट्रीय समुद्री खतरा : नौसेना प्रमुख

नई दिल्ली, प्रेट्र : नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने समुद्री लुटेरे और ड्रग तस्करी को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति का खतरा माना है। इसके साथ ही नौसेना प्रमुख ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समान विचार रखने वाली नौसेनाओं के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना प्रतिबद्ध है। सामूहिक सैन्य क्षमता के इस्तेमाल के लिए उन्होंने नौसेनाओं की बेहतर कार्यप्रणाली की आपसी सीख की वकालत भी की है।

रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों की चौथी बैठक को संबोधित करते हुए एडमिरल सिंह ने कहा, 'समुद्र में जाने वाले बलों के लिए सहयोग एक महत्वपूर्ण शब्द है। समुद्र की प्रकृति ऐसी है जो बांटता नहीं है बल्कि एकजुट करता है। इसे संपर्क का हाईवे कहा जाता है। इसलिए नौसेना अपनी प्रकृति में सहयोगी क्षेत्र में काम करती है।' उन्होंने कहा कि समुद्र और महासागर का असीम विस्तार भी नौसेना को इस वास्तविकता का अनुभव कराता है कि यहां कोई अकेला नहीं है। इसीलिए यह नौसेना के डीएनए का हिस्सा बन गया है।

एडमिरल सिंह ने कहा, समान विचार वाली नौसेना के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना प्रतिबद्ध

करमबीर सिंह फाइल फोटो

नौसेना प्रमुख ने कहा, 'कई तरह के समुद्री खतरे और साझी चुनौतियां हैं। उदाहरण के लिए एक देश में समुद्री लुटेरे हमले करते हैं तो उसके बाद ड्रग तस्करी जिसे हम नार्को-आतंकवाद कहते हैं उसका नंबर आता है। मानव तस्करी और गैरकानूनी रूप से मछली पकड़ना भी ऐसी चुनौतियों में शामिल है। ये सभी ट्रांस-नेशनल या अंतर-क्षेत्रीय प्रकृति के हैं।'

सैनिकों को दिया जाएगा आइटी सेक्टर की नौकरियों के लिए प्रशिक्षण

भारतीय सेना और नेशनल एसोसिएशन ऑफ साफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) अगले सप्ताह बेंगलुरु में एक मंच पर आएंगे। सैनिकों को आइटी सेक्टर में आधुनिक औद्योगिक जरूरतों का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि विशेषज्ञता हासिल कर वे इस क्षेत्र में नौकरियां हासिल कर सकें। यह पहल इसलिए की जा रही है क्योंकि पूर्व में कई बहुराष्ट्रीय फर्म सेना से रिटायर हुए जवानों को उनके लगाव के बावजूद नौकरी देने में विफल रहीं। इसका कारण सैनिक तकनीकी रूप से और कारपोरेट जगत की संस्कृति से भिन्न पाए गए थे। आइटी सेक्टर के विशेषज्ञों के अनुसार इस कदम का उद्योग में व्यापक असर देखने को मिलेगा। यह कदम भारतीय सेना, नैसकॉम और अमेरिका की बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा फर्म वेल्स फार्गो संयुक्त रूप से उठा रही हैं। इस कदम को बहुराष्ट्रीय ई-कामर्स फर्म अमेजन इंडिया का भी समर्थन हासिल है।

राजीव सक्सेना के सरकारी गवाह बनने का स्टेटस हटाने की मांग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दुबई निवासी व्यापारी राजीव सक्सेना के सरकारी गवाह के स्टेटस को हटाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट में आवेदन किया है। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार की अदालत के समक्ष ईडी ने कहा कि राजीव सक्सेना सभी तथ्यों की जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। अदालत ने ईडी के आवेदन पर राजीव सक्सेना से जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। इसी दिन सक्सेना की जमानत रद करने वाली याचिका पर सुनवाई होनी है।

सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि जांच के दौरान सक्सेना एजेंसी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, सरकारी गवाह बनने के बाद भी वह इस मामले से जुड़े अन्य लोगों से संपर्क में हैं। एजेंसी ने दावा किया कि सक्सेना मामले में आरोपित अन्य लोगों को बचाना चाहते हैं। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि 25 बार बुलाने के बावजूद भी सक्सेना जांच में शामिल नहीं हुए। इससे पहले सीबीआइ और ईडी ने पूछताछ के संबंध में सक्सेना को समन जारी किया था।

चिदंबरम ने किया था पद का दुरुपयोग : सीबीआइ

आगे बढ़ा काम ▶ चिदंबरम और बेटे कार्ति समेत 14 के खिलाफ आरोप पत्र दायर

सरकारी गवाह बन चुकीं इंद्राणी मुखर्जी का नाम भी आरोप पत्र में शामिल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आइएनएक्स मीडिया डील के भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति समेत 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इसमें सीबीआइ ने कहा है कि आइएनएक्स मीडिया को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) से मंजूरी दिलाने में पी चिदंबरम ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था।

सीबीआइ ने आइपीसी की धारा 120बी (षडयंत्र रचने), धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा-468 (फर्जी दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वास्तविक दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल करना) के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है।

प्रतीकात्मक फोटो

कार्ति चिदंबरम की कंपनी को हुआ था अवैध भुगतान

आरोप पत्र में सीबीआइ ने कहा कि जांच में पता चला है कि कार्ति चिदंबरम ने एएससीपीएल नाम की फर्जी कंपनी बनाई थी, ताकि अवैध भुगतान लिया जा सके। आइएनएक्स मीडिया ने भी बगैर कोई सेवा दिए 9.96 लाख रुपये एएससीपीएल के खाते में भुगतान किया था।

ईडी की हिरासत में हैं पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम

विशेष अदालत की अनुमति मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चिदंबरम से तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने गुरुवार को उन्हें सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया था। इसके साथ ही सीबीआइ के भ्रष्टाचार मामले में भी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी।

आरोप पत्र में हैं इन लोगों के नाम : आरोप पत्र में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के अलावा कार्ति के चार्टर्ड एकाउंटेंट एस भास्करामन, आइएनएक्स मीडिया लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक पीटर मुखर्जी, नीति आयोग के पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के पूर्व सचिव अनूप के पुजारी, आइएनएक्स मीडिया एएससीएल एंड चेस मैनेजमेंट सर्विस के प्रबोध सक्सेना व रविंद्र प्रसाद, प्रदीप कुमार बग्गा को आरोपित बनाया गया है। सरकारी गवाह बन चुकीं इंद्राणी मुखर्जी का भी इसमें नाम है। आरोप पत्र पर 21 अक्टूबर को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार विचार करेंगे। बता दें कि चिदंबरम को सीबीआइ ने 20 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

विभिन्न देशों को भेजा एलआर, जवाब का इन्तजार : जांच एजेंसी ने आरोप पत्र में बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और लेटर्स रोगेटरी (एलआर) सिंगापुर, मॉरीशस, बरमूडा, इग्लैंड, स्विट्जरलैंड को भेजा जा चुका है और सभी के जवाब का इंतजार है। एलआर मूलरूप से एक देश की अदालत द्वारा दूसरे देश की अदालत को सहयोग करने के संबंध में भेजा जाता है।

इंद्राणी ने ही किया था पर्दाफाश : इंद्राणी ने ही तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम व कार्ति की आइएनएक्स मीडिया व आइएनएक्स प्राइवेट लिमिटेड को दी गई एफडीआइ मंजूरी में भूमिका का पर्दाफाश किया था। इंद्राणी ने सीबीआइ को बताया है कि उन्होंने पांच मिलियन डॉलर (35 करोड़ रुपये) का भुगतान किया था। इस संबंध में मार्च और अप्रैल 2007 में इंद्राणी और चिदंबरम ने बैठक की थी। जांच में पता चला है कि आइएनएक्स मीडिया के डायरेक्टर पीटर मुखर्जी ने चिदंबरम व कार्ति के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची थी।

प्रफुल्ल पटेल से ईडी ने की 12 घंटे पूछताछ

मुंबई, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता और संप्रग सरकार में मंत्री रहे प्रफुल्ल पटेल से करीब 12 घंटे तक पूछताछ की। यह मामला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी इकबाल मिर्ची की कथित गैरकानूनी संपत्तियों से जुड़ी मनी लांड्रिंग जांच का है।

प्रफुल्ल पटेल शुक्रवार सुबह 10.30 पर दक्षिण मुंबई स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे थे। दिनभर की पूछताछ के बाद वरिष्ठ अधिकारी शाम 6.30 बजे चले गए थे, लेकिन जांच अधिकारी प्रफुल्ल से पूछताछ करते रहे। 12 घंटे चली पूछताछ के बाद रात लगभग 10.30 बजे प्रफुल्ल पटेल बाहर निकले। एक ईडी अधिकारी ने दावा किया कि प्रफुल्ल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। भविष्य में उनका सामना पीएमसी बैंक घोटाले के आरोपित और हाउसिंग डेवलेपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के राकेश वधावन से कराया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि प्रफुल्ल और एचडीआइएल के बीच लिंक रहे हैं। बता दें कि ईडी इससे पहले विमानन घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में भी प्रफुल्ल पटेल से पूछताछ कर चुका है।

2024 तक रक्षा निर्यात बढ़कर 35000 करोड़ हो जाएगा : रावत

नई दिल्ली, आइएएनएस : सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा है कि 2024 तक घरेलू रक्षा उद्योग निर्यात बढ़कर 35000 करोड़ रुपये का हो जाएगा। वर्तमान में हमारा देश सालाना 11,000 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात कर रहा है। कांस्टीट्यूशन क्लब में विदेशी रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों की बैठक को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि भारत स्वदेशी रक्षा उत्पादन नीति के लिए प्रतिबद्ध है। इस बैठक में नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह भी मौजूद थे। सरकारी रक्षा उद्योगों के अलावा कई निजी रक्षा फर्म भी इस बैठक में हिस्सा ले रही हैं। करीब 22 निजी रक्षा फर्म इस बैठक के अवसर पर स्वदेशी रक्षा उपकरण निर्यातक संघ (आइडीईए) लांच करने के लिए सामने आए हैं।

जनरल रावत ने कहा, 'हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम न केवल अपने रक्षा बलों को सुसज्जित करने के लिए हथियार और उपकरण बना रहे हैं, बल्कि अब हम निर्यातक के रूप में भी उभर रहे हैं। वर्तमान में हमारा रक्षा निर्यात सालाना 11,000 करोड़ रुपये का है। 2024 तक इस आंकड़े को लगभग 35000 करोड़ रुपये तक पहुंचाया जाना है।'

सेना प्रमुख ने कहा, 'आज की अनिश्चित और जटिल दुनिया में हम अपने सुरक्षा मार्ग में पेश आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। ऐसे में हम रक्षा उद्योगों से अपने रक्षा बलों की जरूरतों को पूरा करने वाले साधन मुहैया कराने की उम्मीद रखते हैं। कुछ वर्षों पहले अनगिनत प्रयास किए गए और भारत में रक्षा क्षेत्र को ऊर्जा भरने के लिए कई योजनाएं लांच की गईं। और इसीलिए हम गहरे तौर पर स्वदेशीकरण की नीति के लिए प्रतिबद्ध हैं।'

केंद्र की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को परिभाषित करते हुए जनरल रावत ने कहा कि यह रक्षा कॉरिडोर के साथ आगे बढ़ेगा। ऐसे कॉरिडोर को भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने, कर रियायत और अन्य मुद्दों के रूप में प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

- वर्तमान में देश का सालाना रक्षा निर्यात 11000 करोड़ का है
- सेना प्रमुख ने कहा, स्वदेशी रक्षा उत्पादन नीति के लिए भारत प्रतिबद्ध

बिपिन रावत फाइल फोटो

मिड-डे मील की गुणवत्ता पर राज्यों के साथ नए सिरे से होगी चर्चा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मील की गुणवत्ता पर उठते सवालों के बीच केंद्र सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को और पुख्ता बनाने की दिशा में मंथन शुरू कर दिया है। राज्यों के साथ जल्द ही इसे लेकर चर्चा की तैयारी है। फिलहाल सभी राज्यों से सुझाव देने को कहा गया है।

राज्यों के स्कूली शिक्षा सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने साफ किया है कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) से मिलने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाए। उसकी गुणवत्ता को जांचने के बाद ही आवंटन लिया जाए। स्कूलों से भी मिलने वाले खाद्यान्न को परखने के लिए कहा गया है। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम कई राज्यों में स्कूलों में सप्लाई किए गए खराब खाद्यान्न की शिकायत मिलने के बाद उठाया गया है। अगली कड़ी में राज्यों के साथ प्रस्तावित चर्चा में स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी कुछ सख्त कदम देखने को मिल सकते हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार देश में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों में जुटी हुई है।

- केंद्र ने स्कूलों को दिए जा रहे खाद्यान्न की गुणवत्ता पर सख्ती के भी दिए निर्देश
- चालू वित्तीय वर्ष के बाकी खाद्यान्न आवंटन से पहले राज्यों को लिखी चिट्ठी

प्रत्येक स्कूलों के लिए किचन गार्डन रखना होगा जरूरी

बच्चों के खाने को पौष्टिक बनाने के साथ उन्हें सामुदायिक वातावरण में ढालने के लिहाज से प्रत्येक सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि इसकी शुरुआत कुछ स्कूलों में प्रयोग के तौर पर की गई थी, लेकिन स्कूलों में इसे लेकर बढ़ती रुचि को देखते हुए अब इसे सभी स्कूलों के लिए जरूरी कर दिया गया है। मंत्रालय ने इसे लेकर एक गाइडलाइन भी तैयार की है। जिसमें स्कूलों को जगह की उपलब्धता के लिहाज से किचन गार्डन तैयार करने के सुझाव दिए गए हैं। ताकि मिड-डे मील के लिए सब्जियां इत्यादि उगाई जा सकें।

जस्टिस शरद अरविंद बोबडे हो सकते हैं देश के अगले मुख्य न्यायाधीश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए सुप्रीम कोर्ट के दूसरे नंबर के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस शरद अरविंद बोबडे के नाम की सिफारिश की है।

सुप्रीम कोर्ट की परंपरा है कि मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने से पहले अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश सरकार को भेजते हैं। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के बाद दूसरे नंबर के वरिष्ठ न्यायाधीश का नाम ही सुझाया जाता है। चीफ जस्टिस गोगोई ने यह चिट्ठी कानून मंत्रालय को भेजी है। सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्रालय देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए सिफारिश प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्रपति को भेजता है, जो इसके आदेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 124 की धारा (2) के तहत देते हैं।

चीफ जस्टिस गोगोई ने 03 अक्टूबर 2018 को देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश पद के लिए शपथ ली थी। गोगोई आगामी 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इस पद पर उनका कार्यकाल 13 महीने और 15 दिनों का है।

केवल 17 महीने रहेंगे मुख्य न्यायाधीश : ऐसे में यदि 18 नवंबर को जस्टिस शरद अरविंद बोबडे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) बनते हैं तो वह इस पद पर करीब 17 महीने ही रहेंगे। चूंकि वह भी 23 अप्रैल, 2021 को रिटायर हो रहे हैं। बोबडे आधार कार्ड, दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक समेत कई बड़े मामलों में अहम फैसले दे चुके हैं और वह अयोध्या मामले में भी संविधान पीठ का हिस्सा हैं।

- देश के मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने अगले सीजेआइ के लिए दिया नाम
- रिटायर होने से एक महीने पहले केंद्र सरकार को पत्र लिख की सिफारिश
- नियुक्त हुए तो इस पद पर 17 महीने ही रहेंगे बोबडे

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के साथ न्यायाधीश एसए बोबडे की फाइल फोटो।

2013 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाए गए थे

जस्टिस बोबडे का जन्म 24 अप्रैल, 1956 को नागपुर में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से बी.ए. और एल.एल.बी की डिग्री ली है। 1978 में वह बार काउंसिल आफ महाराष्ट्र से जुड़ गए। इसके बाद बांबे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में वकालत की और 1998 में वरिष्ठ वकील बने। साल 2000 में उन्होंने बांबे हाईकोर्ट में बतौर एडिशनल जज पदभार ग्रहण किया। फिर वह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज कमान संभाली थी।

पीएमसी बैंक के खाताधारकों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक से नकदी निकालने पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की ओर से लगाई गई रोक हटाने की मांग कर रहे पीएमसी खाताधारकों की याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इन्कार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'हम अनुच्छेद 32 (रिट अधिकार क्षेत्र) के तहत इस याचिका की सुनवाई नहीं करना चाहते। याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए संबंधित हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।' सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस स्थिति की गंभीरता से परिचित है और प्रवर्तन निदेशालय दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर रहा है।

याचिकाकर्ता बेजोन कुमार मिश्रा की ओर से पेश हुए वकील शशांक सुधी ने कहा कि उन्होंने पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) के 500 खाताधारकों की ओर से याचिका दायर की है जिसमें नकदी निकालने पर आरबीआई की ओर से लगाई रोक को हटाने का अनुरोध किया गया है। याचिका में केंद्र सरकार से बैंक खाताधारकों की मेहनत की कमाई की रक्षा करने का निर्देश देने की भी अपील की गई थी।

पीएमसी बैंक घोटाला

- नकद निकासी पर रोक हटाने की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार
- खाताधारकों ने की थी रिजर्व बैंक के निर्देश को रद करने की अपील

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

उल्लेखनीय है कि 4355 करोड़ रुपये के पीएमसी घोटाले के प्रकाश में आने के बाद रिजर्व बैंक ने बैंक से एक सीमा से अधिक नक द निकासी पर रोक लगा दी है। खाताधारक छह माह की अवधि में बैंक से 40 हजार रुपये तक निकाल सकते हैं। इसके खिलाफ महाराष्ट्र में सैकड़ों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नकदी की किल्लत के चलते हलकान लोगों की तबीयत खराब हो रही है। अब तक तीन खाताधारकों की अलग अलग घटनाओं में मौत हो चुकी है।

दिक्कत की बात

पिछले एक साल में नियुक्ति के लिए किए गए 10 प्रयासों के बाद भी नहीं मिली सफलता, 889 पदों के सापेक्ष सिर्फ 60 फीसद कर्मचारी, प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे 330 कर्मचारी

नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पास कर्मचारियों का टोटा

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारत में मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ रही है और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के अलावा मुंबई, दिल्ली और कोलकाता मादक पदार्थों को देश में लाने के मुख्य अंतरराष्ट्रीय मार्ग के तौर पर उभरे हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच सबसे गंभीर चिंता का विषय यह है कि इन पर रोक लगाने के लिए बने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पास पर्याप्त कर्मचारी भी नहीं हैं।

17 मार्च 1986 को एनसीबी की स्थापना की गई थी। फिलहाल इसका नेतृत्व सीबीआइ के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना कर रहे हैं। इससे जुड़े एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि पिछले एक साल में एनसीबी ने कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कम से कम 10 प्रयास किए, लेकिन बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। एनसीबी में मान्य कर्मचारियों की कुल संख्या 889 है, लेकिन ब्यूरो के पास सिर्फ 60 फीसद कर्मचारी हैं। कुल कर्मचारियों में से 330 इसके स्वयं के कर्मचारी हैं जबकि बाकी प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों से आए हैं। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एनसीबी भर्ती नियमों के अनुसार, सिपाही से लेकर उपनिदेशक ओर अंचल निदेशक तक के पद प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति और सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जा सकते हैं।

अधिकारी, टेलिफोन ऑपरेटर, आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, सर्विलांस असिस्टेंट व सिपाहियों की सीधी भर्तियां की जाती हैं और इन पदों को एनसीबी का कैडर पद माना जा सकता है। एनसीबी के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों का काम करने वाले गैंग धीरे-धीरे देश में अपना आधार मजबूत कर रहे हैं। यह मादक पदार्थों की तस्करी में गिरफ्तार किए गए विदेशी नागरिकों की संख्या से स्पष्ट है। 2016 में कुल 219 विदेशी नागरिकों को मादक पदार्थों की तस्करी में गिरफ्तार किया गया था जबकि 2017 में यह संख्या 397 हो गई। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनमे जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और अन्य देशों के नागरिक शामिल हैं। एनसीबी के मुताबिक वर्ष 2016 में कुल 38,990 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 2016 में एनडीपीएस एक्ट के तहत 31,535 मामले दर्ज किए गए। वहीं 2017 में कुल 56,006 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया और दर्ज किए गए मामलों की संख्या 47,344 हो गई। बरामदगी का आकार भी वर्षों में बढ़ा है।

पाकिस्तान की आइएसआइ का मादक पदार्थ नेटवर्क सबसे बड़ा

नार्को-टेररिज्म पर आइबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) की एक रिपोर्ट बताती है कि हाल के वर्षों में पाकिस्तान के मादक पदार्थ उद्योग में तेजी आई है और इसकी खुफिया एजेंसी आइएसआइ भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों में नशीले पदार्थ पहुंचाने पर ज्यादा जोर दे रही है। आइबी अधिकारियों के मुताबिक दुनिया में सबसे बड़ा मादक पदार्थ तस्करी का नेटवर्क आइएसआइ का है। आइएसआइ न केवल भारत में मादक पदार्थों को भेजने में सहयोग प्रदान करती है, बल्कि अमेरिका, केन्या, थाईलैंड सहित अन्य देशों में भी इसका नेटवर्क काम करता है।

23 को होगी प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव याचिका पर सुनवाई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद सदस्यता के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका पर उनकी तरफ से बहस पूरी होने पर याची राजबहादुर का पक्ष सुनने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 23 अक्टूबर की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री के अधिवक्ता सत्यपाल जैन व संतोष जैन ने अपने तर्क में कहा कि याची को याचिका दाखिल करने का न्यायिक अधिकार ही नहीं है। याची ने उन शर्तों और औपचारिकताओं का पालन नहीं किया है, जो एक प्रत्याशी के लिए आवश्यक होती है। कहा कि तकनीकी खामियों को देखते याचिका खारिज करने योग्य है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के एडिशनल सॉलीसिटर जनरल और लॉ कमीशन के स्टैंडिंग मेंबर सत्यपाल जैन ने कहा कि यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के अनेक आदेशों, चुनाव आयोगों के निर्देशों और अन्य चुनाव कानूनों को दृष्टिगत रखते पोषणीय नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने कागजात प्रस्तुत करते हुए याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति की।

कह के रहेंगे माधव जोशी

पीड़ितों को न्याय देने की जगह आतंकियों का बचाव करती है कांग्रेस : मोदी

पीएम बोले ▸ कभी भी मुंबई, महाराष्ट्र और हिंदुस्तान भूल नहीं सकता 1993 के बम धमाकों का घाव

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब भी आतंक से पीड़ितों को न्याय देने की बात आती है, तो कांग्रेस और उसके साथी आतंकियों का बचाव करने लगते हैं। प्रधानमंत्री ने बांद्रा-कुर्ला कांप्लेक्स में भाजपा-शिवसेना महागठबंधन की सभा को संबोधित करते हुए 1993 के बम धमाकों की याद दिलाई।

पीएम ने कहा कि 1993 के बम धमाकों का घाव कभी भी मुंबई, महाराष्ट्र और हिंदुस्तान भूल नहीं सकता। धमाकों में मारे गए परिवारों के साथ उस समय की सरकारों ने कोई न्याय नहीं किया। जिन लोगों ने हमारे अपनों को मारा, वे भाग निकले। उसकी वजह अब खुल कर सामने आने लगी है। ये लोग दोषियों को पकड़ने के बजाय उनके साथ मिर्ची का व्यापार कर रहे हैं। कभी मिर्ची का व्यापार, कभी मिर्ची से व्यापार। प्रधानमंत्री ने राकांपा नेता प्रफुल पटेल की ओर इशारा किया। हाल ही में भगोड़े माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के साथी इकबाल मिर्ची के साथ उनके व्यावसायिक संबंध सामने आए हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को पहचानकर उनके दलों से सावधान रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को महाराष्ट्र और देश के गौरव की कोई परवाह नहीं है।

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस शासनकाल में मुंबई में अक्सर होने वाली आतंकी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय था, जब मुंबई आतंकियों का प्रवेश द्वार बन गई थी। यहां कभी भी आतंकी हमले हो जाते थे। तब विदेशों में बैठे आतंकी संगठन खुद आगे आकर हमलों की जिम्मेदारी लेते थे, लेकिन तब की सरकारें कहती थीं कि नहीं-नहीं ये आपने नहीं, हमारे लोगों ने ही किया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से पूछा, 'क्या अब भी वही हो रहा है?' फिर खुद ही जवाब दिया कि अब आतंक को पालने वाले जानते हैं कि यदि कोई गलती की, तो उसकी पूरी सजा मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट सिर्फ दो-तीन शब्द नहीं हैं। ये भाजपा और उसके सहयोगियों की रीति-नीति और पहचान भी हैं। मोदी ने अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि ये वही लोग थे, जो दशकों से जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और धारा 35ए को पाले रहे। इसके कारण आतंकवाद और भ्रष्टाचार बढ़ता गया। कई लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, लेकिन कांग्रेस जैसे दल अपने स्वार्थ की राजनीति करते रहे। जब हमने 370 और 35ए हटाया जम्मू-कश्मीर-लद्दाख और पूरे देश के साथ एकजुटता से खड़े होने के बजाय हमारे विरोधियों की भाषा देखिए। कांग्रेस-राकांपा की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने पूछा कि ये किसकी मदद कर रहे हैं? किसका भला कर रहे हैं? उनका एक-एक शब्द किसकी वकालत कर रहा है?

एक दिन पहले ही मुंबई आकर आर्थिक मोर्चे पर केंद्र की मोदी सरकार एवं राज्य की फड़नवीस सरकार को घेरकर गए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया। नौकरियां देने वालों को दी जा रहीं सुविधाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गरीबी के खिलाफ लड़ाई में 'जॉब क्रियेटर' की भूमिका बहुत बड़ी होती है। हम लाइसेंस राज को कम कर रहे हैं। लोगों को भयमुक्त करने वाली व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। ईमानदारी से टैक्स चुकाने वाला कभी परेशान न हो, उसका ध्यान रख रहे हैं। एक वह थे, जिन्होंने एंजल टैक्स लगाया। एक हम हैं, जिसने एंजल टैक्स खत्म किया। एक वह थे, जिन्होंने भारी-भरकम कार्पोरेट टैक्स लगाया। एक हम हैं, जिसने कम किया। एक वह थे, जो फोन बैंकिंग के जरिये करोड़ों रुपये उनको दिए, जिनमें से कुछ आज तिहाड़ में हैं, तो कुछ मुंबई की जेल में। एक हम हैं, जो मुद्रा लोन के जरिये गरीबों को मदद दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों का ध्यान जनता को नियंत्रित करने पर था, हमारा ध्यान जनभागीदारी पर है। वीर सावरकर का नाम लिए बगैर ही कांग्रेस पर प्रधानमंत्री ने व्यंग्य किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों (कांग्रेस) ने यही अहसास दिलाया कि देश को गुलामी से एक ही परिवार ने आजादी दिलाई। ऐसे में कई योद्धाओं का कभी जिक्र ही नहीं आने दिया गया।

मुंबई में शुक्रवार को चुनावी रैली के दौरान शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ पीएम नरेंद्र मोदी। प्रेट्र

हरियाणा में बोले पीएम, जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह से लागू किया भारतीय संविधान

बिजेंद्र बंसल, सोनीपत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अखंड भारत के इतिहास में पांच अगस्त की तारीख स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी क्योंकि इस दिन जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू किया गया। वह शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत सोनीपत के गोहाना में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए के कारण जम्मू-कश्मीर के समग्र विकास में जो बाधाएं थीं उन्हें दूर कर दिया गया है। उन्होंने उपस्थित लोगों से सवाल किया कि देश हित राजनीति से ऊपर होना चाहिए या नहीं, जबाव हां में आने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सोनीपत के लोगों की यह भावना अब तक कांग्रेस और उसके जैसे दलों के कानों तक नहीं पहुंची है।

उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार किया कि जब भी कोई देश हित का काम होता है कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है। कांग्रेस की यह बीमारी लाइलाज हो गई है। मोदी ने कहा कि देश अब यह भी जान गया है कि कांग्रेस को यह दर्द क्यों होता है? असल में इनके इस दर्द से पाकिस्तान में बैठे इनके हमदर्दों को फायदा होता है।

कश्मीर गए अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं मिले अधिकार

प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 को हटाया जाना अनुसूचित जाति के लोगों के हित में बताते हुए कहा कि इससे उन लोगों को अब फायदा मिलेगा, जिन्हें वर्षों पहले संयुक्त पंजाब से जम्मू-कश्मीर के लोगों की सेवा करने के लिए ले जाया गया था। तब संयुक्त पंजाब में ही हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समाहित थे। यहां के अनुसूचित जाति के लोगों को 70 साल तक बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर द्वारा बनाए संविधान का फायदा नहीं मिलने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है।

राहुल गांधी पर साधा निशाना : प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके बयानों का उपयोग पाकिस्तान दुनिया के मंचों पर भारत के खिलाफ करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दर्द और पाकिस्तान में बैठे इनके हमदर्दों की केमिस्ट्री देश के लोगों को समझ आ गई है। भाजपा ही जनभावनाओं के अनुरूप अगले पांच साल में सशक्त हरियाणा और सशक्त भारत के संकल्प से काम करेगी। अपने संबोधन में मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार के हर कार्य की प्रशंसा की।

शाह ने राहुल से पूछा, आपके परिवार ने आदिवासियों के लिए क्या किया

गढ़चिरौली, प्रेट्र : कांग्रेस पर रोष प्रकट करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उसके नेता राहुल गांधी से पूछा है कि पिछले 70 सालों में उनके परिवार की चार पीढ़ियों ने आदिवासियों के लिए क्या किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले पांच साल में यह क्षेत्र नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अहेरी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य में पिछली कांग्रेस और राकांपा सरकारों के मुकाबले मोदी सरकार ने आदिवासियों के लिए अधिक काम किया है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस और राकांपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने अन्य पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था। यह लक्ष्य भी आखिरकार मोदी ने ही पूरा किया। उन्होंने कहा कि मैं राहुल बाबा से पूछना चाहता हूं कि आपकी चार पीढ़ियों ने देश पर 70 साल शासन किया है। आपने आदिवासियों के लिए क्या किया? जनता ने मोदी सरकार को केवल पांच साल दिए और उन्होंने इसी अवधि में इस समुदाय के लिए कुछ काम किए हैं। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र और राज्य की सरकारों के कामकाज का हवाला देते हुए कहा कि अकेले गढ़चिरौली में ही 1.30 शौचालय बनवाए गए हैं। अकेले आदिवासी परिवारों को ही यहां 48 हजार गैस सिलेंडर और 48 हजार बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा गरीब आदिवासी लोगों को आठ हजार मकान बनाकर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वह राकांपा अध्यक्ष शरद राव (पवार) और राहुल बाबा से महाराष्ट्र में अपने कामकाज का हिसाब मांग रहे हैं। आखिर उन्होंने विदर्भ और अहेरी के लोगों के लिए क्या किया है? क्या उन्हें इसका हिसाब नहीं देना चाहिए? उन्होंने 78 साल के पवार को चुनौती दी कि वह भाजयुमो के अध्यक्ष से सरकार के कामकाज को लेकर बहस कर सकते हैं। अगर वह चर्चा को राजी हों तो हमारी पांच साल की सरकार का कामकाज उनके 50 साल की सरकारों के कामकाज से बेहतर निकलेगा। उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग के तहत कांग्रेस-राकांपा की पिछली सरकार ने महाराष्ट्र को 1.15 लाख करोड़ रुपये दिए थे, जबकि दूसरी ओर मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग के तहत 4.38 लाख करोड़ रुपये दिए हैं।

पुणे के खापरखेड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते भाजपा अध्यक्ष अमित शाह। एएनआइ

नक्सली विकास के विरोधी : गढ़चिरौली नक्सल प्रभावित जिला होने के चलते शाह ने कहा कि यह प्रचार किया गया है कि विकास की कमी के चलते ही नक्सलवाद बढ़ता है, जबकि असलियत में माओवादी विकास का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, अच्छी सड़कें, रेल सेवाएं और अन्य सुविधाएं देना चाहती है, लेकिन नक्सलवादी ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। अब किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने पिछले पांच सालों में नक्सलवाद की कमर तोड़ दी है। हम इस पूरे इलाके से नक्सलवाद को जड़ से मिटा देंगे।

अनुच्छेद 370 से आतंक बढ़ा : शाह ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 नहीं हटाया, जिसके चलते आतंकवाद को बढ़ावा मिला। इसी के चलते ही जम्मू और कश्मीर में 40 हजार से अधिक लोग मारे गए।

बसपा घोषणा पत्र बनाने में नहीं, करनी में विश्वास रखती है : मायावती

जागरण संवाददाता, झज्जर : बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बसपा घोषणा पत्र बनाने में नहीं, करनी में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा, हमारी कथनी और करनी एक जैसी है। आज भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य क्षेत्रीय दलों के घोषणा पत्र जो आपके सामने आ रहे हैं, उन पर भरोसा मत करना। वह शुक्रवार को हरियाणा के बेरी में चुनावी रैली को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों की नीति, नीयत और कार्यशैली को सवालों के घेरे में रखा। करीब आधे घंटे तक दिए अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हरियाणा में दलितों, मजदूरों और कमजोर वर्ग के लोगों का इतने साल में विकास नहीं हुआ। कांग्रेस और भाजपा की मिलीभगत से सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण को प्रभावहीन बना दिया गया। आज दलितों को आरक्षण का ठीक से लाभ नहीं मिल रहा है। भाजपा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है।

मायावती ने कहा कि आज रोजगार भी निजी कंपनियों के माध्यम से मुहैया कराया जा रहा है। जिसमें किसी भी तरह के आरक्षण तक की व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन बसपा आम लोगों के सहयोग से केंद्र में सत्ता तक पहुंचना चाहती है। उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार ने गरीब बेरोजगारों को भत्ता दिया और साथ ही उनको सरकारी और गैर सरकारी विभागों में स्थाई रोजगार दिया।

'पीएम को नहीं है अर्थव्यवस्था की समझ'

महेश कुमार वैद्य, महेंद्रगढ़

हरियाण चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। महेंद्रगढ़ पहुंचे राहुल ने कहा कि पीएम मोदी को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। राहुल ने कहा कि मोदी बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था पर बात नहीं करते।

उन्होंने कहा कि देश में पिछले 40 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है। हालात चिंताजनक है। आने वाले समय में स्थिति और बदहाल होने जा रही है। आज किसी भी उद्योगपति के पास जाइए या किसी व्यापारी के पास जाइए। लोग खुलकर बता रहे हैं कि नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। राहुल ने कहा कि न महंगाई पर बात हो रही है न किसानों की समस्या पर। मोदी कभी 370 की बात करते हैं तो कभी चांद की बात करते हैं। उन्होंने एक बार फिर मोदी पर अडानी और अंबानी जैसे देश के सबसे अमीर 15 लोगों के लिए काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमीरों का 5 लाख 50 हजार करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, लेकिन किसानों की चिंता नहीं की। प्रधानमंत्री ने 1 लाख 25 हजार करोड़ का कॉरपोरेट टैक्स माफ कर दिया। जिस दिन कॉरपोरेट टैक्स कम किया, उस दिन मीडिया ने अर्थव्यवस्था पटरी पर आने का सपना दिखाया, लेकिन दुनिया में भारत का मजाक बनाया जा रहा है।

हरियाणा के महेंद्रगढ में परिवर्तन रैली को संबोधित करते राहुल गांधी। पुनीत भारद्वाज

राहुल के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग

महेंद्रगढ़ रैली से वापस लौटते समय मौसम खराब होने के चलते राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की रेवाड़ी में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दिल्ली रोड स्थित केएलपी कॉलेज के मैदान में उनके हेलीकॉप्टर को उतारा गया। राहुल के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैडिंग की सूचना जैसे ही जिला के आला अधिकारियों को लगी तो हड़कंप मच गया। प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर पुलिस के आला अधिकारी भी केएलपी कॉलेज पहुंचे। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद राहुल ने केएलपी के खेल मैदान में मौजूद बच्चों के साथ कुछ देर के लिए क्रिकेट भी खेला।

मनमोहन की योजनाओं की तारीफ : राहुल ने कहा कि मनमोहन सिंह ने दस साल में देश को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाया था। मनरेगा जैसी योजना से देश की अर्थव्यवस्था को ताकत दी थी।

राहुल गांधी अभी भी कांग्रेस की मजबूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ सोनिया व प्रियंका की मांग के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवारों को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष से करना पड़ा संतोष

राजनीतिक चुनौतियों के चक्रव्यूह में घिरी कांग्रेस की मुसीबत हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में भी एक बार फिर खुले तौर पर नजर आ रही है। सेहत की चुनौतियों की वजह से सोनिया गांधी चुनाव प्रचार नहीं कर पाईं। तो पार्टी की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा फिलहाल उत्तर प्रदेश से बाहर कांग्रेस की दशा पर निगाह डालने को तैयार नहीं दिख रहीं। पार्टी के दिग्गज नेताओं और उसके मुख्यमंत्रियों की भी चुनाव अभियान में खास भूमिका नहीं दिखी है। शायद तभी पार्टी की कमान छोड़ चुके राहुल गांधी को प्रचार अभियान की कमान देना कांग्रेस की मजबूरी बन गई है।

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की इस सियासी मजबूरी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिन स्टार प्रचारकों के लिए सबसे ज्यादा मांग की थी, उसमें सोनिया गांधी पहले नंबर पर थीं। कांग्रेस अध्यक्ष के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली या रोड शो की सबसे ज्यादा मांग थी। जबकि राहुल गांधी इन दोनों के बाद पार्टी उम्मीदवारों की तीसरी पसंद थे।

मगर हकीकत यह रही कि दोनों सूबों में सोनिया और प्रियंका की एक भी सभा नहीं हुई। जबकि हरियाणा कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने इन दोनों की उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा मांग होने का हवाला देते हुए दक्षिणी और मध्य हरियाणा की सीटों का जिक्र किया। उनके मुताबिक इन दोनों इलाकों के कम से 12 उम्मीदवारों ने सोनिया गांधी तो 8 से 10 प्रत्याशियों ने प्रियंका की चुनावी रैली की मांग की थी। सोनिया की शुक्रवार को हरियाणा के महेंद्रगढ़ की इकलौती रैली भी अंतिम समय में रद हो गई और उनकी जगह राहुल की चुनावी सभा कराई गई। कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान की यह लचर रणनीति तमाम सवालों को जन्म देती है। खासकर यह देखते हुए कि पार्टी की रीति-नीति से लेकर चुनौती से उबारने की पूरी जिम्मेदारी गांधी परिवार के इन तीनों सदस्यों पर ही है। सोनिया गांधी की सेहत पिछले काफी समय से सियासी दौरों में बाधा रही है। स्वास्थ्य की उनकी चुनौती पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। मगर सक्रिय राजनीति में उतरने के बाद भी केवल उत्तर प्रदेश तक ही खुद को सीमित रखने की प्रियंका की रणनीति पर तो अंदरखाने पार्टी में ही सवाल उठाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की भारी शिकस्त और राज्य दर राज्य उसकी खराब होती सियासी हालत को देखते हुए प्रियंका की सीमित भूमिका से जुड़े ऐसे सवालों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इटली में परंपरागत रूप से पुरुष प्रधान सत्ता रही है मगर भारत में मातृसत्तात्मक संस्कृति की विरासत रही है। ऐसे में सवालों का सरोकार कांग्रेस की मौजूदा चुनौतियों से जुड़ा है या नहीं यह तो वक्त बताएगा मगर पार्टी के कार्यकताओं ही नहीं आम जनता के मन में भी इस तरह के तमाम सवाल उमड़-घुमड़ रहे हैं। यह शायद इसलिए कि देश के लोग हमारे लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष के विकल्प के रूप में कांग्रेस की ताकतवर मौजूदगी चाहते हैं।

चुनावी हार-जीत राजनीति का अहम पहलू है मगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही सब कुछ नहीं है। सियासत में उतार-चढ़ाव के ऐसे दौर में कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी से ज्यादा मजबूत और परिपक्व व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। मगर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव अभियान में शीर्षस्थ नेतृत्व की आपसी अंदरूनी सहमति-असहमति के सवालों से कांग्रेस उबर नहीं पायी। शायद यही वजह है कि उपर से लेकर नीचे तक पार्टी का पूरा ढांचा दयनीय और दिशाहीन दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं और चार बड़े सूबों के मुख्यमंत्रियों कमलनाथ, अशोक गहलोत, कैप्टन अमरिंदर और भूपेश बघेल जैसे चेहरों का चुनाव अभियान में उपयोग नहीं कर पाना इस दिशाहीनता का ही पुख्ता सुबूत है। मई में हुए लोकसभा चुनाव से पूर्व के सभी चुनावों में कांग्रेस अपने तमाम दिग्गज चेहरों को मैदान में उतारती रही थी। मगर एक तरफ जहां भाजपा के शीर्ष दो दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह व राजनाथ सिंह के अलावा जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं ने प्रचार अभियान का मोर्चा संभाल रखा है। वहीं कांग्रेस के चारों मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे भीड़ जुटाऊ नेता भी चुनाव अभियान से दूर रहे।

वीर सावरकर की अनुयायी थीं इंदिरा गांधी : रणजीत

मुंबई, एएनआइ : वीर सावरकर को भारत रत्न देने के प्रस्ताव को घोषणा पत्र में शामिल करने पर छिड़े विवाद के बीच उनके पड़पौत्र का बयान आया है। रणजीत सावरकर ने कहा है कि इंदिरा गांधी भी वीर सावरकर की अनुयायी थीं। उन्होंने वह सब कुछ किया जो नेहरू और गांधी के दर्शन के खिलाफ था। रणजीत ने एएनआइ से कहा, 'इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर को सम्मानित किया, मेरा पक्का मानना है कि वह सावरकर की अनुयायी थीं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर किया, सेना और विदेशी संबंधों को मजबूत किया, उन्होंने परमाणु परीक्षण भी किया। यह सब नेहरू और गांधी के दर्शन के खिलाफ है।' रणजीत ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को सावरकर के विश्वास का पालन करना चाहिए, कि धर्म को आप घर में रखें। घर के बाहर आप न हिंदू हैं न मुस्लिम, सिर्फ भारतीय हैं। सावरकर ने सभी से अपेक्षा की कि जो संसद में प्रवेश करे वह जाति, धर्म, लिंग आदि से दूरी बनाए रखे। आप सावरकर से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष आदमी नहीं खोज पाएंगे।

बसपा छोड़ भाजपा के हुए करतार भड़ाना

बिजेंद्र बंसल, नई दिल्ली

▸ हरियाणा विधानसभा चुनाव में रूठे नेताओं को मनाने का मिला जिम्मा

बड़े नाटकीय घटनाक्रम में हरियाणा के पूर्व मंत्री करतार भड़ाना भाजपा में शामिल हो गए। 2019 में मुरैना लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय कृषि मंत्री और पार्टी के हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले करतार भड़ाना को पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा में शामिल किया। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने उन्हें प्राथमिक सदस्यता की स्लिप दी। करतार ने नड्डा से मुलाकात के बाद फरीदाबाद में तोमर से भी मुलाकात की। सूत्र बताते हैं कि तोमर ने भड़ाना को फरीदाबाद, पलवल, नूंह जिला सहित समालखा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के रूठे नेताओं को मनाने का जिम्मा दिया है।

2004 से 2009 तक भाजपा में रह चुके हैं करतार : करतार भड़ाना भाजपा में पहली बार नहीं आए हैं, इससे पहले 2004 में हरियाणा मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर भड़ाना भाजपा में शामिल हुए थे। तब उन्होंने राजस्थान के दौसा लोकसभा क्षेत्र में सचिन पायलट के खिलाफ चुनाव लड़ा था। दौसा में हारने के बाद करतार ने 2005 में हरियाणा में सोहना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन यहां भी हर गए। 2009 में करतार ने बसपा से फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, यहां भी हार गए। सन 2012 में चौधरी अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए और उत्तर प्रदेश के खतौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन गए। 2014 में करतार ने रालोद के ही टिकट पर कैराना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा मगर जीत नहीं सके। इस हार के बाद करतार 2019 में पहले कांग्रेस में सक्रिय हुए, लेकिन जब उनके छोटे भाई अवतार भड़ाना भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए तो उन्होंने बसपा में जाना बेहतर समझा।

नई दिल्ली में शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने करतार सिंह भड़ाना को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। ध्रुव कुमार

हर बड़े गुर्जर नेता के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं भड़ाना बंधु : करतार और उनके छोटे भाई अवतार भड़ाना हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के हर बड़े नेता के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। गुरुग्राम के सोहना विधानसभा क्षेत्र से करतार ने जब भाजपा के राजस्थान से मौजूदा सांसद सुखबीर जौनापुरिया के सामने चुनाव लड़ा तो महज 6733 मत ही ले पाए। सचिन पायलट के अलावा अवतार भड़ाना केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर और खुद करतार भड़ाना हरियाणा के पूर्व मंत्री और बड़े गुर्जर नेता महेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ 2009 में विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं।

समीकरण

इस बार लड़ाई भाजपा-शिवेसना गठबंधन और कांग्रेस-राकांपा गठबंधन के बीच, कई सीटों पर अगल-अलग पार्टियों से आमने-सामने हैं रिश्तेदार

नई पीढ़ी के लड़ाकों का गवाह बन रहा मराठवाड़ा

ओमप्रकाश तिवारी, लातूर

महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र भले ही सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है, लेकिन नए सियासी खिलाड़ियों की पैदावार में यह कतई पीछे नहीं है। यहां कभी विलासराव देशमुख और गोपीनाथ मुंडे आपस में टकराते देखे जाते थे, तो आज उनकी अगली पीढ़ियां ताल ठोंकती नजर आ रही हैं।

कभी हैदराबाद के निजाम की रियासत में शामिल रहा मराठवाड़ा 1960 में महाराष्ट्र का गठन होने के बाद इस राज्य का हिस्सा बना। आठ जिलों औरंगाबाद, बीड, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड़, लातूर और उस्मानाबाद में कुल 46 विधानसभा सीटें हैं। 2014 में कांग्रेस, राकांपा, शिवसेना और भाजपा की अलग-अलग लड़ाई में भाजपा 15, शिवसेना 11, कांग्रेस नौ और राकांपा आठ सीटें पाने में कामयाब रही थीं। इस बार लड़ाई भाजपा-शिवसेना गठबंधन और कांग्रेस-राकांपा गठबंधन के बीच है।

मराठवाड़ा भले पिछड़ा है, लेकिन इसने कई दिग्गज नेता महाराष्ट्र को दिए हैं। लातूर से शिवाजीराव निलंगेकर और विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री रहे, तो नांदेड़ के शंकरराव चव्हाण और उनके पुत्र अशोक चव्हाण भी मुख्यमंत्री रहे। बीड के गोपीनाथ मुंडे 1995 में पहली बार बनी शिवसेना-भाजपा गठबंधन सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे।

लेकिन इतने दिग्गज नेता देनेवाला मराठवाड़ा विकास के मामले में भी सूखा ही रहा। ऊपर से पिछले पांच वर्ष में तीन वर्ष सूखा झेलनेवाले इस क्षेत्र में कुछ वर्ष पहले ट्रेन से पेयजल भिजवाने की नौबत आ गई थी। यही कारण रहा कि पांच वर्ष पहले आई देवेंद्र फड़नवीस ने 2015 से जलयुक्त शिवार योजना के जरिये गांव का पानी गांव में संचय करने की योजना शुरू की। इसके तहत काफी काम हुआ भी है। लेकिन क्षेत्र को इसका लाभ तभी मिल पाएगा जब अच्छी बरसात हो और जलयुक्त शिवार योजना के तहत तैयार तालाब, बावड़ी और नाले पूरी तरह भर जाएं। मराठवाड़ा को सूखे से उबारने के लिए भाजपा ने इस बार के संकल्प पत्र में कोंकण क्षेत्र से बरसात का वह पानी मराठवाड़ा में लाने की घोषणा की है, जो फिलहाल समुद्र में बह जाता है।

मराठवाड़ा इस बार कई रोचक लड़ाइयों का गवाह बनने जा रहा है। इनमें उन्हीं नेताओं की अगली पीढ़ियां जोर-आजमाइश करती दिखाई दे रही हैं, जो अब नहीं रहे। बीड जिले की परली विधानसभा सीट पर गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे और भतीजे धनंजय मुंडे आमने-सामने हैं। पिछला चुनाव धनंजय मुंडे अपनी चचेरी बहन से हारे थे। इस बार वह राकांपा के ही टिकट पर पंकजा के सामने किस्मत आजमा रहे हैं।

इसी प्रकार लातूर से पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के दो बेटे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े बेटे अमित देशमुख लातूर शहर से तो छोटे बेटे धीरज देशमुख लातूर ग्रामीण से मैदान में हैं। अमित पहले भी विधायक रह चुके हैं, जबकि धीरज पहली बार मैदान में हैं।

निलंगा सीट पर पर परली की ही तरह एक ही परिवार के दो सदस्य आमने-सामने हैं। करीब 30 साल पहले कांग्रेस शासन में मुख्यमंत्री रहे शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर के पौत्र एवं फड़नवीस सरकार में मंत्री रहे संभाजी पाटिल निलंगेकर को इस बार अपने ही चाचा अशोक का सामना करना पड़ रहा है। अशोक पाटिल 2014 में एक बार अपने भतीजे से हार चुके हैं। यही नहीं, 2004 में संभाजी पाटिल अपने दादा शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर को भी एक बार पराजित कर चुके हैं। लातूर जिले का हिस्सा निलंगा लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन निलंगेकर परिवार में भाजपा की घुसपैठ के बाद यहां स्थिति बदल चुकी है। लातूर के पड़ोस की सीट तुलजापुर में भी युवा नेता राणा जगजीत सिंह पांच बार कांग्रेस के विधायक रहे मधुकर राव चह्वाण को चुनौती दे रहे हैं। राणा जगजीत सिंह दिग्गज राकांपा नेता एवं पूर्व सांसद पद्मसिंह पाटिल के पुत्र हैं और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं।

सचिन पायलट ने आयकर छापों पर भाजपा को घेरा

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ (फरीदबाद)

राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने तिगांव के कांग्रेस प्रत्याशी ललित नागर और उनके कार्यकर्ताओं पर आयकर विभाग के छापे लगवाने पर भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि ऐसे छापों से कांग्रेस प्रत्याशी डरने वाला नहीं है। तिगांव विधानसभा क्षेत्र में ललित नागर की पहचान बहादुर व जुझारू नेता की है। यहां की जनता उनके साथ खड़ी है।

पायलट शुक्रवार को फरीदाबाद की तिगांव अनाज मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी ललित नागर की चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। जब पायलट छापों का अपने संबोधन में जिक्र कर रहे थे, तब ललित नागर व उनके कार्यकर्ता भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वो 2014 में भी इसी मंडी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आए थे और उनके कहने पर तिगांव के मतदाताओं ने ललित को जिताकर चंडीगढ़ भेजा। ललित ने इन पांच वर्ष में पूरे जिले की समस्याओं को उठाया और क्षेत्र की मजबूती से सेवा की। इस बार फिर एक बार वे ललित के लिए वोट देने का आग्रह करने आए हैं, क्योंकि पूरी भाजपा सरकार उन्हें हराने के लिए जुटी है। अब तक यहां पर भारत के गृह मंत्री, कपड़ा मंत्री, दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री चुनावी सभाओं को संबोधित करने आ चुके हैं। ये लोग इसलिए आ रहे हैं, क्योंकि ललित एक मजबूत नेता हैं।

फरीदाबाद के तिगांव अनाज मंडी में चुनावी सभा को संबोधित करते सचिन पायलट। जागरण

1885 नें निर्मोही अखाड़े के महंत ने फैजाबाद कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की कि हिंदुओं को मस्जिद के अंदर जाकर पूजा करने की अनुमति दी जाए। क्योंकि मुसलमान अंदर नमाज पढ़ते थे, इसलिए इसकी इजाजत नहीं मिली।

गुजरात एटीएस की चार्जशीट में कमलेश की हत्या की साजिश का था जिक्र

खुलने हैं कई राज ▶ हिंदू महासभा के नेता की हत्या के पीछे इस्लामिक स्टेट के कनेक्शन से इन्कार नहीं

13 अक्टूबर को ही अपनी जान की सुरक्षा को लेकर किया था ट्वीट

जागरण संवाददाता, लखनऊ

कमलेश की हत्या के पीछे आइएस (इस्लामिक स्टेट) का कनेक्शन दरकिनार नहीं किया जा सकता। गुजरात में करीब एक साल पहले पकड़े गए आतंकी संगठन आइएस के सक्रिय सदस्य मु. उबैद मिर्जा व कासिम ने पूछताछ में कई राज उगले थे। गुजरात एटीएस ने मई 2018 में दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें उनके द्वारा कमलेश तिवारी की हत्या की साजिश रचे जाने का भी जिक्र था। चार्जशीट में उबैद मिर्जा के एक वीडियो का भी जिक्र था, जिसमें वह लखनऊ के कमलेश तिवारी की हत्या करने की बात कह रहा था। एक अंग्रेजी अखबार में इन तथ्यों पर आधारित खबर के प्रकाशित होने पर 13 अक्टूबर 2019 को कमलेश तिवारी ने एक ट्वीट किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एडीजी जोन लखनऊ और एसएसपी को टैग किया गया था। ट्वीट में कमलेश ने बड़ी साजिश के बावजूद उनकी सुरक्षा बढ़ाने के आवेदन पर कोई निर्णय न लिये जाने पर नाराजगी जताई थी।

दरअसल, कमलेश तिवारी के घर पर मिठाई के जिस डिब्बे में चाकू और पिस्टल रखकर ले जाई गई, वह मिठाई 16 अक्टूबर की रात 9:30 बजे सूरत के उद्योगनगर उधना स्थित धरती फूड प्रोडक्ट प्रा. लि. से खरीदा गया था। डिब्बे में 680 रुपये प्रति किलोग्राम वाली पिस्ता घारी को 530 रुपये देकर 750 ग्राम खरीदा गया था। मिठाई का डिब्बा गुजरात की एक दुकान का होना महज इत्तफाक है, यह फिर किसी गहरी साजिश का हिस्सा। इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बीते दिनों नेपाल के रास्ते कुछ आतंकियों के देश के सीमा में घुसने की बात भी सामने आई है। इन परिस्थितियों में हिंदूवादी नेता की हत्या के पीछे किसी साजिश को नकारा नहीं जा सकता।

घट गई थी सुरक्षा : विवादित टिप्पणी मामले में कमलेश पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी। इस मामले में जेल से छूटने के बाद कमलेश की सुरक्षा में दो गनर लगाये गये थे और घर की सुरक्षा में आठ पुलिसकर्मी तैनात किये गये थे। 2017 में घर की सुरक्षा मे लगे पुलिसकर्मी हटा लिए गए थे। कमलेश का एक गनर भी कम कर दिया गया था। कमलेश ने 27 जून को भी अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए डीएम आवास के सामने प्रदर्शन किया था। पिछले महीने ही कमलेश तिवारी ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए डीएम और एसएसपी को आवेदन दिया था।

तो क्या विमान से आए हत्यारे : सूरत से 16 अक्टूबर की रात 9:30 बजे मिठाई खरीदने के बाद हत्यारों के विमान से लखनऊ आने की संभावना भी है। सूरत से लखनऊ के लिए 17 अक्टूबर की सुबह तीन बजे केवल एक ही ट्रेन 19037 अवध एक्सप्रेस थी। जो कि टूंडला की नॉन इंटरलाकिंग के डायवर्जन के कारण बदले रूट से शुक्रवार दोपहर तीन बजे पहुंच सकी थी। ऐसे में हत्यारों के अहमदाबाद जाकर सीधे विमान से लखनऊ आने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। जांद दल इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है और जल्द ही सभी राज खुलेंगे।

लखनऊके खुर्शेदबाग में हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या के बाद रोती-बिलखतीं उनकी पत्नी को संभालते पड़ोसी (बाएं) और घटनास्थल पर जांच करती पुलिस (दाएं) जागरण

सिर कलम करने पर किया था 1.62 करोड़ इनाम का एलान

जासं, बिजनौर : करीब चार साल पहले धार्मिक टिप्पणी पर जिले के दो मौलाना ने हिंदू महासभा के कमलेश तिवारी का सिर कलम करने पर 1.62 करोड़ रुपये के इनाम का एलान किया था। शुक्रवार को लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या के बाद एक बार फिर दोनों मौलाना के बयान का जिन्न बाहर आ गया। एक दिसंबर 2015 को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कमलेश तिवारी ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की थी। इस पर पुलिस ने उन्हें दो दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया था। कमलेश तिवारी के इस बयान के विरोध में चार दिसंबर 2015 को बिजनौर निवासी मौलाना अनवारुल हक के नेतृत्व में मुस्लिमों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान मौलाना अनवारुल हक ने कमलेश तिवारी का सिर कलम करने वाले को 51 लाख रुपये इनाम देने का एलान किया था। इसके बाद छह दिसंबर 2015 को भनेड़ा गांव में मुफ्ती नईम ने कमलेश तिवारी का सिर कलम करने वाले को एक करोड़ 11 लाख रुपये और हीरों का हार इनाम में देने की घोषणा की थी।

फाइलों में दब गया मामला : कमलेश तिवारी का सिर कलम करने पर इनाम की घोषणा के बाद मौलाना अनवारुल हक व मुफ्ती नईम चर्चा में आ गए। उन दिनों मौलाना अनवारुल हक व मुफ्ती नईम के खिलाफ शहर कोतवाली में एनसीआर (गैर संज्ञेय रिपोर्ट) दर्ज की गई थी। एक मुकदमा भी हुआ। हालांकि तत्कालीन सपा सरकार में पुलिस प्रशासन ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की थी।

अनवारुल पर था दुष्कर्म का मामला : मौलाना अनवारुल हक के खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म का मामला भी दर्ज कराया था। इस मामले में मौलाना अनवारुल हक को जेल जाना पड़ा था।

बिजनौर पुलिस हरकत में : हत्याकांड की जानकारी मिलते ही बिजनौर पुलिस हरकत में आ गई। मौलाना अनवारुल हक के खिलाफ दर्ज मुकदमों की फाइलें पलटी जाने लगीं। कोतवाल रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि उक्त मामलों में विवेचना तो की गई थी लेकिन कार्रवाई क्या हुई, इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है।

गुरुजी ने दही बड़ा खिलाया, फिर भी कर दी हत्या

जागरण संवाददाता, लखनऊ : 'गुरुजी (कमलेश तिवारी) से मिलने आने से 10 मिनट पहले उनके पास फोन आया था। इसके बाद दोनों (हत्यारे) घर आए। नीचे सुरक्षाकर्मी सो रहा था। इस पर जब दोनों ऊपर वाले कमरे में पहुंचे तो गुरुजी भी अपने कमरे से बाहर आ गए। गुरुजी ने उनको पहले दहीबड़ा खिलाया। इसके बाद दोनों युवकों ने पांच सिगरेट लाने के लिए 100 रुपये का नोट दिया। मैं पास की दुकान से सिगरेट लेकर जल्दी से आ गया। इसके बाद गुरुजी ने मसाला लाने को कहा। जब मैं मसाला लेकर पहुंचा तो गुरुजी मेज के नीचे लहूलुहान पड़े थे।' यह कहना है कमलेश तिवारी के घर पर रहने वाले सौराष्ट्र जीत सिंह का। सौराष्ट्र जीत सिंह ही कमलेश तिवारी को अस्पताल लेकर भागा था। बकौल सौराष्ट्र दोनों युवकों और कमलेश के बीच किसी मुस्लिम लड़की की शादी को लेकर भी बात हो रही थी। घटना के बाद 100 नंबर पर फोन किया तो पुलिस भी देर से पहुंची।

समय पर नहीं आता था गनर : कमलेश तिवारी को जो गनर दिया गया था, वह कभी समय पर आता ही नहीं था। उसके देर से आने की शिकायत कमलेश तिवारी पुलिस से कर चुके थे। गनर के उनके घर आने का समय ही दोपहर एक से दो बजे का होता था। माना जा रहा है कि हत्यारों के पास इसकी पुख्ता सूचना थी कि गनर एक बजे के बाद ही आएगा। इससे पहले ही घटना को अंजाम देना होगा। हिंदू समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने पुलिस व्यवस्था में चूक को लेकर नाराजगी भी जताई। जिस कमरे में घटना हुई। उसके बाहर एक अधजली सिगरेट और उसकी खाली डिब्बी भी पड़ी मिली। वहीं घटनास्थल वाले कमरे से लेकर सीढ़ी तक खून के कई निशान भी पाए गए। यह सिगरेट उन युवकों ने ही पी थी।

सरकारों के लिए हमेशा चुनौती बने रहे कमलेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- सपा सरकार में लगी थी रासुका, एक वर्ष से अधिक जेल में रहे
- भाजपा सरकार में राम मंदिर निर्माण के लिए हुई थी गिरफ्तारी

कमलेश तिवारी की हत्या ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की पेशानी पर बल ला दिया है। तिवारी की हत्या ऐसे संवेदनशील वक्त में हुई है जब लखनऊ समेत 11 विधानसभा क्षेत्रों में उप चुनाव चल रहा है और प्रदेश धनतेरस, दीपावली और छठ जैसे त्योहारों की अगवानी के लिए तैयार बैठा है। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आने वाला है। आक्रामक बयानों के चलते लखनऊ निवासी कमलेश तिवारी की अलग पहचान बन गई थी। सपा के एक प्रभावशाली नेता ने आरएसएस पर विवादित टिप्पणी की तो नवंबर 2015 में जवाब में उन्होंने पैगंबर हजरत मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इसके विरोध में देश भर में एक वर्ग की आवाज गूंजने लगी। तिवारी को न केवल जेल भेजा गया बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) में भी वह निरुद्ध किए गए। भाजपा सरकार बनने के डेढ़ माह बाद ही कमलेश ने राम मंदिर निर्माण के लिए संकल्प मार्च निकालने का एलान किया तो फिर उन्हें समर्थकों समेत गिरफ्तार किया गया। वह सरकारों के लिए हमेशा चुनौती बने रहे।

तत्कालीन हिंदू महासभा के नेता के रूप में कमलेश की राजनीतिक सक्रियता बढ़ी, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने हिंदू समाज पार्टी नाम से राजनीतिक संगठन बना लिया। उनके समर्थन में कुछ हिंदू संगठन भी आगे आए। जब उनपर रासुका लगाई गई तो बिजनौर के उलमा ने कमलेश का सिर कलम करने का फतवा जारी कर दिया। इसके बाद उनके संगठन ने प्रदर्शन किया। उनके समर्थक रासुका हटाए जाने की मांग भी करते थे। कमलेश को उन्नाव जेल भेजा गया था। उन्हें अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन रासुका होने की वजह से रिहा नहीं हो पा रहे थे। गिरफ्तारी के करीब एक वर्ष बाद अक्टूबर 2016 में कमलेश तिवारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहत दी और रासुका से मुक्त कर दिया।

गोडसे का मंदिर बनाने का एलान कर चर्चा में आए

कमलेश तिवारी चर्चा में तब आए, जब 2014 में उन्होंने अपने पैतृक गांव (सीतापुर स्थित पारा गांव) में नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाने का एलान किया। कमलेश तिवारी ने दिसंबर 2014 में पारा गांव में गोडसे का मंदिर बनाने का एलान किया। उन्होंने दावा किया था कि 30 जनवरी 2015 को पारा गांव में मंदिर की नींव रखेंगे। तब उनका गांव छावनी में तब्दील हो गया था। उसके बाद कमलेश सीतापुर नहीं पहुंचे।

समझौते पर बात आगे बढ़ी तो फैसले में होगी देरी

माला दीक्षित, नई दिल्ली

- प्रतिनिधि सूट में समझौते की प्रक्रिया बहुत लंबी
- 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे प्रधान न्यायाधीश

अयोध्या राम जन्मभूमि पर मालिकाना हक के विवाद में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी होकर फैसला सुरक्षित होने के बाद लोगों की निगाहें सिर्फ फैसले पर टिकी हैं, लेकिन बीच में मध्यस्थता से समझौते की चर्चा ने नया पेच उलझा दिया है। इस मुकदमे की सुनवाई करने वाली पीठ के अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं इसलिए उसके पहले ही फैसला आने की उम्मीद है। लेकिन कानूनविदों का कहना है कि अगर कोर्ट मध्यस्थता समिति की ओर से कुछ पक्षकारों के बीच हुए समझौते पर संज्ञान लेगा तो 17 नवंबर की समयसीमा के भीतर फैसला आना मुश्किल होगा। अगर प्रधान न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति तक फैसला नहीं आया तो तय नियम के मुताबिक दोबारा से मुकदमा सुना जाएगा। इस विचार को इससे भी बल मिलता है कि मामले की सुनवाई करने वाले पांचों जज चैंबर में बैठे, लेकिन अभी तक कोर्ट से इस बारे में पक्षकारों को कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई है।

अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद का यह मुकदमा कानून की निगाह में प्रतिनिधि सूट है। प्रतिनिधि सूट का मतलब है कि यह मुकदमा मात्र कुछ पक्षकारों के बीच जमीन पर मालिकाना हक का नहीं है बल्कि हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों के बीच है। इस मुकदमे को कानून की तय प्रक्रिया के तहत अखबार में पब्लिक नोटिस जारी कर कोर्ट के आदेश पर प्रतिनिधि सूट बनाया गया था। प्रतिनिधि सूट में समझौते से विवाद सुलझाने के कुछ नियम हैं जिनका कानूनन पालन जरूरी है। ऐसे मुकदमों में दावा वापस लेने या समझौते के जरिये विवाद हल करने की प्रक्रिया के लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश-एक नियम-8 उपनियम-4 और आदेश-23 के प्रावधानों को एक साथ देखना होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसआर सिंह कहते हैं कि प्रतिनिधि सूट के बारे में सीपीसी के आदेश-एक नियम-8 उपनियम-4 में लिखा है कि कोर्ट की इजाजत के बगैर कोई भी पक्ष प्रतिनिधि सूट में न तो मुकदमा वापस ले सकता है, न समझौता कर सकता है और न ही उस मुकदमे को त्याग सकता है। कानून कहता है कि ऐसे मुकदमे में समझौता या दावा वापस लेने से पहले कोर्ट उस मुकदमे में रुचि रखने वाले सभी लोगों को नोटिस देगा, उनकी राय जानेगा और संतुष्ट होने के बाद ही समझौते के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। एसआर सिंह कहते हैं कि इस मुकदमे में अखबार में पब्लिक नोटिस निकालना पड़ेगा क्योंकि आदेश- एक नियम-8 के उपनियम-2 में संबंधित लोगों को नोटिस देने की बात है। उसमें यह भी कहा गया है कि अगर सभी तक नोटिस भेजना व्यवहारिक न हो तो पब्लिक नोटिस दिया जाएगा। इस मुकदमे में सभी हिंदू और मुसलमान लोग रुचि रखते हैं ऐसे में पब्लिक नोटिस ही निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो प्रक्रिया में बहुत वक्त लगेगा और 17 नवंबर तक फैसला आना मुश्किल होगा।

17 नवंबर को जस्टिस रंजन गोगोई सेवानिवृत्त हो जाएंगे और अगर तब तक फैसला नहीं आया और मुकदमे में समझौता भी नहीं हुआ तो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद नई पीठ गठित करनी पड़ेगी और नए सिरे से पूरे मुकदमे की सुनवाई होगी। वह यह भी कहते हैं कि सिर्फ एक-दो पक्षकारों की ओर से दिए गए कथित समझौता प्रस्ताव का ज्यादा मतलब नहीं है और उन्हें नहीं लगता की कोर्ट उस पर संज्ञान लेगा।

सुप्रीम कोर्ट। फाइल फोटो

अयोध्या में खोदाई के दौरान मिले थे भव्य मंदिर के अवशेष

साक्षात्कार

● खोदाई में विवादित ढांचे के नीचे मंदिर होने के किस तरह के अवशेष मिले थे?

-अयोध्या में दो बार खोदाई हुई है। पहली बार 1976-77 में प्रो. बीबी लाल के नेतृत्व में हुई। उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इंस्टीट्यूट के छात्र की हैसियत से मैं भी टीम का सदस्य था। दूसरी बार 2003 में अयोध्या में खोदाई हुई थी। यह खोदाई डॉ. बीआर मणि के नेतृत्व में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर हुई। पहली बार हुई खोदाई में 12 पिलर मिले थे, जो भव्य मंदिर होने का प्रमाण हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, इन पिलर में जो कलश थे, वह मंदिर में ही होते हैं। दूसरी बार हुई खोदाई में भी ऐसे 50 से भी अधिक पिलर मिले थे। जिस तरह दिल्ली की कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद को मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है, ठीक उसी से मिलते-जुलते हालात अयोध्या के हैं।

● ऐसा कहा जाता है कि पहली बार खोदाई करने वाली टीम में आप एक मुस्लिम सदस्य थे, जबकि 2003 में हुई खोदाई में कोई भी मुस्लिम सदस्य नहीं था?

-यह बिल्कुल गलत है, दूसरी बार की खोदाई में चार मुस्लिम अधिकारी थे, जो बेहद अनुभवी थे। इसकी रिपोर्ट बनाने वाली टीम में भी ये चारों अधिकारी शामिल थे। इसके अलावा खोदाई करने वाले 150 मजदूरों में से 40 के करीब मुस्लिम थे।

● यह आप किस आधार पर कह रहे हैं कि विवादित ढांचे के नीचे मंदिर था? वहां बुद्ध विहार भी हो सकता है?

-खोदाई में केवल पिलर ही नहीं मिले थे, बल्कि एक परनाली मिली थी। इसमें मगरमच्छ की आकृति बनी थी, जो मंदिर में ही होती है। एक शिलालेख मिला था, जो राम के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। इस पर लिखा था, जिसने बालि को मारा, यानी राम। जिसने दस सिर वाले को मारा, यानी राम। जहां तक बौद्ध विहार की बात है तो खोदाई में 200 से अधिक वस्तुएं मिलीं, लेकिन बुद्ध से संबंधित इनमें कोई साक्ष्य नहीं मिला।

● सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने कहा कि एएसआइ के पास काम करने की कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है?

-उन्हें शायद पता नहीं है कि यह संस्था कितनी पुरानी है। यहां जो भी होता है साक्ष्यों और वैज्ञानिक तरीके से ही होता है। खोदाई में एक-एक चीज का आकलन और अध्ययन होता है। देश ही नहीं श्रीलंका व बर्मा तक में एएसआइ ने अपनी सेवाएं दी हैं।

● मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि एएसआइ विवादित ढांचे के नीचे मंदिर साबित करने में लगा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे?

-यह कहना बिल्कुल गलत है। मैं खुद एक मुस्लिम हूं, इस्लाम को मानता हूं, मगर साक्ष्यों को कैसे झुठलाया जा सकता है। आपको पता है कि जब मैं दिल्ली में तैनात था तो उस समय कई बार एएसआइ के स्मारकों में धार्मिक गतिविधियों का प्रयास किया गया, जिसे पूरी सख्ती के साथ रोका गया था। बिहार में तैनाती के दौरान 2008 में शेरशाह सूरी के मकबरे के पास उस समय के भाजपा विधायक जवाहर प्रसाद ने मंदिर बनाने का प्रयास किया तो उसे भी रुकवाया। आगरा के ताजमहल में बीएचपी के लोगों ने एक पुराने मंदिर को विस्तार देने की कोशिश की तो उस पर बुलडोजर चलवाया।

डॉ. के के मुहम्मद

मध्यस्थता कमेटी व निर्वाणी अखाड़ा पर लगाया आरोप

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

बयान में कहा गया है कि वे सभी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के एओआर शाहिद रिजवी के मीडिया में आए बयान से अचंभित हैं जिसमें उन्होंने कुछ शर्तों के साथ विवादित ढांचे की जगह दावा छोड़ने की बात कही है। बयान के मुताबिक, यह खबर या तो मध्यस्थता कमेटी ने लीक की है या फिर निर्वाणी अखाड़ा ने लीक की है जो विवादित ढांचे की जगह पर अधिकार का दावा कर रहा है। उनका कहना है कि तब कैसे कोई मध्यस्थता हो सकती है जबकि मामले में मुख्य हिंदू पक्षकार ने साफ घोषित किया था कि वह किसी मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं हैं और बाकी मुस्लिम पक्षकार भी इसके लिए तैयार नहीं थे।

श्रीराम पंचू ने मांगी थी फारुकी के लिए सुरक्षा : बयान के मुताबिक, मध्यस्थता समिति के सदस्य वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू ने सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश को एक ज्ञापन भेजकर जुफर फारुकी को सुरक्षा देने की अपील की थी और कोर्ट ने इस बावत उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया था। इसके बाद गत 16 अक्टूबर को जब मामले पर सुनवाई हो रही थी, उस दौरान भी मध्यस्थता समिति की ओर से एक ज्ञापन सौंपा गया जिसे उजागर नहीं किया गया। जिन लोगों ने मध्यस्थता कमेटी के समक्ष मध्यस्थता की कोशिश की है, वे मामले में प्रतिनिधि नहीं हैं। इस खबर का मीडिया में लीक होने का समय और 17 अक्टूबर को इसकी रिजवी द्वारा पुष्टि सोची समझी योजना हो सकती है। 16 अक्टूबर को पंचू सुप्रीम कोर्ट में देखे गए और वह जुफर फारुकी से संवाद करते भी दिखे। वकीलों ने कहा है, वे साफ करते हैं कि वे मीडिया में लीक इस समझौते के प्रस्ताव को कतई स्वीकार नहीं करते। न ही वह मध्यस्थता की प्रक्रिया और दावा वापस लेने का समझौता स्वीकार करते हैं।

आइपीएस अफसर अनूप एनएसजी के नए प्रमुख

नई दिल्ली, प्रेट्र : गुजरात कैडर के वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी अनूप कुमार सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, 1985 बैच के आइपीएस अधिकारी सिंह की 'ब्लैक कैट्स कमांडो' बल के डीजी के तौर पर नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 'यह नियुक्ति पद संभालने की तारीख से 30 सितंबर 2020 तक या अगले आदेश तक होगी।'

अनुप कुमार सिंह।

'पराली जलाने पर रोक की विस्तृत योजना पेश करे केंद्र'

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- पंजाब व हरियाणा से भी केंद्रीय योजनाओं के आधार पर बनाए एक्शन प्लान की मांगी जानकारी
- किसानों से जुर्माने की वसूली पर रोक कायम, लेकिन कानून की अनदेखी पर नाराजगी
- केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी बनाया प्रतिवादी

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से उन योजनाओं व प्रयासों की जानकारी मांगी है, जो किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए किए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सरकार विस्तार से बताए कि पंजाब व हरियाणा के किसानों को पराली जलाने से विमुख करने के लिए क्या-क्या किया गया है। चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस राजीव शर्मा की खंडपीठ ने पंजाब व हरियाणा से भी केंद्रीय योजनाओं के आधार पर बनाए गए एक्शन प्लान की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रतिवादियों में शामिल कर लिया है।

पराली जलाने के मामले में किसानों द्वारा कानून की अनदेखी पर टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि पंजाब का किसान अब बेचारा नहीं बल्कि लापरवाह हो गया है। चीफ जस्टिस ने महाराष्ट्र और असम के किसानों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी किसान धान की फसल लगाते हैं, पर पराली नहीं जलाते। अभी किसानों पर पराली जलाने के लिए लगाए जाने वाले जुर्माने की वसूली पर रोक को कायम रखते हुए हाई कोर्ट ने सुनवाई को 30 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। गौरतलब है कि कोर्ट ने किसानों की वित्तीय कठिनाइयों और किसानों द्वारा आत्महत्याओं के मद्देनजर पिछली सुनवाई पर पराली जलाने पर किसानों से जुर्माने की वसूली के आदेशों को निलंबित रखे जाने के आदेश दिए थे।

केंद्र ने जारी किए 1100 करोड़ : अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने अदालत को बताया कि किसानों द्वारा पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अब तक 1100 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। कोर्ट द्वारा इस पर विस्तृत जवाब मांगे जाने पर जैन ने अदालत से चार सप्ताह का समय मांगा।

याचिकाकर्ता के वकील चरणपाल सिंह ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए धन को सीधे किसानों के बैंक खातों में डाले जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र धनराशि को बढ़ाने के साथ ही इसे भी एलपीजी सब्सिडी की तरह सीधे किसानों के बैंक खातों में डालने की व्यवस्था करे। उन्होंने एक बार फिर कहा कि प्रदूषण से बचने के लिए निरंतर प्रदूषण करने वाले उद्योगों पर लगाम लगाई जानी चाहिए।

पंजाब के किसानों को गरीब नहीं मान सकते: प्रदूषण के मुद्दे पर किसानों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाने के संकेत देते हुए चीफ जस्टिस रवि शंकर झा ने कहा कि पंजाब देश के कुल कृषि क्षेत्र का सिर्फ 1.5 फीसद है, जबकि यह देश के 50 फीसद अनाज का उत्पादन करता है। ऐसे में पंजाब के किसान को गरीब कैसे माना जा सकता है, जबकि उसे मुफ्त बिजली और कर्ज माफी जैसी सुविधाएं भी मिल रही हैं।

किसानों पर सख्त टिप्पणी

पंजाब का किसान अब बेचारा नहीं बल्कि लापरवाह हो गया है। महाराष्ट्र व असम के किसान भी धान की फसल लगाते हैं पर पराली नहीं जलाते।

भय्याजी बोले

भुवनेश्वर में मीडिया से रूबरू आरएसएस के सर कार्यवाह ने कहा- पूरे देश में लागू होनी चाहिए एनआरसी, जम्मू-कश्मीर से 370 हटाकर सरकार ने किया अच्छा काम, अब कश्मीरी पंडितों को वापस लाने पर हो विचार

राम मंदिर पर निर्णय हिंदू समाज की भावनाओं के अनुरूप हो

संजय कुमार, भुवनेश्वर

राम मंदिर मामले पर आरएसएस के सर कार्यवाह भय्याजी जोशी ने कहा है कि दोनों पक्षों में समझौते की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। अब न्यायालय का निर्णय आना है। फैसला जो आएगा, उस समय देखेंगे। जहां तक फिर से समझौते की बात है तो इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हिंदू समाज की भावनाओं के अनुकूल निर्णय होना चाहिए। वह शुक्रवार को भुवनेश्वर में संघ की तीन दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक के अंतिम दिन पत्रकारों से मुखातिब थे। इस मौके पर आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार व सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर भी उपस्थित थे।

भय्याजी ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पूरे देश में लागू होनी चाहिए। यह देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा सवाल है। इसलिए अवैध तरीके से रह रहे देश के बाहर के लोगों को चिह्नित कर उन्हें बाहर करना सरकार का दायित्व है। भय्याजी ने अनुच्छेद 370 व कश्मीरी पंडितों के सवाल पर कहा कि सरकार ने 370 को हटाकर अच्छा काम किया है। अब वहां कश्मीरी पंडितों की वापसी होनी चाहिए। पूरे देश में समान अचार संहिता लागू करने के सवाल पर कहा कि सरकार को इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। देश के विकास के लिए यह जरूरी है। कानून अलग-अलग होने पर लोग गलत काम करके इसका सहारा लेकर बचने का प्रयास करते हैं। इसलिए सरकार को कामन सिविल कोड जल्द लागू करना चाहिए।

भुवनेश्वर में चल रही आरएसएस की तीन दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक के बारे में प्रेस वार्ता कर संवाददाताओं को जानकारी देते सर कार्यवाह भैय्याजी जोशी व साथ में अन्य। जागरण

आरएसस कार्यकारी मंडल की तीन दिवसीय बैठक संपन्न

भुवनेश्वर के सोया यूनिवर्सिटी कैंपस में चल रही संघ की तीन दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक संघ प्रमुख मोहन भागवत के संबोधन के साथ संपन्न हो गई।

बंगाल में हो रही हिंदुओं की हत्या पर सरकार उठाए कठोर कदम

भय्याजी जोशी ने कहा कि बंगाल में हिंदुओं की हत्याएं काफी दुखद है। जो बंगाल कभी शांतिप्रिय था, आज वहां हत्याओं का दौर चल पड़ा है। साम्यवादियों की सरकार के समय भी ऐसी ही स्थिति थी, इसलिए वर्तमान सरकार को वहां हो रही हत्याओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए।

23 अक्टूबर से 10वीं और 29 अक्टूबर से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी कश्मीर में। जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की चेयरपर्सन वीणा पंडिता ने यह जानकारी दी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 19 अक्टूबर 2019

रिहाई के लिए अदालत नहीं जाएंगे फारूक और उमर

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

दोनों चाहते हैं हिरासत में लिए गए सभी राजनीतिक बंदियों की बिना शर्त रिहाई

पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी हैं नजरबंद

डॉ. फारूक अब्दुल्ला

उमर अब्दुल्ला। फाइल फोटो

नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला व उनके पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपनी रिहाई के लिए अदालत में जाने को तैयार नहीं हैं। दोनों ने एहतियातन हिरासत में लिए गए सभी राजनीतिक बंदियों की बिना शर्त रिहाई की मांग की है।

पांच अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को पारित करने के मद्देनजर राज्य प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्त्ताओं को हिरासत में लिया था। इनमें राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के अलावा पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं। डॉ. फारूक को उनके घर में ही नजरबंद रखा गया है, जबकि उमर को हरि निवास और महबूबा को चश्मा शाही स्थित एक हट में रखा गया है। डॉ. फारूक पर राज्य प्रशासन ने गत 16 सितंबर को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) लगाया है।

हालात में बेहतरी के आधार पर राज्य प्रशासन ने गत माह ही राजनीतिक बंदियों की रिहाई का सिलसिला भी शुरू किया और करीब दो दर्जन लोगों को सशर्त रिहा किया गया। इनमें नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के कई पूर्व विधायक भी शामिल हैं। इस दौरान संबंधित प्रशासन ने फारूक, उमर और महबूबा से भी संपर्क किया। इन नेताओं से कथित तौर पर उनकी रिहाई व अन्य संबंधित मामलों पर चर्चा हुई, लेकिन बात आगे नहीं हुई।

इस बीच, नेकां ने संकेत दिया कि डॉ. फारूक और उमर को बंदी बनाए जाने के खिलाफ वह अदालत में जाएंगे। इसके लिए पार्टी के लीगल सेल ने भी तैयारी कर ली। लीगल सेल के वरिष्ठ नेता और दक्षिण कश्मीर से नेकां के टिकट पर सांसद बनने वाले जस्टिस (रिटायर्ड) हसनैन मसूदी ने इस मुद्दे पर गत दिनों फारूक और उमर से भी मुलाकात की, लेकिन दोनों नेताओं ने अदालत में जाने से इन्कार कर दिया।

हसैन मसूदी ने कहा कि मैंने फारूक और उमर दोनों से मुलाकात की। मैंने उन्हें उनकी रिहाई के लिए अदालत में याचिका दायर करने के बारे में बताया तो उन्होंने इससे इन्कार करते हुए कहा कि वह अदालत में नहीं जाएंगे। दोनों नेताओं ने तय किया है कि वह अकेले अपनी रिहाई के लिए तैयार नहीं हैं। वह सभी राजनीतिक बंदियों की बिना शर्त रिहाई चाहते हैं। दोनों नेताओं ने कहा है कि जब तक कश्मीर में सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर उन्हें उनकी राजनीतिक गतिविधियों को बिना रुकावट आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, वह अपनी हिरासत को अदालत में चुनौती नहीं देंगे।

मेरी बारी कब आएगी...

श्रीनगर में शुक्रवार को बीएसएनएल कार्यालय के बाहर अपने मोबाइल एक्टिवेट करवाने के लिए लगी लोगों की कतार। कश्मीर में मोबाइल की पोस्टपेड सेवा शुरू होने से लोगों को काफी राहत मिली है। जागरण

आतंकियों ने कश्मीर में जलाई सेब से भरी पेटियां

नापाक हरकत ▶ हथियारों से लैस आतंकवादियों ने ट्रक चालकों की पिटाई कर उन्हें कश्मीर छोड़ने का फरमान सुनाया

पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आतंकियों की शुरू की तलाश

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर में आतंकियों ने सेब कारोबारियों को निशाना बनाने की अपनी साजिश को जारी रखते हुए उत्तरी कश्मीर की सोपोर मंडी में सेब से भरी पेटियों में आग लगा दी। इसके बाद आतंकी भाग निकले। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है।

सूत्रों के अनुसार, गुरुवार रात करीब 11 बजे स्वचालित हथियारों से लैस आतंकियों का एक दल सोपोर फल मंडी में दाखिल हुआ। आतंकियों ने वहां स्थानीय किसानों द्वारा नैफेड को बेचने और देश के अन्य हिस्सों में भेजने के लिए रखी गई सेब की पेटियों को आग लगा दी। आतंकियों ने वहां मौजूद कुछ ट्रक चालकों को भी कथित तौर पर पीटा और उन्हें कश्मीर छोड़ने का फरमान सुनाया। हालांकि पुलिस ने इस तथ्य की पुष्टि नहीं की है। कुछ लोगों के मुताबिक, आतंकियों द्वारा जलाई गई सेब की पेटियां मंडी के बाहर एक जगह विशेष पर रखी गई थीं।

सोपोर फल मंडी में सेब की पेटियों को जलाए जाने की खबर मिलते ही पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक आतंकी वहां से भाग चुके थे और सेब की पेटियां जल चुकी थीं। पुलिस ने वहां मौजूद ट्रक चालकों को उसी समय निकटवर्ती सुरक्षित जगह पर पहुंचाया।

पांच दिनों में हुई तीन हत्याएं : यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि बीते पांच दिनों के दौरान आतंकी दक्षिण कश्मीर में एक ट्रक चालक और एक सेब व्यापारी समेत तीन की हत्या कर चुके हैं। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने सितंबर की शुरुआत में तीन सेब व्यापारियों के अलावा एक ढाई साल की बच्ची को भी गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था।

नौ सुरक्षित क्षेत्रों में की जाएगी सेब की खरीदारी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

प्रशासन ने उठाए उत्पादकों, व्यापारियों व ट्रक चालकों की सुरक्षा के लिए कदम

सभी सुरक्षित क्षेत्र मुख्य सड़क या फिर सुरक्षाबलों के शिविरों से हैं सटे

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में काजीगुंड के समीप हाइवे पर किनारे कतार में खड़े सेब से भरे ट्रकों के समीप सेब की टोकरी के साथ एक व्यक्ति। रायटर

कश्मीर घाटी में ट्रक चालकों और सेब व्यापारियों को निशाना बनाए जाने के बाद राज्य प्रशासन ने शोपियां सेब निर्यात और खरीद के लिए नौ स्थानों को सुरक्षित क्षेत्र चिह्नित किया है। यह सभी जोन जिला मुख्यालय को श्रीनगर और हाईवे से जोड़ने वाली मुख्य सड़क या फिर सुरक्षाबलों के शिविरों के पास हैं।

जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह सभी क्षेत्र जिले में मुख्य सड़कों या फिर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के शिविरों के पास हैं। इन इलाकों में 24 घंटे सुरक्षाबलों की गश्त को यकीनी बनाया गया है। ट्रक चालकों को इन जगहों पर अपने वाहन लगाने के लिए कहा गया है। सेब उत्पादकों और व्यापारियों से कहा गया है कि वह अपनी फसल को लेकर सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचे। वहीं, पर उसे खरीदने के लिए व्यापारी और कश्मीर से बाहर भेजने के लिए ट्रक उपलब्ध रहेंगे।

उन्होंने बताया कि मुगल रोड पर पीर की गली के पास पोशाना इलाके में भी 600 ट्रकों को सुरक्षा कारणों और सड़क पर यातायात सुचारु बनाने के लिए रोका गया है। कुछ सूचनाएं मिली थीं कि आतंकी इस सड़क से गुजरने वाले ट्रकों को निशाना बना सकते हैं। मुगल रोड और उससे सटे इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही ट्रकों को कश्मीर के लिए छोड़ा जा रहा है।

इस बीच, राज्य पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आइजी कश्मीर एसपी पाणि संग शोपियां का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने जिला पुलिस और शोपियां में तैनात सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सेब व्यापारियों और उत्पादकों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के साथ ही आतंकरोधी अभियानों का भी जायजा लिया।

उन्होंने फील्ड कमांडरों को फल उत्पादकों के साथ विचार विमर्श कर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए कहा। दिलबाग सिंह ने कहा कि घाटी से बाहर की मंडियों में भेजे जाने वाले सेब की लदाई के लिए सुरक्षित जगहों को चिह्नित किया जाए।

वायुसेना अफसरों की हत्या के मामले में जावेद गिरफ्तार, मिली जमानत

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

25 जनवरी 1990 को श्रीनगर में आतंकी हमले में चार वायुसेना अधिकारी हुए थे शहीद

जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के पूर्व कमांडर जावेद मीर को करीब 30 साल पूर्व श्रीनगर के रावलपोरा में वायुसेना के अधिकारियों पर हमले व हत्या की वारदात के सिलसिले में सीबीआइ ने गिरफ्तार किया है। अलबत्ता, मीर ने अदालत से जमानत ले ली है। अब वह संबंधित मामले की अगले सप्ताह होने वाली सुनवाई के समय अदालत में पेश होगा। जेकेएलएफ के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक भी इस मामले में आरोपित है और इस समय वह तिहाड़ जेल में टेरर फंडिंग के सिलसिले में बंद है।

गौरतलब है कि 25 जनवरी 1990 को रावलपोरा इलाके में जेकेएलएफ के आतंकियों ने वायुसेना के अधिकारियों पर हमला किया था। इसमें स्कवाड्रन लीडर रवि खन्ना समेत चार वायुसेनाकर्मी शहीद हुए थे। आरोप है कि इस हमले में यासीन मलिक और जावेद मीर भी शामिल थे। जावेद मीर को जावेद नलका भी कहते हैं, क्योंकि 1989 में जेकेएलएफ का कमांडर बनने से पहले वह राज्य पीएचई (जलापूर्ति) विभाग में कार्यरत था।

अदालत ने जारी किया था वारंट : सूत्रों ने बताया कि वायुसेना अधिकारियों पर हमले और हत्या के मामले की सुनवाई जम्मू स्थित टाडा अदालत में चल रही है। जावेद मीर को अदालत में पेश होना था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ। इस पर अदालत ने उसके खिलाफ एक वारंट जारी किया था। इसी वारंट के आधार पर दो दिन पूर्व सीबीआइ की एक टीम ने उसे श्रीनगर स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। मीर को उसी समय स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां उसने जांच में पूर्ण सहयोग का यकीन दिलाते हुए बताया कि वह पांच अगस्त से अपने घर में नजरबंद था। इसलिए जम्मू में पेशी के समय हाजिर नहीं हो पाया। उसने बताया कि फोन और इंटरनेट भी बंद था। जावेद ने अगली पेशी में अदालत में हाजिरी का यकीन दिलाया और उसे जमानत पर छोड़ दिया गया।

टाडा अदालत में चल रही सुनवाई : सीबीआइ ने इस मामले में मलिक और मीर समेत छह लोगों के खिलाफ टाडा अदालत में आरोपपत्र दायर किया है। मामले की सुनवाई पर जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एकल पीठ द्वारा 1995 में स्टे प्राप्त किया था। इसके बाद वर्ष 2008 में यासीन मलिक ने विशेष अदालत में याचिका दायर कर अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई को श्रीनगर में स्थानांतरित करने का आग्रह किया था। अदालत ने 20 अप्रैल 2009 को फैसला सुनाते हुए सुनवाई को श्रीनगर में स्थानांतरित किया था। इस पर सीबीआइ ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए मामले की सुनवाई को जम्मू स्थानांतरित कराने के लिए याचिका दायर की थी। जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने 13 मार्च 2019 को याचिका को स्वीकारते हुए वायुसेना के अधिकारियों की हत्या और पूर्व मुख्यमंत्री स्व. मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अपहरण संबंधी मामलों की सुनवाई को जम्मू विंग में स्थानांतरित करने का फैसला सुनाया था।

आतंकी स्लीपर सेल बेंगलुरु और मैसुरु में सक्रिय

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा कि बेंगलुरु और मैसुरु में आतंकवादियों के स्लीपर सेल सक्रिय हैं। बोम्मई ने कहा कि तटीय कर्नाटक और बंगाल की खाड़ी में इन आतंकियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। मैसुरु में बोम्मई ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को तटीय कर्नाटक और कर्नाटक के कुछ अंदरूनी इलाकों में आतंकी गतिविधियों का शक है।

उन्होंने कहा कि इन शहरों में जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) से संबंधित आतंकियों की गतिविधि का शक है। बेंगलुरु और मैसुरु में स्लीपर सेल होने का अंदेशा है। इसलिए एनआइए अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है।

उन्होंने चेताया कि जेएमबी ने तटीय कर्नाटक और राज्य के अंदरूनी हिस्सों में ही अपनी गतिविधियों का विस्तार नहीं किया है, बल्कि बंगाल की खाड़ी और अरब महासागर के तटीय क्षेत्रों में भी किया है। एनआइए की ओर से हाल में दिल्ली में दी गई जानकारी का हवाला देते हुए बोम्मई ने कहा कि जांच एजेंसी ने कश्मीर और बांग्लादेशी आतंकियों पर जोर दिया है।

मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की गतिविधियां बढ़ी हैं। इस स्थिति में पुलिस अलर्ट है। खासकर, बेंगलुरु और मैसुरु में सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की जांच की जा रही है और संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं और उनका विश्लेषण कर रहे हैं।

कर्नाटक के मंत्री बोले-तटीय कर्नाटक व बंगाल की खाड़ी में गतिविधियां बढ़ीं

बेंगलुरु में विशिष्ट एटीएस एक नवंबर से कामकाज शुरू करेगा

इस हफ्ते के शुरू में, मंत्री ने बेंगलुरू विशिष्ट आतंकवाद रोधी दस्ता (एटीएस) गठित करने का एलान किया था। यह दस्ता एनआइए के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगा। बेंगलुरु-विशिष्ट एटीएस एक नवंबर से कामकाज शुरू करेगा। कर्नाटक के पास अपना एटीएस पहले से है।

बीते एक साल में बेंगलुरु के आसपास के इलाकों से जेएमबी के कई संदिग्ध सदस्यों की गिरफ्तारी हुई और उनके पास से विस्फोटक उपकरण समेत अन्य सामान की बरामदगी हुई थी। इसके बाद एटीएस गठित करने पर निर्णय किया गया। ये आतंकवादी बंगाल के बर्धमान में दो अक्टूबर 2014 को हुए विस्फोट में शामिल रहे हैं। इस विस्फोट में दो व्यक्तियों की मौत हो गई थी। वे बेंगलुरु के आसपास छिपे हैं।

कश्मीर में जुमे की नमाज पर रहीं सख्त पाबंदियां

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

हिंसा की आशंका के चलते सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती

जामिया छोड़ सभी मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से हुई जुमे की नमाज

श्रीनगर में लाल चौक के पास शुक्रवार को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद सुरक्षाकर्मी। जागरण

कश्मीर में जुमे की नमाज पर आतंकियों और अलगाववादियों द्वारा गड़बड़ी किए जाने की आशंका के चलते राज्य प्रशासन ने शुक्रवार को सभी संवेदनशील इलाकों में पाबंदियां लगा दीं। इससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ और सभी प्रमुख बाजार बंद रहे। वाहनों की आवाजाही भी कम रही। हालांकि सरकारी कार्यालय और बैंक ही खुले रहे। इस बीच, ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में 11वें शुक्रवार को भी नमाज-ए-जुमा की अजान नहीं हुई।

अलगाववादी और जिहादी तत्वों ने शुक्रवार को विभिन्न इलाकों में राष्ट्र विरोधी प्रदर्शनों की योजना बनाई थी। खुफिया तंत्र ने अलगाववादियों की इस साजिश का अलर्ट सुरक्षा एजेंसियों के लिए पहले ही जारी कर दिया था। इसका संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने डाउन टाउन और श्रीनगर समेत वादी के सभी संवेदनशील इलाकों में पाबंदियां लगा दीं। इसके साथ ही शरारती तत्वों से निपटने के लिए विभिन्न इलाकों और चौराहों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को भी तैनात कर दिया।

पाबंदियों और अलगाववादियों द्वारा हिंसा भड़काए जाने की आशंका के चलते बाजार बंद रहे। लालचौक में पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा। सिर्फ गली-मोहल्लों में कुछ ही दुकानें खुली नजर आईं। सरकारी कार्यालयों में पाबंदियों का असर नजर आया। शिक्षण संस्थान भी बंद रहे। हालांकि सिविल लाइंस इलाकों में किसी भी तरह की पाबंदियां नहीं थीं। इसके बावजूद राजबाग, जवाहर नगर, छन्नपोरा, सराईबाला, गोगजीबाग, राममुंशी बाग, इंदिरा नगर में लोगों की आवाजाही बहुत कम रही।

जुलूस निकालने का प्रयास विफल किया : दोपहर को घाटी में सभी मस्जिदों और दरगाहों में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हुई। सिर्फ छन्नपोरा, आंचर और सौरा में कुछ लोगों ने जुलूस निकालने का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें खदेड़ कर सामान्य स्थिति को बहाल कर दिया। वहीं, सुरक्षाबलों ने भी किसी बाहरी व्यक्ति को नौहट्टा में दाखिल नहीं होने दिया। स्थानीय लोग भी हिंसा की आशंका के चलते जामिया मस्जिद में नहीं आए। इसलिए नमाज नहीं हुई।

वतन की हिफाजत के लिए कश्मीरी युवाओं में जुनून

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जिला बारामुला में भी भर्ती रैली में उमड़ रही युवाओं की भीड़

दो हजार युवक भर्ती होने आए, शैक्षिक दस्तावेज व शारीरिक दमखम परखा गया

कश्मीर का युवा देश के लिए कुछ करने के लिए निकल पड़ा है। भारतीय सेना का हिस्सा बन वतन की हिफाजत के लिए उनके सिर पर जुनून सवार है। पहले कुपवाड़ा फिर बांडीपोरा और अब बारामुला में सैन्य भर्ती रैली में युवाओं का बड़ी संख्या में शामिल होना नए कश्मीर में बदलाव के संकेत हैं।

बीते एक पखवाड़े के दौरान सेना की भर्ती रैली में युवाओं का जोश देखते ही बन रहा है। यही कारण है कि रक्षा मंत्रालय ने उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सटे जिला बारामुला में भी स्थानीय युवकों के लिए भर्ती रैली आयोजित की, जिसमें उम्मीद से अधिक युवा भर्ती होने के लिए पहुंचे। बारामुला के गंठमुला में सेना की चिनार कोर के बैनर तले जैकलाई की 161 इनफैंटरी टीए बटालियन ने भर्ती रैली आयोजित की है।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि हमें उम्मीद नहीं थी कि यहां भी सैकड़ों लड़कों की भीड़ देखने को मिलेगी। दो हजार युवक भर्ती होने के लिए आए हैं। इन युवकों के शैक्षिक दस्तावेज की जांच के बाद उनके शारीरिक दमखम को परखा गया है। इसमें सफल युवकों को मेडिकल जांच से गुजरना होगा। उसके बाद लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसमें सफल रहने वालों को मेरिट के आधार पर भर्ती किया जाएगा।

भर्ती होने आए युवकों में शामिल गुलशन ने आइटीआइ में डिप्लोमा प्राप्त किया है। उसने कहा कि भर्ती रैली में जनरल ड्यूटी सिपाही के अलावा ट्रेड्समैन और क्लर्क की भर्ती भी होगी। मुझे ट्रेड्समैन में नौकरी मिल जाएगी। उसने कहा कि मैंने दो साल पहले जनरल ड्यूटी सिपाही बनने के लिए प्रयास किया था। उस समय मैं कामयाब नहीं हो पाया था, फिर मुझे पता चला कि ट्रेड्समैन भी भर्ती किए जाते हैं। इसके बाद मैंने डिप्लोमा किया। इस बार मुझे मौका मिल जाएगा क्योंकि मेरे वर्ग में बहुत कम लड़के हैं। अशरफ नामक एक युवक ने कहा कि उसका बड़ा भाई भी फौज में है। मैं अपने भाई को देखकर ही फौजी बनने के लिए प्रेरित हुआ हूं।

प्रचार का नया रूप

हाउसफुल-4 के ट्रेन से प्रमोशन के अनुभव से बॉलीवुड के निर्माता खुश, आठ आगामी फिल्मों के निर्माताओं ने बुकिंग के आवेदन दिए

ट्रेनों की बुकिंग के लिए आगे आए कई निर्माता

संजय सिंह, नई दिल्ली

'प्रमोशन ऑन ह्वील्स' ट्रेन के जरिये अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल-4 के प्रचार से प्रेरित होकर बॉलीवुड के कई फिल्म निर्माताओं ने अपनी आगामी फिल्मों के प्रचार के लिए इस ट्रेन की बुकिंग के आवेदन देने शुरू कर दिए हैं। इनमें सलमान खान की 'दबंग-3' तथा दीपिका पादुकोण की 'छपाक' जैसी फिल्में शामिल हैं।

मुश्किल दौर में बॉलीवुड और रेलवे को एक-दूसरे का सहारा मिला है। फिल्म की मार्केटिंग के बढ़ते खर्च से परेशान फिल्म वालों ने ट्रेन का दामन थामा है। उन्हें रेलवे की नई प्रमोशन 'ऑन ह्वील्स' ट्रेन इतनी भाई है अपनी आगामी फिल्मों के प्रचार के लिए उन्होंने टीवी की जगह इस ट्रेन को तरजीह देना शुरू कर दिया है।

वहीं यात्री ट्रेनों को घाटे से उबारने के लिए रोजाना नए प्रयोग किए जा रहे हैं। सेमी हाईस्पीड 'वंदे भारत' के बाद निजी क्षेत्र के सहयोग से लखनऊ और दिल्ली के बीच चलाई गई कारपोरेट ट्रेन 'तेजस' इसका उदाहरण है। इन ट्रेनों ने यात्री ट्रेनों के घाटे को मुनाफे में बदलना शुरू कर दिया है। इस कामयाबी से उत्साहित रेलवे ने सांस्कृतिक, कलात्मक व खेलकूद गतिविधियों के प्रचार-प्रसार की इच्छुक पार्टियों के लिए 'प्रमोशन ऑन ह्वील्स' नाम से ट्रेनों की नई सीरीज शुरू करने का निर्णय लिया है। और ट्रेन को बॉलीवुड निर्माताओं की ओर से अत्यंत उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, पहली 'प्रमोशन ऑन ह्वील' ट्रेन से रेलवे को 53 लाख रुपये की कमाई के साथ 20 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ है। इस रकम में हॉलेज शुल्क के 38 लाख रुपये तथा विनायल फिल्म की रैपिंग का 18 लाख रुपये का खर्च शामिल हैं। मात्र आठ डिब्बों की जरूरत होने से इस ट्रेन पर 22-24 कोच वाली सामान्य मेल-एक्सप्रेस ट्रेन के मुकाबले ईंधन व रखरखाव पर अपेक्षाकृत कम खर्च किया गया। जहां सामान्य मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में रेलवे को 100 रुपये के किराये पर 43 रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है, वहीं यह ट्रेन हर तरह से मुनाफे का सौदा है।

हाउसफुल-4 के बाद आठ और निर्माता अपनी आने वाली फिल्मों के लिए इसकी बुकिंग का आवेदन दे चुके हैं। इनमें सलमान खान की फिल्म दबंग-3, अक्षय कुमार की पैडमैन-2, मेघना गुलजार द्वारा निर्मित व निर्देशित दीपिका पादुकोण की फिल्म 'छपाक', अनुराग कश्यप द्वारा निर्मित व तुषार हीरानंदानी निर्देशित तापसी पन्नू की फिल्म 'सांड की आंख' तथा टी सीरीज की मिलाप झावेरी निर्देशित एवं रीतेश देशमुख व सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनीत फिल्म 'मरजावां' शामिल हैं।

फिल्म वालों का कहना है कि इस ट्रेन से फिल्मों के प्रमोशन और पब्लिसिटी का खर्चा कम होगा।

रूट के स्टेशन अहम

'प्रमोशन ऑन ह्वील्स' की योजना इस प्रकार तैयार की गई है ताकि प्रस्थान एवं गंतव्य स्टेशन के बीच ज्यादा से ज्यादा शहरों और कस्बों के लोगों तक फिल्म के बारे में जागरूकता और उत्सुकता पैदा की जा सके। ट्रेन की विनायल रैपिंग में रंग संयोजन और चित्रांकन में भी इन शहरों के लोगों की रुचि का ध्यान रखा गया। इन ट्रेनों से स्टेशनों पर अव्यवस्था न पैदा हो इसके लिए एहतियाती इंतजाम किए जाएंगे। किसी जगह ज्यादा देर रुकने पर हाल्टिंग शुल्क लिया जाएगा।

टेरर फंडिंग के मुख्य आरोपित मुमताज ने किया सरेंडर

जागरण संवाददाता, लखीमपुर

पुलिस-एटीएस को चकमा देकर पहुंचा सीजेएम कोर्ट, भेजा गया जेल

भांजे के साथ मिलकर नेपाल के खातेदार मुहैया कराता था मुमताज

टेरर फंडिंग के मुख्य आरोपित मुमताज अली ने शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सीजेएम विकास श्रीवास्तव के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। मुमताज ने सरेंडर करने के लिए सीजेएम की अदालत में गुरुवार को अर्जी लगाई थी। तभी से उसके सरेंडर की संभावना थी। मुमताज दोपहर में लंच के बाद सीजेएम कोर्ट में हाजिर हुआ। वह अपने भांजे उम्मेद के साथ विदेश से आने वाले पैसों के लिए नेपाली बैंक के खातेदार मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाता था। एटीएस ने उसके टेरर फंडिंग मामले में वांछित होने की रिपोर्ट कोर्ट में भेज दी थी।

मुमताज पर भारत-नेपाल सीमा से आतंकियों तक कई करोड़ भारतीय मुद्रा पहुंचाने का आरोप है। मुमताज नेपाल की करंसी भारत लाता था। इस काम का वह छह फीसद कमीशन पाता था। भारत में करंसी एक्सचेंज करने के बाद देश की राजधानी से जुड़े आतंकवादियों को फंडिंग की जाती थी। मुमताज की जुबान खुलने से नेपाल के खातेदारों और विदेश से पैसे भेजने वालों के नाम उजागर हो सकेंगे।

यह है मामला

लखीमपुर पुलिस ने एक सप्ताह पहले चार को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से करीब पांच लाख रुपये व सवा लाख नेपाली नोट बरामद हुए थे। आरोप है कि यह लोग नेपाल के बैंक खातों से रकम निकलवा कर भारत लाते थे। उसे भारतीय मुद्रा में बदल कर संदिग्ध आतंकियों तक दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में पहुंचाते थे।

74 दिन बाद भाई से मिलीं महबूबा मुफ्ती

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती लगभग 74 दिनों बाद शुक्रवार को अपने भाई तस्सदुक मुफ्ती से मिली हैं। दोनों के बीच करीब 20 मिनट की मुलाकात हुई। चार अगस्त की मध्यरात्रि को ही राज्य प्रशासन ने महबूबा को एहतियातन हिरासत में ले लिया था। उन्हें चश्मा शाही स्थित एक सरकारी अतिथिगृह में हिरासत में रखा गया है। इस अतिथि गृह को उप जेल का दर्जा दिया गया है।

पांच अगस्त के बाद महबूबा की अपने भाई तस्सदुक के साथ यह पहली मुलाकात है। महबूबा ने तस्सदुक को राज्य विधान परिषद में एमएलसी नियुक्त करने के बाद पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार में पर्यटन मंत्री भी बनाया था। पीडीपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बैठक चली है। पेशे से सिनेमाटोग्राफर तस्सदुक गत वर्ष पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के भंग होने के बाद से ज्यादातर दिल्ली और मुंबई में ही रहते थे। वह कभी-कभार ही श्रीनगर आ रहे थे। अंतिम बार वह जुलाई माह के दूसरे पखवाड़े के दौरान एक समारोह में श्रीनगर में देखे गए थे।

30 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने रुद्रनाथ पहुंचकर इस बार किए बाबा के दर्शन। रुद्रनाथ धाम पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 19 किमी का सफर दुर्गम रास्ते से पैदल तय करना पड़ता है। यहां भगवान शिव के मुख दर्शन होते हैं।

अमिताभ बच्चन को मिली अस्पताल से छुट्टी

दीपेश पांडे, मुंबई

▸ लिवर की समस्या के चलते चार दिन रहे भर्ती

अमिताभ बच्चन। फाइल फोटो

खराब तबियत के चलते पिछले चार दिनों से मुंबई स्थित नानावटी अस्पताल में भर्ती महानायक अमिताभ बच्चन को शुक्रवार रात अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लिवर की समस्या से पीड़ित बिग बी को मंगलवार शाम करीब चार बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को अमिताभ के साथ उनकी पत्नी जया बच्चन, बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय बच्चन भी थीं।

अस्पताल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक खराब तबियत की वजह से बिग बी को गाड़ी से चिकित्सा कक्ष तक व्हीलचेयर पर ले जाया गया था। जया बच्चन बिग बी के साथ अस्पताल में ठहरीं। जबकि अभिषेक और ऐश्वर्या घर चले गए थे। बिग बी की देखभाल के लिए अभिषेक और जया बच्चन बारी-बारी से अस्पताल में रुकते रहे। शुक्रवार शाम भी करीब चार बजे अभिषेक अस्पताल पहुंचे तभी जया बच्चन घर को रवाना हुईं।

वर्ष 1982 में फिल्म 'कुली' की शूटिंग के दौरान लगी चोट के बाद से अमिताभ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। साल 2015 में एक समारोह के दौरान हेपेटाइटिस बी से ग्रसित होने का रहस्योद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा था कि कुली की शूटिंग के दौरान घायल होने के बाद किसी रक्तदाता में हेपेटाइटिस-बी का वायरस था जो उनके शरीर में चला गया था। उस दुर्घटना के 18 साल बाद वर्ष 2000 तक उनका स्वास्थ्य सामान्य रहा। उसके बाद नियमित जांच के दौरान उन्हें लिवर संक्रमित होने की जानकारी मिली। उनका 75 प्रतिशत लिवर खराब हो चुका है। उन्होंने कहा था कि मैं इस वायरस को अपने साथ 18 वर्षों तक ढोता रहा जो मेरे लिवर को धीरे-धीरे खराब कर रहा था। मैंने अपना इलाज शुरू किया और आज भी इसकी दवाइयां खाता हूं। फिलहाल मेरा सिर्फ 25 प्रतिशत लिवर बचा है। अच्छी बात यह है कि सिर्फ 12 प्रतिशत लीवर के साथ कोई भी इंसान जिंदा रह सकता है।'

अमिताभ इन दिनों गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति-सीजन 11' की मेजबानी कर रहे हैं। उसके कुछ एपिसोड शूट बैंक में पहले से हैं। सूत्रों के अनुसार वह मंगलवार से फिर इसकी शूटिंग शुरू कर सकते हैं। वहीं, वह फिल्म झुंड, गुलाबो-सिताबो, चेहरा और ब्रह्मास्त्र भी कर रहे हैं।

उड़ान भरते ही विमान से टकराया पक्षी

जासं, वाराणसी : वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा टल गया। वाराणसी से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के बाद विमान से पक्षी टकरा गया। हालांकि पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से संपर्क कर विमान को एयरपोर्ट पर वापस उतार दिया। इससे विमान में सवार 175 यात्रियों की जान बच गई। विमान को सुरक्षा की दृष्टि से ग्राउंड कर दिया गया। इसके बाद बैंकॉक उड़ान रद कर उस विमान से यात्रियों को दिल्ली भेजा गया। इंडिगो एयरलाइंस का विमान 6ई853 सुबह 10.35 बजे 175 यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए उड़ान भरा। उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद विमान से एक चील टकरा गया। इसकी जानकारी होते ही पायलट ने तुरंत एटीसी से संपर्क कर अपनी सूझबूझ से विमान को नियंत्रित किया और उड़ान भरने के 15 मिनट बाद 10.50 बजे विमान को एयरपोर्ट पर वापस उतारा गया। विमानन क्षेत्र में विमान में बर्ड हिट होना बड़ी घटना मानी जाती है। वहीं बैंकॉक जाने वाले विमान को दिल्ली भेजे जाने से बैंकॉक जाने वाले यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी।

अतिथियों को दूरदर्शन ने दी नसीहत बेवजह न लें नेताओं का नाम

राज्य ब्यूरो, पटना

नई कोशिश

▸ दूरदर्शन के पटना केंद्र की निजी चैनलों की तुलना में बहस को गरिमापूर्ण बनाने की कोशिश

▸ बेवजह पाकिस्तान का भी नाम न लें, महत्वपूर्ण नेताओं के नाम का जिक्र पदनाम के साथ करें

निजी टीवी चैनलों पर बहस के नाम पर होने वाली चीख पुकार से सबक लेते हुए दूरदर्शन के पटना केंद्र ने बहस के कार्यक्रमों में शामिल होने वाले अतिथियों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। हालांकि, इसमें निर्देश के बदले आग्रह का भाव है। इरादा यह है कि टीवी सेट के सामने बैठे दर्शक साफ-साफ सुन सकें कि आखिर वक्ता कह क्या रहे हैं। आम तौर पर निजी चैनल के दर्शकों की शिकायत रहती है कि वे बहस के संदर्भ को समझ नहीं पाते हैं। कभी-कभी तो बहस में शामिल सम्मानित अतिथि गाली-गलौज के बाद मारपीट करने लगते हैं। निर्देश में अतिथियों को कहा गया है कि वह अपनी बात सरल भाषा में दो-ढाई मिनट के भीतर कह दें क्योंकि दूरदर्शन के कार्यक्रमों का समय सीमित रहता है। दूरदर्शन ने बहस में पाकिस्तान का नाम लेने से बचने का भी आग्रह किया है। कहा कि उन पड़ोसी देशों का बेवजह नाम लेने से बचें, जिनसे किसी मुद्दे पर विवाद चल रहा है। उदाहरण के लिए अगर आप बहस के दौरान पाकिस्तान का नाम लेना चाहते हैं तो कहें...हमारा पड़ोसी।

यह भी नसीहत दी है कि विवादास्पद और मतभिन्नता वाले मुद्दे को बहस में न उठाएं। अगर बहुत जरूरी नहीं हो तो नेताओं का नाम न लें। अगर नाम लेना जरूरी ही है तो नाम के साथ पदनाम का जिक्र भी करें। मसलन अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं तो उनके पदनाम का भी जिक्र करें। संभव हो तो कहें...हमारे प्रधानमंत्री...। पत्र में कहा गया है कि दूरदर्शन कोई व्यावसायिक मंच नहीं है। कोशिश रहती है कि इसके कार्यक्रम गरिमा के अनुकूल और स्वस्थ विचारों से भरे हों।

तकनीकी कारणों से हरे और पीले रंग के कपड़े न पहनें : दूरदर्शन ने अतिथियों को हरे और पीले रंग के कपड़े पहन कर आने से भी मना किया है। इसकी तकनीकी वजह बताई गई है। पत्र में कहा गया है कि दूरदर्शन क्रोमा तकनीक का इस्तेमाल करता है। पीले और हरे रंग का इस तकनीक पर अच्छा असर नहीं पड़ता है।

न्यूज गैलरी

आसनसोल की अवैध कोयला खदान से निकाले गए तीनों शव

आसनसोल : बंगाल के आसनसोल में अवैध कोयला खदान में पिछले चार दिनों से फंसे तीन युवकों के शव को गुरुवार की देर रात तक निकाल लिया गया। शुक्रवार को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के पश्चात शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। बता दें कि गत रविवार (13 अक्टूबर) की देर शाम तीनों युवक खदान में उतरे थे। मारे गए तीनों युवकों की पहचान अकबन बागान मांझी पाड़ा निवासी संतोष मरांडी (23), कालीचरण किस्कू (26) और विनय मुर्मू (32) के रूप में की गई। पोस्टमार्टम के पश्चात संतोष का शव उसके भाई दुर्गा मरांडी, कालीचरण का शव उसके भाई देवचंद किस्कू और विनय मुर्मू का शव उसके रिश्ते के भाई अजीत मांझी को सौंप दिया गया। शुक्रवार की शाम तक तीनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं शुक्रवार की सुबह विधायक उज्जवल चटर्जी व पार्षद नेपाल चक्रवर्ती मांझीपाड़ा पहुंचे और मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया। (जासं)

मंडुवाडीह सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 10 घंटे पड़ा रहा शव

गाजियाबाद : मंडुवाडीह–नई दिल्ली सुपरफास्ट के जनरल कोच के शौचालय के पास युवक का शव दस घंटे तक पड़ा रहा। यात्री शव लांघकर शौचालय जाते रहे, लेकिन किसी ने इसकी जानकारी रेलवे प्रशासन या आरपीएफ को नहीं दी। ट्रेन गाजियाबाद स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो एक यात्री ने आरपीएफ को जानकारी दी। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। ट्रेन मंडुवाडीह से नई दिल्ली जा रही थी। जीआरपी थाना प्रभारी अशोक सिसौदिया ने बताया कि गुरुवार को दोपहर में किसी यात्री ने आरपीएफ को जनरल कोच में शव पड़ा होने की जानकारी दी। आरपीएफ ने स्टेशन मास्टर को सूचित किया। आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे डॉक्टर मौके पर पहुंचे। डॉक्टर ने जांच की तो युवक की मौत हो चुकी थी। (जासं)

दिग्विजय की पत्नी का नाम कुलपति के लिए उछला

रायपुर : छत्तीसगढ़ के सियासी हलके में कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम को लेकर शुक्रवार को हलचल तेज हो गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता सिंह का नाम सामने आने के बाद तरह-तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। राज्यपाल की कुलपतियों के साथ बैठक में यह मुद्दा आया। इन चर्चाओं के बीच देर शाम अमृता ने फेसबुक पर इसे चंडूखाने की गप्प करार दिया। अमृता ने कहा है एक खबर बहुत जोरों से चलायी गई है कि मैंने एक आवेदन दिया है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से कहा है कि मुझे एक विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर बना दें। पिछले साल मैंने सुना था कि मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही हूं। बाद में कभी लोकसभा चुनाव, तो कभी मेयर की लाइन में भी मुझे खड़ा कर दिया गया। यहां सब कुछ होता रहता है, बस मुझे ही खबर नहीं होती कि मैं क्या करने जा रही हूं। (नईदुनिया)

मेक्सिको से वापस भेजे गए 311 भारतीय स्वदेश पहुंचे

मिली रिहाई ▸ मेक्सिको के 74 अधिकारियों का दल आया था छोड़ने

36 घंटे की करनी पड़ी यात्रा, पंजाब व हरियाणा के रहने वाले हैं ज्यादातर लोग

नई दिल्ली में शुक्रवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बाहर निकलते मैक्सिको से वापस भेजे गए लोग अपना पासपोर्ट दिखाते हुए। यह लोग मेक्सिको में नियमित रूप से ठहरने की शर्त पूरी नहीं कर रहे थे। प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : मेक्सिको के जरिये अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने की कोशिश में पकड़े गए 300 से ज्यादा भारतीय शुक्रवार को स्वदेश लौट आए। इनमें एक महिला भी है। ज्यादातर लोग पंजाब व हरियाणा के रहने वाले हैं।

एक अधिकारी ने यहां बताया, '311 भारतीयों को वापस भेजा गया है। मेक्सिको के 74 अधिकारी उन्हें यहां लेकर आए हैं।' भारतीयों को स्वदेश लौटने के लिए 36 घंटे की यात्रा करनी पड़ी। मेक्सिको से भारत तक की उड़ान ही 11 घंटे की थी। सभी को पहले मेक्सिको से स्पेन लाया गया और फिर वहां से दिल्ली लाया गया।

वापस लाए गए लोगों में से एक जसप्रीत सिंह ने कहा, 'हम लोग यहां सुबह करीब पांच बजे पहुंचे। औपचारिकताएं पूरी करने में घंटों लग गए। हम दोपहर करीब एक बजे हवाईअड्डे से बाहर निकले।'

मेक्सिको के नेशनल माइग्रेशन इंस्टीट्यूट (आइएनएम) ने बुधवार को एक बयान में कहा था कि भारतीय नागरिक देश में नियमित रूप से ठहरने की शर्त पूरी नहीं कर रहे थे। उन्हें टोलुका शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से बोइंग 747 विमान में बैठाकर नई दिल्ली रवाना कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जून में मेक्सिको की तरफ से घुसपैठ न रोके जाने पर सभी आयातों पर टेरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। इसके बाद मेक्सिको ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने का भरोसा दिया था।

'अमेरिकी ड्रीम' के चक्कर में बेशुमार कष्ट झेला, लाखों रुपये खर्चे : पटियाला निवासी 19 वर्षीय मनदीप ने जून में अमेरिका में काम करने के सपने के साथ घर छोड़ दिया था। हाई स्कूल तक पढ़े मनदीप ने बताया कि एक्वाडोर से लेकर मेक्सिको तक उन्हें सात देशों से गुजरना पड़ा। उन्होंने कहा, 'सात दिनों तक पनामा के जंगल से गुजरने के बाद हम मेक्सिको पहुंचे। हम अमेरिका से 800 किलोमीटर दूर थे कि मेक्सिको के अधिकारियों ने पकड़ लिया और वापस भेज दिया। हमने पनामा के जंगल में कई लाशें देखीं। माना जाता है कि वे भी मेरी तरह अमेरिका जाना चाहते थे।' साहिल मलिक (22) ने बताया कि वह पांच जून को दिल्ली से एक्वाडोर के लिए रवाना हुआ था। विभिन्न यातायात माध्यमों के जरिये वह मेक्सिको पहुंचा। उसने कहा कि अकसर उसे झाड़ियों के जरिये ही देशों की सीमाओं को पार करना पड़ता था। वापस भेजी गई एक मात्र महिला कमलजीत कौर (34) ने बताया कि उसने पति व एक बच्चे के साथ अमेरिका जाने के लिए 53 लाख रुपये खर्च किए थे।

सीडी कांड

अब छत्तीसगढ़ से बाहर सुनवाई की कवायद

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सीडी कांड का जिन्न एक बार फिर बाहर निकला है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सीबीआइ पर बैन कर दिया गया था। अब सीबीआइ ने मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ से बाहर किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच में यह अर्जी दी गई है। मामले की 21 अक्टूबर को पहली सुनवाई होनी है।

सीआरपीसी की धारा 406 के तहत सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है। इस पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई का अधिकार है। इसमें सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के अधीन किसी दूसरे कोर्ट के समान कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर सकता है।

भाजपा शासनकाल में गरमाया था सीडी कांड : 27 अक्टूबर 2017 को कथित अश्लील सीडी का मामला सामने आया था, जिसके बाद राजनीति गरमा गई थी। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के एक कद्दावर मंत्री की कथित अश्लील सीडी सामने आई थी। तब भाजपा सरकार ने सीबीआइ जांच का एलान किया था। इसके बाद सीबीआइ ने जांच शुरू की थी। सीडी कांड में वर्तमान मुख्यमंत्री और तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी हुई थी। सीडी कांड में जब विवाद बढ़ा तो बघेल ने जमानत न लेकर जेल जाने का फैसला किया था। जांच के दौरान सीडी कांड के एक आरोपित रिंकू खनूजा की आत्महत्या के बाद सीबीआइ ने जांच की रफ्तार सुस्त कर दी थी। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद सीडी कांड को लेकर एसआइटी का गठन किया गया था। इसमें भाजपा नेता कैलाश मुरारका सहित पांच लोगों को आरोपित बनाया गया था।

हजारों करोड़ के रोजवैली घोटाले में ईडी ने केकेआर के सीईओ से की पूछताछ

जागरण संवाददाता, कोलकाता

▸ शाहरुख खान की स्वामित्व वाली टीम है केकेआर

हजारों करोड़ रुपये के बहुचर्चित रोजवैली चिटफंड घोटाले की जांच में जुटे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की स्वामित्व वाली आइपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के सीईओ वेंकी मैसूर से घंटों पूछताछ की। नोटिस मिलने के बाद शुक्रवार को वह सॉल्टलेक के सीजीओ कॉम्पलेक्स स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे थे। वहां उनसे ईडी अधिकारियों ने रेजवैली से केकेआर के टाइअप और लेनदेन संबंधी पूछताछ की गई। लंबी पूछताछ के बाद वह सीजीओ कॉम्पलेक्स से बाहर निकले और चले गए। इस बाबत ईडी ओर वेंकी ने कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया। वेंकी मैसूर का बयान मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी ने दर्ज किया है।

गौरतलब हो कि वेंकी मैसूर शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज के भी सीईओ हैं और वह आइपीएल के साथ-साथ उनकी कैरेबियन प्रीमियर लीग की टीम ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स को भी संभालते हैं। वह 2010 में कोलकाता नाइट राइडर्स के सीईओ बने थे। गौरतलब है कि बंगाल के सबसे बड़े चिटफंड घोटाले में शुमार रोजवैली कंपनी साल 2012 और 2013 के आइपीएल टूर्नामेंट में स्पांसर थी। इस दौरान रोजवैली से हुए समझौते और आर्थिक लेनदेन को लेकर सीईओ से ईडी अधिकारियों ने पूछताछ की।

क्या है रोलवैली घोटाला : ज्यादा रिटर्न देने का झांसा देकर रोज वैली ग्रुप ने निवेशकों को हजारों करोड़ों रुपये की चपत लगाई है। इसका पर्दाफाश होने के बाद बंगाल में हड़कंप मच गया था। ईडी की मानें तो रोजवैली , सारधा चिटफंड घोटाले से भी कई गुना बड़ा है। इस चिटफंड घोटाले में लोगों से 17 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जमा की गई थी। इसका पर्दाफाश होने के बाद बांग्ला फिल्म अभिनेत्री ऋतुपर्णा घोष से भी पूछताछ हो चुकी है।

घोटाले में सामने आए कई बड़े नाम

ईडी ने जांच शुरू की, तो पता चला कि चिटफंड घोटाले में जमा रकम का बड़ा हिस्सा कई नेताओं तक पहुंचा था। चिटफंड घोटाले से बंगाल ही नहीं असम, झारखंड, ओडिशा और बिहार के निवेशक भी प्रभावित हुए थे। साल 2015 में रोजवैली ग्रुप के मालिक गौतम कुंडू की गिरफ्तारी हुई थी। इसकी जांच सीबीआइ और ईडी कर रही है। इस दौरान ईडी ने ढाई हजार से ज्यादा अकाउंट फ्रीज किए हैं। इसमें रोजवैली ग्रुप के 800 से 1000 करोड़ रुपये जमा थे। इसमें तृणमूल के कई बड़े नेताओं के नाम भी सामने आए। इसमें तृणमूल सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय, पूर्व सांसद तापस पाल की गिरफ्तारी भी हुई थी। वे दोनों जमानत पर रिहा हैं। इसी मामले में बांग्ला फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत मोहता को इसी साल जनवरी में सीबीआइ ने गिरफ्तार किया है।

बंगाल के तिहरे हत्याकांड पीड़ितों ने फिर कहा– संघ व भाजपा से कोई संबंध नहीं

जागरण संवाददाता, कोलकाता

▸ न्याय की आस लिए ममता बनर्जी से मिलने को सचिवालय पहुंचे परिजन

▸ दशहरा के दिन शिक्षक, उनकी पत्नी व बेटे की कर दी गई थी हत्या

बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के जियागंज में बीते दिनों शिक्षक बंधु प्रकाश पाल और उनकी पत्नी ब्यूटी पाल व आठ वर्षीय बेटे की हत्या के मामले में पीड़ितों ने एक बार फिर कहा है कि उनका आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) व भाजपा से कोई संबंध नहीं है। न्याय की आस लिए शुक्रवार को राज्य सचिवालय नवान्न में सीएम ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे परिजनों ने फिर कहा कि बंधु प्रकाश का संघ या भाजपा से कोई संबंध नहीं था।

जानकारी के अनुसार शुक्रवार को गवाही के लिए शिक्षक दंपती के ससुराल और मायके पक्ष के छह लोगों को सीआइडी मुख्यालय भवानी भवन बुलाया गया था। वहां सीआइडी अधिकारियों के सवालों का जवाब देने के बाद सभी ने सचिवालय जाकर मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जताई। हत्याकांड के बाद उत्पन्न हालात को देखते हुए पुलिस पहरे में उन्हें सचिवालय पहुंचाया गया। लेकिन, पहले से अनुमति नहीं लेने के कारण वह सीधे मुख्यमंत्री ने नहीं मिल सके। उन्हें इंतजार करने को कहा गया था।

गौरतलब हो कि जियागंज में दशहरा के दिन घर में ही बंधु प्रकाश पाल, उनकी गर्भवती पत्नी ब्यूटी और बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसका पर्दाफाश होने के बाद संघ का सक्रिय कार्यकर्ता होने का दावा किया गया था। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी हंगामा मचा था। तिहरे हत्याकांड के चार दिन बाद पुलिस ने गुत्थी सुलझाने का दावा करते हुए उत्पल बेहरा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसने महज 48 हजार रुपये के लिए शिक्षक द्वारा उसका अपमान करने को लेकर हत्या करने की बात कुबूल की थी। पुलिस के इस दावे को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं।

राज्यपाल धनखड़ बोले–मैं बंगाल में पर्यटक नहीं

जागरण संवाददाता, कोलकाता

जगदीप धनखड़। फाइल फोटो

दुर्गा पूजा कार्निवल में बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर अपमान करने का आरोप लगाने के बाद शुक्रवार को एक बार फिर राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रियों द्वारा उनको लेकर दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं राज्य में संवैधानिक प्रधान हूं। यहां जनता की सेवा के लिए आया हूं। कोई पर्यटक नहीं हूं। पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के बयान की पृष्ठभूमि में राज्यपाल ने कहा कि तृणमूल के नेता, मंत्री बगैर विचारे बयान दे रहे हैं, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) में आयोजित 'कोर्ट' बैठक में शामिल होने के बाद पत्रकारों से मुखातिब राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार के रवैए के कारण लोग मुझे पर्यटक समझ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि राज्यपाल की भूमिका क्या होती है। राज्यपाल का मजाक बनाया जा रहा है, जबकि एक राज्यपाल राज्य व केंद्र के बीच का प्रतिनिधि होता है। अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहकर आप मुझे हमेशा काम करता हुआ देखेंगे। मैं राज्यपाल हूं और अपना संवैधानिक कार्य कर रहा हूं। कैसे कोई मंत्री इतने नीचे स्तर पर गिर सकता है। मैं यह सब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर छोड़ता हूं कि वह अपने मंत्रियों को क्या सलाह देती हैं।

मंत्री सुब्रत के बयान पर जताई आपत्ति : राज्यपाल की सुरक्षा से बंगाल पुलिस को हटाकर केंद्रीय सुरक्षा बलों की जेड श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने पर बंगाल के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए धनखड़ ने कहा कि मेरी सुरक्षा को लेकर बगैर जाने सुब्रत मीडिया में बयान दे रहे हैं, एक मंत्री भला ऐसा बयान कैसे दे सकता है। यहां बता दें कि सुब्रत ने गुरुवार को कहा था कि राज्यपाल चाहते तो राज्य सरकार से कहकर सुरक्षा बढ़वा सकते थे। इसके लिए दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं काफी समय से विधायक हूं। मैंने कभी किसी राज्यपाल को ऐसा करते नहीं देखा।

पार्थ चटर्जी पर किया पलटवार : राज्यपाल द्वारा बीते महीने सिलीगुड़ी में बुलाई गई प्रशासनिक बैठक हो या फिर उनके द्वारा जियागंज प्रकरण में दिए गया बयान, सभी मामले में शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने राज्यपाल पर तंज कसा है। पार्थ ने राज्यपाल पर संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं पार्थ ने यह भी कहा था कि बेहतर होता कि राज्य में नए राज्यपाल यहां के पर्यटन स्थलों का लुत्फ उठाते। इस पर शुक्रवार को राज्यपाल ने पार्थ पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। कोई मुझे बताए कि कभी भी मैंने अपनी लक्ष्मण रेखा पार की हो। मेरा काम है कि राज्य व केंद्र सरकार के प्रति लोगो की आस्था व विश्वास को कायम रखना है, जबकि यहां के मंत्री बिना सोचे समझे मेरे बारे में बयान दे रहे हैं।

मुजफ्फरपुर में नहाने के दौरान सात बच्चों की मौत

जेएनएन, मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में शुक्रवार दोपहर नहाने के दौरान पोखर एवं बागमती की पुरानी धारा में डूबने से सात बच्चों की मौत हो गई। डीएम आलोक रंजन घोष के निर्देश पर सरकारी प्रावधान के अनुसार मृतक के परिजन को चार-चार लाख रुपये दिए गए हैं। जिले के विशनपुर बघनगरी गांव की खुशबू कुमारी (17), रजिया खातून(13), अजमेरी खातून(13) तथा नाजनी खातून(13) बकरी चराने चौर में गई थीं। सभी को-ऑपरेटिव के निकट स्थित पोखर के पास आ गईं। बगल में ही बकरी चरा रहीं दो और किशोरी व आठ वर्षीय गोलू भी उनके साथ चले गए। पोखर में सबसे पहले खुशबू उतरी। उसके पीछे-पीछे तीनों भी नहाने चली गई। गोलू ने बताया कि चारों स्नान करते-करते ज्यादा पानी में चली गईं। इस क्रम में खुशबू डूबने लगी। जिसे बचाने के लिए रजिया, अजमेरी व नाजनी आगे बढ़ीं, खुशबू के उनको पकड़ लेने से सभी पानी में डूब गईं। मुजफ्फरपुर के ही रामपुर हरि दक्षिणी में बागमती नदी की पुरानी धारा में नहाने के दौरान एक ही परिवार के तीन भाई-बहनों की डूबकर मौत हो गई।

दीपावली से पहले पटना को साफ–सुथरा करें : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, पटना

▸ डेंगू के डंक पर बिहार सरकार को लगाई फटकार

पटना हाई कोर्ट। फाइल फोटो

जलजमाव, गंदगी, कूड़े का अंबार और डेंगू के डंक पर पटना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई। स्पष्ट शब्दों में कहा कि युद्धस्तर पर अभियान चला कर दीपावली से पहले तक पटना को पूरी तरह साफ सुथरा व जलजमाव मुक्त करे। साथ ही 25 अक्टूबर को अदालत के समक्ष हलफनामा दायर करे। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जलजमाव से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए। अदालत की कार्रवाई के दौरान महाधिवक्ता ललित किशोर ने सरकार की ओर से यह बात रखनी चाही कि शहर के हर हिस्से से जलनिकासी का कार्य पूरा हो चुका है। अधिवक्ता एसएन पाठक ने इसका विरोध किया। अदालत को बताया कि अब भी कई ऐसे इलाके हैं, जहां जलजमाव है।

जज की भी नहीं सुनते अधिकारी : याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश भी अधिकारियों की कारगुजारियों के भुक्तभोगी हैं। न्यायाधीश शिवाजी पांडेय ने जब आपबीती सुनाई तो कोर्ट रूम भी सन्न रह गया। न्यायाधीश ने बताया कि आशियाना में उनके घर के पास टूटे नाले की शिकायत करने के लिए जब नगर आयुक्त को फोन किया तो फोन रिसीव ही नहीं किया गया। मशक्कत के बाद फोन उठाया गया तब शिकायत सुनी गई, पर कार्रवाई नहीं की गई।

बांग्लादेश के गृह मंत्री ने कहा–गोलीबारी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, रिश्ते प्रभावित न हों

▸ बीजीबी व बीएसएफ प्रमुख कर रहे बातचीत, भारतीय मछुआरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

▸ इस घटना में बीएसएफ का जवान शहीद व दूसरा घायल हो गया था

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश के गृहमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि उनके देश के बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) और भारत की सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के प्रमुख 'एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना' को लेकर हुई 'गलतफहमी' को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जिससे बांग्लादेश और भारत के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्ते प्रभावित नहीं होने चाहिए। इस घटना में बीएसएफ का जवान शहीद व दूसरा घायल हो गया था। दूसरी तरफ, एक भारतीय मछुआरे पर दो मामले दर्ज किए गए हैं।

गृहमंत्री असदुज्ज्मां खान कमाल ने यहां प्रेस क्लब में बताया, 'यह अप्रत्याशित घटना थी। बीजीबी व बीएसएफ के रिश्ते बेहद अच्छे रहे हैं। इस घटना से हम सभी अचंभित हैं।' मीडिया ने मंत्री के हवाले से कहा, 'बीजीबी और बीएसएफ के महानिदेशक इस गलतफहमी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा मानना है कि यह दुर्घटना थी और दोनों पक्षों के बीच बातचीत से इसका समाधान कर लिया जाएगा।'

'ढाका ट्रिब्यून' ने खबर दी है कि बीजीबी ने भारतीय मछुआरे प्रणब मंडल के खिलाफ राजशाही के चारघाट थाने में दो मामले दर्ज किए हैं। थाना प्रभारी समित कुमार कुंडू ने कहा कि उस पर अवैध रूप से बांग्लादेश के क्षेत्र में प्रवेश करने और हिलसा प्रजनन के मौसम में पद्मा नदी में मछली मारने के आरोप हैं। बांग्लादेश की मीडिया ने पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले केरहने वाले मछुआरे को शुक्रवार को जेल भेज दिया गया।

बीएसएफ ने कहा, बिना उकसावे के चलाई गईं गोलियां

नई दिल्ली, प्रेट्र : बीएसएफ ने शुक्रवार को कहा कि उसके जवान की हत्या और दूसरे को जख्मी करने की बांग्लादेश की कार्रवाई बिना उकसावे की थी। जब दोनों पक्षों के बीच फ्लैग बैठक हुई तब बीएसएफ जवानों ने 'एक भी गोली' नहीं चलाई। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीजीबी के इस दावे को खारिज कर दिया कि उसके गश्ती दल को 'बीएसएफ के जवानों द्वारा की जा रही गोलीबारी के बीच आत्मरक्षा में गोलियां चलानी पड़ीं।' अधिकारी ने कहा, 'हमारे जवानों ने एक भी गोली नहीं चलाई। बीजीबी की तरफ से यह बिना उकसावे की कार्रवाई थी।' उन्होंने कहा कि इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं।

राजनाथ सिंह ने सैनिक स्कूलों में छात्राओं के नामांकन को मंजूरी दी

▸ राजनाथ सिंह ने आवश्यक बुनियादी सुविधाएं और महिला कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

राजनाथ सिंह। फाइल फोटो

नई दिल्ली प्रेट्र : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिक स्कूलों में 2021-22 से लड़कियों के नामांकन को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी एक बयान में दी गई है। रक्षा मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इन शिक्षण संस्थानों में आवश्यक बुनियादी सुविधाएं और पर्याप्त महिला कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है। यह फैसला दो साल पहले मिजोरम में चिंगचिप सैनिक स्कूल में लड़कियों के नामांकन के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद लिया गया है।

बयान में कहा गया है, 'यह फैसला सरकार के व्यापक समावेशी, स्त्री-पुरुष बराबरी, सशस्त्र बलों में महिलाओं की व्यापक भागीदारी को समर्थन और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के लक्ष्य के अनुरूप है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है।'

सैनिक स्कूल का उद्देश्य पब्लिक स्कूल एजुकेशन को आम आदमी की पहुंच में लाना है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में इसके कैडेट को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भेजना है।

इस समय देश में 33 सैनिक स्कूल हैं। वर्ष 2017 में सैनिक स्कूलों ने छह लड़कियों को प्रवेश देते हुए छात्राओं के नामांकन की शुरुआत की थी। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट के अनुसार उठाया गया था। सैनिक स्कूलों में लड़कियों के नामांकन को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला कैडेटों को शामिल करने की दिशा में बढ़ाए गए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

Download UPSC IAS Material: www.iascgl.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 19 अक्टूबर 2019

दैनिक जागरण

आस्था और दृढ़ इच्छाशक्ति से कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं

आतंक का पोषक पाक

इस पर हैरत नहीं कि आतंकी फंडिंग पर निगाह रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था एफएटीएफ ने फिर यह पाया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को पोषित करने वाले तौर-तरीकों पर लगाम लगाने का काम नहीं किया है। एक ऐसा देश जिसने आतंकवाद को अपने शासन का हिस्सा बना रखा हो और जहां की सेना आतंकी संगठनों को पालने-पोसने का काम करती हो उसके बारे में यदि एफएटीएफ यह उम्मीद कर रही है कि वह आसानी से सही राह पर आ जाएगा तो यह खुशफहमी ही अधिक है। क्या यह अजीब नहीं कि पाकिस्तान 27 बिंदुओं में से पांच पर ही उम्मीदों पर खरा उतर सका, फिर भी उसे मोहलत दे दी गई? कहीं पाकिस्तान को यह मोहलत चीन, तुर्की और मलेशिया की पैरवी के कारण तो नहीं मिली? सच जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जहां चीन इस समय एफएटीएफ का प्रमुख है वहीं मलेशिया और तुर्की पाकिस्तान के नए हमदर्द बनकर उभरे हैं। भारत को यह समझना होगा कि आतंक समर्थक पाकिस्तान के प्रति एफएटीएफ की ओर से पर्याप्त सख्ती न दिखाया जाना शुभ संकेत नहीं।

पाकिस्तान आसानी से आतंक की राह छोड़ने वाला नहीं, इसका प्रमाण केवल यही नहीं कि वह एफएटीएफ के दबाव के बावजूद आतंकी संगठनों को संरक्षण देने से बाज नहीं आ रहा, बल्कि यह भी है कि वहां के शासक इसे अपनी जीत के रूप में रेखांकित कर रहे हैं कि उनका मुल्क काली सूची में शामिल होने से बच गया। वहां के मीडिया का भी यही स्वर है कि अगर पाकिस्तान काली सूची में नहीं जा सका तो यह उसकी जीत ही है। ऐसे स्वरों से यह अच्छे से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान को इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं कि वह आतंकवाद के खिलाफ उचित कार्रवाई न करने के कारण एक वैश्विक संस्था की ग्रे लिस्ट में है। यह भारत का दुर्भाग्य ही है कि ऐसा ढीठ देश उसका पड़ोसी है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि जहां उसकी ओर से पाकिस्तान की घेरेबंदी जारी रहे वहीं अगर वह आतंक का रास्ता न छोड़े तो उसे एफएटीएफ की काली सूची में अवश्य डाला जाए। एफएटीएफ की काली सूची में जाने पर पाकिस्तान ईरान और उत्तर कोरिया के बाद ऐसा तीसरा देश होगा जिसे विश्व समुदाय दुनिया के लिए खतरे के तौर पर देखेगी। सच तो यह है कि वह अभी भी दुनिया के लिए खतरा ही है। उचित यह होगा कि भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष सरीखी संस्थाओं को इससे परिचित कराए कि पाकिस्तान की धरती पर पल रहे किस्म-किस्म के आतंकी जितना भारत के लिए खतरा बने हुए हैं उतना ही अफगानिस्तान के लिए भी।

इजरायल दौरा

झारखंड के किसानों का एक और दल इन दिनों इजरायल दौरे पर है। चार दिवसीय इस दौरे का उद्देश्य राज्य के किसानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कृषि के क्षेत्र में आ रहे बदलावों से अवगत कराना और उन्हें कृषि की अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ना है। इससे पहले भी तीन टीमें जा चुकी हैं। इनमें एक दल महिला किसानों का था। झारखंड देश का पहला राज्य है जिसने एक वर्ष के भीतर इतने किसानों को इजरायल भेजा है। कृषि के क्षेत्र में अपेक्षाकृत पिछड़े माने जाने वाले झारखंड राज्य की इस पहल की जितनी भी सराहना की जाए कम है। किसानों के इजरायल दौरे का किसानों का फायदा भी मिलना शुरू हो गया है। पूर्व में इजरायल भेजे गए किसान अब मास्टर ट्रेनर के रूप में अन्य किसानों को खेती की नवीनतम तकनीक से अवगत करा रहे हैं। नए तरीके से कुछ फसलों की खेती छिटपुट तौर पर शुरू हुई है। बताने की जरूरत नहीं कि किसान खुशहाल होंगे तो राज्य की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी, लेकिन इसे व्यापक तरीके से पूरे राज्य में लागू करना होगा। इजरायल ने अपनी अत्याधुनिक खेती से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। पानी की कमी और खेती योग्य पर्याप्त भूमि न होने के बावजूद इस देश ने कम समय में ही वह कर दिखाया है जो तमाम विकसित देश नहीं कर सके। इससे भारत समेत दुनिया के तमाम देशों को सीखने की जरूरत है। राज्य के किसानों को आधुनिक खेती की ओर मोड़ने के लिए कई और क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे। इजरायल मॉडल को पूरी तरह झारखंड में लागू करना होगा। झारखंड में इजरायल के सहयोग से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के प्रस्ताव पर पिछले वर्ष राज्य सरकार आगे बढ़ी थी, लेकिन फिलहाल यह ठंडे बस्ते में है। झारखंड दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अभी भी राष्ट्रीय मानकों से कहीं पीछे है। इजरायल जैसे देशों की अत्याधुनिक डेयरी तकनीक से युक्त यदि कोई प्लांट झारखंड में स्थापित हो सके तो यह कहीं अधिक कारगर साबित होगा। इसी प्रकार कृषि के कुछ मॉडल प्रोजेक्ट इजरायल के तकनीकी सहयोग से लगाए जा सकते हैं, जहां किसानों को नियमित भ्रमण कराया जा सकता है।

झारखंड से किसानों को उन्नत खेती की आधुनिक तकनीक सीखने के लिए इजरायल भेजा जाना सराहनीय है

भरोसे की कमी से जूझते भारत-चीन

सुधींद्र कुलकर्णी

चीनी राष्ट्रपति के समक्ष सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती यही है कि भारत के साथ रिश्ते कैसे बेहतर बनाए जाएं जिनमें परस्पर विश्वास की कमी है

अवधेश राजपूत

मामल्लपुरम में भारत-चीन के शासनाध्यक्षों की मुलाकात से पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान, सेना प्रमुख और आइएसआइ मुखिया के साथ शी चिनफिंग की गलबहियों ने ऐसे भारतीय विश्लेषकों की त्योरियां और चढ़ा दी थीं जिन्हें चीन फूटी आंख नहीं सुहाता। उन्होंने मामल्लपुरम में वार्ता से पहले ही उसका मर्सिया पढ़ना शुरू कर दिया था कि वुहान वाली भावना हवा हो गई और अनौपचारिक वार्ता के दौर की यह दूसरी कड़ी यहीं दम तोड़ देगी, फिर भी मोदी ने इसे सफल बनाया। उन्होंने कहा कि 'चेन्नई कनेक्ट' के जरिये परस्पर विश्वास की ऐसी भावना विकसित हुई जिससे भारत-चीन सहयोग में एक नए दौर की शुरुआत होगी। आखिर पासा किसने पलटा? वह शख्स कोई और नहीं, बल्कि माओत्से तुंग के बाद चीन के सबसे शक्तिशाली नेता शी चिनफिंग हैं। उन्होंने पाकिस्तान और भारत को एक साथ साधकर बेहद मुश्किल नजर आने वाली कूटनीतिक बाजी अपने नाम की। चीनी राष्ट्रपति के समक्ष सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती यही है कि भारत के साथ रिश्ते कैसे बेहतर बनाए जाएं जिनमें परस्पर विश्वास की कमी है। उनकी यह चुनौती तब और जटिल हो जाती है जब उन्हें यह काम पाकिस्तान के साथ चीन के परंपरागत रिश्तों को कमजोर किए बिना करना हो। तमाम भारतीय मानते हैं कि पाकिस्तान के करीबी किसी देश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी तरह तमाम पाकिस्तानियों को भी यह खटकता है कि उनका सदाबहार दोस्त उनके 'दुश्मन' भारत के साथ मेलजोल बढ़ा रहा है। ऐसे माहौल में पहले इमरान और फिर मोदी के साथ मुलाकात में शी ने दोनों को दोस्ती का भरोसा दिलाया। शी की भाव-भंगिमा पर गौर करने वालों ने स्वाभाविक रूप से देखा होगा कि पाकिस्तानी राजनीतिक-सैन्य नेतृत्व के साथ औपचारिक वार्ता के उलट मोदी संग अनौपचारिक वार्ता में चीनी राष्ट्रपति कहीं ज्यादा सहज और दोस्ताना नजर आए। ऐसे में 'चेन्नई कनेक्ट' महज एक कूटनीतिक जुमले से कहीं ज्यादा मोदी और शी के बीच उभरते नए रिश्तों की अभिव्यक्ति कराता है। सबसे बड़े पड़ोसी के साथ रिश्त सुधारने में मोदी ने गजब की परिपक्वता और चातुर्य का परिचय दिया है और इसमें वह धीरे-धीरे ही सही, लेकिन रणनीतिक कड़ियां भी जोड़ रहे हैं। इस मुश्किल कवायद में मोदी के समक्ष चुनौतियां स्पष्ट हैं। बतौर प्रधानमंत्री अपने साढ़े पांच वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने पाकिस्तान के साथ निरंतरता वाली कोई नीति नहीं अपनाई। न ही पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान ने मोदी के भरोसा बढ़ाने वाले सकारात्मक कदमों पर उचित प्रतिक्रिया दी। मोदी के समर्थक भी पाकिस्तान के प्रति बहुत कट्टर हैं। वास्तव में सत्ता में उनकी दोबारा वापसी कराने में इस पहलू की अहम भूमिका रही। ऐसे में उनके लिए चीन के साथ गलबहियां जारी रखना आसान नहीं होगा, खासतौर से ऐसे देश के साथ जो पाकिस्तान जैसे पुराने सहयोगी का साथ नहीं छोड़ने जा रहा। इसके बावजूद मोदी ने चेन्नई बैठक को लेकर जताई जा रही उन आशंकाओं को निर्मूल साबित किया जो भारत-चीन-पाकिस्तान के बीच अंतर्निहित विरोधाभासों के चलते उसकी नाकामी का अंदेशा जता रही थीं।

इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हाल के दौर में किसी विदेशी नेता के भारतीय दौरे को लेकर जनता में इतनी उत्सुकता नहीं रही जितनी मामल्लपुरम में शी के आगमन को लेकर रही। बीजिंग में इमरान के साथ शी की मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच कोई तारतम्य नहीं दिखा, जबकि चीनी राष्ट्रपति के साथ मोदी की मुलाकात में दिखा कि वह शी के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं और यह बराबरी के स्तर पर हो रहा है।

चेन्नई में मोदी-शी बैठक के इस पहलू ने भी भारतीय जनता का ध्यान आकृष्ट किया कि दोनों की वार्ता में कश्मीर मुद्दे का जिक्र नहीं हुआ। जिक्र हुआ भारत, चीन एवं शेष विश्व के समक्ष आतंकवाद और धार्मिक उन्माद के खतरे का। माना जाता है कि बीजिंग में इमरान, जनरल बाजवा और आइएसआइ प्रमुख से वार्ता में शी ने इसी मसले पर चर्चा की होगी। यह भी संभव है कि शी ने मोदी को इसके बारे में सूचित किया होगा। यह सोचना उचित नहीं होगा कि चीन आतंकवाद या इस्लामिक अलगाववाद के प्रति कोई नरमी रखता होगा, क्योंकि अपने मुस्लिम बहुल प्रांत झिनजियांग में वह खुद इस खतरे को झेल रहा है। पाकिस्तान भी धार्मिक उन्मादियों से पीड़ित है। ऐसे में यह सही समय है कि भारत-चीन और पाकिस्तान इस साझा खतरे से निपटने के लिए सार्थक संवाद शुरू करें। भारतीय, चीनी और पाकिस्तानी नेताओं के साथ अपनी तमाम वार्ताओं में मैंने तीनों देशों के बीच नियमित रूप से ट्रैक-टू कूटनीति को सिरे चढ़ाने की वकालत की है। इससे तीनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच शिखर वार्ता की बुनियाद तैयार होगी।

प्राचीन मंदिरों वाले समुद्र तटीय शहर मामल्लपुरम में शी के साथ संवाद के दौरान मोदी ने एक और महत्वपूर्ण पहलू जोड़ा। यहां हिंदू मंदिरों, आख्यानों और संस्कृति के नयनाभिराम दृश्य दिखाई पड़े। यह प्राचीनकाल में भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कड़ियों को प्रदर्शित करता है जिससे शी भलीभांति परिचित होंगे। शी ने अपने जीवन के 18 वर्ष चीन के दक्षिण पूर्वी फुजियन प्रांत में कम्युनिस्ट पार्टी के कनिष्ठ अधिकारी के तौर पर गुजारे हैं। फुजियन में ऐसी जगहें हैं जिनके तार भारत विशेषकर तमिलनाडु से जुड़े हैं। कुछ साल पहले मैं ग्वांगझू गया था जहां मैंने 1,300 साल पुराना एक काइयुआन मंदिर देखा जिसमें शिव, कृष्ण और नरसिंह भगवान की प्रतिमाएं थीं। मामल्लपुरम में मोदी जब शी को मंदिर दिखा रहे थे तब शी ने ग्वांगझू का जिक्र किया। ग्वांगझू के सामुद्रिक संग्रहालय में मध्यकालीन इतिहास के दौरान भारत और चीन के बीच की तमाम इस्लामिक कड़ियों के नमूने रखे हैं। यह सुखद है कि भारत-चीन रिश्तों की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मोदी और शी ने एक पोत पर कांफ्रेंस करने का एलान किया जिसमें विश्व की दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव की कड़ियां जोड़ी जाएंगी। इतिहास के इन विस्मृत अध्यायों का पुनरावलोकन चेन्नई कनेक्ट की बड़ी थाती रही।

चेन्नई सम्मेलन का सबसे खास पहलू यही है कि शी ने चीन-भारत संबंधों को सुधारने के लिए सौ वर्षीय एजेंडा पेश किया। यह सच है कि दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे से लेकर सीमा विवाद तक तमाम तरह के मतभेद हैं, लेकिन अगर हम अपनी सभ्यतागत बुद्धिमता से मार्गदर्शन लें और मित्रता को लेकर कोई पूर्वाग्रह न रखें तो हम पाकिस्तान सहित सभी देशों के साथ अपने मसले इस तरह सुलझा सकते हैं जिसमें किसी भी पक्ष को कोई नुकसान न हो। वास्तव में भारत और चीन मिलकर इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं।

(लेखक फोरम फॉर ए न्यू साउथ एशिया के संस्थापक हैं)

response@jagran.com

बदले की भावना से उपजे आरोप

क्षमा शर्मा

वर्षों तक लिव इन में रहने के बाद जब संबंध टूट जाएं तो दुष्कर्म का आरोप लगाना बदले की भावना को ही इंगित करता है

अदालतें एक अरसे से इस तरह के फैसले दे रही हैं कि लिव इन के तहत बना संबंध दुष्कर्म नहीं है, लेकिन सरकारें इस तरफ ध्यान नहीं दे रहीं। परिणामस्वरूप लिव इन संबंध टूटने के बाद दुष्कर्म के झूठे आरोपों के मामले सामने आ रहे हैं। यह तब है जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि यदि सहमति से संबंध बने हों और आदमी उन परिस्थितियों के कारण विवाह न कर पाया हो, जिन पर उसका वश नहीं तो उसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। यह फैसला न्यायालय ने महाराष्ट्र के एक डॉक्टर और नर्स के मामले में दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि सहमति से बने संबंधों को दुष्कर्म की धारा के अंतर्गत अपराध नहीं माना जा सकता। इस मामले में नर्स और डॉक्टर इकट्ठे रहते थे, लेकिन जब नर्स को पता चला कि उसकी शादी किसी और से हो गई है तो उसने दुष्कर्म की शिकायत कर दी। डॉक्टर ने मुंबई हाईकोर्ट से अपील की कि उसके खिलाफ एफआइआर रद की जाए, मगर हाईकोर्ट ने इसे नहीं माना था। तब उसने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई। कोर्ट ने एफआइआर को निरस्त करते हुए कहा कि अदालतों को काफी सावधानी से इन मामलों की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में आरोपी ने वासना के वशीभूत होकर महिला से संबंध बनाए या संबंध सहमति के आधार पर बने? यदि दोनों में सहमति से संबंध थे तो संबंध टूटने पर दुष्कर्म का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

एक अन्य मामले में महिला पहले जिस पुरुष के साथ रिश्ते में थी उसने किसी और से विवाह कर लिया, लेकिन शादी जल्दी ही टूट गई। महिला फिर से पहले वाले साथी के संपर्क में आई। इस रिश्ते से एक बच्ची भी हुई, लेकिन महिला ने इस आदमी पर दुष्कर्म का आरोप लगा दिया। इसकी जांच करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये संबंध पूरी तरह से स्त्री-पुरुष की मर्जी से बने थे। इन्हें दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक मामले में ऐसा ही फैसला दिया कि किन्हीं कारणों से शादी न हो पाने पर दुष्कर्म का आरोप नहीं लगाया जा सकता। जो जोड़ा वर्षों से साथ रहा हो, एक साथ घूमा-फिरा हो, पुरुष द्वारा शादी में असमर्थता व्यक्त करने पर भी सभी तरह के संबंध बने रहे हों तो ऐसे में इसे दुष्कर्म कहना उचित नहीं है।

वर्षों तक लिव इन में रहने के बाद जब संबंध टूट जाएं तो दुष्कर्म का आरोप लगाना बदले की भावना को इंगित करता है। हालांकि आज भी इस तरह के संबंधों को समाज में स्वीकृति प्राप्त नहीं है। जैसे ही लड़की या लड़के के घर वालों को इस तरह के संबंधों का पता चलता है तो वे उन्हें खत्म करने का दबाव बनाने लगते हैं। लड़के, लड़कियों की शादी कहीं और तय कर दी जाती है। दरअसल वक्त के साथ हमारी सोच भी बदली है। आज बड़ी संख्या में लड़के, लड़कियां घर से बाहर काम करने निकली हैं। इनमें से कई घर से बाहर कोई सहारा भी ढूंढ लेते हैं। एक तरफ हमें हर तरह की यौन आजादी चाहिए, रिश्ता चाहिए, मगर किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। यदि यौन आजादी चाहिए तो रिश्ते के खत्म हो जाने पर दुष्कर्म का आरोप क्यों लगाना चाहिए? आपसी सहमति का तो अर्थ भी यही है कि किसी रिश्ते को दूसरे पर लादा नहीं गया।

सहमति से संबंध और अपराध में फर्क होता है। दुष्कर्म अपराध है, सहमति नहीं। फिर यदि आप इस तरह के तमाम मामलों को देखें तो दो ही तरह के आरोप लगाए जाते हैं-एक आरोपी ने शादी का झांसा देकर ऐसा किया। और दूसरा यह कि आरोपी ने बुलाया, पेय में कुछ मिलाया, जब लड़की या महिला बेहोश हो गई तो ऐसा किया गया। आखिर ऐसा कैसे होता है कि पढ़ी-लिखी, समझदार महिलाएं किसी के झांसे में आ जाती हैं या कि कोई धोखे से उन्हें नशीला पेय पिला देता है। पुलिस की मानें तो अक्सर ऐसे आरोप झूठे होते हैं और सोच-समझकर लगाए जाते हैं। इस तरह के आरोपों और दुष्कर्म जैसे अपराध में कोई समानता नहीं। दुष्कर्म स्त्री के प्रति जोर-जबर्दस्ती किया गया बेहद गंभीर अपराध है, जबकि लिव इन संबंध टूट जाने के बाद प्रतिक्रिया में किसी को अपराधी ठहराने की कोशिश एक साजिश है। यह उन स्त्रियों का अपमान भी है जो बड़ी संख्या में इस तरह के अपराधों को झेलती हैं और बहुत बार साधनहीन होने के कारण पुलिस और कानून के दरवाजे तक नहीं पहुंच पातीं। लिव इन मामलों में अक्सर जब संबंध टूट जाते हैं तो निराश महिलाएं दुष्कर्म के आरोप लगा देती हैं। यह सिलसिला बंद होना चाहिए। कायदे से तो कानून में बदलाव होना चाहिए।

(लेखिका साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

प्रसन्न जीवन

प्रसन्नता जीवन का अमूल्य उपहार है। सफलता एवं उपलब्धियां उसी के पास आती हैं जो प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति कोई भयंकर पाप नहीं कर सकता। जिस गुण के बिना 90 प्रतिशत व्यक्ति असफल रहते हैं वह गुण है प्रसन्न भाव। यह गुण न बाप बेटे को दे सकता है और न बेटा बाप को। यह तो अपनी कमाई का गुण है। प्रसन्नता से मतलब केवल शारीरिक हास्य से नहीं है। इसके लिए भीतरी पवित्रता जरूरी है। प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति में न भय होता है, न शिकायत और न विरोध। ऐसा विरल व्यक्ति हर ओर से सकारात्मकता बटोरता है।

जिस भी व्यक्ति ने महानता का वरण किया है, उसका रोम-रोम हंसता हुआ प्रतीत होगा। कण-कण उसी के हंसते हैं जिसने समता, सौहार्द और संतुलन का जीवन जीया है। प्रसन्नता जीने का अभ्यास है। कोई भी व्यक्ति अपनी पवित्रता किसी को नहीं दे सकता, किंतु प्रसन्नता दे सकता है। मुस्कुराता हुआ फूल किसका मन नहीं मोहता। प्रसन्न व्यक्ति के प्रकंपन सुखद होते हैं। उनसे मन का भार हल्का होता है। तात्पर्य यही है कि मैं हंसता हूं तो सारा संसार हंसता हुआ प्रतीत होता है। यहां तक मृत शरीर भी उसे हंसता-खिलता दिखाई देता है, क्योंकि देखने वालों का नजरिया चैतन्य भरा है। इसी गुण से तनाव मुक्त जीवन जीया जा सकता है, लिहाजा इस विश्वास को स्वयं में संजोएं। थॉमस एल्वा एडिसन ने ठीक कहा है कि मनुष्य कम से कम इतना बुद्धिमान न हो जाए कि वह हंसने जैसी महान खुशी से वंचित रह जाए।

प्रसन्नता व्यक्ति की कार्यक्षमताओं का विकास करती है और वह कर्म के साथ स्फूर्ति और संतुलन बनाए रखती है। थकान मिटाने का एक बहुत बड़ा उपाय है प्रसन्नता। यह गुण व्यक्ति के खालीपन को भरकर उसके व्यक्तित्व को तरोताजा बना देता है। उसकी योग्यता को बढ़ाता है। उत्तेजना, शोक, बुरे विचार तथा नकारात्मक दृष्टियों से बचाकर व्यक्ति को सहज शांति से भर देता है। इसलिए प्रसन्नता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

ललित गर्ग

तथ्य-कथ्य | स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक

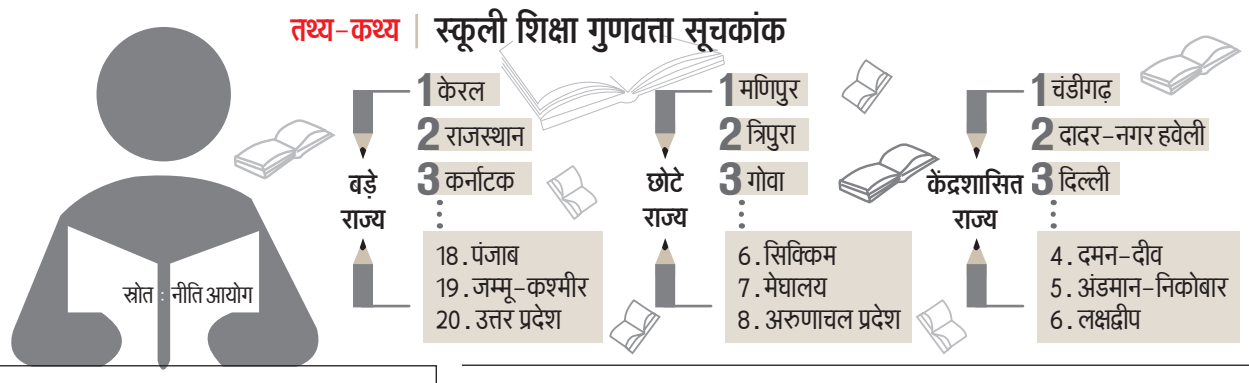

छोटे परदे पर बड़ी शिकायत

मनीषा सिंह

सरकार सोशल मीडिया पर नियंत्रण की व्यवस्था करती नजर आती है, लेकिन टीवी कार्यक्रमों का स्तर सुनिश्चित नहीं कर रही

बिग बॉस सीजन 13 के कई दृश्यों एवं संवादों के खिलाफ एक लिखित शिकायत सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से की गई है, जिसमें इस कार्यक्रम में अश्लीलता और फूहड़ता परोसने का आरोप लगाते हुए शो को बंद कराने की मांग की गई है। साथ ही मांग की गई है कि फिल्मों की तरह टीवी के कार्यक्रमों पर अंकुश के लिए अलग से सेंसरबोर्ड बनाया जाए। अब तो मोबाइल पर वेब सीरीज दिखाने वाले इतने मंच देश में बन गए हैं और उन पर बिग बॉस को टक्कर देती या उससे भी दो हाथ आगे की अश्लीलता परोसी जा रही है। ऐसे सभी कार्यक्रमों के निर्माता प्रायः यह दलील देते हैं ऐसे कार्यक्रमों की अवधारणा ही लोगों के निजी जीवन में ताकझांक पर आधारित होती है। हालांकि ऐसे मामलों में एक आश्चर्य तब जगता है जब हमारा समाज कुछ ऐतिहासिक फिल्मों के कुछ दृश्यों, तथ्यों, संवादों को बिना देखे-सुने ही उन पर आपत्ति जता सकता है, वही समाज बिग बॉस में दिखाई-सुनाई जा रही बातों-दृश्यों पर चुप्पी क्यों ओढ़ लेता है।

इस समस्या का एक पहलू और है। देश में फिल्मों की सामग्री के नियमन की व्यवस्था तो सेंसर बोर्ड के रूप में बनी हुई है, लेकिन टीवी और मोबाइल इंटरनेट पर परोसी जाने वाली सामग्री आपत्तिजनक होने के बावजूद लोगों को झेलनी पड़ती है, क्योंकि वे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण बेबस हैं। गौरतलब है कि हमारे देश में अरसे से यह मांग होती रही है कि टीवी और मोबाइल इंटरनेट पर परोसी जा रही सामग्री के नियमन के लिए भी एक सेंसरबोर्ड होना चाहिए, लेकिन अब तक यह नहीं हो सका है। इसकी जगह टीवी कार्यक्रमों के खिलाफ शिकायत सुनने की एक व्यवस्था ब्रॉडकॉस्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल (बीसीसीसी) अवश्य बनी हुई है, लेकिन जानकारी के अभाव में इस पर कम लोग ही शिकायत दर्ज कराते रहे हैं।

ऐसे समाज में, जहां टीवी हर आयु वर्ग के लोगों में एक राय बनाने की हैसियत रखता है, यह जरूरी है कि धारावाहिक निर्माताओं को मनोरंजन के नाम अनुचित तर्कों के साथ स्तरहीन कार्यक्रम बनाने और दिखाने से रोका जाए। टीवी कार्यक्रम बनाने वाले निर्माताओं को भी समझना होगा कि टीवी से जुड़े होने के कारण उनका एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक दायित्व है और वे इससे विमुख नहीं हो सकते। यदि वे इससे संबंधित नीतियां बनाकर खुद ही उनका पालन सुनिश्चित कर लेते हैं तो अच्छा होगा। अन्यथा उनके खिलाफ भी एक आंदोलन की जरूरत बनती है, खामोशी की नहीं।

यह तो अब पूछा ही जाना चाहिए कि जिस छोटे परदे ने देश के मध्यवर्गीय जनमानस पर एक तरह का कब्जा कर रखा है, क्या उसे नियंत्रण-मुक्त छोड़ा जा सकता है? यह हैरानी की ही बात है कि हमारी सरकार फिल्मों से लेकर सोशल मीडिया तक पर नियंत्रण की व्यवस्था करती नजर आती है, लेकिन टीवी कार्यक्रमों का स्तर सुनिश्चित करने वाला असरदार तंत्र उसने विकसित नहीं किया है। आखिर क्या वजह है कि टेलीविजन इंडस्ट्री को इस मामले में लगभग खुला ही छोड़ा गया है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार है)

मेलबाक्स

जनसंख्या विस्फोट है गरीबी का कारण

गरीबों का जीवन बदलने वाले प्रयोग शीर्षक से लिखे अपने लेख में विवेक कौल ने हाल ही में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत बनर्जी के गरीबों की गरीबी समझने के लिए किए गए प्रयोगों का विश्लेषण किया है। हमारे देश में गरीबों का जीवन तब तक नहीं बदला जा सकता अर्थात इनको गरीबी के दलदल से तब तक बाहर नहीं निकाला जा सकता, जब तक इनको परिवार नियोजन के प्रति जागरूक नहीं किया जाता और इनके लिए बनाई गईं सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंत नहीं हो जाता। अगर देश में इतनी जनसंख्या नहीं होती तो कोई भूखे पेट न सोता, बच्चे कुपोषण का शिकार होकर दम न तोड़ते और न ही कोई बच्चा पेट की आग बुझाने के लिए बोरी उठाकर कूड़े के ढेर तक जाता, बल्कि वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता। आज भी कई लोग अपनी कमाई बढ़ाने के चक्कर में ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन इससे उनकी कमाई तो बढ़ नहीं रही, उलटे वे गरीबी के दलदल में और फंसते जा रहे हैं। जाहिर है गरीबी पर नकेल कसने के लिए जनसंख्या वृद्धि की बढ़ती रफ्तार को रोकना भी जरूरी है। इसके अलावा अक्सर देखा जाता है कि दिल्ली में जो गरीबों के लिए योजनाएं बनती हैं, वे भ्रष्टाचार के कारण देश के दूरदराज के गांवों-शहरों तक पहुंचते-पहुंचते रास्ते में दम तोड़ जाती हैं। गरीब उनका लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। यदि सरकार देश से गरीबी दूर करना चाहती है तो उसे इन दोनों मुद्दों पर ध्यान देना होगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

अलसी और इसका तेल

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने प्रायः हमारे खेतों में उगाई जाने वाली अलसी की एक नई उन्नत प्रजाति टीएल-99 को सफलतापूर्वक विकसित किया है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें परंपरागत उगाई जाने वाले अलसी के तेल में पाए जाने वाले 35 से 67 प्रतिशत तक लिनोलेनिक एसिड की तुलना में मात्र 5 प्रतिशत लिनोलेनिक एसिड है। लिनोलेनिक एसिड की अधिकता की वजह से पुरानी परंपरागत अलसी का तेल बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज्ड होकर खराब हो जाता था, अब इस नई अलसी की प्रजाति के विकसित होने से इसके तेल को बड़े आराम से अधिक समयावधि तक प्रयोग कर सकते हैं। इस तेल में वे सभी गुण हैं जो जैतून के तेल में होते हैं। इस तेल में हृदय रोगियों के लिए सबसे घातक तत्व संतृप्त और असंतृप्त वसा अम्ल बिल्कुल नहीं हैं, ऐसा बताया गया है। अलसी के तेल में 50 से 60 प्रतिशत तक ओमेगा-3 फैटी एसिड या अल्फा लिनोनिन एसिड और लिग्नान होते हैं, जो हृदय की बीमारियों को कम कर देते हैं। इसमें उपस्थित तत्व मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादन को बढ़ाने को उत्प्रेरित करता है, जिससे डायबिटीज मरीजों के लिए भी यह रामबाण औषधि कारगर सिद्ध होगी। आशा की जानी चाहिए कि भारतीय वैज्ञानिक अपनी उच्चतम मेधाशक्ति से अलसी के तेल में उत्तरोत्तर सुधार करके भारत में इसे ऑलिव ऑयल जो बहुत मंहगा होने की वजह से आम भारतीय लोगों की पहुंच से बाहर है, का विकल्प प्रस्तुत कर भारत में महामारी की तरह अपना पैर पसारते जा रहे हृदय रोगों और शुगर रोग की रोकथाम में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे ।

निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

सशक्त विपक्ष जरूरी

दैनिक जागरण के 17 अक्टूबर के अंक में प्रदीप सिंह का लेख, प्रभावी विपक्ष में बाधा बनी कांग्रेस, में परिवार को बाड़ व कांग्रेस को खेत की संज्ञा दी है। इसमें आकलन किया है कि जब बाड़ ही खेत को खाने लगे तो क्या किया जा सकता है। असल में आजादी के बाद कांग्रेस पर नेहरू गांधी परिवार का ही वर्चस्व रहा है। सोनिया गांधी निरंतर 17 साल तक अध्यक्ष पद पर बनी रहीं। सोनिया के बाद राहुल गांधी आए, किंतु वे भी पार्टी को अधर में छोड़कर चलते बने। कांग्रेस के पास परिवार से इतर नया अध्यक्ष चुनने का अवसर था, किंतु कांग्रेस परिवार के मोहपाश से नहीं छूट सकी। संभवतः कांग्रेस को यह भय सता रहा होगा कि यदि नेहरू गांधी परिवार से बाहर अध्यक्ष पद गया तो कांग्रेस बिखर जाएगी। कांग्रेस ने 1984 के लोकसभा चुनाव में चार सौ से ज्यादा सीटें जीती थीं, लेकिन अब बहुत कमजोर हो गई है, वहीं भाजपा के पास अपार बहुमत है। ऐसे में सत्ता में बैठी कोई भी पार्टी निरंकुश हो सकती है। इसलिए एक सशक्त विपक्ष का होना अनिवार्य है।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन.संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

30.3 जीएचआइ स्कोर रहा है भारत का 100 में से, हाल ही में जारी जीएचआइ यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के तहत। इतने अधिक स्कोर का मतलब है कि भारत में भूख का गंभीर संकट है।

आजकल

रिजवान अंसारी
अध्येता, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

भूख को हराने की होड़ में हम पीछे क्यों

बुनियादी ढांचों के व्यापक निर्माण से विकास की राह पर अग्रसर हमारा देश भुखमरी और कुपोषण की समस्या से निजात पाने में कामयाब नहीं हो पाया है जो बड़ी चिंता का विषय है। हालिया जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की दशा इस लिहाज से गंभीर बताई गई है। ऐसे कौन से कारण हैं जिनके चलते देश में अब तक ऐसी स्थिति है? उन सभी कारणों को तलाशना ज्यादा मुश्किल नहीं है, और यदि कारण की तलाश हो जाए तो समस्या का समाधान आसानी से हो जाना चाहिए, जो शायद नहीं हो रहा

प्रतीकात्मक

हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की स्थिति बहुत खराब बताई गई है। इस सूचकांक के अनुसार दुनिया के 117 देशों में भारत 102वें पायदान पर है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत दुनिया के शीर्ष 16 ऐसे देशों में शामिल है जहां भूख की स्थिति भवायह है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भुखमरी सूचकांक में उसका स्थान दक्षिण एशिया के देशों से भी नीचे है। भारत की रैंक 102 है, जबकि बाकी दक्षिण एशियाई देश 66वें से 94 स्थान के बीच हैं। इस सूचकांक में पाकिस्तान 94वें पायदान पर है जबकि बांग्लादेश और क्रमशः श्रीलंका 88वें और 66वें पायदान पर हैं। भारत ब्रिक्स देशों में भी सबसे पीछे है। गौरतलब है कि ब्रिक्स का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश दक्षिण अफ्रीका 59वें स्थान पर है।

भारत में भूख की गंभीर दशा : दरअसल इस सूचकांक में भूख की स्थिति के आधार पर देशों को शून्य से 100 अंक दिए गए हैं। इसमें शून्य अंक सर्वोत्तम यानी भूख की स्थिति नहीं होने को प्रदर्शित करता है। 10 से कम अंक का मतलब है कि देश में भूख की बेहद कम समस्या है। 10 से लेकर 19.9 तक अंक होने का मतलब है कि यह समस्या यहां है। इसी तरह 20 से 34.9 अंक का मतलब भूख का गंभीर संकट और 35 से 49.9 अंक का मतलब है कि हालत चुनौतीपूर्ण है। 50 या इससे ज्यादा अंक का मतलब है कि वहां भूख की बेहद भयावह स्थिति है। मालूम हो कि इस सूचकांक में भारत को 30.3 अंक मिला है जिसका मतलब है कि यहां भूख का गंभीर संकट है।

भुखमरी से लगातार खराब हो रही देश की दशा : दरअसल भुखमरी के मामले में भारत की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। वर्ष 2014 में 55वें स्थान पर होने के बावजूद 2015 में 80वें, वर्ष 2016 में 97वें, 2017 में 100वें और अब 2019 में भारत 102वें पायदान पर खिसक चुका है। ऐसे में सवाल है कि किन कारणों से देश की दशा बेहतर नहीं हो पा रही है। वैसे तो हम खाद्यान्न और दुग्ध-उत्पादन में शिखर पर हैं। लेकिन इसके बावजूद यहां विश्व के 25 फीसद वैसे लोग निवास करते हैं जो दो जून की रोटी के मोहताज हैं।

इस नवीनतम रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन को भी एक वजह बताई गई है। कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भूख का संकट चुनौतीपूर्ण स्तर पर पहुंच गया और इससे दुनिया के पिछड़े क्षेत्रों में लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता और कठिन हो गई। इतना ही नहीं, जलवायु परिवर्तन से भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई भी प्रभावित हो रही है। साथ ही फसलों से मिलने वाले भोजन की पोषण क्षमता भी घट रही है। इस रिपोर्ट की मानें तो दुनिया ने वर्ष 2000 के बाद भूख के संकट को कम तो किया है, लेकिन इस समस्या से पूरी तरह निजात पाने की दिशा में अब भी लंबी दूरी तय करनी होगी।

भारत में दुनिया के 40 प्रतिशत कुपोषित बच्चे : भारत की बात करें तो यह विश्व के करीब 40 प्रतिशत कुपोषित बच्चों का देश है जहां हर वर्ष लगभग 25 लाख बच्चों की जान पोषण के अभाव में चली जाती है। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में शुमार भारत में कुपोषण की दर लगभग 55 फीसद है जबकि उप सहारा अफ्रीका के देशों में यह 27 फीसद है। अतः यह आंकड़ा हमारी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करता है। हम खाद्यान्न एवं दुग्ध उत्पादन में शिखर पर खड़े तो हैं, लेकिन यहां विश्व के 25 प्रतिशत भूखे लोग भी निवास करते हैं जो दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी का महज 1.2 फीसद ही खर्च करती है जो दुनिया भर के देशों द्वारा इस मद में खर्च की जाने वाली रकम के लिहाज से औसतन बहुत कम है। यहां तक कि अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्रों में भी यह प्रतिशत 1.7 के आसपास है।

विश्व के 27 प्रतिशत कुपोषित लोग भारत में रहते हैं। अभी भी भारत की आबादी का करीब एक चौथाई हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए विवश है। कुपोषण की दयनीय स्थिति के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। मसलन पोषण कार्यक्रमों का उचित क्रियान्वयन न होना, हमारी सरकारों द्वारा गरीबी और बेरोजगारी की उपेक्षा करना, मनरेगा जैसे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार इत्यादि। इसके अलावा गोदामों में रखा पांच करोड़ टन अनाज बिना गरीबों तक पहुंचे सड़ जाता है, लेकिन जरूरतमंदों को नसीब नहीं हो पाता। सवाल ये है कि आखिर हमारी सरकार इन जरूरतमंदों के प्रति इतनी निष्क्रिय क्यों है? प्रक्रियाओं को इतना सुलभ क्यों नहीं बनाया जाता कि गरीबों तक अनाज आसानी से पहुंच सके? फिर यहां पर एक बड़ा प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि कुपोषण की भयावह होती तस्वीर के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है?

कुपोषण की इस भयावह तस्वीर को बदलने के लिए संजीदगी से कोशिश करने की जरूरत है। मसलन आइसीडीएस (पोषण से जुड़ी एकीकृत बाल विकास सेवाएं), पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), मनरेगा (रोजगार) आदि योजनाओं के उचित क्रियान्वयन की जरूरत है। हमें यह भी समझना होगा कि कुपोषण एक जटिल समस्या है और इसका सीधा संबंध कुपोषित बच्चों के परिवारों की आजीविका से भी है। वास्तव में जब तक गरीब परिवारों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है तो कुपोषण मिटाना नामुमकिन है। लिहाजा कुपोषण की पहचान वाले परिवारों को जनवितरण प्रणाली एवं मनरेगा के तहत सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। पोषण पुनर्वास केंद्रों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपयुक्त उपकरण एवं पर्याप्त संख्या में बेड का प्रबंध करना आवश्यक है। साथ ही बाल विशेषज्ञों की उचित तैनाती पर बल देना भी जरूरी है।

इससे इतर देखें तो हालिया कई रिपोर्ट में देश की बेरोजगारी दर को उच्च स्तर पर बताया गया है। लिहाजा सरकार को रोगजार सृजन के लिए विशेष पहल करने की जरूरत है। इससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सकेगी जिससे जीवन-स्तर में सुधार होगा। शिक्षा की दशा सुधारने की जरूरत है ताकि कम उम्र बाल विवाह को रोक कर बच्चों को कुपोषित होने से बचाया जा सके। इसके अलावा, रोटी बैंक की संकल्पना को अमलीजामा पहनाने से भी इस समस्या को कम किया जा सकता है। देश के कई चुनिंदा शहरों में इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन इसे व्यापक पैमाने पर अपनाने की जरूरत है।

बच्चों में बढ़ाना होगा सुपोषण का दायरा

अलका आर्य
सामाजिक कार्यकर्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार 'मन की बात' में देश के बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने वाले विषय पर अपनी राय व्यक्त की है। प्रधानमंत्री की चिंता वाजिब भी है, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य पर एक निगाह डालें तो नए आंकड़े सचेत करते हैं कि देश को कुपोषण के खात्मे के लिए अपने प्रयासों में निरंतरता और गुणवत्ता को बढ़ाना होगा। हाल ही में यूनिसेफ ने 20 वर्षों बाद बाल पोषण पर एक रिपोर्ट जारी की है, जो बताती है कि भारत में हर दूसरा बच्चा किसी न किसी रूप में कुपोषित है। विश्व में पांच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में तीन में से एक बच्चा कुपोषित है, यानी ऐसे बच्चे या तो अल्पपोषित हैं या मोटे हैं। दो वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में करीब एक तिहाई बच्चे खराब आहार पर जीवित हैं और उन्हें ऐसा भोजन नहीं खिलाया जा रहा जो उनके शरीर व दिमाग को तेजी से विकसित करने में मददगार हो। भारत में 35 प्रतिशत बच्चे नाटे कद के हैं, 17 प्रतिशत बच्चे कद के हिसाब से पतले हैं, जबकि 33 प्रतिशत बच्चों का वजन कम है। बच्चों की स्थिति पर यह रिपोर्ट आगाह करती है कि कुपोषण के खात्मे के लिए खराब खान-पान की आदतों में सुधार करना बहुत जरूरी है। अब ऐसे बच्चे भी कुपोषित माने जाने लगे हैं जिनका वजन अधिक है या मोटापे से ग्रस्त हैं।

खराब आहार विश्व भर में बच्चों के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा रहा है। गरीबी, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और भोजन संबंधी खराब चयन अस्वस्थ यानी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले आहार की ओर ले जा रहे हैं। घटिया भोजन के नतीजे भुगतने वाले बच्चों की संख्या चिंताजनक है। विश्व भर में पांच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में 50 प्रतिशत बच्चों में जरूरी विटामिन और पोषक तत्वों की कमी है। हमें यह समझना होगा कि बच्चों के कुपोषण का दूरगामी प्रभाव पड़ता है। अनेक शोध रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि इंसान के दिमाग का 90 प्रतिशत विकास उसकी जिंदगी के पहले एक हजार दिनों में होता है। यह वही अहम दौर होता है जब यह तय हो जाता है कि कोई कैसे सोचेगा व क्या महसूस करेगा और अपनी बाल्यावस्था से लेकर बड़े होने तक क्या सीखेगा। अगर शिशु की खुराक उसके शरीर और दिमाग को तेजी से विकसित करने वाली नहीं है तो उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। ऐसे बच्चों में सीखने में कमजोर रहने, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता और बहुत से मामलों में मौत का जोखिम बना रहता है।

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में पहला समग्र राष्ट्रीय पोषण सर्वे जारी किया है जिसमें वर्ष 2016-18 के दौरान देश के 30 राज्यों व केंद्रशासित राज्यों में 19 वर्ष तक की उम्र के 1,12,000 बच्चों का मूल्यांकन किया गया था। यह राष्ट्रीय सर्वे बताता है कि सुपोषण की दिशा में कुछ हद तक प्रगति हुई है। इस सर्वे में यह बात सामने आई है कि 10-19 वर्ष आयुवर्ग में हर चौथा किशोर अपनी आयु के हिसाब से पतला है। इसी आयुवर्ग के पांच प्रतिशत किशोरों का वजन अधिक है या मोटे हैं। मुल्क में एक से चार वर्ष आयुवर्ग के 41 प्रतिशत बच्चे अनीमिक हैं। 10-19 वर्ष आयुवर्ग की 40 प्रतिशत किशोरियां अनीमिक हैं जबकि इसी आयुवर्ग के 18 प्रतिशत किशोर अनीमिक हैं। अनीमिया भारत के लिए चिंता का विषय है। देश के अधिकतर किशोरों को पर्याप्त पोषाहार नहीं मिलता है।

भारत में भोजन खपत संबंधी रुझानों से पता चलता है कि बाल आहार में प्रोटीन की बहुत कमी है और सूक्ष्मपोषक तत्वों की भी कमी है। कई दशकों से आय में वृद्धि होने के बावजूद प्रोटीन आधारित कैलोरी कम ही है। इस संदर्भ में भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि डॉ. यासमिन अली हक कहती हैं कि जब सेहतमंद विकल्प उपलब्ध हों और ये किफायती हों तो बच्चे व परिवार बेहतर भोजन का चयन करते हैं। सभी बच्चों तक पौष्टिक, सुरक्षित, किफायती आहार पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता में शुमार होना चाहिए व सरकार ऐसी कार्रवाई करती नजर भी आनी चाहिए और बच्चे, किशोर इसकी जद से बाहर आते दिखाई दें।

खरी-खरी

साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे...

शशांक दुबे

जैसे ही पत्नी दिवाली की सफाई की पेशकश करती है, अपन मुंह फुला लेते हैं। पहले तो अपन टालने के लिए कहते हैं, रविवार को तो काका आ रहे हैं टाइप। पत्नी भी कम नहीं, सभी टालने वाली समस्याओं का हल निकाल देती हैं। फिर हम पुरानी चादर को चिदंबरम मार्का लुंगी की शक्ल देकर महमूद की तरह लपेटते हैं और मय झाड़ू के तैयार हो जाते हैं। इतना बड़ा घर, कहां-कहां सफाई करें? हमें पहली बार थ्रीबीएचके लेने का अफसोस होता है और वनबीएचके वाले संसार के सबसे सुखी प्राणी लगते हैं। कहां-कहां झाड़ू मारें? यह वैसा ही यक्ष प्रश्न है, जैसा ज्यादा बाल वाले कस्टमर को देख सैलून वाले के मन में आता होगा, कहां पर कैंची बजाएं और कहां कंघी फिराएं?

खैर छोड़िये आखिर हम पोहे फंसाते हैं, चाय सुड़कते हैं और पलंग का गद्दा हटाकर उस पर कुर्सी रखकर पत्नी के कंधे पर हाथ रख दीवार के भीतर खास तौर से सामान रखने के लिए बनाए गए स्थान में मुंडी घुसेड़ते हैं। मुंडी अंदर डालते ही हमारी चीख निकल जाती है, जिसे सुन पत्नी के हाथ कांपते हैं, कुर्सी लुढ़क जाती है। लेकिन 'राम जिसे राखे, उन्हें कौन चाखे?' हम फिर भी बाल-बाल बच जाते हैं।

'क्या यार पापा! आप भी मम्मी की तरह छिपकली से डरते हो!' ऐसा बेटी बन्नू कहती है। हम डर के मारे एलान करते हैं, इस साल इस जगह की सफाई कैंसल, सिर्फ पंखे, अलमारी और ट्रॉफियां ही साफ करेंगे। हम एक ट्रॉफी उठाते हैं और कॉलोनी के क्लब वालों को कठिन डिजाइन वाली ट्रॉफी बनाने के लिए कोसते हुए रुमाल की भोंगली बनाकर नटराज की मूर्ति की बांहों में रुमाल का आवन-जावन करने लगते हैं।

तभी घाटे में चल रहा लैंडलाइन घनघनाता है। हम चोंगा उठाकर लुढ़की हुई कुर्सी को सीधी कर उस पर तशरीफ रखते हैं और बेखयाली में पेट पर हाथ घुमाते-घुमाते, बनियान के छेद को क्रमशः बढ़ाते हुए शहर में हालिया हुए प्रोग्राम की भद पीटने की असफल कोशिश करने लगते हैं। ऐसा करते-करते लंच टाइम हो जाता है। अब तक की प्रगति देख पत्नी हथियार डाल देती है, 'आप तो नहा लीजिए। बाकी सफाई कल रद्दी वाले सोमेश भैया के साथ मैं और बन्नू कर लेंगे। हम अनुशासित सिपाही की तरह तुरंत बाथरूम की ओर कूच करते हैं और फिर मस्त शॉवर में गुनगुनाते हैं, साथी हाथ बढ़ाना...साथी रे...!

ट्वीट-ट्वीट

पूर्व में 'हुआ- नहीं हुआ' की बहस को किनारे रख सरकार 'अब' यह तय करे कि भारत रत्न किन्हें दिया जाए। शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूं।
राज बब्बर@RajBabbarMP

हम सब जानते हैं कि कौन कमलेश तिवारी की मौत चाहता था। आखिर उसे सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? निश्चित तौर पर यह सुरक्षा में बड़ी चूक है। योगी सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हत्यारे जल्द से जल्द पकड़े जाएं।
शेफाली वैद्य@ShefVaidya

समस्या गांवों में ज्यादा है। एफएमसीजी यानी साबुन, शैंपू, बिस्किट जैसी चीजों की बिक्री सितंबर की तिमाही में पांच प्रतिशत की दर से बढ़ी। पिछले साल इसी तिमाही में यह 20 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी। सात साल में पहली बार शहरों के मुकाबले गांवों में बिक्री की ग्रोथ कम हुई है। बढ़ती बेरोजगारी इसकी वजह हो सकती है।
मिलिंद खांडेकर@milindkhandekar

मानसून प्रबंधन भी बने पाठ्यक्रम का हिस्सा

पंकज चतुर्वेदी
स्वतंत्र टिप्पणीकार

यह हम सभी जानते हैं कि भारत के लोक-जीवन, अर्थव्यवस्था, पर्व-त्योहार का मूल आधार मानसून का मिजाज है। कमजोर मानसून पूरे देश को सूना कर देता है। मानसून भारत के अस्तित्व की धुरी है। जो महानगर-शहर पूरे साल वायु प्रदूषण के कारण हल्कान रहते हैं, इसी मौसम में वहां के लोगों को सांस लेने को साफ हवा मिलती है। खेती-हरियाली और साल भर के जल का जुगाड़ इसी बरसात पर निर्भर है। इसके बावजूद जब प्रकृति अपना आशीर्वाद इन बूंदों के रूप में देती है तो समाज व सरकार इसे बड़े खलनायक के रूप में पेश करने लगते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे देश में मानसून को सम्मान करने की परंपरा समाप्त होती जा रही है- कारण है शहरों की ओर पलायन व गांवों का शहरीकरण।

विडंबना यह है कि हम अपनी जरूरतों के कुछ लीटर पानी को घटाने को तो राजी हैं, लेकिन मानसून से मिले जल को संरक्षित करने के मार्ग में खुद ही रोड़ अटकाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि नदी की अपनी याददाश्त होती है, वह दो सौ वर्षों तक अपने इलाके को भूलती नहीं। गौर से देखें तो आज जिन इलाकों में नदी से तबाही पर विलाप हो रहा है, वे सभी किसी नदी के बीते दो सदी के रास्ते में यह सोच कर बसा लिए गए कि अब तो नदी दूसरे रास्ते बह रही है, खाली जगह पर बस्ती बसा ली जाए। दिल्ली के पुराने खादर बीते पांच दशक में ओखला-जामिया नगर से लेकर गीता कालोनी, बुराड़ी जैसी घनी कालोनियों में बस गए और अब सरकार यमुना का पानी अपने घर में रोकने के लिए खादर बनाने की बात कर रही है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन व डिपो समेत अनेक नए निर्माण यमुना के क्षेत्र में बीते वर्षों के दौरान किए गए हैं।

बिहार में उन्नीसवीं सदी तक हिमालय से चल कर कोई छह हजार नदियां आती थीं जो संख्या आज घट कर बमुश्किल 600 रह गई है। मध्य प्रदेश में नर्मदा, बेतवा, काली सिंध आदि में लगातार पानी की गहराई घट रही है। दुखद है कि जब खेती, उद्योग और पेयजल की बढ़ती मांग के कारण जल संकट भयावह हो रहा है वहीं जल को सहेज कर रखने वाली नदियां उथली, गंदी और जल-हीन हो रही हैं।

देश में जहां-जहां नदियों की अविरल धारा को बांध बना कर रोका गया, उस क्षेत्र को इस वर्ष की बारिश ने जल-मग्न कर दिया। अभी तक बाढ़ के कारण संपत्ति के नुकसान का सटीक आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति जैसे सड़क आदि, खेतों में खड़ी फसल, मवेशी, मकान आदि की तबाही करोड़ो में है। सरदार सरोवर को पूरी क्षमता से भरने की जिद में उसके दरवाजे खोले नहीं गए जिससे मध्य प्रदेश के बड़वानी और धार जिले के 45 गांव पानी में डूब गए। राजस्थान के 810 बांधों में से 388 लबालब हो गए और जैसे ही उनके दरवाजे खोले गए तो नगर-कस्बे जलमग्न हो गए। राज्य के पांच बड़े बांध कोटा बैराज, राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर और माही बजाज के सभी गेट खोलने पड़े हैं। कोटा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ, झालावाड़ में बाढ़ के हालात बन गए। बारां, झालावाड़ में कई दिन स्कूल बंद रहे। कोटा में इससे व्यापक नुकसान हुआ। हर जगह पानी के प्रकोप का कारण बांध थे।

मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ते ही होशंगाबाद के तवा बांध के सभी 13 गेटों को 14-14 फुट खोल दिया गया और इसी के साथ कोई साढ़े तीन सौ किलोमीटर इलाके के खेत-बस्ती, सड़क सब पानी में डूब गए। आजाद भारत के पहले बड़े बांध भाखड़ा बांध के फ्लड गेट खोल कर जैसे ही करीब 63 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया, पंजाब व हिमाचल के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। दक्षिणी राज्यों, खासतौर पर केरल में लगातार दूसरे वर्ष बाढ़ के हालात के लिए पर्यावरणीय कारकों के अलावा बेतहाशा बांधों की भूमिका अब सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में गंगा व यमुना को जहां भी बांधने के प्रयास हुए, वहां इस बार जल-तबाही है।

हमारी नदियां उथली हैं और उनको अतिक्रमण के कारण संकरा किया गया। नदियों का अतिरिक्त पानी सहेजने वाले तालाब-बावली-कुएं नदारद हैं। फिर पानी सहेजने व उसके इस्तेमाल के लिए बनाए गए बांध, अरबों की लगात, दशकों के समय, विस्थापन के बाद भी थोड़ी सी बरसात को समेट नहीं पा रहे हैं।

असल में हम अपने मानसून के मिजाज, बदलते मौसम में बदलती बरसात, बरसात के जल को सहेज कर रखने के प्राकृतिक खजानों की रक्षा के प्रति न तो गंभीर हैं और न ही कुछ नया सीखना चाहते हैं। पूरा जल तंत्र महज भूजल पर टिका है, जबकि यह सर्वविदित तथ्य है कि भूजल पेयजल का सुरक्षित साधन नहीं है। मानसून अब केवल भूगोल या मौसम विज्ञान नहीं है, इससे बहुत कुछ जुड़ा है। मानसून-प्रबंधन का गहन अध्ययन हमारे स्कूलों से ले कर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में हो, जिसके तहत केवल मानसून से पानी ही नहीं, उससे जुड़ी फसलों, सड़कों, शहरों में बरसाती पानी के निकासी के माकूल प्रबंधों व संरक्षण जैसे अध्याय हों।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

वित्त मंत्री का कहना सही है कि बैंकों की दशा के लिए पूर्व की मनमोहन सरकार जिम्मेदार है?

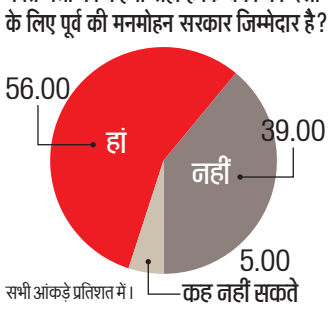

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या भारतीय इतिहास को फिर से लिखा जाना चाहिए?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

अल्टीमेटम दस मिलें नहीं पड़ेगा फर्क,
होना तय है पाक का अब तो बेड़ा गर्क।
अब तो बेड़ा गर्क न सुधरें मियां नियाजी,
भले हाथ से जाय पाक की पूरी बाजी।
ये है पाकिस्तान न होंगे आतंकी कम,
एफएटीएफ लाख उसे दे अल्टीमेटम।
– ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

डॉ. मोनिका शर्मा
स्वतंत्र टिप्पणीकार

सोशल मीडिया का हो सकारात्मक उपयोग

सोशल मीडिया का इस्तेमाल आजकल बहुत बढ़ गया है। सकारात्मक की बजाय इसका नकारात्मक इस्तेमाल अधिक हो रहा है, लेकिन हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे सीख ली जा सकती है और इसका सकारात्मक उपयोग बढ़ाया जा सकता है

हाल ही में बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य के अनेक हिस्सों में बारिश के बाद हुए भारी जलजमाव की विभीषिका में सोशल मीडिया के जरिये लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आए। घरों में फंसे लोगों की जानकारियां साझा करने से लेकर सहायता पहुंचाने तक, बड़ी संख्या में लोगों ने सोशल मीडिया का प्रभावी और सकारात्मक इस्तेमाल किया। कई लोगों को तो घरों से तब निकाला जा सका जब उन्होंने स्वयं के पानी से घिरे होने की खबर साझा की।

बीते दिनों सोशल मीडिया में ही वायरल एक वीडियो ने स्टेशन पर भीख मांगकर किसी तरह गुजारा करने वाली एक महिला का जीवन बदल दिया। पश्चिम बंगाल में एक रेलवे स्टेशन पर गाना गाने वाली इस महिला का एक शख्स ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया में ही बदली और निखरी छवि में लोगों को दिख रही यह महिला अब फिल्मी दुनिया के जाने माने संगीतकार के साथ अपने गाने रिकॉर्ड कर चुकी हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब सोशल मीडिया के ऐसे सकारात्मक और सार्थक इस्तेमाल की बानगी सामने आई है। इस मायावी दुनिया के माध्यम से कभी किसी परिवार से बिछड़े बच्चे को मिलवाने की तो कभी किसी प्रतिभा को मंच दिलवाने की खबरें भी आती रहती हैं। कुछ समय पहले महाराष्ट्र का एक किसान भी 'बालीराजा' नाम का वाट्सएप ग्रुप बनाकर चर्चा में आया था। इस वाट्सएप ग्रुप में उनके साथ महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई किसान भी जुड़े हैं। इस ग्रुप के जरिये खेती-किसानी से जुड़ी नई तकनीकों और जानकारियों का लाभ किसानों को मिल रहा है।

साहित्य से जुड़े संवाद से लेकर गृहणियों की रोजमर्रा की समस्याओं तक के लिए फेसबुक और वाट्सएप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई समूह बने हुए हैं जहां सकारात्मक संवाद होता है। जरूरी सूचनाएं साझा की जाती हैं, अपने अनुभव साझा कर एक-दूसरे को मार्गदर्शन दिया जाता है। इससे स्वयं तक सिमटे कितने ही लोगों का हुनर देश-दुनिया तक पहुंचता है।

तकनीक जीवन को सुविधाजनक और सरल बनाने के लिए है। स्मार्ट गैजेट्स के जरिये यह सुविधा अब हमारी मुट्ठी में हैं। ऐसे में सूचनाओं को साझा करने और अपने विचार रखने की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले इन साधनों के इस्तेमाल करने का तरीका इसके सदुपयोग या दुरूपयोग को तय करता है। तकनीक से भी स्याह और उजला, दोनों ही पहलू जुड़े हुए हैं। इसे सनक बना लेने के खामियाजे भी हैं और आत्मनियंत्रण के साथ सदुपयोग करने के सकारात्मक परिणाम भी। ऐसे में हमारे देश में सोशल मीडिया के सार्थक इस्तेमाल को लेकर वाकई सोचने की दरकार है। आजाद अभिव्यक्ति के नाम पर हर सीमा को पार करते हुए कुछ भी कहने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा आजकल सोशल मीडिया में देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया के अधिकतर मंचों पर अभिव्यक्त विचार अब घृणा और उपहास करने वाले भावों से सराबोर नजर आने लगे हैं। जिम्मेदार अभिव्यक्ति के बजाय ये मंच असामाजिक और अविश्वसनीय बातों का अड्डा बन रहे हैं। कभी लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के रूप में अस्तित्व में आए ये साझा मंच आज अराजक चरित्र वाले माध्यम बन गए हैं जिसके चलते अभिव्यक्ति अब कोलाहल बन रही है। दुनिया से जोड़ने वाल यह माध्यम अपनों से ही दूर कर रहा है।

प्रतीकात्मक

दरअसल सोशल मीडिया ने इस संसार के लिए 'ग्लोबल विलेज' की अवधारणा को वाकई एक हकीकत बना दिया है। क्लिक भर में खबरें, तस्वीरें और जानकारियां दुनिया भर में पहुंच जाती हैं। भारत में भी आज 20 करोड़ से ज्यादा वाट्सएप यूजर सक्रिय हैं। हमारे यहां हर हफ्ते यूजर्स का औसतन 17 घंटे का समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बीत रहा है जिनमें ट्विटर, फेसबुक, वाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे कई मंच शामिल हैं। 'ग्लोबल वेब इंडेक्स' की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में जितने लोग सोशल मीडिया पर समय बिता रहे हैं उनमें से 85 फीसद फेसबुक पर हैं। यूट्यूब इस मामले में दूसरे नंबर पर है। कमोबेश हर आभासी मंच के जरिये हजारों भ्रामक वीडियो आए दिन लोगों तक पहुंचते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दुनिया के 22 देशों में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक 64 फीसद भारतीयों को फर्जी खबरों का सामना करना पड़ता है। वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 57 प्रतिशत है। अफसोस कि हर हाथ में मौजूद स्मार्टफोन और सस्ते डाटा के चलते यह समस्या और बढ़ ही रही है। सोशल मीडिया की वजह से अपराध भी बढ़ रहे हैं और अकेलापन भी। ऐसे में इन मंचों का सकारात्मक इस्तेमाल एक नई उम्मीद जगाता है।

अफसोस कि हालिया बरसों में सोशल मीडिया केवल फर्जी समाचार फैलाने, द्वेष भरी टिप्पणियां करने और किसी की व्यक्तिगत छवि बिगाड़ने के लिए ही सुर्खियों में आया। यहां साझा की जाने वाली चीजों के साथ एक उन्माद भी जुड़ गया जिसके चलते ना किसी की निजता का मान करने की सोच रही और ना ही अफवाहें फैलाने से पहले सोचने-समझने की दरकार। सोशल मीडिया ऐसी सामग्री का अड्डा बन रहा है जहां फैली नकारात्मक खबरें समाज में खून-खराबे का कारण तक बन रही हैं। वाट्सएप पर फैली बच्चा चोरी की अफवाहों के चलते कई लोगों की जान ले गई है। आधारहीन संदेह के कारण अब तक कई निर्दोष अपनी जान गवां चुके हैं। अफसोस कि आभासी दुनिया में फैली ऐसी अफवाहों पर लोग विश्वास भी कर लेते हैं। बिना किसी प्रामाणिक जानकारी के सोच-समझ खोकर भीड़ बन पीड़ित लोगों पर टूट पड़ते हैं, जबकि सोशल मीडिया केवल नकारात्मक खबरें फैलाने और अजब-गजब हरकतें कर प्रसिद्धि पाने का जरिया भर नहीं, बशर्ते इसका सही इस्तेमाल किया जाय। ऐसे में गिनती की ही सही, पर ऐसी खबरें वाकई सुकूनदाई हैं कि इन आभासी मंचों के जरिये बेहतरी लाने वाले प्रयास भी किए जा सकते हैं। एक वायरल वीडियो किसी का जीवन संवार सकता है। दूरदराज के गांवों में बैठे किसान कृषि से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। कोई गृहिणी अपने घर से काम करते हुए उसका प्रचार-प्रसार कर सकती है। किसी की प्रतिभा को पहचान मिल सकती है। प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों तक सही जानकारी और मदद पहुंच सकती है।

10 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर सिर्फ पांच घंटे 16 मिनट में बन गए हॉलीवुड अभिनेत्री जेनिफर एनिस्टन के। इस सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर सबसे तेज 10 लाख फॉलोअर्स बनाने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम दर्ज किया।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 19 अक्टूबर 2019

नक्सलगढ़ के बच्चे गोलियां नहीं, दागते हैं दनादन गोल

फुटबॉल खेलते नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे। नईदुनिया

अजमत अली, भिलाई

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र रावघाट और इसके आसपास के 64 गांवों के बच्चों की खेल प्रतिभा को भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) निखार रहा है। यहां के 40 से अधिक बच्चे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और खो-खो में राष्ट्रीय स्तर पर रहे हैं।

जंगल में करीब 40 किलोमीटर अंदर रहने वाले जो बच्चे पहले इन खेलों के बारे में जानते तक नहीं थे, अब गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक जीत रहे हैं। हाल ही में यहां के बच्चों ने शालेय वॉलीबॉल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है। संतोष ट्रॉफी के लिए भी इनका चयन हुआ है। बीएसपी का उद्देश्य क्षेत्र का विकास और शिक्षा व खेल के जरिये इन बच्चों को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाना है, जिससे वे मुख्यधारा से भटकें ना। नक्सलगढ़ से निकले ये बच्चे आज गोलियां नहीं, मैदान में दनादन गोल दागते हैं तो हर किसी का सीना चौड़ा हो जाता है। बीएसपी ने वर्ष 2006 से नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम मैदान में खेल मेला आयोजित करना शुरू किया था। यह सिलसिला अब भी जारी है। यहां विभिन्न खेलों में आठवीं से 12वीं तक की कक्षाओं से निकली प्रतिभाओं को वह गोद ले लेता है। इसके बाद उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण, रहना-खाना सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध कराता है। खेल में आगे बढ़ने पर नौकरी के रास्ते भी निकल आते हैं।

दो हजार खिलाड़ियों में करीब 600 बेटियां : वर्तमान में दो हजार से ज्यादा स्कूली खिलाड़ियों में करीब 600 बेटियां हैं, जो एथलेटिक्स और फुटबॉल में प्रतिभा दिखा रही हैं। बीएसपी इन पर सालाना करीब 30 लाख रुपये खर्च करता है। 17 वर्षीय सुरेश कुमार फुटबॉल का स्टार खिलाड़ी है। एशियन स्कूल गेम्स में इंडिया टीम में अपना लोहा मनवाने पर सिक्किम यूनाइटेड टीम ने उससे कांट्रैक्ट किया है। इस बार छत्तीसगढ़ से संतोष ट्रॉफी में वह खेला है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल सुब्रतो कप में भी उसने दनादन गोल दागे हैं।

बीएसपी इसलिए चला रहा मुहिम : रावघाट में लौह अयस्क खदानें हैं, जिन्हें करीब 50 साल तक खनन के लिए बीएसपी ने लीज पर ले रखा है। खनन शुरू करने से पहले वह यहां की तस्वीर बदलना चाहता है। यहां के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है, जिससे कि समाज की मुख्यधारा से भटककर वह नक्सलवाद की राह पर न बढ़ें।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

जागरण विशेष

- छत्तीसगढ़ में 64 गांवों के बच्चों की खेल प्रतिभा को निखार रहा बीएसपी
- बच्चे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन आदि खेलों में मनवा रहे अपनी प्रतिभा का लोहा

रावघाट में भिलाई इस्पात संयंत्र खनन शुरू करने वाला है। इससे जहां देश को मजबूती मिलेगी, वहीं क्षेत्र का विकास भी होगा। बीएसपी की मुहिम रंग ला रही है और खेल के क्षेत्र में प्रतिभाएं निखर रही हैं। खेल के लिए बीएसपी पूरी तरह से मदद करता रहेगा।

-अनिर्बान दास गुप्ता, सीईओ, बीएसपी

नक्सलियों ने पिता को उतारा था मौत के घाट

वर्ष 2004 में बीजापुर के भैरमगढ़ तहसील के सरपंच और एक अन्य की हत्या नक्सलियों ने की थी। मां ने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उन्हें वनवासी आश्रम भेज दिया। बीएसपी के राजहरा स्थित आश्रम में मनोज करताम, अर्जुन कर्मा और जयराम कर्मा को रखकर पढ़ाया जा रहा था। वर्ष 2015 में इन्हें सेल अकादमी में रखा गया। जयराम बीजापुर लौटकर शिक्षा की रोशनी फैला रहा है। अर्जुन सेल अकादमी में हैमर थ्रो में अंतरराष्ट्रीय पदक लाने की तैयारी कर रहा है। मनोज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) में तैयारियों में जुटा है। नक्सल प्रभावित इन बच्चों के नाम 15 से ज्यादा नेशनल खेलने की उपलब्धियां हैं।

चिंताजनक ▶ प्रयागराज में गत 22 जुलाई को खुले उप्र के पहले मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र में आए सबसे ज्यादा युवा

मोबाइल की लत के शिकार 90 फीसद युवा

पिछले दो माह में पहुंचे 210 मोबाइल मनोरोगी

मनीष मिश्र, प्रयागराज

स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल युवाओं को मनोरोगी बना रहा है। इसकी वजह से काफी संख्या में लोग नोमोफोबिया की गिरफ्त में आ गए हैं। इससे परेशान अभिभावक अपने बच्चों की इस लत को छुड़ाने के लिए मनोचिकित्सक से सलाह ले रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मंडलीय (काल्विन) अस्पताल में खुले मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र के आंकड़े पर गौर करें तो 90 फीसद युवक और युवतियां मोबाइल की दुनिया में खो चुके हैं। 22 जुलाई 2019 को काल्विन अस्पताल में प्रदेश का इकलौता मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र खुला। यहां सिर्फ ऐसे लोगों का इलाज होता है जो नोमोफोबिया नामक मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। करीब दो माह के आंकड़ों को देखा जाए तो यहां 210 लोग पहुंचे। इसमें 90 फीसद 12 से 25 साल की उम्र के हैं।

सभी गेम, चैटिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल सबसे अधिक करते हैं। बाकी अधिक उम्र के आए, जो खुद मोबाइल से दूर होने के बारे में सलाह लेने पहुंचे।

प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मंडलीय अस्पताल के मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र में छात्रा को मोबाइल से दूरी बनाने के लिए टिप्स देते मनोचिकित्सक। जागरण

केस एक : एक छात्र नैनी स्थित एक निजी संस्थान से बीटेक कर रहा है। शिक्षक पिता का यह बेटा पढ़ाई में कमजोर था। अन्य छात्रों के जरिये अभिभावक को यह जानकारी हुई कि वह हमेशा मोबाइल में व्यस्त रहता है। समझाने पर भी कोई असर नहीं हुआ। मना करने पर अभिभावकों से मारपीट करने लगा। ऐसे में अभिभावक उसे लेकर मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र पहुंचे। यहां साइकोथेरेपी व बायो फीडबैक मशीन का सहारा लेकर उसे इस लत से निजात दिलाया जा सका। अब उसने मोबाइल से कुछ दूरी बना ली है।

केस दो : एक छात्रा नोमोफोबिया की गिरफ्त में थी। कॉलेज हो या घर, हर जगह मोबाइल में ही खोई रहती थी। एक दिन घर में जब मोबाइल से दूरी बनाने के लिए अधिक सख्ती बरती गई तो वह घर से ही गायब हो गई। दूसरे दिन अपनी सहेली के घर पर मिली। अभिभावक उसे मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र ले गए। उसकी काउंसिलिंग कर साइकोथेरेपी के माध्यम से इलाज किया गया। अब पहले की अपेक्षा वह ठीक है।

विशेषज्ञों का क्या है कहना

मनोचिकित्सक परामर्शदाता डॉ. राकेश पासवान ने बताया कि मोबाइल का नशा बच्चों व युवाओं के दिमाग पर नकारात्मक भाव पैदा कर रहा है। बच्चों के लिए व्यावहारिक संशोधन तकनीक व बड़ों के लिए संज्ञात्मक व्यावहारिक थेरेपी की मदद ली जाती है। आवश्यकता पड़ने पर बायो फीडबैक मशीन का भी सहारा लिया जाता है।

क्या है नोमोफोबिया

स्मार्टफोन की लत को नोमोफोबिया कहते हैं। यह इस बात का फोबिया (डर) है कि कहीं आपका फोन खो न जाए या आपको उसके बिना न रहना पड़े। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को 'नोमोफोब' कहा जाता है। नोमोफोबिया हमारे शरीर के साथ-साथ हमारे दिमागी सेहत को भी प्रभावित करता है।

मोबाइल की लत के अन्य नुकसान

कंप्यूटर विजन सिंड्रोम
मोबाइल स्क्रीन देखते समय लोग आंखें सिकोड़ते हैं। इससे आंखें सूखने और धुंधला दिखने की समस्या हो जाती है। इसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहा जाता है।

रीढ़ की हड्डी पर असर
लगातार स्मार्टफोन का उपयोग करने पर कंधे और गर्दन झुके रहते हैं। इस वजह से रीढ़ की हड्डी प्रभावित होने लगती है और दर्द की शिकायत रहती है। साथ ही मोबाइल स्क्रीन पर लगातार नजरें गड़ाए रखने वालों को गर्दन के दर्द की शिकायत भी आम है।

मथुरा में कात्यायनी मंदिर में अब पूजा-पाठ का भी शुल्क

जागरण संवाददाता, मथुरा : मथुरा के प्राचीन सिद्धपीठ कात्यायनी मंदिर में साधकों को अब साधना करने पर शुल्क अदा करना पड़ेगा। मंदिर में पाठ-पूजा, जप-अनुष्ठान पर ट्रस्ट ने शुल्क तय कर दिया है। प्रबंधन इसे आज की जरूरत बता रहा है, तो भक्त और संत समाज ने फैसले की निंदा की है। संत इसे श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ बता रहे हैं। प्राचीन कात्यायनी पीठ भारत के अज्ञात 108 व ज्ञात 51 पीठों में एक प्राचीन सिद्धपीठ है। स्वामी केशवानंद द्वारा स्थापित कात्यायनी मंदिर में ट्रस्ट ने नोटिस जारी कर पूजा-पाठ, जप-अनुष्ठान पर शुल्क तय कर दिया। मंदिर प्रबंधक विजय मिश्र का कहना है कि ट्रस्टियों के निर्णय को लागू करना उनकी मजबूरी है।

ये तय हुए शुल्क : ट्रस्ट द्वारा तय किए गए शुल्क में मंडप में पूजा, पाठ, जप, हवन के लिए 1100 से 5100 रुपये, शतचंडी अनुष्ठान को 11 हजार से 31 हजार, कथा आयोजन के लिए 51 हजार, एक दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 11 हजार, एक दिन का पाठ-जप एक ब्राह्मण पर 500 से 1100 रुपये, एक से अधिक दिन के लिए 11 हजार से 31 हजार रुपये, रुद्राभिषेक के लिए 5100 रुपये, एक दिवसीय अनुष्ठान 500 से 1100, एक दिन से अधिक 11 हजार से 31 हजार, लंबे समय तक चलने वाले अनुष्ठान के लिए 5100 रुपये प्रतिमाह देने होंगे।

अंत्योदय की खातिर 'ग्राम उदय'

अरविंद सिंह, अंबेडकर नगर

- दुनिया के बाजार में उलझे फिर भी नहीं भूले अपना गांव
- शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और युवाओं के लिए बनीं अलग-अलग समितियां

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर मानिकपुर गांव में भी दूसरे गांवों की तरह तमाम समस्याएं थीं, लेकिन अब अंत्योदय के खातिर यहां 'ग्राम उदय' हो रहा है। अब इस गांव में देसी-विदेशी पुस्तकों से समृद्ध लाइब्रेरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहित युवाओं की मदद के लिए अलग-अलग समितियां भी हैं। यह किसी सरकारी सहयोग से नहीं हुआ, बल्कि यह सब कुछ यहां के लोगों ने ही किया है।

सुशिक्षित समाज

यहां के लोग दुनिया के बाजार में उलझे, मगर अपने गांव को नहीं भूले। इंग्लैंड में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरिजेश सिंह की पुणे में इंडस्ट्री जमा चुके दोस्त पंकज और लखनऊ में तैनात अग्निशमन अधिकारी विजय सिंह से बात होती तो गांव की चर्चा जरूर चलती। हालचाल गांव के हालात पर आकर ठहरता तो इसे बदलने की कसक इनके मन में उठती। इसी के चलते एक दिन गिरिजेश ने दोनों मित्रों से 'ग्राम उदय' पर चर्चा की। 2015 में तीनों दोस्त गांव में वरिष्ठों और युवाओं के साथ इस पर बात करने बैठे। सबने इनकी सोच का साथ दिया और दिसंबर 2016 में शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा कल्याण और खेती के उत्थान के लिए समितियां गठित हो गईं। इनका जिम्मा गांव में मौजूद लोग संभालते हैं। गांव से दूर रहने वाले संसाधन जुटाने के साथ कीमती सुझाव देते हैं। प्रोफेसर, प्राचार्य, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, सैनिक जैसे पदों पर तैनात गांव के विभिन्न लोग इस तरह से वहां के अंतिम व्यक्ति के विकास में योगदान कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर मानिकपुर गांव में योग कराते समिति के सदस्य। जागरण

कृषि समिति के सदस्य केले की फसल को बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था करते हुए। जागरण

गिरिजेश के पिता अवध बिहारी और चाचा नवल बिहारी उनकी मंशा से प्रभावित हुए और घर दान दे दिया। यहां लाइब्रेरी खुली तो देश-विदेश में रह रहे गांव के युवाओं ने किताबें भेजकर इसे समृद्ध कर दिया। इस अध्ययन केंद्र का संचालन शिक्षा समिति करती है। इसमें गांव के रिटायर शिक्षक मुफ्त पढ़ाते हैं। बच्चों का सामूहिक जन्मदिन मनाया जाता है। प्रतिवर्ष ग्राम उदय वार्षिकोत्सव में मेधावियों का सम्मान होता है। गांव के प्राथमिक विद्यालय को आपसी सहयोग से सजाया गया है। सुबह योग समिति यहां योग कराती है। इसमें बच्चे, महिलाएं युवा और बुजुर्ग तक प्राणायाम करते हैं। खेल समिति प्रतिभाओं को निखार रही है। युवा समिति के सदस्य पूर्व मेजर प्रमोद कुमार गांव में युवाओं को सेना में भर्ती होने का प्रशिक्षण देते हैं। कृषि समिति कम लागत में खेती के तरीके बताने के साथ उत्पाद को उचित बाजार भी मुहैया कराने में मदद करती है।

> कई देशों का भ्रमण किया, लोगों को काम करते देखा। लगा कि इससे अधिक मेहनती लोग हमारे गांव में हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन की कमी के चलते पिछड़े हैं। एक टीस यह भी थी कि जहां पढ़े-लिखे हैं वहां के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में 'ग्राम उदय' का विचार आया। ग्रामीणों को उनके प्रयास से आगे बढ़ने का अवसर देना ही मकसद है।
>
> -गिरिजेश सिंह (वाट्सएप पर बताया)

> गिरिजेश का विचार सुना तो गांव के लिए कुछ करने की इच्छा पूरी होती दिखी। भागमभाग से निकलकर गांव में पहुंचने के बाद जिंदगी भी खुशहाल लगने लगती है। बस यहां का पिछड़ापन मन को कचोटता रहा। हमारा प्रयास है कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार काम में दक्ष किया जाए, जिससे ग्राम उदय की मंशा सफल हो।
>
> -विजय सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

यहां लाखों रुपये में होती है फिल्मी सितारों के नाम वाले गधों की बिक्री

शिवा अवस्थी, चित्रकूट

प्रभु श्रीराम की तपोस्थली चित्रकूट में दीपावली पर नरक चौदस से तीन दिन तक मंदाकिनी तट पर गधों का ऐतिहासिक मेला लगता है। इसमें फिल्मी सितारों व नेताओं के नाम वाले गधे लाखों रुपये में खरीदे-बेचे जाते हैं। कई राज्यों से आए कारोबारी करोड़ों रुपये का कारोबार करते हैं।

अच्छी नस्ल खरीदने की होड़ : मुगल शासक औरंगजेब ने चित्रकूट में इस मेले की शुरुआत कराई थी। देशभर में सेना लेकर घूमते समय सैन्य बल के पास घोड़ों की कमी होने पर मेला लगाया गया था। इसमें अफगानिस्तान तक के गधे व खच्चर बिक्री के लिए आए थे। उनको मुगल सेना में शामिल किया गया था। उसके बाद से मेला लगने का क्रम जारी है।

यहां से आते क्रेता-विक्रेता: मेला में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड व नेपाल तक के कारोबारी व खरीदार आते हैं। बुंदेली सेना के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह के मुताबिक, नया गांव कस्बे के कटरा गूदर मैदान में लगने वाले मेले का कारोबारी साल भर इंतजार करते हैं।

- दीपावली पर नरक चौदस से शुरू होता तीन दिवसीय मेला
- देश के कई प्रांतों से आते हैं कारोबारी, दस करोड़ तक का होता है कारोबार

पांच लाख तक लग चुकी बोली : स्थानीय व्यापारी राजेश कुमार बताते हैं कि गधा मेले में व्यापारी काबुल में घोड़ा बिक्री की तर्ज पर बोली लगाते हैं। पिछले वर्षों में पांच लाख रुपये तक की बोली में गधे बिक चुके हैं।

फिल्मी सितारों के नाम

अंतरराज्यीय गधा मेला में फिल्मी सितारों के छद्म नाम रखकर गधों की बिक्री होती है। कुछ नेताओं पर भी नाम रखते हैं। व्यापारियों को रौनक, चांदनी, आरजू, महिमा, पारुल, नगीना व हिना जैसे नाम भी अच्छे लगते हैं। फिल्मी अभिनेत्रियों के नाम वाले गधों की मांग सबसे अधिक रहती है।

ईंट, मौरंग, बालू व गिट्टी ढोते हैं

कारोबारी गधों से संकरी गली में ईंट-मौरंग, गिट्टी और बालू ढोकर पहुंचाने का काम कराते हैं। कुछ अच्छी नस्ल के गधों को तांगा में भी इस्तेमाल करते हैं। एक गधा प्रतिदिन एक से डेढ़ हजार रुपये तक कमाई करता है, जबकि उस पर 250 रुपये खर्च होता है।

इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में सुलतानपुर का नाम

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर : सीड बम के जरिये पौधरोपण करने में उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जिले में 14 अगस्त को एक साथ 110 गांवों में 14 लाख 28 हजार 277 से अधिक सीड बमों की बौछार की गई थी। मकसद था पूरे जिले को हरियाली से युक्त करना। इससे पहले देश के किसी भी जिले ने यह रिकॉर्ड नहीं बनाया है। अब सुलतानपुर का नाम इस रिकॉर्ड के लिए एशिया बुक के लिए भी भेजा जा चुका है।

गोमती नदी के किनारे दोनों ओर 137 किलोमीटर क्षेत्र में व 110 गांवों में सीड बम की वर्षा कराई गई। सीड बम बनाने के लिए हजारों समाजसेवी संगठनों की लाखों महिलाओं व अन्य लोगों को जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद बीजयुक्त मिट्टी नुमा बम तैयार किए गए थे।

> इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के बाद अब इसे एशिया बुक के लिए भी भेज दिया गया है। दीपावली तक इसका प्रमाण पत्र मिल जाने की उम्मीद है।
>
> -निकुंज कुमार तोमर, ब्रांड एंबेसडर, स्वच्छ भारत अभियान

लुधियाना में दिखेगी एमएफ हुसैन की एक करोड़ रुपये की 'गजगामिनी'

जागरण संवाददाता, लुधियाना

- होटल हयात रिजेंसी में आज से लगेगी दो दिवसीय पेंटिंग प्रदर्शनी
- हरिद्वार के बाद पहली बार पंजाब के लुधियाना में होगा आयोजन

पेंटिंग की जब भी बात आती है तो एक कलाकार, जिनका नाम प्रमुखता से आता है वो हैं एमएफ हुसैन। पंजाब के लुधियाना में माशा आर्ट होटल हयात रिजेंसी में शनिवार से दो दिवसीय प्रदर्शनी में कई शानदार पेंटिंग्स प्रदर्शनी के लिए रखी जाएंगी। इसमें हुसैन की कई पेंटिंग शामिल होंगी। शुक्रवार को प्रदर्शनी का प्रिव्यू किया गया, जिसमें हुसैन की एलीफेंट सीरीज के तहत तैयार गजगामिनी पेंटिंग दिखाई गई। इस पेंटिंग की कीमत एक करोड़ रुपये बताई जा रही है। देहरादून के बाद पंजाब के लुधियाना में हुसैन की पेंटिंग को पहली बार प्रदर्शित का जाएंगी।

माशा आर्ट के सह-संस्थापक समर्थ माधुर और इशिता खेतरपाल ने बताया कि लुधियानवी दुनियाभर की सैर करते हैं। यहां के लोगों को आर्ट की समझ है, जिसके चलते प्रख्यात चित्रकारों की कला उनके सामने लेकर आए हैं। प्रदर्शनी में जो भी धनराशि अर्जित होगी, उसे हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन को दिया जाएगा।

एमएफ हुसैन की एक करोड़ रुपये की कीमत वाली पेंटिंग गजगामिनी के बारे में जानकारी देते समर्थ और इशिता। जागरण

इन कलाकारों की भी कलाकृतियां दिखाई जाएंगी : देश के अन्य प्रख्यात कलाकारों अमर सुल्तान, भास्कर राव, एसएच रजा, सतीश गुजराल, रमेश गोरजाला, चंद्राशेखर मोरकंडा की पेंटिंग्स भी प्रदर्शनी में देखने को मिलेंगी। प्रदर्शित होने वाली पेंटिंग्स की शुरुआत 20 हजार रुपये से है।

पीएम ऑफिस में भी लगी है कामधेनु पेंटिंग : प्रदर्शनी में रमेश गोरजाला की पेंटिंग भी रखी गई हैं। उनकी कामधेनु पेंटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस में भी लगी है। एक वेडिंग कार्ड में प्रधानमंत्री ने रमेश गोरजाला की कामधेनु पेंटिंग को देखा था, जिसके बाद वर्ष 2015 में रमेश ने उनके ऑफिस के लिए यह पेंटिंग तैयार की थी। कामधेनु पेंटिंग की कीमत करीब पांच लाख रुपये है।

बना रहे आत्मनिर्भर

विद्यालय में अवकाश के दौरान गांव-गांव जाकर देते हैं बच्चों को प्रशिक्षण, अभी तक एक हजार से अधिक बच्चों को क्राफ्ट सिखा चुके हैं उत्तराखंड के सहायक अध्यापक आशीष

बच्चों को कबाड़ से कलाकारी सिखा रहे गुरु जी

राजीव खत्री, पौड़ी

घर में पड़े कबाड़ को सुंदर वस्तुएं बनाने के उपयोग में कैसे लाया जाता है, यह सीख कोई उत्तराखंड के पौड़ी जिले के एकेश्वर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में तैनात सहायक अध्यापक आशीष नेगी से लें। वह स्कूल की छुट्टियों के दौरान यहां के गांव-गांव में घूमकर बच्चों को कूड़े का उपयोग करने की सीख दे रहे हैं। आशीष अब तक एक हजार से अधिक बच्चों को कबाड़ पर कलाकारी करना सिखा चुके हैं। उनके इस प्रेरणादायी कार्य को देखते हुए अब तक 20 अन्य शिक्षक भी उनके साथ जुड़ चुके हैं।

पौड़ी निवासी आशीष नेगी की वर्ष 2011 में जीआइसी एकेश्वर में कला विषय के सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हुई थी। उन्हें बचपन से ही पेंटिंग व क्राफ्ट का शौक रहा है। शिक्षक बनने के बाद उन्होंने अपने इस शौक को बच्चों तक पहुंचाने की ठानी।

आशीष बताते हैं कि क्राफ्ट रोजगार का बेहतर जरिया भी हो सकता है, इसलिए वह चाहते हैं कि बच्चे इस विधा में पारंगत हों। आशीष क्राफ्ट के प्रशिक्षण के लिए सरकारी विद्यालयों के छात्रों को चुनते हैं। कहते हैं, अधिकांश सरकारी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र पढ़ते हैं, जो महंगे संस्थानों में जाकर इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं ले सकते। हालांकि, उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उचित प्रशिक्षण न मिल पाने के कारण यह प्रतिभा उभरकर सामने नहीं आ पाती। इसलिए उनका ध्यान इन्हीं छात्रों पर होता है।

पौड़ी में बच्चों को बेकार की चीजों से क्राफ्ट बनाने का प्रशिक्षण देते शिक्षक आशीष। जागरण

रामलीला में निभाई भूमिका, रावण का पुतला बनाने में भी दिया सहयोग

आशीष पौड़ी शहर की ऐतिहासिक रामलीला में भी पूरी सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभाते हैं। आशीष यहां बतौर मेकअप आर्टिस्ट अपनी सेवाएं देते हैं। इस बार उन्होंने रामलीला में रावण का 42 फीट ऊंचा पुतला बनाने में भी सहयोग दिया।

अब तक देशभर में कर चुके हैं 650 से अधिक नुक्कड़ नाटक

आशीष रंगमंच के कलाकार भी हैं। वह एक नाट्य संस्था से जुड़कर अब तक देशभर में 650 से अधिक नुक्कड़ नाटक कर चुके हैं। साथ ही सरकारी विद्यालयों के छात्रों को भी रंगमंच के गुर सिखा रहे हैं।

पेंटिंग और थिएटर के गुर भी सिखाते हैं

आशीष अब तक सरकारी विद्यालयों के लगभग एक हजार छात्रों को क्राफ्ट का प्रशिक्षण दे चुके हैं। इसके अलावा वह बच्चों को पेंटिंग व थिएटर के गुर भी सिखा रहे हैं। बकौल आशीष, 'अब तक मेरे साथ 20 अन्य शिक्षक भी इस मुहिम में जुड़ चुके हैं। हम लोग महीने में एक बार कुछ धनराशि एकत्र कर किसी सरकारी विद्यालय में क्राफ्ट का प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं।'

छोटे स्टेशनों पर भी मिलेगी टिकट आरक्षण की सुविधा

प्रदीप चौरसिया, मुरादाबाद

- सर्वे शुरू, जनरल टिकट सिस्टम होगा अपग्रेड

रेलवे जल्द ही छोटे-छोटे स्टेशनों पर भी रिजर्वेशन टिकट उपलब्ध करने की सुविधा देने जा रहा है। इसके लिए जनरल टिकट सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। सर्वे शुरू हो गया है। इन स्टेशनों पर जनरल टिकट की बिक्री करने वाले कर्मचारी रिजर्वेशन टिकट भी बनाएंगे।

यात्री सुविधा पर रेलवे विशेष ध्यान दे रहा है। रेल प्रशासन ने मांग के आधार पर सभी श्रेणी के स्टेशनों पर जनरल टिकट के साथ आरक्षण टिकट देने की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। प्रथम चरण में मुख्य रेलमार्ग के स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध होनी है। हॉल्ट स्टेशनों पर मैनुअल टिकट के स्थान पर मशीन से टिकट मिलेंगे। प्रवर मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा ने बताया कि छोटे-छोटे स्टेशनों पर जनरल टिकट के साथ आरक्षण टिकट उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए सर्वे कराया जा रहा है। जहां आरक्षण टिकट की मांग होगी, वहीं यह सुविधा मिलेगी।

रेलवे स्टेशनों पर यह व्यवस्था कर रही काम : हॉल्ट को छोड़कर सभी स्टेशनों पर अनरिजर्व टिकट सिस्टम (यूटीएस) लगा हुआ है, जहां से जनरल टिकट मिलता है। क्लास ए वन और ए क्लास के स्टेशनों पर आरक्षण टिकट के लिए अलग से काउंटर है। मांग के आधार पर बी श्रेणी के कुछ स्टेशनों पर जनरल टिकट के साथ आरक्षण टिकट की व्यवस्था होगी। मुरादाबाद रेल मंडल में 151 रेलवे स्टेशन हैं। इसमें बी श्रेणी के 12 स्टेशनों पर जनरल के साथ आरक्षण टिकट देने की व्यवस्था है। सी श्रेणी के स्टेशनों पर आरक्षण टिकट देने की व्यवस्था नहीं है।

दैनिक जागरण

सबरंग

शहर को जानने के...

नई दिल्ली, शनिवार, 19 अक्टूबर, 2019

सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें : sabrang@nda.jagran.com

https://www.facebook.com/jagransabrang/

दिल्ली के मच्छरों से डर गए थे मुगल और गोरे भी

किस्सा किताबों से

यूं तो लोग अब बहुत साफ सफाई रखने लगे हैं और जागरूकता के कैंपेन भी खूब चलाए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हर सप्ताह अपने घर आंगन में सफाई कर डेंगू के मच्छर पनपने से बचने की अपील करते हैं। फिर भी दिल्ली मच्छरों से बेहद डरती है। लेकिन यह सब आज ही नहीं हो रहा मच्छरों के प्रकोप से तो मुगल और अंग्रेज भी भयभीत हो गए थे। इतिहासकार डॉ फैजान अहमद कहते हैं कि लालकिला के ठीक पीछे यमुना नदी बहती थी। वहीं एक तरफ पूरा रिज एरिया था। ऐसे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मच्छरों से परेशानी तो होती ही थी। लेकिन मच्छरों से परेशानी पर विशेष रूप से नहीं लिखा गया है। कुछ किताबों में इसका जिक्र मिलता है। मसलन, आइने अकबरी, अकबरनामा में लिखा गया है कि मच्छरों को भगाने की पूरी कोशिश की जाती थी। दवा, अर्क का छिड़काव किया जाता था। उस समय की परशियन किताबों में मच्छरों के भगाने के नुस्खे भी लिखे मिलते हैं। जैसे फूलों से जर्द बनाते थे, उसी तरह फूलों से मच्छर भगाने की चीजें भी इस्तेमाल की जाती थीं। दवाकुश बनाते थे। यही नहीं महलों में धुआं भी किया जाता था। बाकि हकीम थे ही जो इलाज करते थे। अब बात अंग्रेजों की करें तो जब 1857 में अंग्रेजों ने लालकिला पर कब्जा जमाया तो अंदर का नजारा देखकर वे परेशान हो गए। अंदर पानी आपूर्ति की नालियां और बाग थे। अंग्रेजों ने इन्हें मच्छर पनपने की दुरुस्त जगह मान बहुत बदलाव किया। इतना ही नहीं उन्होंने बहुत से भवन तोड़कर नए बनवाए। बकौल आरवी स्मिथ दिल्ली के भारत की आधिकारिक राजधानी बनने की घोषणा के बाद जब 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार हुआ जिसमें हजारों लोगों की भीड़ थी। तब ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी कि-हमें भारत की जनता को यह बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है कि सरकार और उसके मंत्रियों की सलाह पर देश को बेहतर ढंग से प्रशासित करने के लिए ब्रितानिया सरकार भारत की राजधानी को कलकत्ता (कोलकाता) से दिल्ली स्थानांतरित करती है। इस घोषणा के साथ ही दिल्ली इतिहास के एक अन्य अध्याय की तरफ अग्रसर हो गई। हालांकि इस फैसले की आलोचना भी हुई थी। द इंग्लिशमैन अखबार ने लगभग चेताते हुए लिखा कि जो दिल्ली जा रहे हैं वो दलदल, गर्मी, मच्छर, फोड़े, फुंसी, सांप, कीड़े से परेशान हो जाएंगे। आजादी से पहले लोग किस तरह मच्छरों से बचते थे। इसकी एक बानगी हर्बर्ट चार्ल्स फांसवे की किताब 'दिल्लीः पास्ट एंड प्रजेंट' में मिलती है। जिसमें वो आजादी के पहले दिल्लीवालों के रहन सहन को बड़ी संजीदगी से बयां करते हैं। वो लिखते हैं कि लोग पिकनिक मनाना पसंद करते थे। वहां रात भी गुजारते थे लोग। वह दृश्य बड़ा अद्भुत था। करीब एक साथ 20 बेड लगते थे। सभी बेड पर मच्छरदानी लगती थी। आर्किटेक्ट एके जैन कहते हैं कि कोलकाता से देश की राजधानी दिल्ली को बनाने के एलान के चार दिन बाद यानी 15 दिसंबर,1911 को जॉर्ज पंचम ने नई दिल्ली की नींव का पत्थर किंग्सवे कैंप, कोरेनेशन पार्क के पास में रखा। पहले भावी नई दिल्ली में वाइसराय आवास (अब राष्ट्रपति भवन) संसद भवन, साऊथ ब्लॉक, नार्थ ब्लॉक, कमांडर-इन चीफ आवास (तीन मूर्ति भवन) वगैरह का डिजाइन तैयार करने के लिए हेनरी वॉगन लैंकस्टर का नाम भी चल रहा था एडविन लुटियन के साथ, पर अंत में लुटियन को नई दिल्ली का मुख्य आर्किटेक्ट का पद सौंपा गया। एक कमेटी का गठन हुआ सन 1913 में। इसका नाम था 'दिल्ली टाउन प्लेनिंग कमेटी'। इसके प्रभारी एडविन लुटियन थे। लुटियन ने कोरेनेशन पार्क को भव्य राजधानी के लिहाज से खारिज कर दिया। उसने कहा कि यहां जगह कम है। मच्छर भी ज्यादा हैं। हालांकि यहां सचिवालय वगैरह बना दिए गए थे। इन्हीं भवन में वर्तमान दिल्ली विधानसभा है। बाद में लुटियन को रायसीना हिल्स पसंद आई। आजादी के बाद भी मच्छरों से बचने के लिए जागरूकता की अलख जगाई जाती रही।

रैंप पर सजेंगे शाहपुर के संस्कार

गांव की महिलाओं को रैंप पर चलते देखने का भी एक सुखद अनुभव होगा। वो भी दिल्ली के एक खास ठेठ जाट गांव...यानी शाहपुर जाट में। हालांकि इस गांव की पहचान...शक्ल सूरत ने अब फैशन का लिबास ओढ़ लिया है फिर भी यहां के कुछ घरों की दीवारें...पीढ़ियां परंपराओं को रिवायतों को सहेजे हुए हैं। बहरहाल हम इस गांव की चर्चा आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली सरकार यहां शरद उत्सव कराने जा रही है। कला-रीति परंपराओं के अलावे इस उत्सव की एक और खास बात गांव की बुजुर्ग महिलाओं का फैशन शो होगा। सबरंग के इस अंक में इस गांव की माटी...इतिहास और आयोजन स्थल से रूबरू करा रहे संजीव कुमार मिश्र :

शाहपुर जाट शरदोत्सव

गांव, शाहपुर जाट। इसके इतिहास में झांकेंगे तो 900 साल पहले, हरियाणा के इंद्री गांव का एक डागर कबीला शाहपुर जाट गांव स्थानांतरित हुआ। शाह माने (धन) पुर माने (कॉलोनी) और जाट माने एक कबीला...ऐसा तब कहा जाता था, जिसका विशुद्ध अर्थ हुआ अमीर जाटों का इलाका। यहां के कुछ हवेली नुमा घरों को देखकर ऐसी अनुभूति भी होती है। हालांकि अब छोटी-छोटी गलियों के भीतर बड़े-बड़े फैशन डिजाइनर के शोरूम बन गए हैं। सिने जगत बड़े ड्रेस डिजाइनर्स के डिजाइंस यहां मिल जाएंगे। बहरहाल गांव के इतिहास की परतों को पलटने से पहले आज से शुरू हो रहे आयोजन से रूबरू होते हैं जिसके लिए तोहफा वाला गुंबद परिसर में तैयारी हो रही है। सफाई हो चुकी है। पूरे गांव में उत्सव का माहौल नजर आता है। महिलाएं विशेष तैयारी में जुटी हैं आखिर उन्हें फैशन शो में हिस्सा जो लेना है। दिल्ली सरकार द्वारा मनाए जा रहे शरद उत्सव के लिए इस स्थान का चयन भी विशेष तौर भी किया गया है। चूंकि आयोजन में 14 वीं शताब्दी के स्मारक के खंडहरों की यात्रा से लेकर गांव के बुजुर्गों के साथ मॉडल के रूप में एक फैशन शो के रूप में छाप छोड़ने की तैयारी है। तभी तो उत्सव की टैगलाइन भी कुछ ऐसी है..."जब फैशन इतिहास से मिलता है"। शाहपुर जाट एक प्राचीन गांव है, जिसका दिलचस्प इतिहास है और वर्तमान में यह गांव फैशन हब के रूप में अतुलनीय पहचान बनाए हुए है। यह उत्सव इन दोनों का ही मिश्रण होगा।

ऐसी ही सजी है शाहपुर जाट की दर-ओ-दीवारें

तोहफा वाला गुंबद पर एक हेरिटेज वॉक कराई जाएगी जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान 1303 में निर्मित सिरी किले का एक हिस्सा था, साथ ही यहां एक दिवाली बाजार भी लगेगा। तोहफा वाला गुंबद के खंडहरों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित कर रहा है। इसका एक आयोजन इसी गुंबद के सामने वाले नगर निगम के पार्क में भी होगा। वॉक के अलावा दिवाली बाजार में गांव के ही कुम्हार, मूक बधिर और पारंपरिक बुनकरों के उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे।

कला और संस्कृति का संगम: शाहपुर जाट गांव की शान दिल्ली क्या देश-विदेश में सभी जगह एक अलग फैशन की छाप छोड़ती है। मुंबई से लेकर विदेश तक के लोगों की चहल-पहल यहां सामान्य है। चूंकि गलियों में कहीं बड़े बुटीक हैं और कहीं ब्रांडेड शोरूम। एक और खास बात आपको यहां दिखेगी यहां की सड़कों के नाम भी अद्भुत हैं दादा जंगी लेन, बॉलीवुड लेन, मेरे पास मां है लेन, स्क्वेयर रंगोली लेन, फैशन स्ट्रीट की सड़क आदि आदि। फैशन स्ट्रीट में प्रवेश करते ही मन नारंगी रंग में रंगने लगता है। गली की दोनों ओर नारंगी रंग में रंगी दीवारें आकर्षित करती हैं और यहां

घरों के दरवाजों को भी एंटीक लुक दिया गया है जिनमें बुटीक सजाए गए हैं। यहां तकरीबन सभी बुटीक के अपने खरीददार हैं। दो दिन इसी जगह न सिर्फ दिल्ली की बल्कि विदेशी पर्यटकों से भी शरद उत्सव की महफिल सजेगी। 19 अक्टूबर, शनिवार यानी आज हरियाणवी और पंजाबी लोकनृत्यों का आनंद होगा और हास्य कवि सुनील जोगी, स्टैंडअप कामेडियन संजय राजौरा दर्शकों को लोटपोट कर देंगे। वहीं रविवार को एक विशेष फैशन शो आयोजित होगा। बालीवुड सिंगर मोनाली ठाकुर की दिलकश आवाज भी सुनने को मिलेगी।

फैशन का धनी गांव: शाहपुर जाट गांव की दादा जंगी हाउस लेन में करीब 40 बुटीक हैं। इस लेन का नाम दादा जंगी सुन लोग चौंकते हैं और इसके बारे में जानने को उत्सुक होते हैं। बताते हैं कि यह नाम यहां रहने वाले दादा हेत राम के नाम पर पड़ा। दादा हेत राम ने कई लड़ाई लड़ीं। वे फौज में थे। इसलिए उनका नाम दादा जंगी रख दिया गया। इस लेन में अपना फैशन बुटीक चलाने वाली ईशा बताती हैं कि हर डिजाइनर की अपनी एक अलग पहचान होती है। वो उसी हिसाब से अपने डिजाइन तय करता है। लेकिन दुबई में ज्यादातर गाउन चलता है इसलिए यहां बड़ी तादाद में डिजाइनर गाउन तैयार किए जाते हैं। यहां की कॉलर वाली शर्ट, नेहरु कट वाली जैकेट, चाइनीज कॉलर, वेलवेट जैकेट, रॉयल हैरिटेज में जोधपुरी पैंट, बंद गले के शॉर्ट जैकेट, प्वाइंटेड बैली शूज खूब मशहूर हैं। शादी का अवसर हो या घर-दफ्तर का कोई और फंक्शन लोग यहां से शापिंग करना पसंद करते हैं। इसके अलावा सिल्क की साड़ियां, जामवार और ब्रोकेड, फ्यूजन के साथ ईवनिंग गाउन, ब्रोकेड और सिल्क की जैकेट मिक्स एंड मैच फैब्रिक के साथ, लांग लेंथ अनारकली, मिक्स एंड मैच श्रग्स, डिजिटल प्रिंट, शॉर्ट और एंकल लेंथ स्कर्ट, लांग जैकेट, सिमिट्रिकल डिजाइन, पैनल जैकेट, ब्लॉक प्रिंट्स ट्रेंड भी पसंद आते हैं। फैशन की बात हो रही हो वो भी शाहपुर जाट की गलियों में और रितू बेरी का नाम ना आए तो बेमानी होगी। रितू बेरी ने भी अपने करियर की शुरुआत इसी गांव से की थी। बेरी ने अपना पहला बुटिक यहीं खोला था। अभिनेत्री पूनम ढिल्लो, बॉलीवुड की बहुत सी अभिनेत्री अपनी ड्रेस यहीं डिजाइन कराती हैं। दिल्ली में रहने वाली नफीसा अली भी यहां खरीददारी करती हैं। लेकिन यहां का ज्यादातर काम विदेशी आर्डर के लिए किया जाता है।

विदेश में मिली पहचान : शाहपुर जाट दुनिया के फैशन इंडस्ट्री में एक खास मकाम बना चुका है। यहां तकरीबन सभी डिजाइनर के क्लाइंट दुबई, हॉगकांग, यूरोपियन देशों में है। फिल्म इंडस्ट्री के भी कई लोग अपने कॉस्ट्यूम यही तैयार करवाते हैं। आज से करीब बीस साल पहले इस गांव में दो ही बुटीक थे। इस गांव में बंगाली कढ़ाई करने वाले लोग तो पहले से ही रहा करते थे, लेकिन तब यहां पर दिल्ली के दूसरे स्थानों से इन कारीगरों को काम मिला करता था। आज तस्वीर बदल चुकी है। यहां तकरीबन चार हजार से ज्यादा बंगाली कारीगर आ बसे हैं। इसके अलावा रंगरेजों की भी कई दुकाने यहां खुल चुकी हैं। यहां हर गली के मोड़ पर रंगरेज मिल जाएंगे। और तकरीबन 150 बुटीक हैं। कुछ नामी डिजाइनर हैं तो कुछ नए डिजाइनर। दुनिया के नक्शे में फैशन हब के रूप में शाहपुर जाट का नाम शुमार है।

अमीर जाटों का इलाका : यूं तो गांव का कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता लेकिन इतिहास के जानकारों की मानें तो पता चलता है कि 10,000 साल पहले (8000 ईसा पूर्व), कुछ हिंदू राजाओं ने इस क्षेत्र की स्थापना की, जहां, वर्तमान शाहपुर जाट स्थित है। यहां एक किला और महल था। हालांकि 5000 साल पहले जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया था, वे उस किले के पत्थर ले गए। तोमर (हिंदू जाट वंश) ने 11 वीं शताब्दी ईस्वी में दिल्ली पर शासन किया, 12 वीं शताब्दी ईस्वी में, पृथ्वीराज चौहान शासक था, उसी सदी में मुस्लिमों द्वारा हिंदू शासन की जगह ले ली गई। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में दिल्ली के पहले मुस्लिम शहर सिरीफोर्ट की स्थापना की थी। यह बहुत ही समृद्ध था लेकिन बाद के शासकों ने अपने महल आदि बनवाने के लिए सिरी की निर्माण सामग्री के उपयोग के चक्कर में इसे तबाह कर दिय। आज, इसकी दीवारों के कुछ हिस्सों, चूने, मस्जिदों और कुछ ऐतिहासिक अवशेषों के साथ बनी हवेलियां गांव में मौजूद हैं। लगभग 900 सौ साल पहले, हरियाणा का इंद्री गांव-एक डागर कबीला शाहपुर जाट गांव स्थानांतरित हो गया। उपजाऊ भूमि और उनके कृषि कौशल ने उन्हें कुछ ही समय में धन संचय करने में मदद की, पंवार कबीले और अन्य जातियों को उस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया, जिसे तब तक शाह (धन) पुर (कॉलोनी) जाट (एक कबीला) कहा जाता था, जिसका अर्थ अमीर जाटों का इलाका था। इस तरह इसका नाम शाहपुर जाट पड़ा।

तुगलक की वास्तुकला का नायाब नमूना

इतिहासकार राना सफवी कहती हैं कि तोहफेवाला गुंबद खिलजी और तुगलक की वास्तुकला की याद दिलाती है। एकदम शांत माहौल में यह अलंकृत दिखती है। यह चारों ओर से बढ़ती हुई जंगली घास के साथ एक अनपेक्षित आंगन के अंदर है, लेकिन अभी तक कम से कम किसी ने अंदर अतिक्रमण नहीं किया है। अंदर और गुंबददार, मेहराबदार कोने पर गुंबद के निचले हिस्से में हैं। बाहर, गुंबद एक अष्टकोणीय ड्रम पर है। तीन तीन धनुषाकार आकृतियां शामिल हैं। मेहराब के सामने वाला भाग तीन धनुषाकार प्रवेश द्वार है, जबकि दूसरे दो कक्ष में दो छोटे धनुषाकार प्रवेश द्वार हैं और मध्य प्रवेश द्वार के स्थान पर एक तालाबंद मेहराबदार है। दक्षिणी सिरे पर पहले एक सीढ़ी भी थी। जो टॉप पर ले जाती थी लेकिन अब नहीं दिखती। इसी गुंबद में हेरिटेज वॉक का भी आयोजन किया जाएगा।

रिझाते हैं शीशों से झांकते जेवरात

बाजार बड़े काम का

दरीबां कला की गली में जैसे ही एक अनजान शख्स के तौर पर पहुंचेंगे तो आप पहले पहल हैरत में पड़ जाएंगे कि यहां कैसे बेशकीमती, बेहद जुदा आभूषण सजे हैं। जैसे-जैसे आपके कदम बढ़ते जाएंगे गली के दोनों ओर चमचमाते शीशों से झांकते आभूषण अपने सौंदर्य से आपका मन मोह लेंगे। आप कभी जेब की सोचेंगे तो कभी मन को थामेंगे, इसी उधेड़बुन में आप दो-चार दुकानों पर तो ठहर कर निहारेंगे ही। मुगलकालीन आभूषण के इस बाजार में आज भी 700 से अधिक ज्वैलर्स की दुकानें हैं। सदियां बीत गईं, लेकिन यहां के आभूषण और डिजाइन आज भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। विभिन्न राज्यों से आए कारीगरों की कारीगरी ऐसी होती है कि हर मन को रिझाती है। खासकर जड़ाऊ सादाकारी, कुंदन पोलकी व हीरे के जेवरात दरीबा कलां की पहचान हैं। भारत के प्राचीन ज्वैलरी बाजारों में से एक दरीबा का ब्रांड इतना लोकप्रिय है कि विदेश से खरीदार यहां आते हैं। सोने व हीरे के साथ ही चांदी की आकर्षक ज्वैलरी की मांग अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में है।

महारानियां बग्घी पर आती थीं जेवर खरीदने : मुगल शासन ने जब आगरा से दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तब चांदनी चौक स्थित यह बाजार भी अस्तित्व में आया। सन् 1650 में बसे इस बाजार में मुगल बादशाह और महारानियों के लिए आभूषण बनाए जाते थे। शाहजहां की बेटी रोशनआरा और जहांआरा तो यहां के आभूषणों पर इस कदर फिदा थीं कि लालकिला से बग्घी पर बैठ खुद इस बाजार में आती थीं और अपने आभूषण पसंद किया करती थीं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तक यहां के आभूषण लालकिला की चमक बढ़ाते रहे। चांदनी चौक के सेठ-साहूकार के घरों में भी यहां के जेवरातों की हनक है। आज भी यहां से आभूषणों पर मुगलई कलाकारी की झलक साफ तौर पर देखने को मिल जाती है। नए और पुराने डिजाइन के तालमेल से तैयार यहां के आभूषण कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। यहां कई दुकानें 250 साल से भी अधिक पुरानी हैं और अपने डिजाइन और शुद्धता से आज भी ग्राहकों के दिलों में जगह बनाए हुए है।

खास है जड़ाऊ सादाकारी: जड़ाऊ सादाकारी आभूषण मुगल राजाओं और महारानियों को खास पसंद थे। दरअसल लालकिला व आगरा किला की दीवारों पर जिस तरह के बेल बूटे अंकित हैं, जड़ाऊ सादाकारी में भी उसी प्रकार के बेल बूटे उकेरे जाते हैं। सोने से तैयार इस हार में रूबी व पन्ना जड़ा जाता है। हालांकि अब इस हार का वजन थोड़ा हल्का हो गया है, लेकिन महिलाओं के बीच इस हार की लोकप्रियता आज भी उतनी ही है। इस हार को तैयार करने में कम से कम 15 दिन का समय लग जाता है।

बन चुका है ब्रांड: वर्ष 1752 की रतन चंद ज्वालामल की दुकान इस बाजार में सबसे पुरानी है। इसे रतन चंद ने शुरू किया था। अब इसे उनकी सातवीं पीढ़ी के तरुण गुप्ता व आठवीं पीढ़ी के उनके बेटे कार्तिक गुप्ता संभाल रहे हैं। वे बताते हैं कि यहां आभूषणों के कुछ डिजाइन ऐसे हैं, जो यहीं के हैं और उसे एक ब्रांड के तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि इसमें मुगलई दस्तकारी की झलक है। पहले तो हाथ से ही सारे गहने तैयार होते थे। लेकिन अब मशीन का भी उपयोग होने लगा है।

परवेज मुर्शरफ के घर में यहां के इत्र की खुशबू:सिर्फ आभूषण ही नहीं, यहां खाने-पीने से लेकर स्लेट-पेंसिल और इत्र की भी दुकानें खासा मशहूर हैं। गुलाबमल जौहरीमल के इत्र की दुकान करीब 200 साल से अधिक पुरानी है। इसके इत्र की खुशबू पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के घर तक पहुंच चुकी है। वर्ष 2009 में परवेज मुशर्रफ जब दिल्ली आए थे तब अपनी मां के लिए इस दुकान से बारिश में मिट्टी से आने वाली सोंधी खुशबू वाली इत्र लेकर गए थे।

– नेमिष हेमंत

इन्हीं गलियों में बग्घी पर बैठकर कभी खरीदारी करने आते थे मुगल बादशाह और महारानियां। जागरण

पीढ़ियों से चली आ रही दुकान

यहां दुकानदारों और खरीदारों के बीच पीढ़ियों से नाता चला आ रहा है। यहां के ग्राहक ऐसे हैं जो पीढ़ियों से इस बाजार से ही आभूषणों की खरीदारी करते आ रहे हैं। यहां के आभूषणों पर एक विश्वास और डिजाइन ने ग्राहकों और दुकानदारों के बीच एक रिश्ता कायम कर दिया है। दरीबा कलां के पुराने ग्राहकों में सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दूसरे राज्य और विदेश के लोग भी शामिल हैं।

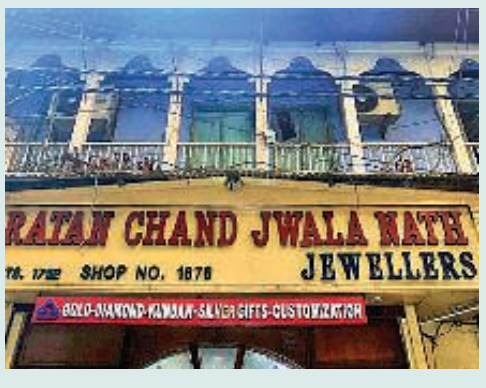

दिल्ली की देहरी

नलिन चौहान
दिल्ली के अनजाने इतिहास के खोजी

समय की धारा पर भारत-सोवियत संबंध

यह एक कम जाना तथ्य है कि हिंदुस्तान ने आजादी मिलने से पहले ही सोवियत संघ के साथ राजनयिक संबंध कायम कर लिए थे। जबकि पहला सोवियत राजनयिक स्वतंत्र भारत में ही दिल्ली पहुंचा था। 13 अप्रैल 1947 को दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। और नवंबर 1947 में दिल्ली पहुंचने वाले पहले सोवियत राजनयिक पावेल यर्जिन (1919-1992) थे। ऐसे में, यर्जिन के सामने सबसे बड़ी चुनौती तत्कालीन भारत सरकार की सहायता से सोवियत दूतावास के लिए एक उपयुक्त स्थान की तलाश थी। यर्जिन के दिल्ली पहुंचने के अगले दिन ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने उन्हें मिलने के लिए आमंत्रित किया। इस बैठक में नेहरु ने सोवियत राजनयिक को बताया कि भारत सरकार ने सोवियत संघ के दूतावास के लिए त्रावणकोर हाउस का चयन किया है।

उसके शीघ्र बाद ही किरील नोविकोव (1905-1983) को भारत में सोवियत राजदूत नियुक्त किया गया। इससे पहले, वर्ष 1939 में नोविकोव सोवियत विदेश मंत्रालय में नियुक्त थे। वे लंदन स्थित सोवियत दूतावास में डीसीएम बने। जबकि वर्ष 1945 में हुए प्रसिद्ध याल्टा सम्मेलन के वे मुख्य आयोजक थे।

दिसंबर 1947 में दिल्ली पहुंचे नोविकोव को यह जानकर बेहद खुशी हुई कि त्रावणकोर हाउस सरीखी शानदार इमारत सोवियत दूतावास होगी। वर्ष 1953 तक नोविकोव भारत में तैनात रहे। वर्ष 1960 में सोवियत संघ दूतावास त्रावणकोर हाउस से स्थानांतरित होकर चाणक्यपुरी में एक नई इमारत में पहुंच गया। जबकि 1960-1964 यानी चार साल की अवधि में त्रावणकोर हाउस में सोवियत सेंटर फॉर साइंस एंड कल्चर बना रहा।

सोवियत संघ के दूतावास के लिए इसी त्रावणकोर हाउस का चयन किया गया था।

21 दिसंबर, 1947 किरील नोविकोव पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे। किरील भारत में सोवियत राजदूत नियुक्त किए गए थे। फोटो : सौजन्य रूसी दूतावास

7 सितंबर 1946 को एक रेडियो प्रसारण में अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष के रूप में नेहरु ने सोवियत नागरिकों को भारत की ओर से शुभकामनाएं देते हुए इस बात की घोषणा कि 'वे एशिया में हमारे पड़ोसी हैं और अनिवार्य रूप से हमें मिलकर अनेक साझा कार्यों का बीड़ा उठाना होगा और एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत कुछ करना होगा।

सोवियत नेताओं ने भी ऐसी भावनाओं के साथ पूरी तरह अपनी सम्मति जताई। इसका ही परिणाम था कि 13 अप्रैल 1947 को दोनों देशों ने राजनयिक संबंध स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की। तब अंग्रेजों से भारतीय नेतृत्व के हाथों में सत्ता हस्तांतरण की वार्ता को लेकर अपनी आशंकाओं के बावजूद सोवियत संघ ने स्वतंत्रता पूर्व भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का फैसला लिया। एक तरह से, यह भारत में सोवियत संघ की गहरी रुचि का प्रतीक था। जो कि दोनों देशों के भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए एक शुभंकर साबित हुआ।

15 अगस्त, 1947 को भारत की आजादी के बाद कुछ समय के लिए, भारत-सोवियत संबंधों में वह पहले वाली गर्मजोशी नहीं रही। यहां तक कि दोनों देशों में कुछ दूरियां भी बढ़ीं। फिर भी उस समय संयुक्त राष्ट्र में भारत और सोवियत संघ उपनिवेशवाद और नस्लवाद के मुद्दों पर एकमत और साथ थे। उदाहरण के लिए, सोवियत संघ ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों की दुर्दशा और इंडोनेशियाई निवासियों के स्वतंत्रता संघर्ष की ओर ध्यान आकर्षित कराने की भारत की कोशिशों का पुरजोर समर्थन किया। उसके शीघ्र बाद भारत की पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता और कोरियाई युद्ध की समाप्ति के लिए निरंतर प्रयासों ने सोवियत नेताओं को इस बात का भरोसा दिलाया कि भारत पश्चिमी शक्तियों के दबावों को दरकिनार करते हुए वैश्विक मामलों में एक स्वतंत्र मार्ग का पक्षधर है। इससे भारत-सोवियत संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ी।

सोवियत संघ ने अब कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चर्चा में सक्रिय रुचि लेना शुरू किया और पूरी मजबूती से भारतीय पक्ष के समर्थन में खड़ा रहा। वर्ष 1952 में सुरक्षा परिषद में सोवियत प्रतिनिधि के भाषणों से यह बात साबित होती है। दिसंबर 1953 में पहले भारत-सोवियत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह दोनों देशों के बीच व्यापार के विस्तार की एक महत्वाकांक्षी, पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। जिससे भारत को कुछ ऐसे फायदे थे जो कि आमतौर पर पश्चिमी देशों के साथ होने वाले समान व्यापारिक समझौतों में नहीं होते थे। जैसे, दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये में व्यापार होने की बात थी। इतना ही नहीं, आपसी व्यापार को बढ़ाने के अलावा भुगतान संतुलन को भी बनाए रखने के प्रयास किए गए। इस दौरान, परस्पर सांस्कृतिक संपर्क के बढ़ने का परिणाम दोनों देशों में विविध क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की आपसी यात्राओं के रूप में सामने आया।

राष्ट्रीय संस्करण
शनिवार 19 अक्टूबर 2019
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

गुणवत्ता जांच में 37.7 परसेंट प्रोसेस्ड मिल्क सैंपल फेल

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में बेचे जा रहे अधिकतर प्रोसेस्ड मिल्क गुणवत्ता जांच में खरे नहीं उतर सके हैं। इनमें कई बड़े ब्रांड्स के नाम भी शामिल हैं। खाद्य क्षेत्र के नियामक एफएसएसएआइ द्वारा लिए गए कुल सैंपल में से 37.7 परसेंट गुणवत्ता के कई पैमानों पर फेल हो गए हैं। सुरक्षा के पैमाने पर भी प्रोसेस्ड मिल्क के 10.4 परसेंट सैंपल फेल रहे हैं। हालांकि बिना प्रोसेस्ड मिल्क में यह संख्या 4.8 परसेंट ही रही। सर्वे में शामिल सैंपल में से 12 परसेंट में मिलावट पाई गई।

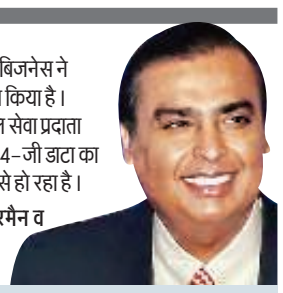

हमारे कंज्यूमर बिजनेस ने जबर्दस्त प्रदर्शन किया है। जियो सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता बन गई है। सबसे ज्यादा 4-जी डाटा का उपयोग भी इसी नेटवर्क से हो रहा है।

— मुकेश अंबानी, चेयरमैन व एमडी, आरआइएल

सेंसेक्स	39,298.38 ▲ 246.32	निफ्टी	11,661.85 ▲ 75.50	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 38,925 ▼ ₹145	चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 46,325 ▼ ₹315	$ डॉलर	₹ 71.14 ▼ ₹0.02	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 60.12

दिया भरोसा ▶ कहा – खराब हालात के बावजूद भारत की विकास दर बेहतर

भारत अभी भी सबसे तेज गति वाली इकोनॉमी : निर्मला सीतारमण

यह भी कहा – सरकार विकास दर को और गति देने के कर रही सभी प्रयास

वाशिंगटन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने विश्व बैंक और आइएमएफ की सालाना बैठक के इतर ब्रिक्स-एफएमसीबीजी की बैठक में हिस्सा लिया। एएनआइ

वाशिंगटन, प्रेट्र : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आइएमएफ द्वारा विकास दर का अनुमान घटाने के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेज विकास करने वाली इकोनॉमी है। उन्होंने कहा कि देश की विकास दर में तेजी लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व बैंक और आइएमएफ की सालाना बैठक में भाग लेने के लिए वाशिंगटन पहुंचीं सीतारमण ने कहा कि आइएमएफ ने भारत और चीन दोनों की 6.1 परसेंट की समान विकास दर रहने उम्मीद जताई है। लेकिन वे भारत और चीन में तुलना नहीं कर रही हैं। आइएमएफ ने अपनी हालिया रिपोर्ट में ग्लोबल इकोनॉमी की विकास दर का अनुमान घटा दिया है। इसने भारत की विकास दर के अनुमान को भी घटाया है, इसके बावजूद भारत सबसे तेज विकास करने वाली इकोनॉमी बना हुआ है।

आइएमएफ के मुताबिक भारत इस वर्ष 6.1 परसेंट की गति से विकास करेगा, जबकि अगले वर्ष इसकी विकास दर सात परसेंट रहने की उम्मीद है। सीतारमण ने कहा कि वैश्विक हालात को देखते हुए भारत का प्रदर्शन बेहतर है, उनकी इच्छा है कि यह और अधिक तेज गति से विकास करे। विकास को गति देने के लिए वे हरसंभव प्रयास कर रही हैं। लेकिन इससे यह तथ्य कमजोर नहीं होता कि भारत सबसे तेज विकास करने वाली इकोनॉमी है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे इस तेज विकास दर से निश्चिंत नहीं हैं, और इसे बढ़ाने के लगातार प्रयास कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि यह बात सच है कि इकोनॉमी पहले की तरह से वृद्धि नहीं कर रही है। यह सात-आठ परसेंट की विकास दर नहीं दर्ज कर रही, लेकिन हम इस बात को नकार नहीं सकते कि इस हालात में भी हमारी इकोनॉमी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी सेक्टर की बातें सुनी जा रहीं हैं और सरकार उनकी समस्याएं दूर करने का हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका ध्यान इस बात पर नहीं है कि इकोनॉमी की सुस्ती ढांचागत या साइक्लिक, वह सिर्फ इस बात पर ध्यान दे रहीं हैं कि लोग क्या चाहते हैं और उसी हिसाब से कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्व घाटे के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस समय उनके पास इसकी चिंता करने का समय नहीं है, इस समय उनका ध्यान उद्योग जगत की समस्याओं को दूर करने पर है।

दूर हो रहे भारत-अमेरिका के व्यापारिक मतभेद

वाशिंगटन, प्रेट्र : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत-अमेरिका के व्यापार मतभेद कम हो रहे हैं और जल्द ही व्यापार समझौता होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय दोनों देशों देशों के बीच समझौते को लेकर प्रयासरत है। इसके परिणाम जल्दी सामने आएंगे। जिन मुद्दों पर बातचीत चल रही है वे काफी पेचीदा हैं। कुछ चीजें हल हो चुकी हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही समझौता हो जाएगा। इससे पहले मंगलवार को अमेरिका ने कहा था कि उसके वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस और भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बीच व्यापार वार्ता सकारात्मक रही थी।

अमेरिकी डेयरी उत्पादों के दाम जल्द घटने की बनी संभावना

- सचिवों की समिति की वैठक सोमवार को
- उत्पादों पर आयात शुल्क की दर घटाने पर होगी चर्चा
- अगले सप्ताह अंतरमंत्रालयी समिति करेगी विचार

प्रतीकात्मक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारतीय बाजार में कुछ अमेरिकी उत्पादों की पहुंच और आसान हो सकती है। इस संबंध में अगले सप्ताह सचिवों की अंतरमंत्रालयी समिति विचार करेगी। इसके तहत डेयरी उत्पादों से लेकर मेडिकल डिवाइस और अखरोट जैसे उत्पादों पर आयात शुल्क में राहत देने का प्रस्ताव है।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय कारोबार को रफ्तार देने की दिशा में हो रही बातचीत के तहत यह कदम उठाया जाना है। अमेरिका की तरफ से भी कुछ भारतीय उत्पादों को बाजार पहुंच आसान बनाने का फैसला हो सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस (जीएसपी) के तहत मिलने वाली ड्यूटी राहत फिर से शुरू कर सकता है।

विभिन्न मंत्रालयों के साथ चर्चा के लिए जारी कुछ उत्पादों की सूची के मुताबिक अमेरिका से आयात होने वाले मेडिकल, डेयरी और कृषि क्षेत्र के कुछ उत्पादों के अलावा सेब और अखरोट पर आयात शुल्क की दर घटाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त दालों पर आयात शुल्क में कमी का प्रस्ताव भी वाणिज्य मंत्रालय ने किया है, जिस पर कृषि मंत्रालय की राय मांगी गई है।

सूत्रों के मुताबिक अमेरिका से आयात होने वाले फ्रोजन चिकन और बरबॉन व्हिस्की पर भी आयात शुल्क की दर घटाने का प्रस्ताव है। सेब पर आयात शुल्क की दर को 50 से घटाकर 10 फीसद और अखरोट पर सौ फीसद से घटाकर दस फीसद करने का प्रस्ताव है। सोमवार को होने वाली बैठक में सभी मंत्रालय इन प्रस्तावों पर अपना पक्ष रखेंगे। बैठक में कृषि, खाद्य व सार्वजनिक वितरण, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोलियम और गैस तथा कृषि, पशुपालन व डेयरी मंत्रालयों के साथ-साथ राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य आयोग के अधिकारी हिस्सा लेंगे।

चीन की विकास दर 27 वर्षों के निचले स्तर पर

बीजिंग, एएफपी : चीन की आर्थिक विकास दर इस वर्ष तीसरी तिमाही में 27 वर्षों के निचले स्तर पर आ गई। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई-सितंबर में देश की आर्थिक वृद्धि दर महज छह प्रतिशत रह गई।

इससे पहले वाली तिमाही यानी अप्रैल-जून में भी चीन के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर महज 6.2 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा भी पिछले करीब तीन दशकों का निचला स्तर था। चीन की वृद्धि दर में कमी की प्रमुख वजह अमेरिका के साथ ट्रेड वार का जारी रहना और घरेलू मांग का नरम पड़ना है। यह वृद्धि दर 1992 के बाद सबसे कमजोर तिमाही आंकड़ा है। हालांकि यह सरकार के 2019 में आर्थिक वृद्धि दर 6-6.5 प्रतिशत रखने के लक्ष्य के दायरे में है। वर्ष 2018 में चीन की आर्थिक वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत थी।

स्थिरता का दावा : ब्यूरो के प्रवक्ता माओ शेंगयांग ने कहा, 'अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर शुरुआती तीन तिमाहियों में स्थिरता देखी गई है।' उन्होंने कहा कि हालांकि हमें घरेलू और वैश्विक, दोनों मोर्चों पर गंभीर आर्थिक हालात के प्रति सजग रहना होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में नरमी और बाहरी व्यापार में बढ़ती अनिश्चिता एवं अस्थिरता से चीन अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है।

बेहतरी के उपाय कर रही सरकार : बीजिंग ने इकोनॉमी को सहारा देने के कई कदम उठाए हैं। उसने करों पर टैक्स की दरों में भारी कटौती की है। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इसी सप्ताह बुधवार को बैंकों को 200 अरब युआन (लगभग 2,800 करोड़ डॉलर या करीब 1.96 लाख करोड़ रुपये) मुहैया कराए हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज को रिकॉर्ड तिमाही मुनाफा

- दूसरी तिमाही में कंपनी ने कमाए 11,262 करोड़ रुपये
- रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस ने दिया मुनाफे को दम

मुंबई, प्रेट्र : मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) ने कंज्यूमर बिजनेस के जबर्दस्त प्रदर्शन के दम पर अब तक का रिकॉर्ड तिमाही मुनाफा कमाया है। कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर, 2019) में उसे 11,262 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। कंपनी इससे पहले पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही (जनवरी-मार्च, 2019) में कंपनी ने सबसे ज्यादा 10,362 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। शुक्रवार को ही आरआइएल शेयर बाजारों में नौ लाख करोड़ रुपये का पूंजीकरण छूने वाली पहली कंपनी भी बन गई। हालांकि बाजार बंद होने पर उसका पूंजीकरण घटकर 8.97 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा रहा।

आरआइएल ने शुक्रवार को कहा कि समीक्षाधीन अवधि में उसका कंसोलिडेटेड राजस्व 4.8 फीसद बढ़ोतरी के साथ 1,63,854 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी ने कर-पूर्व लाभ का एक-तिहाई हिस्सा रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस से हासिल किया। चालू वित्त वर्ष के आखिर में कंपनी के कर-पूर्व लाभ में इन दोनों की हिस्सेदारी करीब 25 फीसद थी। कंपनी ने कहा कि अब उसके रिटेल स्टोर्स का कुल क्षेत्रफल 2.45 करोड़ वर्गफुट पर पहुंच गया। कंपनी के स्टोर्स की पहुंच अब 6,700 शहरों से ज्यादा तक हो गई है। हालांकि रिकॉर्ड 99 लाख टन कच्चे तेल के उत्पादन के बावजूद कंपनी के पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस के कर-पूर्व लाभ में 6.4 फीसद की गिरावट आई और यह 7,602 करोड़ रुपये रह गया।

जियो को बंपर मुनाफा : चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में रिलायंस जियो ने 45.4 फीसद उछाल के साथ 990 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी का परिचालन राजस्व 33.7 फीसद बढ़कर 12,354 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा। हालांकि समीक्षाधीन अवधि में कंपनी का प्रति ग्राहक औसत राजस्व (आरपू) दो रुपये की मामूली गिरावट के साथ 120 रुपये रही। लेकिन ग्राहकों के बढ़ते आधार से इस कमी की भरपाई हो गई।

महत्वपूर्ण आंकड़े

10,901 पर पहुंच गई कंपनी के रिटेल स्टोर की संख्या, जो मार्च के अंत में 10,644 थी

2,322 करोड़ रुपये रहा 67 फीसद बढ़ोतरी के साथ रिटेल बिजनेस का कर-पूर्व लाभ

बात पते की

इस नतीजे के साथ ही देश में किसी भी निजी कंपनी द्वारा सबसे ज्यादा तिमाही मुनाफा कमाने का भी रिकॉर्ड आरआइएल के नाम हो गया है। हालांकि देश में सबसे ज्यादा तिमाही मुनाफे का रिकॉर्ड अभी भी सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आइओसी) के ही नाम है। आइओसी ने वित्त वर्ष 2012-13 की आखिरी तिमाही (जनवरी-मार्च, 2013) में 14,512.81 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था।

मुकेश अंबानी बोले

35 करोड़ ग्राहकों का आधार पार कर जियो दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करती डिजिटल सर्विसेज कंपनी बन गई है। कंपनी अभी भी हर महीने एक करोड़ से ज्यादा ग्राहक जोड़ रही है। हमारे रिटेल बिजनेस की विकास गति बेहतरीन रही है। रिलायंस रिटेल ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है।

उत्तरी राज्यों में टमाटर, प्याज और दाल की जल्द बढ़ेगी आपूर्ति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आवश्यक वस्तुओं की महंगाई की निगरानी के लिए गठित हाई लेवल कमेटी राजधानी दिल्ली प्रक्षेत्र (एनसीआर) समेत उत्तरी राज्यों में टमाटर, प्याज और दाल जैसी जिंसों की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला लिया है। समिति की बैठक में राजधानी दिल्ली में शनिवार से ही टमाटर की आपूर्ति बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसकी पहली खेप के शनिवार शाम तक पहुंच जाने की उम्मीद है।

मॉनिटरिंग कमेटी की शुक्रवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा टमाटर की महंगाई को लेकर हुई। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में टमाटर की पर्याप्त आपूर्ति का फैसला लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक यहां के लिए टमाटर की पहली खेप आंध्र प्रदेश के प्रमुख टमाटर उत्पादक क्षेत्रों से रवाना हो चुकी है। मदर डेयरी की दुकानों से टमाटर 55 रुपये प्रति किलो से अधिक मूल्य पर नहीं बेचा जाएगी। कृषि मंत्रालय के अफसरों ने बैठक में बताया कि मानसून की ज्यादा बारिश का कोई असर टमाटर की खेती अथवा उत्पादन पर नहीं पड़ा है। कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से टमाटर की आपूर्ति बेंगलुरु मंडी में हो रही है। बैठक में उपभोक्ता सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव के साथ कृषि मंत्रालय के आला अफसरों ने हिस्सा लिया, जिसमे हॉर्टिकल्चर कमिश्नर के साथ नैफेड के प्रबंध निदेशक भी मौजूद थे। टमाटर, प्याज और दाल की आपूर्ति के बारे में नैफेड के प्रबंध निदेशक को दो दिनों में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है। टमाटर की उपलब्धता के बारे में हॉर्टिकल्चर कमिश्नर को उत्पादक क्षेत्रों का पता लगाने को कहा गया है। टमाटर और प्याज की मांग उत्तर प्रदेश से भी आ रही है, जहां कीमतें बहुत अधिक बढ़ी हुई हैं।

प्याज को लेकर नैफेड ने बैठक में बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से कई तरह की मुश्किलें पैदा की जा रही हैं। दिल्ली पहुंचे प्याज भरे ट्रकों को राज्य सरकार के अफसर क्वालिटी के नाम पर रिजेक्ट कर रहे हैं। जबकि उनके अफसर उत्पादक मंडियों में ही उसे जांचते हैं। नैफेड ने सभी राज्यों से 16 रुपये किलो की दर से प्याज खरीदने की पेशकश की है।

बैठक में बताया गया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से नई फसल वाली प्याज की आपूर्ति भी शुरू हो गई है। बताया गया कि दिवाली के बाद दूसरे राज्यों से भी पर्याप्त प्याज की आपूर्ति चालू हो जाएगी। इसी तरह दालों की आपूर्ति को लेकर भी नैफेड ने स्पष्ट किया कि राजधानी दिल्ली में एनसीसीएफ, मदर डेयरी और नैफेड की दुकानों से दालें एक किलोग्राम और आधा किलोग्राम के पैकेट में बाजार मूल्य के मुकाबले रियायती दरों पर बेची जाएंगी।

प्रतीकात्मक

- राजधानी दिल्ली में शनिवार से ही बढ़ जाएगी टमाटर की आपूर्ति
- नैफेड के गोदामों में प्याज और दालों के पर्याप्त स्टॉक

धीमा विकास देख आरबीआइ ने घटाया था रेपो रेट

मुंबई, प्रेट्र : आरबीआइ ने कहा है कि सुस्त होती इकोनॉमी और निजी निवेश में नरमी के चलते उसने रेपो रेट में कटौती करने का फैसला किया था। इसी महीने की शुरुआत में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक हुई थी, जिसके मिनट्स शुक्रवार को जारी किए गए।

आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्रीय बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दर (रेपो रेट) में 25 आधार अंकों यानी 0.25 परसेंट की कटौती की थी। इस वर्ष जनवरी से अब तक यह पांचवीं कटौती थी। चालू वर्ष में आरबीआइ रेपो रेट में 135 आधार अंकों यानी 1.35 प्रतिशत की कटौती कर चुका है। मिनट्स के मुताबिक दास ने बैठक में कहा कि घरेलू मांग और निजी खपत में कमी देखी गई है। इस वजह से कुल मांग में गिरावट हुई है। यह निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। बैठक में दास ने घटते निजी निवेश और कॉरपोरेट सेक्टर की हिचक को लेकर भी चिंता जताई थी। हालांकि हाल के समय में मेन्यूफैक्चिरिंग के क्षेत्र में क्षमता का लगभग औसत प्रयोग हुआ है।

दास ने कहा कि इकोनॉमी को गति देने के लिए सरकार ने भी हाल में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस समय इकोनॉमी को गति देने के लिए हर तरह से प्रयास किए जाने की जरूरत है। गवर्नर ने रेपो रेट को लेकर अपना मत जाहिर करते हुए कहा था कि बीते कुछ समय में मंहगाई भी निर्धारित लक्ष्य के भीतर ही रही है, इसलिए मैं रेपो रेट घटाने के विचार पर सहमत हूं। इसके बाद एमपीसी के सभी छह सदस्यों ने रेपो रेट को 0.25 परसेंट कम करने को लेकर सहमति जताई। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय के दौरान दास ने कई मौकों पर कहा है कि आगामी बैठक में भी आरबीआइ नीतिगत ब्याज दरों में कटौती पर विचार कर सकता है।

प्रतीकात्मक

- मांग को बढ़ावा देने के लिए बनी रेपो रेट घटाने की सहमति
- गवर्नर समेत सभी छह सदस्य कटौती को लेकर थे एकमत

सीएससी में मिलेंगे अमूल के प्रोडक्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर अब अमूल के डेयरी भी उत्पाद उपलब्ध होंगे। इसके लिए सीएससी ने अमूल के साथ समझौता किया है। समझौते के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले सीएससी अब अपने सेंटर पर ही अमूल कैफे खोल सकेंगे, जहां अमूल आइसक्रीम समेत दूसरे डेयरी उत्पादों की बिक्री होगी।

सीएससी ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड देशभर में 3.5 लाख सेंटर चलाता है। कंपनी के सीईओ दिनेश त्यागी ने बताया कि हमने अमूल के साथ समझौता किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत पहले 100 सेंटर गुजरात में खोले जाएंगे। इसके बाद दूसरे राज्यों में इस तरह के कैफे खोले जाएंगे। इसके तहत आइसक्रीम के लिए अलग और और अन्य डेयरी प्रोडक्ट के लिए अलग रेफ्रिजरेटर की जरूरत होगी।

सिंगल-यूज प्लास्टिक का विकल्प दीजिए, सरकार से मिलेगा इनाम

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने स्टार्ट-अप्स के लिए सिंगल-यूज प्लास्टिक का विकल्प प्रस्तुत करने की चुनौती रखी है। इसके तहत पहले विजेता को तीन लाख और दूसरे नंबर पर आने वाले को दो लाख रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआइआइटी) ने बताया कि यह चुनौती इनोवेटर्स और स्टार्ट-अप को सिंगल-यूज प्लास्टिक का विकल्प पेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यह चुनौती सभी स्टार्ट-अप कंपनियों के लिए खुली होगी। लेकिन पेश किए प्रोडक्ट व्यावहारिक हों, प्रोडक्ट के सैद्धांतिक सबूत हों या बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन संभव हो। विजेताओं का चुनाव विशेषज्ञों का एक पैनल करेगा। प्रतिभागियों में से सबसे पहले उपयुक्त की छंटनी की जाएगी। इसके बाद विभाग द्वारा निर्धारित किए गए मानकों पर खरा उतरने वाले उत्पाद को पुरस्कृत किया जाएगा। विजेताओं की घोषणा इसी महीने की 31 तारीख को की जाएगी।

गौरतलब है कि सरकार सिंगल-यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने की कोशिशों में जुटी है। इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। अभी इस तरह की प्रदूषणकारी प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले सिंगल-यूज प्लास्टिक के अंतर्गत प्लास्टिक के बैग, सोडा और पानी की बोतलें, खाने को पैक करने की चीजें, पेय पदार्थों के लिए उपयोग में आने वाली छोटी पाइप (स्ट्रॉ) आदि हैं।

प्रतीकात्मक

- शीर्ष विजेता को सरकार देगी तीन लाख रुपये का इनाम
- दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले पाएंगे दो-दो लाख रुपये

गैलेक्सी-10 के फिंगरप्रिंट लॉकिंग सिस्टम में खामी की बात सैमसंग ने स्वीकारी

सियोल, एएफपी : सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी-10 सीरीज के कई मॉडल में सुरक्षा संबंधी गंभीर खामी की बात स्वीकारी है। यह समस्या फोन के फिंगरप्रिंट लॉकिंग सिस्टम में है। इस खामी की वजह से फोन को इसके यूजर के अलावा कोई दूसरा भी अनलॉक कर सकता है। कंपनी ने अपने ग्राहकों को पहले से दर्ज फिंगरप्रिंट डिलीट करने की सलाह दी है।

इसी सप्ताह ब्रिटेन के एक यूजर ने इस संबंध में शिकायत की थी। उसने एक समाचार पत्र को बताया था कि उसके गैलेक्सी-10 फोन को कोई दूसरा व्यक्ति आसानी से खोल सकता है। यूजर ने बताया था कि उसके फोन पर स्क्रीन प्रोटेक्टर रखने के बाद बिना रजिस्टर्ड फिंगर से भी फोन अनलॉक किया जा सकता है। इस दौरान उसने अपने फाइनेंशियल अकाउंट को लेकर चिंता जताई थी। सैमसंग की ओर से जारी वक्तव्य में गैलेक्सी नोट-10, 10+, गैलेक्सी एस-10, एस-10+ और एस-10 5जी के यूजर्स को पहले से रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट डिलीट करने और नए सिरे से रजिस्टर्ड करने की सलाह दी गई है। कंपनी ने कहा है कि जब तक वह नया अपडेट जारी नहीं करती तब तक यूजर सिलिकॉन स्क्रीन प्रोटेक्टर का प्रयोग नहीं करें। गौरतलब है कि दुनिया सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी पहले भी कई बार अपने मोबाइल फोन के मॉडल को लेकर विवादों से घिर चुकी है। वर्ष 2016 में कंपनी के गैलेक्सी नोट-7 मॉडल में बैटरी फटने की समस्या सामने आई थी।

मजबूती

लगातार छठे सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए बाजार, सेंसेक्स 246.32, निफ्टी 75.50 अंक चढ़कर हुए बंद, लगभग सभी सेक्टरों में रहा खरीदारी का माहौल

शेयर बाजारों में सात महीनों की सबसे लंबी बढ़त

मुंबई, प्रेट्र : शुक्रवार को लगातार छठे सत्र में प्रमुख भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। इस दौरान लगभग सभी सेक्टरों में खरीदारी का माहौल बना रहा। दिन के कारोबार में 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 246.32 अंक यानी 0.63 परसेंट उछाल के साथ 39,298.38 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 75.50 अंक यानी 0.65 परसेंट के उछाल के साथ 11,661.85 पर बंद हुआ। इस वर्ष मध्य मार्च के बाद घरेलू शेयर बाजारों की यह सबसे लंबी बढ़त है।

सेंसेक्स में यस बैंक के शेयरों ने सबसे ज्यादा 8.44 परसेंट का उछाल दर्ज किया। साथ ही मारुति सुजुकी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एलएंडटी और एसबीआइ के शेयरों ने भी बढ़त दर्ज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के तिमाही आंकड़े आने से पहले इसके शेयरों में 1.37 परसेंट का उछाल आया। दूसरी ओर टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल, आइसीआइसीआइ बैंक, एक्सिस बैंक, और इन्फोसिस के शेयर 1.05 परसेंट तक गिर गए।

कोटक सिक्युरिटीज में पीसीजी रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट संजीव जरबाड़े के मुताबिक ट्रेड-वार्ता की प्रगति और ब्रेक्जिट समझौते को लेकर आ रही खबरों से उत्साहित विदेशी निवेशक ने भारतीय बाजारों में रुचि दिखाई। इसके चलते इस सप्ताह बाजारों में लगातार तेजी बनी हुई है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी रखने के संकेतों से निवेशकों में उत्साह कायम रहा। उधर चीन की विकास दर में गिरावट की खबर के बाद एशिया के अन्य मार्केट में शंघाई, हांगकांग और सियोल के बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि टोक्यो के मार्केट बढ़त के साथ बंद हुए।

इस वर्ष मार्च के बाद घरेलू शेयर बाजार पहली बार छह सत्रों में बढ़े हैं। प्रतीकात्मक

सरकारी कंपनियों के शेयरों में तेज उछाल

नई दिल्ली, प्रेट्र : शुक्रवार के कारोबार में सरकारी कंपनियों (पीएसयू) के शेयरों में जमकर खरीदारी हुई। इस दौरान भेल के शेयरों में 22 परसेंट तक उछाल दर्ज किया गया। बीएसई में सूचीबद्ध अन्य सरकारी कंपनियों में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयर 19.66 परसेंट, एमएमटीसी 17.36 परसेंट, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 9.31 परसेंट और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के शेयर 8.42 परसेंट उछले। इसके अलावा सेल, एनबीसीसी, एनएमडीसी, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, एसजेवीएन और ऑयल इंडिया के शेयरों में 7.90 परसेंट तक का उछाल दर्ज किया गया।

नौ लाख करोड़ रुपये को छूकर लौटी रिलायंस

नई दिल्ली, प्रेट्र : शुक्रवार के कारोबार में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नौ लाख करोड़ रुपये के बाजार मूल्यांकन को पार गई। हालांकि कारोबार बंद होने पर यह नौ लाख से नीचे आ गई। आरआइएल इस मनोवैज्ञानिक स्तर को छूने वाली पहली कंपनी बन गई है। इससे पहले पिछले वर्ष अगस्त में यह आठ लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली घरेलू कंपनी बनी थी। दिन के कारोबार में एक समय कंपनी का बाजार पूंजीकरण 9,05,214 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

हालांकि बाजार बंद होने पर यह 8,97,179.47 के स्तर के साथ सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है। शुक्रवार को कंपनी के शेयर 1.37 परसेंट उछाल के साथ बंद हुए। इंट्रा-डे में इसके शेयरों ने 2.28 परसेंट तक का उछाल दर्ज किया। वहीं शेयर बाजार में दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 7,71,996.87 करोड़ रुपये है। जबकि तीसरे स्थान पर एचडीएफसी बैंक और चौथे स्थान पर एचयूएल का नाम आता है। गौरतलब है कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध किसी कंपनी का बाजार पूंजीकरण प्रतिदिन के कारोबार के मुताबिक तय होता है।

जनमत
मुद्दा

लोगों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित बनाने के लिए मौजूदा भारतीय बैंकिंग कानून पर्याप्त हैं?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं। **MUDDA** लिखें, स्पेस देकर **YES** या **NO** लिखकर 57272 पर भेजें।

14 नागरिकों की मौत हो गई पूर्वोत्तर सीरिया में तुर्की के हमलों में गुरुवार देर रात को। खास बात यह रही कि ये हमले तुर्की-अमेरिका के समझौते के बाद हुए। तुर्की अधिकारिक रूप से पांच दिन के लिए संघर्ष विराम पर सहमत हुआ है।

ट्रंप कैबिनेट से एक और मंत्री का इस्तीफा

न्यूयॉर्क टाइम्स से

वाशिंगटन : ट्रंप प्रशासन का साथ छोड़ने वाले शीर्ष अधिकारियों की सूची में ऊर्जा मंत्री रिक पेरी का भी नाम जुड़ गया है। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गुरुवार को कहा कि वह इस्तीफा देने जा रहे हैं। पेरी का नाम यूक्रेन स्कैंडल में सामने आया है। इस मामले की जांच कर रही संसदीय समिति ने पेरी से दस्तावेज मांगे हैं। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने गत 25 जुलाई को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से फोन पर बात की थी और राष्ट्रपति चुनाव में अपने संभावित डेमोक्रेट प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन को बदनाम करने के लिए उन पर दबाव बनाया था। इसी मामले को लेकर ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए जांच चल रही है।

ट्रंप ने टेक्सास में बताया कि पेरी साल के आखिर में अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। पेरी के इस्तीफे की अटकलें पिछले कई हफ्ते से लगाई जा रही थीं। यह खबर आई थी कि बिडेन के बेटे हंटर के खिलाफ जांच शुरू कराने के लिए यूक्रेनी अधिकारियों पर दबाव बनाने में उन्होंने भी भूमिका निभाई थी। पेरी ने गत बुधवार को वाल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वह ट्रंप के निर्देश पर यूक्रेन संबंधी मामलों को लेकर उनके निजी वकील रूडी गिउलियानी के संपर्क में थे। पेरी (69) ने मार्च, 2017 में ऊर्जा मंत्री का पदभार संभाला था।

- यूक्रेन स्कैंडल में आया है ऊर्जा मंत्री रिक पेरी का नाम
- मामले की जांच कर रही संसदीय समिति ने उनसे मांगे हैं दस्तावेज
- पेरी साल के आखिर में अपने पद से इस्तीफा दे देंगे

रिक पेरी। फाइल

ट्रंप प्रशासन छोड़ने वाले कुछ प्रमुख नाम

11 अक्टूबर, 2019 को केविन मैक्लीनन ने कार्यवाहक गृह सुरक्षा मंत्री का पद छोड़ा

7 अप्रैल, 2019 को कर्स्टजेन नीलसन का गृह सुरक्षा मंत्री पद से इस्तीफा

31 दिसंबर, 2018 को जेम्स मैटिस का रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा

9 अक्टूबर, 2018 को भारतवंशी निक्की हेली का संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत पद से इस्तीफा

31 मार्च, 2018 को रेक्स टिलरसन ने विदेश मंत्री पद छोड़ा

31 जुलाई, 2017 को जॉन एफ केली का आंतरिक सुरक्षा मंत्री पद से इस्तीफा

मंडेला की बेटी बनीं द. कोरिया में दक्षिण अफ्रीका की राजदूत

सियोल, एएनआइ : दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल विजेता नेल्सन मंडेला की बेटी जिनेनी मंडेला को दक्षिण कोरिया में दक्षिण अफ्रीका की राजदूत के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी संभाल ली है। वह मंडेला और उनकी दूसरी पत्नी विनी की सबसे बड़ी संतान हैं।

जिनेनी फाइल

जिनेनी ने गुरुवार को यहां दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात के बाद कहा, 'मुझे कोरिया में काम करने में वाकई बेहद खुशी हो रही है। मेरा मानना है कि दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे द्विपक्षीय संबंध हैं। मैं इन संबंधों को प्रगाढ़ करना जारी रखूंगी।' 60 वर्षीय जिनेनी मंडेला डलेमिनी जल्द ही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन से मुलाकात करेंगी। उन्हें इस साल की शुरुआत में दक्षिण कोरिया का राजदूत नामित किया गया था। वह इससे पहले अर्जेंटीना में भी दक्षिण अफ्रीकी राजदूत के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं।

जुकरबर्ग ने फेसबुक को बताया पांचवां स्तंभ

सैन फ्रांसिस्को, आइएएनएस : सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपने प्लेटफॉर्म को दुनिया का पांचवां स्तंभ बताया है। वाशिंगटन डीसी स्थित जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में गुरुवार को अपने संबोधन में जुकरबर्ग ने कहा, सोशल मीडिया के जरिये लोग अपनी बात अन्य तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। उन्हें अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वह सीधे ही अपनी बात कह सकते हैं। जुकरबर्ग ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया ने सत्ता का विकेंद्रीकरण कर उसे सीधे जनता के हाथों में सौंप दिया है।

बीते कुछ समय से यूजर्स की निजता सुरक्षित रखने में विफल रहने, डाटा चोरी और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विरोधी अभ्यासों के कारण फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार और नेताओं के निशाने पर रहे हैं। ऐसे में जुकरबर्ग के इस बयान को अहम माना जा रहा है। उन्होंने कहा, 'सोशल मीडिया ने लोगों को सबसे प्रभावशाली अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से नवाजा है।

आज सोशल मीडिया समाज के पांचवें स्तंभ की तरह मजबूती से खड़ा है।' राजनीतिक विज्ञापनों की जांच के सवाल पर उन्होंने कहा, 'हम राजनीतिक विज्ञापनों के तथ्यों की जांच नहीं करते। ऐसा नेताओं की मदद के लिए नहीं किया जाता है। हम बस लोगों तक नेताओं की बात पहुंचाना चाहते हैं ताकि वह खुद फैसला ले सकें।' इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि किसी को भी ऐसे कंटेंट प्रसारित करने की अनुमति नहीं है, जिससे हिंसा फैले।

- फेसबुक सीईओ ने कहा, सोशल मीडिया के जरिये जनता के हाथों में पहुंची सत्ता

जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में बोलते फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग। रायटर

मार्टिन लूथर किंग की बेटी ने कहा, भ्रामक जानकारियों के चलते हुई थी मेरे पिता की हत्या

सैन फ्रांसिस्को, रायटर : सियासी विज्ञापनों के तथ्यों की जांच नहीं करने के बयान पर फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग फिर सवालों के घेरे में हैं। अमेरिका के गांधी कहे जाने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बेटी बर्निस ने भी उनके इस बयान पर आपत्ति जताई है। बर्निस ने ट्वीट किया, 'मैंने फेसबुक सीईओ का भाषण सुना। वह राजनीतिक विज्ञापनों के तथ्यों की जांच के पक्ष में नहीं हैं और सही-गलत का फैसला जनता के हाथ में छोड़ना चाहते हैं। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि राजनेताओं द्वारा भ्रामक जानकारियां फैलाए जाने के चलते ही मेरे पिता की हत्या हुई थी।' जुकरबर्ग ने जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में अपने भाषण के दौरान दो बार किंग जूनियर का जिक्र किया था। नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले किंग जूनियर की चार अप्रैल, 1968 को टेनिसी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फेसबुक के प्रवक्ता ने बर्निस के इस बयान का स्वागत करते हुए कहा, 'बर्निस के विचार हमारे लिए अमूल्य हैं और हम उसका सम्मान करते हैं। अगले हफ्ते इस मुद्दे पर उनसे चर्चा की जाएगी।'

एफएटीएफ की काली सूची में जाने से बचा पाक, 2020 तक का वक्त मिला

दी चेतावनी ▶ एफएटीएफ अध्यक्ष ने कहा, तय समय में ठोस कदम नहीं उठाए तो होगी दिक्कत

तब तक एफएटीएफ की ग्रे सूची में ही बना रहेगा पाक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आतंकी संगठनों को धन मुहैया कराने के ढांचे को रोकने में पाकिस्तान मोटे तौर असफल रहा है इसके बावजूद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उसे ब्लैक लिस्ट नहीं किया है। आतंकी फंडिंग रोकने के लिए सुझाए गए उपायों पर ठोस कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान को अब फरवरी, 2020 तक का वक्त दिया गया है और तब तक के लिए उसे ग्रे सूची में ही रखा गया है। एफएटीएफ के अध्यक्ष शियांगमिन लिउ ने पेरिस में पिछले तीन दिनों की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में चेतावनी भरे लहजे में कहा, "पाकिस्तान सरकार को 27 मानकों पर कार्रवाई करने को कहा गया था लेकिन उसकी तरफ से सिर्फ 5 मानकों पर संतोषप्रद कार्रवाई हुई है। अगर वह फरवरी, 2020 तक शेष मानकों पर ठोस कदम नहीं उठाता है तो उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।" बता दें कि शियांगमिन लिउ पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद दोस्त चीन के रहने वाले हैं।

एफएटीएफ ने पाकिस्तान से 10 कदम उठाने को कहा है। इसमें अल-कायदा, जैश-ए-मुहम्मद, जमात-उद-दावा समेत संयुक्त राष्ट्र से घोषित हर आतंकी संगठनों या उससे जुड़े आतंकियों के परोक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर वित्तीय ढांचे को ध्वस्त करने जैसे कदम शामिल हैं। इसके लिए पाकिस्तान को 27 तरह की कार्ययोजना लागू करनी होगी।

एफएटीएफ की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पाकिस्तान ने पिछले एक साल के भीतर आतंकियों की फंडिंग को रोकने के लिए खास कार्रवाई नहीं की है। जून, 2019 में अमेरिका के ऑरलैंडो में एफएटीएफ की बैठक में भी यही कहा गया था कि पाकिस्तान पांच कार्ययोजना ही लागू कर सका है। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं करने के पीछे एफएटीएफ अध्यक्ष का कहना था, 'हमारा उद्देश्य हर सदस्य देश को आतंकी संगठनों के खिलाफ कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है नहीं कि सिर्फ दंडित करना।'

एफएटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि, अगर पाकिस्तान फरवरी, 2020 तक अपने स्तर पर सभी कार्य योजना को पूरा नहीं करता है तो संगठन के सभी सदस्यों को कहा जाएगा कि वे पाकिस्तान के साथ कारोबार या वित्तीय लेन-देन करने वाले सभी वित्तीय संस्थानों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दें।

अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को विश्व बैंक या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज मिलने में भी मुश्किल होगी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान भारत पर एफएटीएफ के जरिए उनके देश को दिवालिया करने की कोशिश करने का आरोप लगाते रहे हैं।

हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी मानते हैं कि पाकिस्तान पर एफएटीएफ की तरफ से दबाव बनाने का मकसद यह है कि वह आतंकी फंडिंग व आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करे। भारत भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और बदहाल हो, क्योंकि उसका फायदा आतंकी संगठन उठा सकते हैं।

जानकारी देते एफएटीएफ के अध्यक्ष शियांगमिन लिउ। प्रेट्र

- 27 मानकों में केवल पांच मानकों में पाक की कार्रवाई संतोषप्रद मिली

निगरानी सूची में शामिल देश

आतंकी फंडिंग रोकने में नाकामी पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने दुनिया के कई देशों को निगरानी सूची में रखा है। इन देशों में बहामास, बोत्सवाना, यमन, सीरिया, त्रिनिडाड व टोबैगो, इथोपिया, कंबोडिया, पाकिस्तान, घाना, पनामा, श्रीलंका और ट्यूनिशिया शामिल हैं।

पाक ने कहा, कार्य योजना लागू करने के लिए प्रतिबद्ध

इस्लामाबाद, प्रेट्र : टेरर फंडिंग पर एफएटीएफ की चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि वह कार्ययोजना को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि एफएटीएफ में उसके प्रतिनिधिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय संस्था की कार्य योजना को पूरी तरह से लागू करने उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता को दोहराया है। बयान में कहा गया है प्रतिनिधिमंडल ने उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दी है।

यूरोप का ब्रेक्जिट सौदे को समर्थन, ब्रिटेन के सांसदों से सहयोग की अपील

ब्रसेल्स, एएफपी : यूरोपीय संघ के नेताओं ने कड़ी मशक्कत के बाद हुए ब्रेक्जिट समझौते को अपना समर्थन दिया है, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के सामने अब इसे ब्रिटिश संसद से पारित कराने की बेहद कड़ी चुनौती है।

यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने अन्य नेताओं द्वारा सौदे को स्वीकृत किए जाने के बाद संवाददाताओं से कहा, 'ऐसा प्रतीत होता है कि हम अंतिम चरण के काफी करीब हैं।' लेकिन जॉनसन के आशावित होने के बावजूद ब्रिटेन की विपक्षी पार्टियों और हाउस ऑफ कॉमंस में प्रधानमंत्री के अपने भी कुछ सहयोगियों ने तुरंत चेताया कि वे शनिवार को विशेष बैठक के दौरान इस पर होने वाले मतदान में इसके पक्ष में वोट नहीं डालेंगे।

अगर सौदा खारिज हो जाता है तो प्रधानमंत्री का कानूनी कर्तव्य होगा कि उन्हें ईयू नेताओं से ब्रेक्जिट को तीसरी बार स्थगित करने के लिए कहना होगा। इसी के साथ 31 अक्टूबर तक ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने की उनकी प्रतिबद्धता भी टूट जाएगी।

यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन क्लॉड जंकर ने आगाह किया है कि इसे खारिज किए जाने से बेहद जटिल स्थिति पैदा हो जाएगी जबकि टस्क ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो वह सदस्य राष्ट्रों से इस पर प्रतिक्रिया देने को लेकर विचार-विमर्श करेंगे।

जॉनसन ने भरोसा जताया है कि सांसद सौदे का समर्थन करेंगे, लेकिन विपक्ष और यहां तक कि सहयोगी पार्टी के साझेदारों से मिली तत्काल प्रतिक्रिया इस पक्ष में नहीं दिखी।

सुरक्षित क्षेत्र न छोड़ा तो मंगलवार से फिर हमले

तुर्की के हमले के बाद इराक के बरदरश शहर में शरण लिए हुए सीरीयाई कुर्द। रायटर

इस्तांबुल, एएफपी : तुर्की के राष्ट्रपति रीसेप तैयप एर्दोगन ने धमकी दी है कि अस्थायी समझौते के तहत अगर सुरक्षित क्षेत्र के लिए जगह नहीं छोड़ी गई तो मंगलवार से सीरिया पर फिर से हवाई हमले शुरू हो जाएंगे। अमेरिका के उप राष्ट्रपति माइक पेंस और विदेश मंत्री माइक पोंपियो के साथ हुई साढ़े चार घंटे की वार्ता के बाद गुरुवार रात एर्दोगन पांच दिन के लिए सीरियाई कुर्दों पर हमले रोकने के लिए तैयार हुए हैं। एर्दोगन सीरिया के तटवर्ती इलाके में उन सीरियाई शरणार्थियों को बसाना चाहते हैं जो हिंसा के चलते उनके देश में आ गए हैं। यूरोपीय यूनियन ने एर्दोगन की घोषणा को औपचारिक युद्धविराम मानने से इन्कार कर दिया है।

पेंस के साथ हुई वार्ता में एर्दोगन पांच दिनों के लिए हमले रोकने के लिए तैयार हुए। लेकिन उन्होंने यह शर्त रख दी कि इन पांच दिनों में कुर्द लड़ाकों को वह इलाका खाली करना होगा जिसे वह शरणार्थियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाना चाहते हैं। जाहिर है कि शरणार्थियों की आड़ में एर्दोगन अपने विरोधी कुर्दों को सीरिया की उनकी जमीन से बेदखल करना चाहते हैं, साथ ही सीरियाई भूमि को अपने राजनीतिक प्रभाव में लेना चाहते हैं। एर्दोगन ने साफ किया है कि यह सुरक्षित क्षेत्र तुर्की की सीमा के किनारे 444 किलोमीटर लंबा और 32 किलोमीटर गहरा सीरियाई भूभाग होगा। अमेरिका और सीरिया की घोषणा के उलट न्यूज एजेंसी सना और मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली सीरियन ऑब्जरवेटरी का दावा है कि शुक्रवार को भी तुर्की के विमानों ने सीरिया के सीमावर्ती इलाकों में बमबारी की। इस बमबारी में पांच लोग मारे गए हैं जबकि 20 घायल हुए हैं। सीरियाई कुर्दों पर तुर्की के हमले नौ अक्टूबर को शुरू हुए थे। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौन स्वीकृति माना गया था लेकिन जैसे ही अंतरराष्ट्रीय विरोध तेज हुआ और अमेरिका में भी मुखालफत की आवाज बुलंद हुई, ट्रंप ने पाला बदलते हुए तुर्की पर हमले रोकने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया।

- तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की धमकी

लेबनान में हिंसा भड़की

वाट्स एप के जरिए कॉल पर प्रतिमाह छह डॉलर टैक्स लगाने के विरोध में लेबनान में हिंसा भड़क गई। राजधानी बेरुत सहित कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। इस दौरान व्यापक पैमाने पर आगजनी की घटनाएं हुईं। हालांकि, हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा। लेबनान को इस समय कई आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार टैक्सों में वृद्धि करने पर मजबूर है। रायटर

अफगानिस्तान की मस्जिद में आतंकी विस्फोट, 62 लोगों की जान गई

काबुल, एपी : अफगानिस्तान में इबादत के लिए जुटे लोगों पर शुक्रवार को फिर दहशतगर्दों का कहर बरपा। भीषण बम धमाके में मस्जिद मलबे में तब्दील हो गई, धुंए और धूल का गुबार छंटा तो दर्जनों लोगों की लाशें सामने पड़ी थीं और घायलों की चीख-पुकार से इलाका गूंज रहा था। देर शाम तक मृतकों की संख्या 62 तक पहुंच चुकी है जबकि 36 घायल हैं।

घायलों में भी कुछ की हालत गंभीर है। हमले की जिम्मेदारी अभी किसी ने नहीं ली है। लेकिन इलाके में आतंकी संगठन तालिबान और इस्लामिक स्टेट (आइएस), दोनों ही सक्रिय भूमिका में हैं।

नांगरहार प्रांत के गवर्नर के प्रवक्ता अताउल्ला खोगयानी ने कहा है कि शुरुआती जांच में स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मस्जिद में हुआ हमला आत्मघाती था या किसी अन्य तरीके से विस्फोट किया गया। आदमियों के साथ बड़ी संख्या में बच्चे भी हमले के शिकार हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता जहीर आदिल ने बताया है कि गंभीर हालत वाले 23 घायलों को प्रांतीय राजधानी जलालाबाद के अस्पताल में भेज दिया गया है जबकि बाकी का इलाज हसकामेना जिला अस्पताल में किया जा रहा है। यह हमला संयुक्त राष्ट्र की वह रिपोर्ट सार्वजनिक होने के एक दिन बाद हुआ है जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान के गृहयुद्ध में सबसे ज्यादा वहां के निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। इन निर्दोषों की मौत पर अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ाने के लिए लड़ रहे संगठनों को सोचना चाहिए। 2019 के सितंबर तक कुल 2,563 नागरिक मारे गए, जो संख्या 2018 में मारे गए लोगों से 26 प्रतिशत ज्यादा है।

अफगानिस्तान में विस्फोट के बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाते सेना के जवान। रायटर

ट्रंप ने मैदान में खेलते बच्चों से की तुर्की और कुर्द लड़ाकों की तुलना

वाशिंगटन, द न्यूयॉर्क टाइम्स : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की और कुर्द लड़ाकों की तुलना मैदान में खेल रहे बच्चों से की है, जो लड़ने के बाद ही सुलह के रस्ते पर आते हैं। कुर्द लड़ाकों के कब्जे वाले उत्तर-पूर्वी सीरिया में तुर्की के सैन्य अभियान से दोनों पक्षों में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। तुर्की के इस हमले के लिए, अमेरिका की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रही है। वह सीरिया से अमेरिकी सैनिक वापस बुलाने और कुर्द का साथ छोड़ने के लिए ट्रंप की आलोचना कर रही है। कई रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा था कि हमला करने के लिए अमेरिकी सरकार ने ही तुर्की को हरी झंडी दी थी। ट्रंप प्रशासन ने इन दावों को खारिज करते हुए तुर्की पर कई प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।

डलास में गुरुवार को एक चुनावी रैली में ट्रंप के सुर बदले नजर आए। उन्होंने न सिर्फ सीरिया से सैनिक हटाने के निर्णय का बचाव किया बल्कि तुर्की को हमला करने का अवसर देने के लिए अपनी पीठ भी थपथपाई।

उनके अनुसार ऐसा करने से ही दोनों पक्ष समझौते के लिए राजी हो सकते थे। करीब 20 हजार समर्थकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, 'पिछले हफ्ते हुई हिंसा कई मायनों में लाभदायक ही रही। मैंने जो किया वह गैरपरंपरागत था। लेकिन कई बार आपको दो देशों को भी बच्चों की तरह आपस में लड़ने के लिए छोड़ना पड़ता है। इसके बाद ही आप उन्हें अलग कर सुलह कराने की कोशिश करते हैं।'

- सीरिया से अमेरिकी सैनिक वापस बुलाने के फैसले का किया बचाव

हांगकांग में रविवार के प्रदर्शन को पुलिस ने नहीं दी अनुमति

हांगकांग, रायटर : लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारियों ने शुक्रवार को मार्च कर रविवार के विरोध-प्रदर्शन के लिए समर्थन मांगा। पुलिस ने रविवार के प्रदर्शन को अवैध घोषित कर दिया है और इसे विफल करने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसलिए आंदोलनकारियों के लिए ताकत दिखाने की चुनौती पैदा हो गई है। आंदोलनकारी इस बार कुछ ज्यादा करने की तैयारी में हैं।

आंदोलन की दृष्टि से चालू सप्ताह अपेक्षाकृत शांत रहा है। छिटपुट विरोध प्रदर्शनों के अतिरिक्त लोकतंत्र की मांग वाले आंदोलन में कुछ खास नहीं हुआ। हां, लोकतंत्र समर्थक विधायकों ने विधानसभा में हंगामा जरूर किया और चीन समर्थक को कड़ा संदेश दिया। रविवार के विरोध प्रदर्शन की अनुमति पुलिस ने यह कहकर नहीं दी है कि पूर्व के प्रदर्शनों की शुरुआत तो शांति से हुई लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें चरमपंथी आंदोलनकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद भीड़ का इस्तेमाल हिंसा फैलाने में किया गया।

वेनेजुएला के चुनाव पर अमेरिका की आपत्ति को चीन ने 'अनुचित' बताया

बीजिंग, एएफपी : संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में वेनेजुएला के निर्वाचन को त्रासदी बताने वाले अमेरिकी बयान को चीन ने अनुचित करार दिया है। कई ऐडवोकेसी समूहों के विरोध के बावजूद वेनेजुएला संगठन का सदस्य निर्वाचित हुआ है।

वेनेजुएलाई राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की वामपंथी सरकार पर आरोप है कि उन्होंने विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया है और बिगड़ती अर्थव्यवस्था के बीच अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए यातना का सहारा ले रहे हैं।

अमेरिका सहित 50 से अधिक देशों ने अपना रुख पलट कर वेनेजुएला की राष्ट्रीय असेंबली के अध्यक्ष जुआन गुएडो को वैध कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी है। अब भी संयुक्त राष्ट्र में मादुरो को प्रबल समर्थन प्राप्त है जिनमें रूस और चीन जैसे देश शामिल हैं।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा, 'जो अमेरिका कह रहा है वह पूरी तरह से अनुचित है।' बीजिंग में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, 'चुनाव के नतीजे अंतरराष्ट्रीय समाज की इच्छा को इंगित करता है और यह तार्किक और कानूनी है।' शुआंग ने कहा, 'हम अमेरिका को सलाह देते हैं कि वह मानवाधिकार के मुद्दे का राजनीतिकरण न करे।' चीन की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब गुरुवार को मानवाधिकार समूहों ने वेनेजुएला के चुनाव की निंदा करते हुए इसे वेनेजुएला के लोगों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के मुंह पर तमाचा करार दिया था। उल्लेखनीय है कि यूएनएचआरसी में लातिन अमेरिका के लिए निर्धारित दो सीटों में से एक के लिए हुए चुनाव में वेनेजुएला ने कोस्टा रिका को हराकर जीत दर्ज की जिसे अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के लिए असहज करने वाला और वेनेजुएला के लोगों के लिए त्रासदी करार दिया।

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अमेरिका ने वेनेजुएला के निर्वाचन को त्रासदी बताया है
- चीन ने कहा जो अमेरिका कह रहा वह पूरी तरह से गलत

एफबीआइ की 10 शीर्ष वांछितों की सूची में शामिल भारतीय की तलाश

न्यूयॉर्क, आइएएनएस : अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (एफबीआइ) की 10 शीर्ष वांछित अपराधियों की सूची में शामिल भारतीय नागरिक भद्रेश कुमार पटेल की तलाश तेज हो गई है। पत्नी की हत्या के बाद से प्रदेश पिछले चार साल से छिपता फिर रहा है। एफबीआइ के साथ ही भारतीय जांच एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी हैं।

भारत में गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र में उसकी तलाश हो रही है। मूल रूप से अहमदाबाद के विरमगाम के रहने वाले भद्रेश ने अमेरिका के मैरीलैंड के हैनोवर में एक स्टोर में 12 अप्रैल 2015 को अपनी 21 साल की पत्नी पलक की हत्या कर दी थी। दोनों स्टोर में साथ काम करते थे। घटना वाली रात भी दोनों स्टोर में साथ थे। इसके बाद से भद्रेश फरार हो गया था। अमेरिका के 10 शीर्ष वांछितों की सूची में भद्रेश का नाम पहली बार 2017 में आया था। अमेरिका ने भद्रेश पर एक लाख डॉलर (लगभग 70 लाख रुपये) का इनाम घोषित है।

मेक्सिको में अल चापो गिरोह से मुठभेड़ के दौरान भारी हिंसा

मेक्सिको सिटी, रायटर : मेक्सिको में ड्रग लॉर्ड जोक्विन अल चापो गुजमान के गिरोह के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ के बाद व्यापक हिंसा फैल गई। इसमें दो लोग मारे गए जबकि 21 घायल हुए हैं। सुरक्षित निकलने के लिए सुरक्षा बलों को गुजमान के बेटे को छोड़ना पड़ा। गुजमान अमेरिकी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसकी गैरमौजूदगी में उसका यह बेटा मेक्सिको में ड्रग कारोबार संभाल रहा है।

देश के आंतरिक सुरक्षा मामलों के मंत्री अल्फोंसो डुराजो ने बताया कि क्यूलियाकैन शहर में मुखबिर की सूचना पर नेशनल गार्ड ने जब एक मकान में प्रवेश किया, तो उन्होंने वहां पर ओविडियो गुजमान समेत चार लोगों को वहां पाया। ओविडियो अमेरिका में ड्रग तस्करी के मामले में वांछित है। नेशनल गार्ड ने जब उसे पकड़ा तो कई बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और सेना के जवानों से गिरोह के सदस्यों की मुठभेड़ शुरू हो गई। दिनदहाड़े हुई इस मुठभेड़ में अपराधी गिरोह भारी पड़ा और उसने सुरक्षा बलों की कई गाड़ियों और एक गैस स्टेशन में आग लगा दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने ओविडियो को छोड़कर इलाके से बाहर निकलना ही उचित माना। मुठभेड़ में दोनों ओर से हुई भीषण फायरिंग और आगजनी से शहर के आसमान में धुंए का गुबार छा गया, बाजार बंद हो गए और भयभीत लोग घरों में जा दुबके। डुराजो ने कहा है कि जनहानि से बचने और इलाके में शांति स्थापित करने के लिए सुरक्षा बलों ने वहां से निकलना ठीक समझा। उल्लेखनीय है कि मेक्सिको में ड्रग माफिया काफी मजबूत है। पुलिस ने जब भी उसके खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की है, तभी पुलिस को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है।

- सुरक्षा बलों को बचने के लिए ड्रग लॉर्ड के बेटे को छोड़ना पड़ा
- गिरोह से मुठभेड़ के दौरान हुई भीषण फायरिंग, छाया धुंए का गुबार

पाक में नए कानून के तहत ईशनिंदा मामले में व्यक्ति को पांच साल की कैद

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने सोशल मीडिया पर ईशनिंदा से संबंधित सामग्री डालने के मामले में एक शख्स को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। यह देश के नए साइबर आपराधिक कानून के तहत सजा का पहला मामला है। साइबर अपराध के विशेष अदालत ने शिया पंथ के सक्रिय सदस्य साजिद अली को सजा सुनाई है। उस पर 2017 में फेसबुक पर 'बेअदबी भरी, ईशनिंदा करने वाली और अपमानजनक' सामग्री डालने का आरोप था।

अली को इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम 2016 और पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 298ए के तहत सजा सुनाई गई है। अली बहावलनगर के क्रिश्चियन तहसील का रहने वाला है। उसके खिलाफ स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

यह मामला बाद में क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर संघीय जांच एजेंसी (एफआइए) साइबर अपराध सर्किल लाहौर के सुपुर्द कर दिया गया था।

ये भी जानिए
भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा जब पिछली बार रांची में टेस्ट खेलने उतरे थे, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 525 गेंदों की मैराथन पारी में 21 चौकों की मदद से 202 रन बनाए थे।

शतकों की हैट्रिक पर होगी मयंक की नजरें

दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरा टेस्ट **मैच आज से** चोटिल कुलदीप के तीसरे टेस्ट में खेलने की संभावनाओं को झटका

संजीव रंजन • रांची

भारतीय क्रिकेट टीम शनिवार से जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट में यहां जेएससीए स्टेडियम में उतरेगी तो सभी की निगाहें सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल पर होंगी। पहले दो टेस्ट में शतक लगाने वाले कर्नाटक के ओपनर मयंक के पास अब इस सीरीज में शतकों की हैट्रिक लगाने का मौका है। अगर वह ऐसा करते हैं तो विजय हजारे, सुनील गावस्कर, विनोद कांबली, विराट कोहली के बाद लगातार तीन टेस्ट में तीन शतक लगाने वाले वाले पांचवें भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। मयंक ने विशाखापत्तम में पहले टेस्ट की पहली पारी में 215 जबकि पुणे में दूसरे टेस्ट में पहली पारी में 108 रन बनाए थे।

रोहित, मयंक व कोहली का खूब चला है बल्ला : सीरीज में अब तक रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल व विराट कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़े हैं जबकि जडेजा ने मध्य क्रम में उपयोगी पारियां खेली हैं। पहली बार भारतीय पारी का आगाज करने वाले रोहित शर्मा ने पहले टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जड़ा जबकि मयंक अग्रवाल ने दोनों टेस्ट में शतकीय पारी खेलकर यह बता दिया कि यह जोड़ी टेस्ट के लिए भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए सही है। पुणे में कोहली ने 254 रन की जादुई पारी खेली जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। रोहित पुणे में नहीं चल पाए थे और वह इसकी भरपाई यहां करना चाहेंगे जबकि अब तक सीरीज में दो अर्धशतक लगाने वाले चेतेश्वर पुजारा तिहरे अंक तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।

क्लीन स्वीप का बेहतरीन मौका : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-0 से सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर चुकी भारतीय टीम रांची में भी कोई ढील देने के मूड में नहीं है। विराट कोहली ने शुक्रवार को जिस तरह अभ्यास कर खिलाड़ियों के साथ बातचीत की उससे यह स्पष्ट हो गया है कि वह जीत से कम कुछ नहीं चाहते। सीरीज के लिए यह टेस्ट भले ही औपचारिक लग रहा है लेकिन इसमें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए महत्वपूर्ण अंक दांव पर लगे होंगे इसलिए कोहली की टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस अंतिम मैच में भी किसी तरह की कसर नहीं छोड़ेगी। इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को 40 अंक मिलेंगे। विश्व चैंपियनशिप में भारत के अभी दो सीरीज के चार मैचों के बाद 200 अंक हैं और उसने अपने करीबी प्रतिद्वंद्वी न्यूजीलैंड और श्रीलंका पर 140 अंकों की बड़ी बढ़त बना रखी है। कोहली पहले ही बता चुके हैं कि अंतिम टेस्ट मैच में भी काफी कुछ दांव पर लगा है और उनकी टीम किसी भी तरह से ढिलाई नहीं बरतेगी।

कोहली के पास स्मिथ को पछाड़ने का मौका : भारतीय कप्तान के पास एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्मिथ को पछाड़ने का मौका होगा। टेस्ट रैंकिंग में स्मिथ से मात्र एक अंक से भारतीय कप्तान पीछे हैं। रांची में बड़ी पारी खेल कोहली एक बार फिर शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। स्मिथ के 937 अंक हैं जबकि कोहली के 936 अंक हैं। वैसे भी इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा रहा है। दो टेस्ट मैचों में भारत ने केवल 16 विकेट गंवाए। मेहमान टीम के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में सफल नहीं रहे हैं।

कुलदीप हुए चोटिल : पिच को देखने के बाद यह तय हो गया है कि दोनों टीमों में स्पिनर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसे में माना जा रहा था कि भारतीय टीम चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को अंतिम एकादश में शामिल करेगी, लेकिन कंधे में दर्द के कारण उनका तीसरे टेस्ट में खेलना लगभग नामुमकिन है। टीम ने उनके कवर के रूप में झारखंड के बायें हाथ के स्पिनर शाहबाज नदीम को टीम में शामिल किया है। अब तीसरे स्पिनर के तौर पर कौन मैदान पर उतरेगा इस पर सस्पेंस बन गया है। सीरीज में भारतीय गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। विशेषकर अश्विन व जडेजा दमदार रहे हैं। ऐसे में अंतिम एकादश क्या होगा इसका फैसला सुबह ही पता चलेगा।

गेंदबाजों का दमदार प्रदर्शन : सीरीज में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेहमान टीम को दबाव में रखा है। तेज व स्पिन गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरे टेस्ट में टॉस की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को लाभ मिलेगा। तीसरे दिन से पिच के टर्न लेने की संभावना है। अब तक टॉस ने भी भारत का साथ दिया और अगर अंतिम टेस्ट मैच में सिक्का फाफ डुप्लेसिस का साथ देता है तो चीजें थोड़ा रोमांचक हो सकती हैं।

अफ्रीकी बल्लेबाजों को दिखाना होगा दम: दक्षिण अफ्रीका टीम को अगर तीसरे टेस्ट में बेहतर परिणाम चाहिए तो उसे एक टीम के रूप में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने विशाखापत्तनम में कुछ दम दिखाया था लेकिन पुणे में वे नाकाम रहे थे। केवल पुछल्ले बल्लेबाजों ने ही भारतीय गेंदबाजों को कुछ परेशान किया। डुप्लेसिस ने चोटी के बल्लेबाजों डीन एल्गर, क्विंटन डिकॉक और तेंबा बावुमा जैसे अनुभवी बल्लेबाजों से जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करने के लिए कहा है। वैसे एडेन मार्करैम के चोटिल होने के कारण बाहर होने से दक्षिण अफ्रीका की परेशानियां बढ़ी हैं। गेंदबाजी की बात करें तो कैगिसो रबादा, वर्नोन फिलेंडर और एनरिक नॉर्टजे अब तक भारतीय तेज गेंदबाजों की तरह प्रभावी नहीं रहे हैं। उसके सीनियर स्पिनर केशव महाराज भी इस मैच में नहीं खेल पाएंगे और ऐसे में दक्षिण अफ्रीकी आक्रमण के लिए भारतीय बल्लेबाजों को रोकना मुश्किल होगा।

रांची में अभ्यास सत्र के दौरान दौड़ लगाते मयंक अग्रवाल और विराट कोहली • एएनआइ

02 सरा टेस्ट जेएससीए स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां भारत- ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था

02 शतक भारत की ओर से इस मैदान पर अब तक लगे हैं। यहां चेतेश्वर पुजारा और रिद्धिमान साहा शतक जड़ चुके हैं

05 विकेट जडेजा ने यहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पारी में लिए थे। उस मैच में उन्होंने नौ विकेट लिए थे। यह इस मैदान में किसी भारतीय गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका

टीम	मैच	जीत	हार	ड्रॉ	अंक
भारत	4	4	0	0	200
न्यूजीलैंड	2	1	1	0	60
श्रीलंका	2	1	1	0	60
ऑस्ट्रेलिया	5	2	2	1	56
इंग्लैंड	5	2	2	1	56
वेस्टइंडीज	2	0	2	0	00
द. अफ्रीका	2	0	2	0	00

बारिश की आशंका

रांची : तीसरे टेस्ट मैच में बारिश की भी आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार 20 व 21 अक्टूबर को रुक-रुक कर बारिश हो सकती है। हालांकि झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने कहा है कि बारिश रुकने के 15 से 20 मिनट के बाद ही खेल शुरू हो जाएगा। मैदान पर जल का जमाव नहीं होगा।

टीमें इस प्रकार हैं : भारत : विराट कोहली (कप्तान), मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, रहाणे (उप कप्तान), हनुमा विहारी, रिद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मुहम्मद शमी, उमेश, इशांत शर्मा, रिषभ पंत, शुभमन गिल, शाहबाज नदीम।

दक्षिण अफ्रीका : फाफ डुप्लेसिस (कप्तान), तेंबा बावुमा (उप कप्तान), क्विंटन डिकॉक, डीन एल्गर, जुबैर हमजा, जॉर्ज लिंडे, सेनुरन मुथुस्वामी, लुंगी नगिदी, एनरिक नॉर्टजे, वर्नोन फिलेंडर, डेन पीट, कैगिसो रबादा, थेनिस व रूडी सेकंड।

गांगुली को मिलना चाहिए सबका साथ

गौतम गंभीर
फिलक

सबसे पहले तो पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का अगला बीसीसीआइ अध्यक्ष बनना भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ी छलांग है। सामान्य तौर पर बीसीसीआइ का कार्य अब तक पीछे हटने वाला और अस्पष्ट रहा है, लेकिन एक पूर्व क्रिकेटर का इस अहम पद पर बैठना एक सुखद कदम है। मुझे नहीं पता कि कैसे यह हुआ और मैं यह जानने के लिए उत्सुक भी हूं। मुझे खुशी है कि भारतीय क्रिकेट का नेतृत्व वह इंसान करेगा जिसे क्रिकेट की अच्छी समझ है। जिस तरह के बदलाव उन्होंने बंगाल क्रिकेट संघ में किए यह साफ संकेत है कि दादा केवल पूर्व क्रिकेटर नहीं है जो मैदान पर बदलाव करते थे।

उनके प्रशासनिक कौशल का टेस्ट होगा लेकिन जहां तक मैं दादा को जानता हूं उनकी सम्मिलित विकास की क्षमता उन्हें अच्छी जगह पर बनाए रखेगी लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि दादा को इसके लिए 10 महीनों से ज्यादा का समय मिलना चाहिए, नहीं तो सारा परिश्रम बेकार जाएगा। मुझे उम्मीद है कि दादा को उनसे भी सहायता मिलेगी, जिन्होंने दादा को बधाई नहीं दी। एक क्रिकेटर के तौर पर, वह अच्छे परिणाम इसीलिए ला सके क्योंकि उन्हें ड्रेसिंग रूम और बीसीसीआइ से सहयोग मिला। दादा के लिए स्वर्गीय जगमोहन डालमिया का साथ मिले बिना काम करना चुनौतियों भरा हो सकता था। इसके बाद उन्होंने और कोच जॉन राइट ने सहवाग, नेहरा, युवराज हरभजन और जहीर जैसे खिलाड़ियों को तैयार किया, लेकिन दादा खुशकिस्मत थे कि उन्हें द्रविड़, कुंबले, तेंदुलकर और लक्ष्मण जैसे साथी मिले। अब दादा को इसी तरह के सहयोग की सहायता बीसीसीआइ के बड़े दिग्गजों से है। मुझ पर विश्वास करें, दुनिया अब भारतीय क्रिकेट पर पहले से ज्यादा नजर बनाए रहेगी। मैं दिग्गज क्रिकेटर ब्रायन लारा के भारतीय क्रिकेट पर किए गए कमेंट को पढ़कर काफी खुश हुआ। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि विश्व क्रिकेट मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है, लेकिन यह विराट कोहली की समस्या नहीं है। अगर लारा आज कहते हैं कि हमारी गेंदबाजी उन्हें वेस्टइंडीज के पुराने दिनों की याद दिलाती है तो इसका श्रेय कप्तान और सहयोगी स्टाफ को ही जाता है। तेज गेंदबाजी और भारतीय क्रिकेट दो अलग-अलग चीजें रही हैं, लेकिन अगर हम जसप्रीत बुमराह के बगैर यह टेस्ट सीरीज जीत जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम सुधार कर रहे हैं। इस पर मैं और विस्तार से बात करूं, तो हमारे पास द्रविड़, गेंदबाजी कोच भरत अरुण, क्षेत्ररक्षण कोच आर. श्रीधर और पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर जैसे लोग हैं। ये सभी सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय क्रिकेट पर अपना मजबूत प्रभाव छोड़ा है। द्रविड़ आराम से किसी भी आइपीएल टीम के कोच या मेंटर बन सकते थे और बाकी के समय में कुछ अलग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जूनियर क्रिकेटरों के साथ काम करने का फैसला करके एक नजीर पेश की। यह उदाहरण है कि भारतीय सहयोगी स्टाफ क्रिकेट में क्या दे रहा है।

THE ULTIMATE INVERTER BATTERY
EXIDE INVATUBULAR

कौन कहता है मैंने शाको को हटा दिया है : बजरंग

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: भारत के दिग्गज पहलवान बजरंग पूनिया ने शुक्रवार को उन खबरों का खंडन किया जिसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने निजी कोच शाको बेंतिनिडिस को हटा दिया है। उन्होंने साफ किया कि जॉर्जियाई मूल के उनके कोच उनके साथ हैं और उनका इरादा अपने सहायक स्टाफ में कोई बदलाव करने का नहीं है।

विश्व चैंपियनशिप में तीन पदक जीतने वाले भारत के इकलौते पहलवान बजरंग को लेकर खबरें चल रही हैं कि उन्होंने अपने कोच शाको से नाता तोड़ लिया है। बजरंग ने कहा कि मुझे यह नहीं समझ आ रहा है कि यह किसने और क्यों कहा। शाको मेरे कोच हैं और इसके बारे में मुझसे पूछा जाना चाहिए था। ऐसी खबरों को पढ़कर मुझे बहुत खराब लग रहा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वह मेरे निजी कोच हैं जिनकी व्यस्था जेएसडब्ल्यू द्वारा की गई है। यह रिपोर्ट समझ से परे है कि आखिर मैं उन्हें क्यों हटा दूंगा। यह कौन कह रहा है और क्यों। मेरा अपने कोच को बदलने का कोई इरादा नहीं है। उधर जब जेएसडब्ल्यू से संपर्क करके इस मसले पर सफाई मांगी गई तो उसने साफ कर दिया कि ना तो वह और ना ही बजरंग कभी भी शाको को जाने देना चाहते हैं। हालांकि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआइ) विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में शाको द्वारा विरोध बैटन फेंकने से खुश नहीं था। इसकी वजह से बजरंग को एक पेनाल्टी अंक खानी पड़ी थी जिसने मुकाबले के नतीजे पर असर डाला। डब्ल्यूएफआइ ने कहा है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता।

जौहरी और सबा होंगे नए बीसीसीआइ के निशाने पर

जांच के घेरे में आ सकते हैं इन दोनों के द्वारा लिए गए फैसले, महिला टीम के सहायक स्टाफ की नियुक्ति में हुए विवाद से मिलेगा मौका

अभिषेक त्रिपाठी • नई दिल्ली

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के नेतृत्व में आने वाली बीसीसीआइ पदाधिकारियों की नई फौज के निशाने पर सबसे पहले सीईओ राहुल जौहरी और जीएम (क्रिकेट परिचालन) सबा करीम होंगे क्योंकि राज्य क्रिकेट संघों के अधिकतर दिग्गज इनसे खुश नहीं हैं।

महिला टीम के सहायक स्टाफ की नियुक्ति को लेकर हुए हालिया विवाद ने बीसीसीआइ के नए पदाधिकारियों को मौका दे दिया है। मालूम हो कि 23 अक्टूबर को सौरव गांगुली अध्यक्ष, जय शाह सचिव, अरुण सिंह धूमल कोषाध्यक्ष, माहिम वर्मा उपध्यक्ष और जयेश जॉर्ज संयुक्त सचिव पद पर आसीन होंगे। बोर्ड के एक दिग्गज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) के कार्यकाल के दौरान जौहरी और सबा ने मनमाने फैसले किए जिसका हिसाब लेने का समय आ गया है। इनके अलावा भी कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में काफी शिकायतें हैं। उनकी भी जांच की जाएगी। महिला टीम के सहायक स्टाफ की नियुक्ति में की गई गलतियां तो एक बानगी है, ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जिससे भारतीय क्रिकेट का नुकसान हुआ है। यही नहीं इनके कार्यकाल के दौरान बीसीसीआइ के पूर्व दिग्गजों और कई राज्य संघों के अधिकारियों की काफी बेइज्जती भी की गई। इनके रहते पिछले कुछ सालों में आइसीसी में बीसीसीआइ का रुतबा घटा है।

इडुल्जी और रंगास्वामी भड़कीं

नई दिल्ली : सीओए सदस्य डायना इडुल्जी और बीसीसीआइ की शीर्ष परिषद की नई सदस्य शांता रंगास्वामी ने शुक्रवार को सीईओ राहुल जौहरी को पत्र लिखकर महिला राष्ट्रीय टीम के लिए सहायक स्टाफ की 'असंवैधानिक' नियुक्ति पर सवाल उठाए। सबा करीम इन नियुक्तियों के लिए वह संदेह के घेरे में हैं। हेमलता काला की अगुआई वाली महिला चयन समिति ने एक दिन पहले सीईओ को मेल लिखकर दावा किया था कि उन्हें सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया से दूर रखा गया था। इडुल्जी और रंगास्वामी ने इस रवैये की आलोचना की। मालूम हो कि 23 अक्टूबर से पहले वर्तमान अधिकारी अपने मनमुताबिक फैसले ले रहे हैं। बीसीसीआइ के नए संविधान के अनुसार चयनकर्ता ही पुरुष और महिला राष्ट्रीय टीम के सहयोगी स्टाफ नियुक्त करते हैं।

गलत प्रक्रिया अपनाई गई

इडुल्जी ने सीईओ को पत्र में लिखा कि महिला चयनकर्ताओं द्वारा आपको लिखे गए ईमेल को पढ़कर मैं हैरान हूं कि वीडियो विश्लेषक के चयन के लिए गलत प्रक्रिया अपनाई गई। चयनित पुष्कर सावंत वेस्टइंडीज के लिए फ्लाइट भी बुक करा चुके हैं जिन्हें सबा करीम इस पद पर चाहते थे। महिला चयनकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्हें महिला टीम के गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण कोच की नियुक्ति के लिए भी विश्वास में नहीं लिया गया था। उन्हें सिर्फ वीडियो विश्लेषक की भूमिका के लिए साक्षात्कार कराने को कहा गया। इडुल्जी और रंगास्वामी ने दावा किया कि इसके लिए भी नियमों का उल्लंघन किया गया। एनसीए के गेंदबाजी कोच नरेंद्र हिरवानी और टी. दिलीप भारतीय महिला टीम के साथ क्रमश: गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण कोच के रूप में वेस्टइंडीज जाएंगे।

शास्त्री की दोबारा नियुक्ति की जरूरत नहीं : गांगुली

कोलकाता : अध्यक्ष सौरव गांगुली के टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री से रिश्ते भले ही ठीक न हों लेकिन गांगुली ने कहा है कि कोच को दोबारा नियुक्ति की जरूरत नहीं है। शास्त्री को कोच चुनने वाली क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) को बोर्ड के लोकपाल डीके जैन ने हितों के टकराव में घसीटा था और ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थीं कि अगर सीएसी का गठन अवैध घोषित होता है तो शास्त्री की कुर्सी जा सकती है। गांगुली ने कहा है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। गांगुली ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इससे शास्त्री के चयन में कुछ परेशानी आएगी।

टॉस के लिए किसी दूसरे को भेजने के लिए तैयार हैं डु प्लेसिस

जागरण संवाददाता, रांची: एशिया में लगातार नौ मैचों में टॉस हारने से बेचैन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान रांची में हर हाल में टॉस जीतना चाहते हैं। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने कहा, हम यहां अपनी शर्तों पर मुकाबला करना चाहते हैं और शनिवार को हम टॉस जीतने के लिए संभवतः कुछ नया करेंगे। इसके लिए उन्हें टॉस के लिए विराट के साथ टीम के किसी दूसरे खिलाड़ी को भेजने में भी कोई गुरेज नहीं है। मौजूदा टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका भारतीय परिस्थितियों में जूझता रहा है और पहले दो टेस्ट मैचों में टॉस हारने के कारण चीजें और भी ज्यादा उसके बस से बाहर चली गईं।

डुप्लेसिस ने मैच की पूर्व संध्या पर कहा कि हम वास्तव में चाहते हैं कि हम इस टीम से अपनी शर्तों पर मुकाबला करें। पहले टेस्ट मैच में कुछ चरणों में हमने ऐसा किया इसलिए उम्मीद है कि शनिवार को हम टॉस से इसकी शुरुआत करेंगे। उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि संभवतः हम बदलाव करेंगे। मेरा रिकॉर्ड अभी तक इसमें (टॉस जीतने) अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में शनिवार को टॉस के लिए किसी अन्य को भेजा जा सकता है। डुप्लेसिस ने कहा कि अगर उनकी टीम को पहले बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। अगर आप पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा करते हो तो फिर वहां से कुछ भी संभव है। उम्मीद है कि अगले दो दिन में इसका पता चल जाएगा और हम अच्छा स्कोर बनाएंगे। पिच थोड़ी सूखी लग रही है और ऐसे में पहली पारी के रन महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके बाद दूसरी पारी में कुछ भी हो सकता है।

दर्शक दीर्घा से टीम का हौसला बढ़ाएंगे धौनी

जागरण संवाददाता, रांची: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच शनिवार से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी भी मौजूद रहेंगे। धौनी एक खिलाड़ी के रूप में नहीं बल्कि दर्शक के रूप में टीम इंडिया का हौसला बढ़ाते नजर आएंगे। धौनी पिछले 10 दिनों से रांची से बाहर हैं। पारिवारिक सूत्रों की मानें तो वह शनिवार को रांची आ जाएंगे। धौनी के स्कूल के समय के कोच केआर बनर्जी ने बताया कि माही शनिवार तक रांची आ जाएगा।

वहीं झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के सचिव संजय सहाय ने बताया कि धौनी का हम स्वागत करते हैं। वह हमारे गौरव हैं। मैच में उनकी उपस्थिति ना सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएगी बल्कि दर्शक भी खुश होंगे। 2017 में हुए टेस्ट मैच में भी धौनी मैच के दिनों में स्टेडियम आकर भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते थे।

दादा का बीसीसीआइ अध्यक्ष बनना अच्छा संकेत : साहा

जागरण संवाददाता, रांची : भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा मानते हैं कि दादा (सौरव गांगुली) का बीसीसीआइ अध्यक्ष बनना भारतीय खिलाड़ियों के लिए अच्छा संकेत है।

मैच के पूर्व संवाददाता सम्मेलन में साहा ने कहा दादा लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेले हैं उन्हें पता है कि खिलाड़ियों का कहां और क्या परेशानी होती है। उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होगी। एक खिलाड़ी ही दूसरे खिलाड़ी के दर्द को समझ सकता है इसलिए मुझे लगता है कि कप्तानी की तरह यहां भी वह नए युग की शुरुआत करेंगे। दादा के नेतृत्व में कई अच्छे काम होंगे। साहा ने कहा कि युवा विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत के साथ कोई समस्या नहीं है हमारी ट्यूनिंग बेहतर है। उसे जब भी कोई समस्या होती है तो मुझसे वह बात करता है। वह प्रतिभावान है और अनुभव के साथ साथ बेहतर होता चला जाएगा। विकेटकीपिंग से जुड़े सवाल पर रिद्धिमान साहा ने कहा कि यह मुश्किल जॉब है। बेहतर करते है तो ठीक है अगर कुछ गलत हुआ तो सब कुछ विकेटकीपर के ऊपर लाद दिया जाता है। रांची के जेएससीए स्टेडियम में रिद्धिमान साहा ने साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ117 रन बनाए थे।

गांगुली को सम्मानित करेगा कैब

खेल संवाददाता, कोलकाता

बीसीसीआइ के भावी अध्यक्ष सौरव गांगुली को 25 अक्टूबर को बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) सम्मानित करेगा। सम्मान समारोह में टीम इंडिया में सौरव के प्रथम कप्तान रहे मुहम्मद अजहरुद्दीन के अलावा युवराज सिंह, वीवीएस लक्ष्मण एवं हरभजन सिंह मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बंगाल रणजी टीम के सारे पूर्व कप्तानों को भी आमंत्रित किया गया है।

कैब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सम्मान समारोह के पहले कोलकाता के एक पांच सितारा होटल में होने की बात थी लेकिन बाद में ईडन गार्डेंस स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम के सामने इसका आयोजन करने का निर्णय लिया गया। सम्मान समारोह में सौरव को चांदी का एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। स्मृति चिन्ह में सौरव के चेहरे की प्रतिकृति होगी। 'दादा' के क्रिकेट जीवन पर आधारित एक वृत्तचित्र भी प्रदर्शित किया जाएगा। बता दें कि सौरव 23 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर बीसीसीआइ के अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाल लेंगे। उसी खुशी में कैब की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सौरव कैब के अध्यक्ष भी हैं। जगमोहन डालमिया के बाद वे बंगाल से यह पदभार संभालने वाले दूसरे व्यक्ति होंगे। गौरतलब है कि कैब की ओर से गत 15 अक्टूबर को भी सौरव के कोलकाता लौटने पर ईडन गार्डेंस में उनका भव्य स्वागत किया गया था। स्टेडियम को फूलों से सजाया गया था। सौरव के लिए 10 पाउंड का एक केक भी तैयार किया गया था, जिसे उन्होंने कैब पदाधिकारियों की उपस्थिति में काटा था।

बीसीसीआइ के भावी अध्यक्ष गांगुली।

फुटबॉल डायरी विरोध प्रदर्शन की वजह से टला बहुप्रतीक्षित मैच, दोनों क्लबों के पास नई तारीख तय करने के लिए 21 अक्टूबर तक का समय

बार्सिलोना-रीयल के बीच होने वाला एल क्लासिको टला

मैड्रिड, एएफपी : कैटलोनिया में चल रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना और रीयल मैड्रिड के बीच होने वाले बहुप्रतीक्षित एल क्लासिको की भिड़ंत को टाल दिया गया है। स्पेनिश फुटबॉल महासंघ (आरएफईएफ) ने इसकी जानकारी दी।

अब दोनों क्लबों के पास नई तारीख को चुनने के लिए सोमवार को स्थानीय समयानुसार 10 बजे सुबह तक का वक्त है। अगर तब तक दोनों क्लब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते तो आरएफईएफ इस पर फैसला लेगा। बार्सिलोना और रीयल के बीच 26 अक्टूबर को कैंप नाउ में एल क्लासिको की भिड़ंत होनी थी लेकिन वहां हो रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से इसको फिलहाल टाल दिया गया है। आरएफईएफ ने कहा कि बार्सिलोना और रीयल मैड्रिड को नई तारीख की घोषणा 21 अक्टूबर से पहले करनी होगी। अगर ये दोनों किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं तो प्रतियोगिता समिति नई तारीख पर विचार करेगी।

स्पेनिश फुटबॉल लीग (एलएफपी) ने बुधवार को कहा था कि तीन दिनों से जारी गतिरोध के चलते उसने आरएफईएफ से इस मुकाबले को बार्सिलोना से हटाकर मैड्रिड में कराने की मांग की थी। बार्सिलोना के नौ संप्रदायवादी नेताओं को जेल भेजे जाने की वजह से वहां पिछले कई दिनों से उग्र प्रदर्शन हो रहा है। ये लोग स्पेन से अलग कैटलोनिया देश बनाने की मांग कर रहे थे।

बार्सिलोना और रीयल के लिए कड़े इम्तहान की घड़ी : राजनीतिक ड्रामे के बीच अगले सप्ताह होने वाला एल क्लासिको भले ही टल चुका है लेकिन बार्सिलोना और रीयल मैड्रिड को इस सप्ताह कड़े इम्तेहान से गुजरना होगा। शनिवार को ला लीगा में बार्सिलोना को ईबर से भिड़ना है। एक दिन पहले इस मुकाबले की प्रेस वार्ता की गई ताकि बार्सिलोना की टीम एल प्रात एयरपोर्ट पर होने वाले विरोध प्रदर्शन से बचने के लिए 589 किलोमीटर लंबी बस यात्रा शुरू किर सके। उधर रीयल मैड्रिड को भी शनिवार को मालोर्का से भिड़ना है। मैनेजर जिनेदिन जिदान की रीयल टीम को इस मुकाबले में अपने स्टार लुका मॉड्रिक और गेरेथ बेल के बगैर उतरना पड़ सकता है। ये दोनों खिलाड़ी चोटिल हैं। शनिवार को ही ला लीगा के एक अन्य मुकाबले में एटलेटिको मैड्रिड को वेलेंसिया से भिड़ना है।

कैटलोनिया में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच फुटबॉल खेलते बच्चे • रायटर

नई शुरुआत पर सिटी की निगाहें

लंदन : इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में अगले दो दिन काफी रोमांच भरे रहने वाले हैं। शनिवार को मैनचेस्टर सिटी की टीम क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ उतरेगी जहां उसकी निगाहें जीत के साथ नई शुरुआत करने पर होगी। वहीं शनिवार को ही वाटफोर्ड के खिलाफ टॉटनहम मैदान में उतरेगा और हाल के समय में अपने खराब प्रदर्शन के दौर से निकलने की कोशिश करेगा। उधर रविवार को शानदार फॉर्म में चल रही लिवरपूल की टीम मैनचेस्टर युनाइटेड के खिलाफ उसके घरेलू मैदान पर उतरेगी। इस दौरान लिवरपूल ओल्ड ट्रैफर्ड में पिछले पांच वर्षों में पहली जीत दर्ज करके खराब दौर से गुजर रहे युनाइटेड के जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश करेगा। क्लब के खराब प्रदर्शन के बावजूद युनाइटेड के मैनेजर ओले गनर सोल्सकजेर ने कहा है कि उनके लिए युनाइटेड की नौकरी बहुत बड़ी नहीं है और वह इस क्लब को संभाल सकते हैं। अब तक युनाइटेड मौजूदा सत्र में केवल दो अंक हासिल कर पाया है।

बाकी रेस भी पोडियम पर समाप्त करने की कोशिश करूंगा : मार्केज

उमेश राजपूत, मोटेगी (जापान) : मोटो ग्रांप्रि 2019 के 16वें चरण की क्वालीफाइंग रेस जब शनिवार को यहां शुरू होगी तो सभी की नजरें भाग लेने वाले बाइक रेसरों में से स्पेन के मार्क मार्केज पर होंगी, जो पहले ही मोटो ग्रांप्रि 2019 विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। हालांकि, इसके बावजूद रेपसोल होंडा के बाइक रेसर मार्केज इस रेस को बिलकुल भी हल्के में नहीं लेना चाहते हैं और उनका इरादा अपनी जीत के अंतर को बड़ा करने का है। इस रेस में कुल 23 बाइक रेसर भाग ले रहे हैं।

2012 में अपने मोटो ग्रांप्रि की शुरुआत करने वाले 26 सालके मार्केज अब तक छह विश्व चैंपियनशिप पर कब्जा जमा चुके हैं और 2016 से लगातार चार बार विश्व खिताब अपने नाम कर चुके हैं। शुक्रवार को यहां पहली और दूसरी फ्री प्रैक्टिस में चौथे और तीसरे स्थान पर रहने वाले मार्केज का इरादा बाकी बचीं चार रेसों में से कुछ और में पोल पोजीशन हासिल करने का है।

उन्होंने कहा कि मैं उसी मानसिकता के साथ ही जाऊंगा. मैं बाकी बची हुई सभी रेस भी पोडियम पर समाप्त करने की कोशिश करूंगा। ये पिछली चार रेस जीतना असंभव नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। कुछ सर्किटों में यामाहा के रेसर बहुत तेज थे तो कुछ सर्किटों में डुकाटी के, लेकिन मैं अपना ध्यान केंद्रित रखने और उसी मानसिकता के साथ जाने की कोशिश करूंगा, जैसे मैंने पूरे सत्र में किया है। मार्केज ने 2013 में पहली बार विश्व चैंपियनशिप जीती थी और फिर अगले साल 2014 में इस खिताब का बचाव किया था।

रोमांच
- मोटो ग्रांप्रि 2019 के 16वें चरण की क्वालीफाइंग रेस आज
- पहले ही विश्व चैंपियनशिप पर कब्जा जमा चुके हैं स्पेन के मार्क
- 2016 से लगातार चार बार बन चुके हैं विश्व चैंपियन

पत्रकार वार्ता में मौजूद स्पेन के मार्क मार्केज। जागरण

पूर्व क्रिकेटर माधव आप्टे की याद में होगी शोक सभा

मुंबई : मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) भारत और मुंबई के पूर्व पूर्व सलामी बल्लेबाज माधव आप्टे की याद में 22 अक्टूबर को शोक सभा का आयोजन करेगा। आप्टे का 86 साल की उम्र में 23 सितंबर को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। एमसीए ने बताया कि भारत और मुंबई के पूर्व खिलाड़ी माधव आप्टे की याद में एमसीए के तत्वावधान में संबद्ध क्लबों के सदस्यों, क्रिकेटरों और अंपायरों की शोक सभा 22 अक्टूबर को होगी।

बांग्लादेश से ड्रॉ खेलने के बाद अभी काफी मैच बचे हैं और बहुत कुछ करना बाकी है।
– इगोर स्टिमक, भारतीय फुटबॉल टीम के कोच

न्यूज गैलरी

एशियन चैंपियनशिप में भारत ने जीते 21 पदक

नई दिल्ली : भारतीय मुक्केबाजों ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के फुजैराह में एशियन जूनियर चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए छह स्वर्ण, नौ रजत के साथ कुल 21 पदक जीते। इस टूर्नामेंट में 26 देशों के मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया जिनमें भारत कुल पदकों जीतने के मामले में सबसे आगे रहा लेकिन वह तालिका में उज्बेकिस्तान (20 पदक) के बाद दूसरे स्थान पर रहा जिसने छह स्वर्ण अपने नाम किए। भारतीय पुरुष टीम ने दो स्वर्ण, तीन रजत और इतने ही कांस्य पदक जीते जबकि महिला टीम ने चार स्वर्ण, छह रजत और तीन कांस्य जीते। (प्रेट्र)

भारत और ब्रिटेन ने खेला ड्रॉ

जोहोर बाहरू (मलेशिया) : भारत और ब्रिटेन की पुरुष हॉकी टीम ने नौवें सुल्तान जोहोर कप के आखिरी राउंड रॉबिन मुकाबले में 3-3 से ड्रॉ खेला। ब्रिटेन को 27वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर के रूप में पहला मौका मिला और इयोन वाल की ड्रैग फ्लिक से टीम ने शुरुआती बढ़त हासिल की। इसके बाद एंड्रयू मैककोनेल ने गोल करके जापान को दोहरी बढ़त दिलाई। भारत के शिलानंद लाकड़ा ने इस अंतर को कम किया और फिर मनदीप मोर ने 51वें मिनट में गोल करके स्कोर 2-2 से बराबर किया। इसके बाद 57वें मिनट भारत के शारदा नंद तिवारी ने पेनाल्टी स्टोक पर गोल करके बारत को बराबरी दिलाई लेकिन मुकाबले से एक मिनट पहले इंग्लैंड ने बराबरी का गोल दागा। (प्रेट्र)

भारतीय हॉकी टीम का एलान

नई दिल्ली : हाकी इंडिया ने आगामी एफआइएच हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर के लिए शुक्रवार को पुरुष और महिला टीमों की घोषणा की। 18 सदस्यीय पुरुष टीम की कप्तानी मनप्रीत सिंह करेंगे जबकि स्ट्राइकर एसवी सुनील उप कप्तान होंगे। वहीं इंग्लैंड दौरे पर गई महिला टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है जिसकी कमान रानी रामपाल होंगी जबकि उप कप्तान गोलकीपर सविता होंगी। पुरुष और महिला टीमें ओडिशा के भुवनेश्वर में एक और दो नवंबर को अपने-अपने प्रतिद्वंद्वियों से भिड़ेंगी। इस क्वालीफायर टूर्नामेंट में भारत का सामना रूस से होगा। (प्रेट्र)

ली जुई रुई ने लिया संन्यास

नई दिल्ली : पूर्व ओलंपिक चैंपियन चीन की महिला शटलर ली जुई रुई ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। विश्व बैडमिंटन महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर बताया कि 14 सुपर सीरीज खिताब जीतने वाली ली को एक हमेशा एक आक्रामक खिलाड़ी के रूप में याद रखा जाएगा। (प्रेट्र)

झटका ▸ टी-20 में बाबर आजम और टेस्ट टीम के कप्तान होंगे अजहर अली

सरफराज अहमद से कप्तानी छीनी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टी-20 सीरीज के लिए टीम से भी हुए बाहर

कराची, प्रेट्र : सरफराज अहमद को पाकिस्तान की टेस्ट और टी-20 टीम के कप्तान पद से हटा दिया गया है। अजहर अली को टेस्ट तथा बाबर आजम को अगले साल होने वाले टी-20 विश्व कप तक सबसे छोटे प्रारूप के लिए टीम की कमान सौंपी गई है। इंग्लैंड में आयोजित आइसीसी विश्व कप में पाकिस्तानी टीम के खराब प्रदर्शन के बाद से सरफराज पर तलवार लटक रही थी। ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली आगामी सीरीज के लिए भी उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है। पाकिस्तानी टीम तीन टी-20 और दो टेस्ट मैच खेलेगी। यह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान का पदार्पण होगा।

सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान ने साल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और टी-20 रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचा था। हाल ही में इस टीम ने श्रीलंका के खिलाफ घर में 10 साल बाद सीरीज खेली और बुरी तरह हार गई। कप्तानी से हटाए जाने परे सरफराज ने कहा कि उच्च स्तर पर पाकिस्तान का नेतृत्व करना बेहद सम्मानजनक रहा। मैं अपने सभी सहयोगियों, कोचों और चयनकताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस यात्रा में मेरी मदद की है। मेरी शुभकामनाएं अजहर अली, बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है और मुझे आशा है कि वे आगे भी मजबूत और मजबूत होते रहेंगे। टेस्ट टीम के नए कप्तान अजहर ने कहा कि मेरा लक्ष्य न केवल जीत हासिल करना है बल्कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और खुद को अभिव्यक्त करने के लिए अवसर प्रदान करना भी है ताकि पाकिस्तान क्रिकेट शीर्ष तक पहुंचने की अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सके। मैंने हमेशा अपने क्रिकेट को कठिन और निष्पक्ष तरीके से खेला है और आगे भी यह सुनिश्चित करूंगा कि क्रिकेट की भावना को बनाए रखूं और टीम एवं देश की छवि बेहतर करूं।

बाबर ने कहा कि विश्व की नंबर-1 टीम का कप्तान बनाया जाना अभी तक मेरे करियर का सबसे बड़ा पल है। मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूं और इस प्रक्रिया के दौरान बहुत कुछ सीखना भी चाहता हूं। सरफराज ने इस प्रारूप में शानदार कप्तानी करते हुए एक उदाहरण पेश किया है और यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी उपलब्धियों को आगे बढ़ाऊं ताकि हम एक दमदार टीम बने रह सके।

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद। फाइल फोटो

इंग्लैंड ने जीतन पटेल को गेंदबाजी सलाहकार के रूप में चुना

लंदन, एएफपी : इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टी-20 सीरीज के लिए जीतन पटेल को स्पिन गेंदबाजी सलाहकार के रूप में टीम के साथ जोड़ा है। क्रिकेट वेलिंग्टन के साथ पटेल का करार है। हालांकि, उसने पटेल को इंग्लैंड की टीम के साथ जुड़ने की अनुमति दे दी है। पटेल इसके कारण प्लंकेट शील्ड प्रतियोगिता के शुरुआती तीन मैच नहीं खेलेंगे। अगले सप्ताह इंग्लैंड के क्राइस्टचर्च पहुंचने पर पटेल टीम से जुड़ेंगे। न्यूजीलैंड के पूर्व स्पिनर पटेल ने कहा कि मुझे मौका मिला और मैंने क्रिकेट वेलिंग्टन से बात की। वह इसे लेकर बहुत सकारात्मक थे। सबसे पहले इसके जरिए खेल से इतर मेरा विकास होगा और मेरे टीम में न होने से अन्य खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा। पटेल ने कहा कि मुझे नहीं पता कि यह कैसा रहेगा और मुझे यह भी नहीं पता है कि क्या मैं इसमें बेहतर कर पाऊंगा। लेकिन मैं प्रयास जरूर करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ खिलाड़ियों को मदद कर सकती है।

हार्दिक ने साझा की मां के साथ तस्वीर

अपनी मां संग भारतीय क्रिकेटर हार्दिक। ट्विटर

नई दिल्ली, आइएनए : भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शुक्रवार को अपनी मां के साथ एक बेहद प्यारी तस्वीर साझा की। ट्विटर पर तस्वीर को साझा करते हुए हार्दिक ने लिखा, मां मैं हमेशा तुम्हारी तरफदारी करूंगा। इससे पहले हार्दिक ने 16 अक्टूबर को भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव द्वारा दी गई भारतीय टीम की कैप की तस्वीर साझा की थी। हार्दिक की हाल ही में लंदन में पीठ के पिछले हिस्से की सर्जरी हुई है और वह फिलहाल अपनी फिटनेस हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं।

आज मिलेगा नया कबड्डी चैंपियन

प्रो कबड्डी लीग

‘ये बेहद जबर्दस्त मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमें पहली बार फाइनल में हैं। हमें यकीन है कि ये एक देखने वाला मैच होगा।
–बीसी रमेश, कोच बंगाल वारियर्स

दोनों टीमें काफी अनुशासित हैं। कोच के तौर पर मैं वादा करता हूं कि हमारी टीम प्रशंसकों को निराश नहीं करेगी।
–कृष्णन कुमार हुड्डा, कोच दबंग दिल्ली

विशाल श्रेष्ठ, कोलकाता : तीन महीने तक चले कड़े मुकाबले के बाद आखिरकार फैसले का दिन आ गया है। आज यानि शनिवार को प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) को नया चैंपियन मिल जाएगा। एक तरफ दिल्ली के दबंग हैं तो दूसरी तरफ बंगाल के वारियर्स। दोनों की निगाहें अपने पहले खिताब पर हैं। अहमदाबाद का एका एरिना स्टेडियम भी इस आखिरी जंग के लिए तैयार है। आंकड़ों पर गौर करें तो इसे बराबरी का मुकाबला कहा जा सकता है। दोनों टीमें पीकेएल के इतिहास में अब तक 14 बार भिड़ी हैं और 6-6 मैच जीती हैं। दो मैच टाई रहे हैं। हालांकि मौजूदा सत्र के लिहाज से बंगाल का पलड़ा भारी है। इस सत्र में दोनों टीमों के बीच दो मैच हुए हैं, जिनमें से एक बंगाल ने जीता है और दूसरा टाई रहा है।

मनिंदर पर सस्पेंस बरकरार: बंगाल के चोटिल कप्तान मनिंदर सिंह के खेलने पर सस्पेंस बरकरार है। यू मुंबा के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल में उनकी अनुपस्थिति में मुहम्मद इस्माइल नबीबख्श ने टीम की कमान संभाली थी। मनिंदर अपनी टीम के शीर्ष रेडर भी हैं। इस सत्र के 20 मैचों में उन्होंने 205 अंक अर्जित किए हैं, जिनमें 10 सुपर-10 शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के खिलाफ उनका प्रदर्शन हमेशा ही शानदार रहा है।

दिल्ली को नवीन से काफी उम्मीदें : दिल्ली को एक बार फिर अपने स्टार रेडर नवीन कुमार से भारी उम्मीदें हैं। वह इस सत्र में दिल्ली के सबसे सफल खिलाड़ी रहे हैं। नवीन के जबरस्त फॉर्म का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक मैच को छोड़कर बाकी सभी मैचों में सुपर-10 अर्जित किए हैं। नवीन ने 22 मैचों में 283 रेड अंक अर्जित किए हैं, जिनमें 21 सुपर-10 शामिल हैं।

बनेंगे ये रिकॉर्ड : पीकेएल-7 के फाइनल में कई व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनेंगे या बनने की संभावना हैं। अगर दबंग दिल्ली जीतती है तो विशाल माणे पीकेएल के इतिहास में तीन विजयी टीमों का हिस्सा बनने वाले पहले खिलाड़ी हो जाएंगे। वह दूसरे सत्र में यू मुंबा और पांचवें सत्र में पटना पाइरेट्स के सदस्य थे। वहीं बंगाल के जीवा कुमार मैदान में उतरने पर अपना चौथा फाइनल खेलेंगे। पिछले तीनों खिताबी मुकाबले उन्होंने यूं मुंबा की तरफ से खेले थे। बंगाल के सुकेश हेगड़े के लिए यह फाइनल इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि यह पीकेएल में उनका 100वां मैच होगा।

बोनस अंक जुटाने में माहिर है दिल्ली : दिल्ली का एक मजबूत पक्ष यह है कि वह बोनस अंक जुटाने में माहिर है।

जरीन मसले पर बीएफआइ को सर्वश्रेष्ठ फैसला लेने को कहूंगा : रिजिजू

भारत सरकार में खेल मंत्री किरण रिजिजू। फाइल फोटो

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

▸ खेल मंत्री ने भारतीय मुक्केबाज के पत्र का दिया जवाब

▸ ओलंपिक क्वालीफायर में मेरी कॉम को चुनने की खबर से नाराज हैं निखत

खेल मंत्री किरण रिजिजू ने महिला मुक्केबाज निखत जरीन के एमसी मेरी कॉम के खिलाफ ट्रायल मुकाबला कराने की मांग पर कहा कि वह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआइ) को केवल देश और खिलाड़ियों के हित में सर्वश्रेष्ठ फैसला करने के लिए कह सकते हैं।

जरीन ने गुरुवार को रिजिजू को पत्र लिखकर चीन में अगले साल होने वाले ओलंपिक क्वालीफायर के लिए भारतीय टीम के चयन से पहले मेरी कॉम के खिलाफ ट्रायल मुकाबला आयोजित करने की मांग की थी। इससे पहले बीएफआइ ने कहा था कि मेरी कॉम (51 किग्रा) के हाल में रूस में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए वह छह बार की विश्व चैंपियन को चुनना चाहता है। इसके बाद ही जरीन ने यह पत्र लिखा।

रिजिजू ने जरीन के पत्र के जवाब में कहा कि निश्चित तौर पर मुक्केबाजी महासंघ को देश, खेल और खिलाड़ियों के सर्वश्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला करने के लिए कहूंगा। हालांकि मंत्री को खेल संघों द्वारा खिलाड़ियों के चयन में शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि खेल संघ ओलंपिक चार्टर के अनुसार स्वायत्त हैं।

मेरी कॉम ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह बीएफआइ के फैसले के अनुसार चलेंगी। बीएफआइ ने पहले कहा था कि विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण और रजत पदक विजेता मुक्केबाजों का ही ओलंपिक क्वालीफायर के लिए सीधे चयन होगा। जरीन को विश्व चैंपियनशिप से पहले भी ट्रायल मुकाबले का मौका नहीं दिया गया था। महासंघ ने तब इंडिया ओपन और प्रेसिडेंट कप में स्वर्ण पदक जीतने के कारण मेरी कॉम का चयन करने का फैसला किया था। जरीन को भारत के एकमात्र व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा का भी समर्थन मिला है।

उधर जरीन ने खेल मंत्री के पत्र के बाद कहा कि जल्दी जवाब देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करती हूं कि उन खिलाड़ियों के पक्षपात या भाई-भतीजावाद नहीं होगा जो देश के सम्मान के लिए कड़ी मेहनत करते हैं।

बीएफआइ बुलाएगा चयन समिति की बैठक

नई दिल्ली : जरीन के मसले पर विचार करने के लिए बीएफआइ अगले सप्ताह चयन समिति की बैठक बुलाएगा। एक सूत्र ने बताया कि बीएफआइ अध्यक्ष देश से बाहर हैं। उनके आने का इंतजार है। हम राष्ट्रीय चयन समिति की बैठक फिर से बुलाएंगे। वहां खिलाड़ी नहीं होंगे। यह बैठक आने वाले सप्ताह में हो सकती है। अभी दिल्ली में इसके सदस्य नहीं हैं लेकिन उन्हें बुलाया जाएगा।

विविध

श्री हरिमंदिर साहिब के दर्शन करेंगे 90 देशों के राजदूत

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

▸ श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव से पहले भारत देगा दुनिया को संदेश

▸ राजदूतों को लेकर विशेष विमान से अमृतसर पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी

श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव की भव्यता का संदेश दुनिया भर में पहुंचाने के लिए भारत सरकार आगामी मंगलवार को 90 देशों के राजदूतों को अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब के दर्शन करवाने जा रही है। इन सभी राजदूतों को भारत में प्रकाश पर्व को लेकर जारी तैयारियों की जानकारी दी जाएगी।

राजदूतों को विशेष विमान से केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी के नेतृत्व में अमृतसर लाया जाएगा। इस दौरे के दौरान पारंपरिक गिद्धा और भांगड़ा नृत्य का आयोजन होगा, जिसके बाद उन्हें श्री हरिमंदिर साहिब के दर्शन करवाए जाएंगे। उन्हें सिख इतिहास और पंजाबी संस्कृति से अवगत करवाने के लिए विशेष गैलरियों के दर्शन भी करवाए जाएंगे। इसके बाद उन्हें श्री हरमंदिर साहिब का प्रसिद्ध लंगर भी छकाया जाएगा।

अर्ध कुंभ मेले में गए थे राजदूत : उल्लेखनीय है कि इससे पहले भारत सरकार ने दिसंबर 2018 में प्रयागराज में आयोजित अर्ध कुंभ मेले से पहले भी 70 देशों के राजदूतों को वहां का दौरा करवाया था। अर्ध कुंभ की तैयारियों के बारे में उन्हें जानकारी दी गई थी।

भारत सरकार का मास्टर स्ट्रोक : 550वें प्रकाशोत्सव पर भारत-पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने के प्रयासों और इस महोत्सव की भव्यता का श्रेय लेने को लेकर भारत और पाकिस्तान सरकार के बीच जारी कशमकश में भारत सरकार का यह कदम एक मास्टर-स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। इन राजदूतों में बोलिविया, बुरकिना फासो, कोस्टा रिका, इजिप्ट, इराक, इंडोनेशिया, इज़राइल जैसे देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा विदेश मंत्रालय फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और यूएई जैसे लगभग आधा दर्जन देशों में गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़े अहम तथ्यों के डिजिटल डिस्प्ले का प्रयास भी कर रहा है। कोशिश है कि वहां के लोग भी गुरु नानक देव जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं से अवगत हो पाएं।

पंजाब सरकार और एसजीपीसी करेगी प्रबंध : राजदूतों के इस दौरे का आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। पंजाब सरकार और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) इस दौरे के सभी प्रबंध करेगी। माना जा रहा है कि भारत सरकार ऐसे आयोजनों से विश्व समुदाय को भारत की धार्मिक विविधता और भारतीयों की धार्मिक स्वच्छंदता का संदेश देना चाहती है। सरकार बताना चाहती है कि यहां लोग अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं।

20 डालर की फीस पर अंतिम निर्णय बाकी : गौरतलब है कि करतारपुर कॉरिडोर खुलने में लगभग सवा दो सप्ताह बचे हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच कॉरिडोर को खोलने की शर्तें अभी अंतिम रूप नहीं ले पाई हैं। पाकिस्तान द्वारा भारतीय तीर्थयात्रियों से 20 डॉलर की फीस वसूलने की शर्त पर दोनों पक्षों में अभी गतिरोध जारी है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार, प्रवेश शुल्क के अलावा अन्य सभी विषयों पर दोनों पक्ष समझौते पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान सरकार की ओर से प्रस्तावित प्रति यात्री लगभग 1420 रुपये की फीस करतारपुर गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने की इच्छा रखने वाले सामान्य लोगों के लिए काफी अधिक है। भारतीय पक्ष उम्मीद कर रहा है कि दोनों पक्ष फीस के मसले पर भी समझौते पर पहुंच जाएंगे।

भारतीय अधिकारी की तैनाती पर पाक सहमत : जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में महोत्सव के दौरान भारतीय उच्चायोग के अधिकारी को करतारपुर में तैनात किए जाने पर सहमति दे दी है। विशेष दिवसों पर दस हजार भारतीय यात्रियों के करतारपुर में प्रवेश पर भी पाकिस्तान सरकार ने हामी भर दी है। तीर्थ यात्रियों के लिए करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में दर्शन और यात्रियों के लिए प्रवेश और निकास के समय निर्धारित करने पर भी अंतिम फैसला होना है।

आध्यात्मिक गुरु कल्कि की 500 करोड़ की अघोषित आय का पता चला

▸ आयकर विभाग ने 40 ठिकानों पर की छापेमारी

▸ कुल 93 करोड़ रुपये मूल्य की नकदी व संपत्तियां जब्त

▸ 88 किलो सोने के गहने और 1,271 कैरेट हीरे भी शामिल

चेन्नई, प्रेट्र : आयकर विभाग की तरफ से दक्षिण भारत के राज्यों में की गई छापेमारी में आध्यात्मिक गुरु कल्कि भगवान द्वारा स्थापित कई कंपनियों व ट्रस्टों की 500 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय पकड़ी गई।

आयकर विभाग के आधिकारिक बयान में शुक्रवार को बताया गया कि अघोषित आय में 409 करोड़ की बेहिसाब प्राप्ति रसीदें (कैश रीसिप्ट) शामिल हैं। इस दौरान 43.9 करोड़ रुपये की नकदी व 18 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की अमेरिकी मुद्रा भी जब्त की गई। कुल 93 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां जब्त की गई हैं। इनमें 88 किलो सोने के गहने, जिनकी कीमत 26 करोड़ रुपये है तथा करीब पांच करोड़ रुपये के 1,271 कैरेट हीरे शामिल हैं।

बयान के अनुसार, बुधवार को आध्यात्मिक गुरु द्वारा स्थापित कंपनियों व ट्रस्टों के 40 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इनमें चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु व आंध्र प्रदेश के वरदैयापालम (तमिलनाडु सीमा के करीब) शामिल हैं। कंपनी व ट्रस्टों के ठिकानों पर छापे अब भी जारी हैं। आध्यात्मिक गुरु की कंपनियां कल्याण पाठ्यक्रम (वेलनेस कोर्सेज) का संचालन करती हैं। एकात्म दर्शन पर आधारित इन पाठ्यक्रमों व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन वरदैयापालम, चेन्नई व बेंगलुरु स्थित कई आवासीय परिसरों में किया जाता है। इनके अनुयायियों में विदेशी भी शामिल हैं, जो यहां आकर रहते हैं और विदेशी मुद्रा में फीस चुकाते हैं। रियल स्टेट, निर्माण व देश-विदेश में खेल के क्षेत्रों से जुड़े इस समूह का संचालन आध्यात्मिक गुरु व उनके पुत्र करते हैं।

आयकर विभाग ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर छापे की कार्रवाई शुरू की गई। बताया गया था कि समूह उन प्राप्तियों को छिपा रहा है, जिनका निवेश विदेश व आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की संपत्तियों में किया गया है। छापेमारी के दौरान समूह की तरफ से संचालित किए जाने वाले विभिन्न केंद्रों व आश्रमों की प्राप्तियों को नियमित रूप से छिपाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ये साक्ष्य एक प्रमुख कर्मचारी के पास से बरामद हुए, जो कैश कलेक्शन का ब्योरा रखता है। उसने कैश कलेक्शन को खाते से अलग रखा था, जिससे उस राशि का निवेश अन्यत्र किया जा सके। यह भी पता चला है कि समूह ने संपत्तियों की बिक्री के जरिये भी अघोषित आय अर्जित की है। पहली नजर में वर्ष 2014-15 के बाद 409 करोड़ की बेहिसाब प्राप्तियां सामने आई हैं। आध्यात्मिक गुरु व उनके पुत्र के घर छापे में मिली नकदी व अन्य कीमती सामग्री से इन प्राप्तियों के साक्ष्य मिलते हैं।

टैक्स हैवेन देशों में भी किया है निवेश : आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आध्यात्मिक गुरु के समूह ने भारत के साथ-साथ टैक्स हैवेन देशों में भी निवेश किया है। इनकी कुछ कंपनियां चीन, अमेरिका, सिंगापुर व यूएई में भी हैं। इन कंपनियों के जरिये उन विदेशी ग्राहकों से पैसे वसूले जाते हैं, जो भारत में आवासीय पाठ्यक्रम में शामिल होने आते हैं।

फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, सात गिरफ्तार

जासं, कोलकाता : कोलकाता पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए अलग-अलग स्थानों से सात लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फर्जी काल सेंटर के नाम पर विदेशियों को ठगते थे। कोलकाता के संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) ने इसकी जानकारी दी।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के अधिवक्ता भूपिंदर सिंह बिंद्रा ने इस बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि कोई गिरोह माइक्रोसॉफ्ट के नाम पर सर्विस देने के बहाने लोगों से लाखों रुपये की ठगी कर रहा है। मूलरूप से अमेरिका के लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। शिकायत दर्ज होने के बाद हरकत में साइबर क्राइम शाखा की पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शहर में यूचार्ज ई-मार्केटिंग प्रा. लि. और विजन कॉल सेंटर प्रा. लि. के नाम पर दो स्थानों पर फर्जी कॉल सेंटर चलाए जा रहे थे। इसकी भनक लगते ही पुलिस ने काल सेंटरों पर छापा मारकर गिरोह में शामिल सात लोगों को दबोच लिया।

घर-घर पहुंचाई जाएगी अंतिम हिंदू सम्राट की गौरवगाथा

महेश कुमार वैद्य, रेवाड़ी

▸ इंटेक के रेवाड़ी चेप्टर संयोजक ने किया हेमू की हवेली का जीर्णोद्धार

हेमू के नाम से इतिहास में चर्चित अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की गौरवगाथा घर-घर पहुंचाई जाएगी। धर्म जागरण मंच सहित कई संगठन इस काम में सहयोग करेंगे। हेमचंद्र विक्रमादित्य की जन्मस्थली अलवर के गांव माचेड़ी में है, जबकि कर्मभूमि रेवाड़ी के कुतुबपुर मोहल्ले में है। माचेड़ी के ग्रामीण अब हेमू की स्मृति में आयोजन के लिए भी आगे आने लगे हैं। इस वर्ष माचेड़ी में तीसरा आयोजन हुआ। धर्म जागरण मंच के अखिल भारतीय संयोजक कमलेश आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और उपस्थित लोगों से हेमू की गौरवगाथा घर-घर पहुंचाने का आह्वान किया।

वक्ताओं ने दैनिक जागरण का हेमचंद्र विक्रमादित्य के गौरवशाली इतिहास को प्रमुखता से प्रकाशित करने के लिए आभार व्यक्त किया। जागरण में प्रकाशित हो चुके आठ लेख बैकड्रॉप पर थे। दुर्गावाहिनी की हरियाणा प्रदेश संयोजक डॉ. इंदुराव की पहल पर माचेड़ी के गोपाल सिंह, पृथ्वी सिंह और कई अन्य लोगों ने आयोजन किया। धर्म जागरण मंच के संयोजन कमलेश ने कहा कि हमें अपने उन पूर्वजों को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने माटी के लिए बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि हेमू ने उस काल खंड में हिंदू धर्म की पताका को फहराई, जिसमें आक्रमणकारी देश को लूट रहे थे। उन्होंने कहा कि स्कूलों व कॉलेजों में प्रार्थना सभाओं में हेमू की वीरगाथा पढ़ाई जानी चाहिए। विश्वविद्यालयों में हेमू की पीठ स्थापित होनी चाहिए। स्कूलों व लाइब्रेरी के नामकरण होने चाहिए। इसके लिए माचेड़ी के ग्रामीण विभिन्न राज्यों के शिक्षा बोर्डों और शिक्षा मंत्रियों के पास आग्रह भेजें।

‘मेरी बेटी भाजपा शासित राज्य में पकड़ी गई होती तो उसकी हत्या हो जाती’

जागरण संवाददाता, बरेली

▸ चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा के पिता ने लगाया आरोप

पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा के पिता ने भाजपा सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अगर मेरी बेटी उत्तर प्रदेश या फिर भाजपा शासित राज्य में पकड़ी गई होती तो उसे मार डाला जाता। वह भाजपा सरकार से जान बचाकर पहले दिल्ली गई थी और फिर वहां से राजस्थान चली गई। वहां कांग्रेस की सरकार थी। वह रुहेलखंड विश्वविद्यालय में अपनी बेटी और बेटे का दाखिला कराने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाकर पकड़ा गया है, वे मेरी बच्ची के सीनियर और दोस्त थे। आरोप लगाया कि अगर वे मेरी बेटी की मदद नहीं करते तो चिन्मयानंद के गुंडे उसे कॉलेज में ही मार डालते। एसआइटी दो माह से केवल फिरौती मांगने के केस को जानबूझकर खींच रही है। वह बोले कि जरूरत पड़ी तो सीबीआइ जांच की मांग करेंगे।

छात्रा पर अब रुहेलखंड विश्वविद्यालय के एलएलएम तृतीय सेमेस्टर में 75 फीसद उपस्थिति का दबाव है। छात्रा ने 28 नवंबर से शुरू हो रही परीक्षा के लिए शुक्रवार को फार्म भी भर दिया। रजिस्ट्रार डॉ. सुनीता पांडेय ने छात्रा और उसके पिता से साफ कह दिया है कि अगर 75 फीसद उपस्थिति कक्षा में नहीं हुई तो नियम के अनुसार छात्रा को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि कोर्ट के आदेश पर विशेष परिस्थिति में जरूर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है।

इस दौरान मीडिया से बातचीत में छात्रा के पिता ने विशेष जांच दल (एसआइटी) की जांच को संदेह के घेरे में खड़ा किया। कहा कि वीडियो और रंगदारी के मामले में उसे जानबूझकर दोषी साबित करने की कोशिश की जा रही है। झूठे सुबूत बनाए जा रहे हैं। छात्रा ने कहा कि रंगदारी से जुड़े वीडियो किसने बनाए और उसका क्या इस्तेमाल हुआ, उसे कोई जानकारी नहीं है। छात्रा ने खुद पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया।

छात्रा ने जब चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाया तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया था। उत्तर प्रदेश शासन को निर्देश दिया था कि एसआइटी जांच कराएं और छात्रा की आगे की पढ़ाई का इंतजाम किया जाए। चूंकि छात्रा व उसका भाई चिन्मयानंद के कॉलेज में ही पढ़ाई करते थे, इसलिए दोनों का प्रवेश बरेली में कराने को कहा गया। 25 सितंबर को छात्रा को जेल भेज दिया गया। इसके बाद प्रवेश के लिए उसके वकील ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां अपील की थी। कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को उसके प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कराई गई। वहीं उसके भाई का अन्य लॉ कॉलेज में एलएलबी में प्रवेश कराया गया।

मौसम विशेष

पंजाब के उत्तरी भागों में आंशिक बादलों के साथ हल्की वर्षा संभव है। हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान में आंशिक बादलों के साथ गर्म रहेगा। जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में सुबह ठंडी और सुहावनी रहेगी। दिन आरामदायक रहेगा। कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा होगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	33/24/व	अहमदाबाद	33/24/व
कोलकाता	33/24/सा	बड़ौदा	33/22/व
चेन्नई	32/24/व	नागपुर	33/20/व
हैदराबाद	29/23/आंबा	इन्दौर	30/21/आंबा
बंगलूरु	27/19/सा	राँची	33/22/आंबा
त्रिवेन्द्रम	32/24/व	पटना	32/22/आंबा
गुवाहाटी	29/21/व	जमशेदपुर	34/23/व
गंगटोक	13/04/व	पुणे	31/21/व

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 19 अक्टूबर 2019
आजकल
16
www.jagran.com

महामारी बनने वाली बीमारी टीबी (तपेदिक) का इलाज सामने आया

1943 में आज ही अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक एंटीबॉयोटिक दवा तैयार की थी, जिसका नाम स्ट्रेप्टोमाइसिन था। यह पहली ऐसी दवा थी जिससे टीबी का उपचार संभव हुआ था। इस दवा की खोज अल्बर्ट शेट्ज नामक एक छात्र ने की थी। इसके लिए 1952 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था।

जर्मनी में खुला था दुनिया का पहला डिस्कोथेक

1959 में आज ही डिस्कोथेक स्कॉच क्लब के उद्घाटन की रिपोर्टिंग करने आए क्लाउस क्यूरिनी नामक पत्रकार ने रिकार्ड प्लेयर का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया लोगों का मनोरंजन किया। इसी के साथ क्लाउस दुनिया के पहले डिस्क जॉकी भी बन गए।

महान खगोलशास्त्री थे नोबेल विजेता सुब्रमण्यन चंद्रशेखर

भारतीय-अमेरिकी खगोलशास्त्री सुब्रमण्यन चंद्रशेखर का जन्म 1910 में आज ही लाहौर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मद्रास में हुई थी। उन्होंने तारों की संरचना और उनके विकास की प्रक्रिया का गहरा अध्ययन किया था। इसके लिए उन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने 'हवाइट ड्वॉर्फ' नामक नक्षत्रों से जुड़ा सिद्धांत दिया। इन नक्षत्रों के लिए उन्होंने जो सीमा निर्धारित की है, उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। उन्होंने ब्लैक होल्स पर भी काम किया। वह नोबेल पुरस्कार विजेता महान वैज्ञानिक सीवी रमन के भतीजे थे। 21 अगस्त, 1995 को दुनिया को अलविदा कह तारों में विलीन हो गए।

इधर-उधर की

बकरी ने लोगों को कर दिया मिमियाने पर विवश

न्यूयॉर्क, एजेंसी : 'तेज भागती इस बकरी के अगर आप मालिक हैं तो फौरन दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। यह बकरी कानून-व्यवस्था को धता बताते हुए इधर उधर भाग रही है। अराजकता का माहौल पैदा कर रही है। कृपया आइए और इसे पकड़ने में हमारी मदद कीजिए।' अलास्का के फेयरीबैंक्स एनीमल कंट्रोल की तरफ से फेसबुक पर डाली गई इस सूचना के बाद यहां हर कोई इस बकरी के पीछे पड़ गया। वह सड़कों को इधर-उधर पार करती हुई भागी चली जा रही थी। लोगों ने प्यार से उसे करी बुलाना शुरू कर दिया। लोगों ने जब इसकी तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट करते हुए इसके मौजूद होने के स्थान का जिक्र किया तो सुरक्षाकर्मियों को काफी मशक्कत के बाद इसे पकड़ने में सफलता मिली। सुरक्षाकर्मियों के अनुसार करी पालतू बकरी नहीं है बल्कि यह बकरियों के झुंड से निकल भागी थी। सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाएं इसके मालिक तक पहुंची तो उसने अधिकारियों से गुहार लगाई कि वे बकरी को माफ कर दें।

रचा इतिहास ▶ क्रिस्टीना कोच व जेसिका मीर ने की आइएसएस के बाहर चहलकदमी

पहली बार सिर्फ महिलाओं ने किया स्पेसवॉक

2024 तक पहली महिला को चांद पर भेजने की तैयारी

221 बार स्पेसवॉक हो चुका अब तक आइएसएस के बाहर

15 महिलाएं, पुरुषों के साथ 42 स्पेसवॉक में शामिल हो चुकी हैं

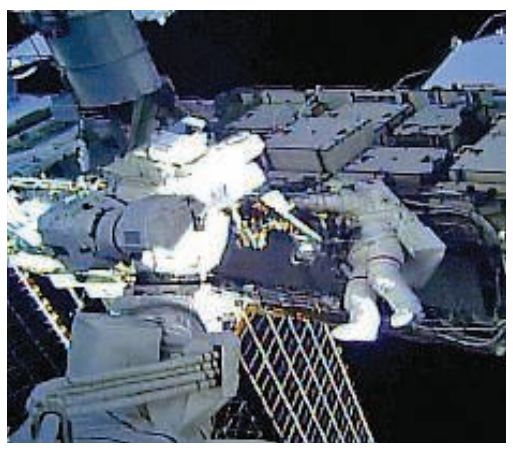

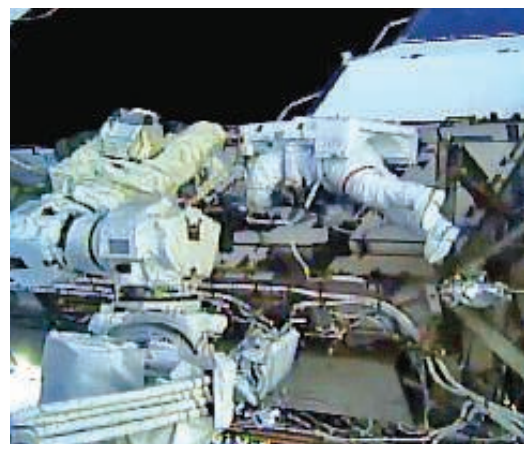

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आइएसएस) के बाहर स्पेसवॉक करतीं अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर (पहली) व क्रिस्टीना कोच (दूसरी)। एएफपी/रायटर

शुक्रवार शाम पांच बजे शुरू हुआ अभियान

वाशिंगटन, आइएएनएस : अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय स्पेस सेंटर (आइएसएस) के बाहर चहलकदमी (स्पेसवॉक) कर इतिहास रच दिया है। यह पहली बार है, जब सिर्फ महिला अंतरिक्ष यात्रियों की टीम ने आइएसएस के बाहर चहलकदमी की है। इस अभियान को लेकर नासा ने कहा, 'महिला अंतरिक्ष यात्रियों की जोड़ी का यह मिशन मील का पत्थर है। यह और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि एजेंसी 2024 तक पहली महिला को चांद पर भेजने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।'

नासा के मुताबिक कोच चौथी बार स्पेसवॉक कर रही हैं। वहीं मीर पहली बार इस तरह के अभियान का हिस्सा बनी हैं। दोनों को इस अभियान के दौरान आइएसएस के खराब पड़े पॉवर कंट्रोलर 'बैट्री चार्ज-डिसचार्ज यूनिट' को बदलना था। यह यूनिट 11 अक्टूबर से ही खराब था लेकिन, इससे स्टेशन में चल रहे शोध या वहां मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित नहीं हुई थी। यूनिट को बदलने के लिए दोनों भारतीय समयानुसार शाम पांच बजे आइएसएस से बाहर आई थीं।

मार्च में ही होना था अभियान : सिर्फ महिलाओं द्वारा अंतरिक्ष में चहलकदमी का यह अभियान गत मार्च में ही होना था। नासा के अनुसार, क्रिस्टीना कोच के साथ एनी मैकक्लेन उस अभियान का हिस्सा थीं। हालांकि, उपयुक्त स्पेससूट ना होने की वजह से उसे टाल दिया गया था।

स्टेशन की मरम्मत के लिए अब तक का 221 वां स्पेसवॉक : आइएसएस व उसमें लगे उपकरणों की मरम्मत के लिए अब तक कुल 221 स्पेसवॉक हुए हैं। इस साल आठ बार इसी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों ने स्टेशन के बाहर चहलकदमी की थी। इन अभियानों में पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पहले भी कई महिलाओं ने हिस्सा लिया था। अब तक 15 महिलाएं पुरुषों के साथ 42 स्पेसवॉक में शामिल हो चुकी हैं।

फिल्म रिव्यू

उद्वेलित नहीं करती प्रतिशोध-कथा

लाल कप्तान

निर्देशन : नवदीप सिंह
मुख्य कलाकार : सैफ अली खान, मानव विज, जोया हुसैन, सिमोन सिंह
अवधि : 2 घंटे 35 मिनट

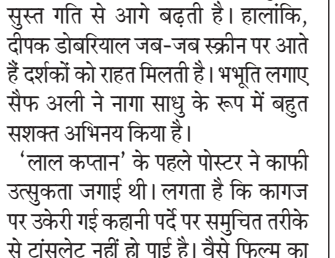

फिल्म 'एनएच 10' के करीब चार साल बाद नवदीप सिंह ने पीरियड ड्रामा 'लाल कप्तान' का निर्देशन किया है। फिल्म की कहानी काल्पनिक है, लेकिन उसे बक्सर के युद्ध (वर्ष 1764) के आसपास गढ़ा गया है। इस फिल्म में किरदार लगातार सफर कर रहे होते हैं, हालांकि वे किस स्थान पर हैं, फिल्म में इसकी कोई जानकारी नहीं होती। ब्रिटिश शासकों की भारत में मजबूत होती पैठ की पृष्ठभूमि में प्रतिशोध की कहानी गढ़ी गई है।

कहानी का आरंभ एक नवयुवक को फांसी देने के दृश्य के साथ होता है। कहानी 25 साल आगे बढ़ती है। नागा साधु गोसाईं (सैफ अली खान) खुद को भोलेनाथ का सिपाही कहता है। वह रहमत खान (मानव विज) की खोज में हैं, जो पिछले दो साल से मुनेरगढ़ के राजा हुकुम सिंह का किलेदार है। गोसाईं खूंखार और इनामी डाकू को मारकर उससे एक लॉकेट हासिल करता है, जिसका रहस्य बाद में उजागर होता है। उधर, किलेदार रहमत खान खजाना लेकर अंग्रेजों से मुलाकात की तैयारी में हैं। उसके साथ उसकी बेगम (सिमोन सिंह) और दुधमुंहा बेटा है। सफर के इस पड़ाव में रहमत और गोसाईं मिलते हैं। इसके बाद फिल्म में धीरे-धीरे किरदारों की परतें खुलती हैं।

'लाल कप्तान' में मुख्य किरदारों के साथ एक जानवर रहता है। सैफ अली के किरदार के साथ घोड़ा है, तो दीपक डोबरियाल के साथ दो कुत्ते रहते हैं। दीपक का किरदार सूंघकर पता बताने में माहिर है। फिल्म का शुरुआती हिस्सा सैफ अली खान के किरदार को स्थापित करने में चला गया है। शुरू में जोया के किरदार का लहजा बुंदेली है, जो बाद में खड़ी बोली में बदल जाता है। प्रतिशोध का यह ड्रामा कौतूहल, नफरत या प्रेम का भाव उद्वेलित नहीं कर पाता है। फिल्म की शूटिंग ज्यादातर रियल लोकेशन पर की गई है। नागा साधु के गेटअप में सैफ अली का आक्रोश और गुस्सा उनकी आंखों में झलकता है। हालांकि, उनकी जटाओं का इस्तेमाल लेखक-निर्देशक ने कहीं भी करने का प्रयास नहीं किया है। जोया हुसैन का किरदार पेचीदा और घुमावदार रखा गया है। नॉन गैलमरस किरदार में होने के बावजूद वह आकर्षक लगी हैं। सिमोन सिंह ने रहमत खान की बीवी की भूमिका में उसके तेवर बखूबी व्यक्त किए हैं। हालांकि, उनके किरदार की गहराई में लेखक-निर्देशक नहीं गए हैं।

कॉमेडी से इतर दीपक डोबरियाल को अपने अभिनय का नया आयाम दिखाने का भरपूर मौका मिला है। उनका अंग्रेजी में हाउ डू यू डू बोलना बहुत ही रोचक लगता है। मानव विज कम डायलॉग के बावजूद अपने हावभाव और आंखों के माध्यम से अपने मनोभावों को बखूबी व्यक्त कर पाते हैं। नवदीप सिंह ने इस फिल्म को एक पीरियड वेस्टर्न बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिल्म की लंबाई दर्शकों को बोर करती है। फिल्म बहुत ही सुस्त गति से आगे बढ़ती है। हालांकि, दीपक डोबरियाल जब-जब स्क्रीन पर आते हैं दर्शकों को राहत मिलती है। भभूति लगाए सैफ अली ने नागा साधु के रूप में बहुत सशक्त अभिनय किया है।

'लाल कप्तान' के पहले पोस्टर ने काफी उत्सुकता जगाई थी। लगता है कि कागज पर उकेरी गई कहानी पर्दे पर समुचित तरीके से ट्रांसलेट नहीं हो पाई है। वैसे फिल्म का बैकग्राउंड संगीत अच्छा है। फिल्म का अंत सीक्वल का संकेत देता है।

-स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

अब बच्चों का ख्याल रखेगा स्मार्ट स्पीकर

वाशिंगटन, प्रेट्र : शोधकर्ताओं ने एक नया स्मार्ट स्पीकर विकसित किया है, जो व्हाइट नॉइस के माध्यम से बच्चों को सोने में मदद करता है साथ ही उनकी सांस और गतिविधि की निगरानी भी करता है।

अमेरिका की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार ब्रेथ जूनियर नामक स्मार्ट स्पीकर व्हाइट नॉइस बजाता है और यह देखता है कि व्हाइट नॉइस का असर किस तरह से हो रहा है। यह पता लगाने के लिए वह शिशु की छाती से सांस लेने की गति का पता लगाता है। शोधकर्ताओं ने एक अस्पताल की नवजात गहन इकाई में पांच नवजात बच्चों के साथ ब्रेथ जूनियर का परीक्षण किया। इस दौरान जब बच्चों की श्वसन दर का पता लगाया गया तो पाया गया कि यह दर एक आदर्श पैमाने के बिल्कुल करीब थी।

वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर जैकब सनसाइन ने बताया कि नए माता-पिता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि उनके बच्चे पर्याप्त नींद लें। वे सोते हुए भी अपने बच्चे की निगरानी करना चाहते हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की कोशिश की गई जो शिशु की स्वसन दर की निगरानी करती है और व्हाइट नॉइस के माध्यम से उनको सुखद नींद भी दिलाती है। इस प्रणाली को एक स्मार्ट स्पीकर में समाहित किया गया है।

शोधकर्ताओं ने बताया कि ब्रेथ जूनियर के माध्यम से शिशुओं में असामान्य सांस के पैटर्न का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि एप्निया के दौरान शिशुओं की श्वसन दर असामान्य रहती है। जो शिशु जल्दी पैदा होते हैं उनके मस्तिष्क में स्वसन केंद्र नहीं विकसित हो पाते हैं।

अमेरिका के शोधकर्ताओं ने इस स्पीकर का नाम 'ब्रेथ जूनियर' रखा है। प्रतीकात्मक

क्या होता है व्हाइट नॉइस

आपको याद होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जमाने में जब एंटीना हिलने से या चैनल बदलने के दौरान स्क्रीन पर काले-सफेद मच्छर जैसे दिखने लगते थे और तेज सरसराहट की आवाज होती थी। इसे ही व्हाइट नॉइस कहा जाता है। दरअसल व्हाइट नॉइस विभिन्न ध्वनि आवृत्तियों का संयोजन होता है। यह एक आरामदायक ध्वनि होती है। यह अन्य उन आवाजों को दबा देता है जिससे सोता हुआ बच्चा जाग सकता है।

अधिक वजन वाले लोगों के फेफड़ों में जमा होता है वसा

वाशिंगटन, प्रेट्र : शोधकर्ताओं ने पहली बार यह बताया है कि अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त लोगों के फेफड़ों में भी वसा जमा हो सकता है। हालांकि, शोधकर्ता यह पहले से जानते थे कि जो लोग मोटापे से ग्रस्त हैं उनमें घरघराहट या अस्थमा की ज्यादा संभावना रहती है, लेकिन इसके कारणों को अब तक पूरी तरह से नहीं बताया गया था।

यूरोपियन रेस्पिरेटरी जर्नल में प्रकाशित नए अध्ययन से पता चलता है कि वसायुक्त ऊतक शरीर में वायुमार्ग की संरचना को बदल देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सर चार्ल्स गर्डनर हॉस्पिटल के एक शोधकर्ता जान एलियट ने बताया कि शोध के लिए दान किए गए 52 लोगों के फेफड़ों का अध्ययन किया। इनमें से 16 की मौत अस्थमा की वजह से हुई थी। 15 ऐसे थे जिन्हें अस्थमा नहीं था और 21 एसे थे जिन्हें अस्थमा था, लेकिन उनकी मौत दूसरी वजह से हुई। शोधकर्ताओं ने फेफड़ों में वसायुक्त ऊतक की खोज की फिर उस व्यक्ति के बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआइ) से तुलना की। इस दौरान पाया कि जिनका वजन ज्यादा था उनके फेफड़ों में वसायुक्त ऊतक ज्यादा पाए गए।

शोध अनुसंधान

वजन कम करना है तो नाश्ते से पहले करें एक्सरसाइज

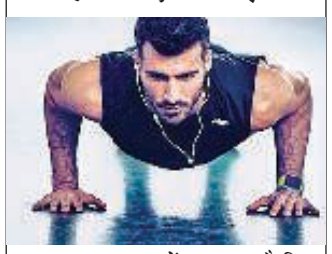

एक नए अध्ययन में पाया गया है कि नाश्ते से पहले एक्सरसाइज करने से सेहत को ज्यादा फायदा हो सकता है। खाने और एक्सरसाइज के समय में बदलाव करने से ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। इससे वजन कम करने में भी मदद मिल सकती है। ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता जेवियर गोंजालेज के अनुसार, हमने नाश्ते से पहले एक्सरसाइज करने वालों में फैट की खपत का स्तर दोगुना पाया। यह निष्कर्ष ज्यादा वजन वाले 30 लोगों पर छह सप्ताह तक किए गए एक अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। नाश्ते से पहले एक्सरसाइज करने वालों में इंसुलिन के लिए प्रतिक्रिया में वृद्धि पाई गई। यह फर्क खाने के समय में बदलाव करने से आया। - आइएएनएस

नर्व कैंसर के इलाज में मदद करेगी नई थेरेपी

वैज्ञानिकों को एक टारगेटेड थेरेपी विकसित करने में बड़ी सफलता मिली है। इस थेरेपी से न्यूरोब्लास्टोमा नामक खतरनाक पीडीएट्रिक्स नर्व कैंसर से पीड़ित बच्चों के उपचार में मदद मिल सकती है। न्यूरोब्लास्टोमा से पीड़ित किशोर उम्र के बच्चों में आमतौर पर इस घातक बीमारी की जल्द पहचान नहीं हो पाती। इस वजह से बीमारी गंभीर हो जाती है। अमेरिका के एकॉन स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने ताजमेटोस्टेट नामक टारगेटेड थेरेपी विकसित की है। यह थेरेपी ईजेएच2 नामक एंजाइम को अक्षम बनाती है। यह एंजाइम ऐसे जीन को रोकता है, जो सामान्य न्यूरॉन (तंत्रिका कोशिका) की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। नतीजन न्यूरोब्लास्टोमा सेल्स खत्म होने लगती हैं। न्यूरोब्लास्टोमा एड्रिनल ग्लैंड की अपरिपक्व नर्व सेल्स में उत्पन्न होता है। -एएनआइ

जब गिलहरी से डर गई लोमड़ी

शिकार पर निकली लोमड़ी को चेतावनी देती दिखाई देती पहाड़ी गिलहरी (हिमालयन मर्मोट) की इस तस्वीर को वन्यजीव 2019 की कैटगरी में सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। इस दृश्य को चीन के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बायो योंगकिंग ने अपने कैमरे में कैद किया। यह नजारा चीन के किंघई-तिब्बती पठार क्षेत्र का है। (साभार-गार्जियन)

अलास्का में हादसे का शिकार हुआ विमान

अलास्का में बेरिंग सागर के पास एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त पेनएयर एयरवेज का विमान हादसे का शिकार हो गया। इस विमान में 42 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसमें हाईस्कूल की तैराकी टीम भी सवार थी। माना जा रहा है कि तेज हवाओं की वजह से विमान का लैंडिंग के वक्त संतुलन बिगड़ गया। पेनएयर के सीईओ डेव पफीगर ने बताया कि हमारी प्रार्थनाएं घायलों के साथ हैं। उन्होंने लोगों के सुरक्षित बचने पर भगवान का शुक्रिया अदा किया। एपी

स्क्रीन शॉट

बचपन की दोस्त के लिए रणवीर सिंह ने बदला अपना शेड्यूल

आम तौर पर सितारों के शेड्यूल में बदलाव की गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन जब बात बचपन की दोस्ती की आती है, तो हर बदलाव मुमकिन है। कुछ ऐसा ही किया रणवीर सिंह ने भी। दरअसल, उनकी फ्रेंड ब्राइडल डिजाइन सिमोन खंबाटा उनकी बचपन की दोस्त हैं। जब दोनों 11 साल के थे, तब से उनकी दोस्ती है। सिमोन उनके साथ कई यात्राओं पर भी गई हैं। स्टार बनने के बाद रणवीर का शूटिंग के सिलसिले में मुंबई से बाहर आना-जाना लगा रहता है। इस बार जब उनकी दोस्त को उनकी जरूरत थी, तो रणवीर मुंबई में ही थे। सूत्रों की माने तो सिमोन वेडिंग एग्जिबिशन में अपना कलेक्शन शोकेस करने वाली थीं। जैसे ही इसकी खबर रणवीर को लगी, उन्होंने सिमोन के शो में रैंप वॉक करने के लिए उस दिन के सारे काम रद कर दिए और पूरा दिन दोस्त को समर्पित कर दिया। सिमोन अपने शो में रणवीर सिंह के शो स्टॉपर बनने के फैसले से बहुत खुश थीं। उन्होंने कहा कि रणवीर और उनकी दोस्ती समय के साथ गहरी हुई है। जब रणवीर अपनी बर्थडे पार्टी में गोविंदा के गानों पर डांस किया करते थे, वह तब से ही यह बात जानती थीं कि वह एक दिन बहुत बड़े स्टार बनेंगे। रणवीर ने सिमोन की तारीफ में कहा कि 'सिमोन बेहद क्रिएटिव हैं। बड़े होते समय हमारी कई यादें एक-दूसरे के साथ जुड़ी हैं। मुझे खुशी है कि मैं उनकी उपलब्धियों को एक छोटा-सा हिस्सा बन पाया हूं।'

सिद्धार्थ मल्होत्रा की अंगुलियों पर नजर आया सर्वधर्म टैटू

सिद्धार्थ मल्होत्रा की अगली फिल्म 'मरजावां' हैं। उसमें एक बार फिर वह अपने एक्शन अवतार में नजर आएंगे। फिल्म में उनके अपोजिट तारा सुतारिया हैं। उनका किरदार गूंगी लड़की का है। तारा इससे पहले 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' में नजर आई थीं। जबकि इस फिल्म के पहले हिस्से यानी 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने फिल्मी सफर का आगाज किया था। अब यह दोनों स्टूडेंट 'मरजावां' में रोमांस करते दिखेंगे। खास बात यह है कि सिद्धार्थ के हाथों की अंगुलियों पर क्रॉस (क्रिश्चियन), अल्लाह (इस्लाम), वाहेगुरु (सिख), ऊं (हिंदू) के टैटू दिखाई देंगे। बताया जाता है कि इसके जरिए फिल्म 'सर्व धर्म समभाव' का संदेश देना चाहती है। यह टैटू अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर अभिनीत सुपरहिट फिल्म 'अमर अकबर एंथोनी' की याद दिला रही है। उसमें तीनों किरदारों की परवरिश अलग-अलग धर्म में हुई थी। मिलाप जावेरी निर्देशित 'मरजावां' में रितेश देशमुख पहली बार बौने के किरदार में नजर आएंगे।

किया दावा

डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट में दी गई जानकारी, भारत में वर्ष 2017 के मुकाबले 50 हजार टीबी के मामले हुए कम

भारत में दर्ज नहीं हुए टीबी के 5 .4 लाख मामले

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत में पिछले साल तपेदिक (टीबी) के 5.4 लाख मामले दस्तावेज में दर्ज होने से रह गए। हालांकि, देश में वर्ष 2017 के मुकाबले वर्ष 2018 में टीबी के मरीजों की संख्या में 50 हजार की कमी आई है। यह दावा विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट में किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017 में भारत में टीबी के 27.4 लाख मरीज पाए गए, जबकि वर्ष 2018 में इनकी संख्या 26.9 लाख रही। यही नहीं, प्रति एक लाख आबादी के सापेक्ष टीबी के मरीजों की संख्या वर्ष 2017 में 204 थी जो वर्ष 2018 में घटकर 199 हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के अनुसार, 'विश्व भर के देशों में चलने वाले टीबी कार्यक्रमों में औसतन 30 लाख मरीज दस्तावेज में दर्ज होने से छूट जाते हैं। भारत में वर्ष 2018 में 26.9 लाख टीबी के मरीज पाए गए, जिनमें से 21.5 लाख ही भारत सरकार के दस्तावेजों में दर्ज हो पाए। 5.40 लाख टीबी के मरीज दस्तावेजों में दर्ज होने से छूट गए।'

हालांकि, इस दौरान भारत को टीबी पर जीत की दिशा में कई उल्लेखनीय सफलताएं भी हाथ लगीं। रिफैंपसिन नामक टीबी की दवा की जांच के दौरान वर्ष 2017 में 32 फीसद मरीज प्रतिरोधी पाए गए, जबकि वर्ष 2018 में इनकी संख्या बढ़कर 46 फीसद हो गई। बीमारी के उपचार में सफलता की दर वर्ष 2016 में 69 थी जो वर्ष 2017 में 81 फीसद हो गई। डब्लूएचओ के महानिदेशक डॉ. टीए घेब्रेयस ने कहा, 'टीबी पर जीत के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। इसका मतलब है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना होगा।' बता दें कि टीबी के मामले इस वजह से ज्यादा बढ़ते हैं क्योंकि शुरुआती समय में मरीज को इसकी पहचान नहीं हो पाती और सही देखरेख के आभाव में यह बीमारी गंभीर हो जाती है।

प्रतीकात्मक

199 टीबी मरीज हैं भारत में प्रति एक लाख की आबादी में 2018 के आंकड़ों के अनुसार

2017 में भारत में टीबी के 27.4 लाख मरीज पाए गए, जबकि वर्ष 2018 में इनकी संख्या 26.9 लाख रही

वर्ष 2018 में लोगों ने लिया सबसे ज्यादा आत्मरक्षक उपचार

ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में लोगों ने अभूतपूर्व तरीके से आत्मरक्षक उपचार लिया। इसका प्रमुख कारण रहा कि टीबी की पहचान व उपचार की सुविधा बढ़ी है। वर्ष 2017 में दुनिया भर में टीबी से 16 लाख लोगों की मौत हुई, जो वर्ष 2018 में घटकर 15 लाख हो गई। शुरुआती चरण में रोग का पता चलने पर बीमारी का तुरंत इलाज कराया जा सका।

एक्टिंग के लिए दूसरे काम नहीं छोड़ सकतीं गुल

अभिनेत्री गुल पनाग जल्द ही फिल्म 'बाईपास रोड' में दिखाई देंगी। हालांकि गुल का अब एक्टिंग की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि सिर्फ अभिनय पर ध्यान देना खुद को सीमित कर लेना है। गुल कहती हैं, 'मुझे हाल ही में काफी अच्छे रोल मिले हैं, लेकिन अब मैं इसमें खुद को बांध नहीं सकती। मेरे लिए एक्टिंग ही सब कुछ नहीं है। हमेशा से मुझे अलग-अलग क्षेत्रों में रुचि रही है।' वह कहती हैं, 'एक्टिंग ने मुझे दूसरे कामों में भी सक्षम बनाया है। चाहे वह मेरा राजनैतिक करियर हो, सोशल एक्टिविटी हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर मेरे अन्य कार्य, इन सब को करने में मुझे एक्टिंग ने मदद की, क्योंकि एक एक्ट्रेस के रूप में मैंने सार्वजनिक जीवन जीना शुरू किया। एक पर्सनैलिटी के रूप में मुझे पहचान मिली। इसका उपयोग मैंने अपने विचारों को हर प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने में किया।' गुल कहती हैं कि अब उनके पास बहुत से काम हैं, जिन्हें मैं एक्टिंग के कारण छोड़ नहीं सकती।' 'डोर', 'मनोरमा सिक्स फीट अंडर', 'समर 2007' और 'अब तक छप्पन' जैसी फिल्मों में काम करने वाली गुल स्क्रीन पर एक मजबूत महिला के रूप में दिखाई दी हैं। 'बाईपास' में उनके साथ नील नितिन मुकेश, अदा शर्मा और सुधांशु पांडे भी दिखाई देंगे। इस फिल्म में गुल ने नील की सौतेली मां रोमिला का किरदार निभाया है। फिल्म 1 नवंबर को रिलीज होगी।

उम्मीद से कैंसर को हराया राकेश ने

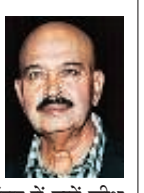

कैंसर से संघर्ष कर सामान्य जीवन में लौटने के बाद फिल्ममेकर राकेश रोशन ने बताया कि उन्होंने किस तरह इसका मुकाबला किया। राकेश ने बताया कि पिछले साल सितंबर में उन्हें जीभ के नीचे छाला हुआ था। एक दिन वह एक दोस्त से मिलने अस्पताल गए, तो डॉक्टर के कहने पर बायोप्सी कराई। वह कहते हैं, 'मुझे अंदेशा हो गया था कि मुझे कैंसर है। कैंसर विशेषज्ञ सर्जरी के बारे में डरावनी सलाह देते। इसी बीच रितिक ने एक डॉक्टर से संपर्क किया और सर्जरी के दो दिन बाद घर आ गया। शारीरिक रूप से मैं कमजोर हो गया था, लेकिन मानसिक रूप से खुद को मजबूत बना रखा। ऐसे समय में नकारात्मक विचारों से बचना जरूरी है। थ्रोट कैंसर की वजह से सर्जरी के बाद पानी पीना तक मुश्किल हो गया था, लेकिन मैंने उम्मीद बनाए रखी। मैं जानता था अगर मैं नकारात्मक सोच रखूंगा तो रिकवर नहीं कर पाऊंगा।' इस दौरान परिवार का सहयोग रहा।